

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

आर्थिक एवं वाणिज्यिक निबन्ध

(संक्षेपिका लेखन एवं अपठित सहित)

लेखक

डॉ० शिवध्यानसिंह चौहान

एम० कॉम०, पी०एच० डी०

प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग,

बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा

१९६१

वंसल पब्लिशिंग हाउस
आगरा

प्रकाशक :
वंसल पब्लिशिंग हाउस
रोगन मुहल्ला,
झागरा ।

प्रथम संस्करण—१९६१

मूल्य . रु० २'८१

मुद्रक :
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्रेस
शीतला गली,
झागरा ।

लेखन कला सीखने की विधि

निम्न कक्षाओं में लेख लिखना उतना कठिन काम नहीं जितना उच्च कक्षाओं में। निम्न कक्षा के विद्यार्थियों से यही आशा की जाती है कि वे सही एवं स्पष्ट भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकें; विषय के सर्वाङ्गपूर्ण ज्ञान की आशा उनसे नहीं की जाती। किन्तु उच्च कक्षा के विद्यार्थियों से शुद्ध भाषा और स्पष्ट भाव प्रकाशन के साथ-साथ विषय का ज्ञान भी अपेक्षित है।

उच्च कोटि का लेख लिखने के लिए अध्ययन, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है। बहुधा युवकों के सम्मुख जो कठिनाई उपस्थित होती है, वह है आवश्यक सामग्री की। उनका विषय ज्ञान सीमित होता है और उन्हें कुछ भी कहने में हिचक लगती है। कारण यह है कि उनका अनुभव और अध्ययन अत्यन्त सीमित होते हैं। अतएव लिखना सीखने वाले विद्यार्थियों को विस्तृत अध्ययन और सामान्य ज्ञान-संचय की बड़ी भारी आवश्यकता है।

अध्ययन—अध्ययन को सफल बनाने के लिए थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। जिस विषय का हमें अध्ययन करना है, उसमें रूचि उत्पन्न करें और उस सम्बन्ध में जो भी पुस्तक-पुस्तिकाएँ मिल सकें उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के साथ-साथ एक कापी पर संक्षिप्त विवरण भी लिखते जायें। यदि कभी उस विषय पर आकाश-वाणी (Radio) भ्रमवा किसी वक्ता द्वारा किसी प्रसिद्ध लेखक अथवा विद्वान के विचार प्राप्त करने का अवसर मिले तो उन्हें भी ध्यान से सुनें और लिख लें। वाणिज्य के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अन्य पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ 'सम्पदा', 'उद्योग व्यापार पत्रिका' इस्टर्न इकॉनोमिस्ट (The Eastern Economist), इकॉनोमिक वीकली (The Economic Weekly), कामर्स (The Commerce), कैपिटल (The Capital) इत्यादि पत्रिकाओं को अवश्य देखते रहें। इन पत्रिकाओं में उन्हे आर्थिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि के लेख और वैज्ञानिक आलोचना मिल जायगी।

इस भाँति विषय का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त उस पर मनन करना चाहिए और दूसरों के विचारों का अपने निजी विचारों से मेल मिलाना चाहिए। हमारा अध्ययन हमारे मानसिक संस्थान का अंगतभी बन सकता है जबकि अधीत विषय का अपने पूर्वाजित ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाय। इसके लिए मनन आवश्यक है। हमको मतभेद और समानताएँ दोनों ही ध्यान में रखनी चाहिए। नये प्रयोगों को ध्यान में रखकर उनका अभ्यास करने के लिए अवसर निकाल व्यवहार में लाना होगा

और शब्दों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसकी व्युत्पत्ति और कोष का अर्थ जानना होगा। हम किसी लेख से तभी लाभ उठा सकते हैं जबकि हम उसमें हचि उत्पन्न करें, और उसे अपने मनन का मुख्य विषय बना लें।

निरीक्षण—केवल अध्ययन मात्र पर्याप्त नहीं है क्योंकि सारा ज्ञान पुस्तकों में ही निहित नहीं होता। हम वास्तविक ज्ञान अपने निज के अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त करते हैं। अध्ययन दूसरों की आँखों से देखना है और निरीक्षण स्वयं अपनी आँखों से। हम दैनिक जीवन की घटनाओं से और अपने चारों ओर के वातावरण एवं वस्तुओं के निरीक्षण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ससारा में हमें आँख खोलकर चलना चाहिए। अपने ज्ञान की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि जो कोई नई घटना अथवा वस्तु देखें, उसका अपने पुस्तकस्थ ज्ञान से मिलात करे और विवेचना के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, अपने ज्ञान में संशोधन कर लें। लेखक को अपनी कल्पना से पूरा-पूरा काम लेना चाहिए और निष्कर्ष निकालने चाहिए। जिस विषय का हम अध्ययन करें उसके निरीक्षण का भी पूर्ण प्रयास करें।

अभ्यास—अभ्यास मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यास द्वारा ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। दिना पानी में पुसे तैरना नहीं आता। इसी भाँति बिना अभ्यास के ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। बहुधा विद्यार्थी किसी विषय पर लिखने का इसलिए प्रयास नहीं करते कि उस पर उगहोने कभी कुछ लिखा नहीं है। उनको नवीन विषय को लेकर कुछ भी लिखने में बड़ा संकोच और हिचकिचाहट होती है, वे आत्म विश्वास खो बैठते हैं और यह समझने लगते हैं कि जो कुछ वे लिखेंगे वह अधूरा, अस्पष्ट और अपूर्ण होगा। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। बिना प्रयास के न तो कभी कोई कुछ सीख सकता है और न भूलों का ही सुधार कर सकता है। ठोकर खाकर बुद्धि आती है, भूल करने के उपरान्त ही भूल सुधार होता है। एक साथ न कोई बड़ा ज्ञान अन्न सकता है, न लेखक, क्षणाभर में न हम उत्तमि के शिखर पर पहुँच सकते हैं और न अवनति के गर्त में ही गिर सकते हैं। प्रत्येक कार्य धीरे धीरे समया-नुसार होता है। अतः हमें आत्म-विश्वास रखकर, धैर्य और साहस के साथ कठिन से कठिन विषय का अभ्यास करने में हिचकिचाना न चाहिए। लेख ठीक कराने का चाहे अवसर मिले या न मिले, लेख लिखना उपयोगी है। यदि स्वयं अपने विचार न हों तो दूसरों के विचारों को अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास जानने से भी लाभ होता है। लेख लिखने के उपरान्त यदि सतोष न हो तो उसे दो तीन चार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और स्वयं ही आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने चाहिए। यदि किसी को दिखाकर सम्मति प्राप्त करने का या संशोधन कराने का अवसर मिल सके तो अति-उत्सह है। जो संशोधन किया जाय उसको वाद रखना चाहिए। एक एक प्रकार के कई लेख लिखने से अनायास ही अभ्यास बढ़ता है और हम में लेखन शक्ति आती है। पहले छोटे लेखों से अभ्यास प्रारम्भ करें। फिर क्रमशः बड़े बड़े लेख लिखने का प्रयास करें।

ही-संदर्भ या परिच्छेद रखना वाछनीय है। उन संदर्भों में स्वाभाविक क्रम स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक है। कभी किसी बात अथवा तर्क को दुहराना न चाहिए।

संगति और निर्वाह—विचारों में संगति रखना परम आवश्यक है। यह संगति तभी आ सकती है जबकि विचार स्पष्ट हों। यदि कोई विचार स्पष्ट न हो तो उतने ही विचारों को संकित करना चाहिए जितने कि पूर्णतः स्पष्ट हो। सन्देहात्मक भावों के उल्लेख से हमारा लेख कमजोर होता है और हमारी भाषा अस्पष्ट। जिस भाव या विचार का उल्लेख करें, उसका पूरा निर्वाह करना चाहिए, उसके किसी पक्ष को छोड़ना न छोड़ें। विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर हम अपना तर्क उपस्थित करें। लिखते समय हमें यह समझ कर विषय को समझाना चाहिए कि पाठक उस विषय से सर्वथा अनभिज्ञ है। अतः उसे अच्छा समझकर मोटी से मोटी बात भी बड़ी सावधानी और तर्क द्वारा समझानी है।

भाषा और शैली—भाषा और शैली की उत्तमता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि विचार की। उत्तम भाषा और शैली से लेखक के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अशुद्ध और अस्पष्ट भाषा सुन्दर से सुन्दर विचारों के पाठित्व को नष्ट कर देती है और विचार मरुभूमि में पड़े हुए बीजों की भाँति अनुत्पादक रह जाते हैं। जहाँ तक सम्भव हो दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम प्रचलित शब्दों को भी निबालने का प्रयत्न करें। दूसरी भाषाओं के जो शब्द देश में प्रचलित हो चुके हैं और हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं, उनके स्थान पर हमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। स्टेशन के स्थान पर हम रेल का शब्द लिखें, थर्मामीटर के लिए ताप-मापक, सिनेमा के लिए चल-चित्र, तथा सालटेन के लिए दीपक कहे, तो अर्थ के स्थान पर अनर्थ होने की सम्भावना है, किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि विदेशी भाषाओं के शब्द अपनी भाषा का ही जामा पहिन कर आँवें।

भाषा सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो बहुत समास वाले या बर्ण बहु शब्दों का व्यवहार न किया जाए। विलम्ब भाषा लिखने का कभी प्रयत्न न करना चाहिए। सरल किन्तु भावपूर्ण भाषा ही जिसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें उत्तम एवं प्रभावशाली भाषा समझी जाती है। जहाँ तक सम्भव हो वाक्य छोटे ही हो।

शैली हमारी अपनी अलग होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। प्रारम्भ में हमें उसका पता चाहे न लगे किन्तु अभ्यास से हमें शैली पूर्णतः स्पष्ट हो जायगी। सभी विषयों में हमें अपनी शैली का निर्वाह करना चाहिए।

आकार—परीक्षा में लेख लिखते समय निर्धारित सीमा का उल्लंघन न करना चाहिए। यदि एक हजार शब्दों का लेख लिखाया जाए तो हम एक हजार पचास अथवा नौ सौ पचास शब्द लिख सकते हैं, किन्तु इस परिधि के बाहर जाना उचित नहीं है। छोटे लेख लिखने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि हम विषय के कुछ ही पहलुओं पर विचार करें। चाहे छोटा लेख लिखाया जाए चाहे बड़ा, प्रत्येक दशा में हमारा विचार-विमर्श सर्वाङ्गपूर्ण होना चाहिए, विषय का कोई भी पहलू छोड़ना न चाहिए। पक्ष-विपक्ष की विचारधारा पर पूर्ण प्रकाश डालना चाहिए। छोटे लेख में प्रत्येक बात संक्षेप में कहनी चाहिए और बड़े लेख में विस्तारपूर्वक।

उद्धरण—दूसरी भाषा के उद्धरण लेख के मुख्य अंग के रूप नहीं दिए जा सकते। उनका संक्षिप्त भाव लेख में देकर उनका मूल पन्ने के नीचे की टीका के रूप में दिया जा सकता है। हाँ, हिन्दी भाषा में लेख लिखते समय संस्कृत अथवा सजातीय भारतीय भाषाओं के उद्धरण मूल लेख का अंग हो सकते हैं, किन्तु अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषाओं के नहीं।

“मेरी कल्पना को सहकारी खेती से जमीन का काया पलट हो जायेगा और लोगों की गरीबी और बेकारी का काला मुंह हो जायगा।”

—न० गांधी (हरिजन ६-३-१९४७)

१—सहकारी खेती

रूप-रेखा

१. सहकारी खेती की आवश्यकता
 - (क) प्रति व्यक्ति कम भूमि अथवा छोटी जोतें ।
 - (ख) खेती का बिखरा होना ।
 - (ग) भूमि का असमान वितरण ।
२. सहकारी खेती की परिभाषा
 - (क) पारस्परिक सहयोग की भावना ।
 - (ख) प्रजातन्त्रीय प्रबन्ध ।
 - (ग) धन का उचित वितरण ।
३. सहकारी खेती के प्रचलित रूप
 - (क) सहकारी श्रेष्ठतर खेती ।
 - (ख) सहकारी संयुक्त खेती ।
 - (ग) सहकारी कृषक खेती ।
 - (घ) सहकारी सामूहिक खेती ।
४. सहकारी खेती के लाभ
 - (क) भूमि, श्रम एवं यंत्र-उपकरणों का सदुपयोग ।
 - (ख) कृषि उपज में बढ़ोत्तरी ।
 - (ग) एकता की भावना ।
५. सहकारी खेती की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति
६. सहकारी खेती के मार्ग में कठिनाइयाँ
 - (क) किसान का भूमि के प्रति मोह ।
 - (ख) योग्य कर्मचारियों का अभाव ।
 - (ग) वर्ग संघर्ष एवं ग्रामीण फूट ।

- (ग) सदस्यो म प्राय वा विनरण किसी सर्वमान्य ढग से, अर्थात् भूमि की मात्रा अथवा धन के अनुपात में हो ।

प्रचलित रूप

सहकारी खेती के चार रूप देखने में आते हैं—(क) श्रेष्ठतर कृषि, (ख) समुक्त कृषि, (ग) कृषक कृषि, (घ) सामूहिक कृषि ।

(क) श्रेष्ठतर कृषि—इस या अधिक व्यक्ति अपने सम्मिलित हित के लिए मिल कर सहकारी समिति बनाते हैं । प्रत्येक सदस्य खेती स्वतन्त्र रूप में अलग-अलग करता है । बवल सम्मिलित हित के उपादन कार्य समिति करती है : ऋण व्यवस्था, उत्तम खाद, उत्तम बीज, यंत्र, ऋण-विक्रय, सिंचाई, बाँध बनाना, सब निवारण, बुवाई, कटाई, गह्राई इत्यादि । समिति सभी सदस्यों को समान नीति पालन करने का आग्रह करती है । सदस्यों के अंशों अथवा आयमानुसार लाभ का बँटवारा किया जाता है ।

(ख) समुक्त कृषि—छोटे-छोटे किसान अपनी जोती को मिलाकर बड़ी जोतें बना लेते हैं, यद्यपि भूमि पर उनका पृथक स्वामित्व बना रहता है । उपज में से खर्च निकाल कर भूमि के मूल्यानुसार लाभानु सदस्यों को दिया जाता है । सदस्य समिति के आशानुसार कार्य करते हैं, उन्हें कार्य के लिये मजदूरी दी जाती है ।

(ग) कृषक खेती—समिति पट्टे पर या बयनामे द्वारा भूमि ले कर सदस्यों को बाँट देती है जिस पर खेती करने में वे स्वतन्त्र होते हैं । सदस्य समिति को निश्चिन लगान देते हैं तथा उसके पट्टेदार अथवा आसामी की भाँति काम करते हैं । समिति आवश्यक धन, खाद, बीज, यन्त्र, ऋण-विक्रय इत्यादि की उचित व्यवस्था करती है । भूमिकर अथवा उपज के अनुसार लाभ सदस्य बाँट लेते हैं । इस भाँति भूमिहीन किसानों को खेती करने का अवसर मिलता है ।

(घ) सामूहिक कृषि—सामूहिक कृषि के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व, प्रबन्ध और खेती कराने का सारा उत्तरदायित्व समिति के ऊपर होता है । समिति भूमि मोल अथवा पट्टे पर लेती है और सदस्यों से सामूहिक रूप में खेती कराती है । कार्य करने के लिये सदस्यों को मजदूरी दी जाती है । लाभ का बँटवारा मजदूरी अथवा लगाए हुए साधनों के अनुपात में होता है ।

लाभ

सहकारी खेती से देश के छोटे और बिखरे हुए भू-खण्डों के अनेक दोष दूर हो जायेंगे तथा कृषि-कार्य लाभकर हो सकेगा । उसके अनेक लाभों में निम्नांकित की कल्पना की जाती है :

(१) प्रति एकड़ उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि हो कर देश की गरीबी दूर होगी ।

(२) किसान की आय में वृद्धि होकर उसका जीवन-स्तर उच्च हो सकेगा ।

(३) कृषि-योग्य भूमि का प्रपेक्षाकृत प्रच्छा उपयोग होगा। अनुमान लगाया गया है कि खेतों की मेढबंदी समाप्त होने से ५० लाख एकर अतिरिक्त भूमि पर खेतों होने लगेंगी।

(४) सहकारी कृषि से धर्म शक्ति का सदुपयोग हो सकेगा। खेतों के छोटे टुकड़ों पर धर्म का भ्रंश क्षय होता है, और बहुत सा समय एक खेत से दूसरे तक जाने में व्यर्थ जाता है।

(५) हल बैल, उपकरण और सिंचाई सुविधाओं का समुचित एवं सुनिरचित उपयोग संभव हो सकेगा।

(६) बड़े खेतों पर वैज्ञानिक गवेषण और प्राथमिक सहायता सुलभ हो सकेगी।

(७) गाँवों में सामाजिक एवं सामुदायिक एकता की भावना बढ़ेगी।

(८) सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता इत्यादि सहज सुलभ हो सकेगी।

(९) उत्तम संगठन के कारण कृषि सम्बन्धी प्राकड़ों का सचय संभव हो सकेगा।

(१०) कृषि उपज की विप्रे में और आवश्यक पदार्थों के कम की सुविधा होगी।

(११) सरकार और किसान के बीच घनिष्ठता एवं सहयोग का वातावरण उत्पन्न होगा।

वर्तमान स्थिति

युद्धोत्तर काल में सहकारी कृषि की ओर भारत का विशेष ध्यान गया है। इसका कारण कृषि उपज बढ़ाने और लाल समस्या पर काबू पाने का है। १९४६ में भारत सरकार ने एक शिष्ट प्रमण्डल क्लिस्तीन भेजा किन्तु उसके फलस्वरूप कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं उठाया जा सका। प्रथम योजना में छोटे किसानों को सहकारी समितियों में संगठित करने और राज्यों की सरकारों को कोई कमबद्ध कार्य धर्म बना कर प्रयोग करने का विचार व्यक्त किया गया। द्वितीय योजना में प्रत्येक जिले में एक या दो कृषि फार्मों पर प्रयागात्मक योजनाएँ चालू करने और उन्हें खेती सहकारिता, कृषि तथा विस्तार सेवाओं के प्रशिक्षण केंद्रों में परिवर्तित करने की बात कही गई। इसी समय १९५६ में भारत सरकार ने खेतों को एक शिष्टमंडल भेजा जिसका आवेदन जून १९५७ में प्रकाशित हुआ। सितम्बर १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की एक स्थायी समिति (Standing Committee) ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की शेष अवधि में देश में ३००० कृषि सहकारी समितियाँ बनाने का सुझाव रखा। नवम्बर १९५८ में उक्त सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा सहकारी खेती

के महत्व की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। इसी विचारधारा के अनुसार जनवरी १९५६ में कांग्रेस महासमिति ने अपना नागपुर का विवादास्पद प्रस्ताव देश के सामने रखा। मार्च १९५६ में नागपुर प्रस्ताव के विचार को लोक-सभा ने प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया। इनसे देश में इस प्रश्न पर भारी वाद-विवाद खड़ा हो गया। अतएव जून १९५६ में भारत सरकार ने इस प्रश्न के पूर्ण अध्ययन के लिये एक कार्यकारी समुदाय (Working Group) की नियुक्ति की जिसने फरवरी १९६० में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख उपस्थित किया। समुदाय ने ४ वर्ष की अवधि में देश के प्रत्येक जिले में एक के हिसाब से ३,२०० सहकारी कृषि समितियों की प्रयोगात्मक योजनाएँ चालू करने का सुझाव दिया है। समुदाय के सुझावों के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०,००० कृषि सहकारी समितियाँ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये ३,२०० प्रयोगात्मक समितियों के अतिरिक्त होंगी।

इस समय देश में २,४४२ सहकारी कृषि समितियाँ हैं जिनमें ४८,००० व्यक्ति काम करते हैं और ३,३४,००० एकड़ भूमि पर इनके द्वारा कृषि की जाती है। सबसे अधिक समितियाँ पंजाब में (६७८) हैं। बम्बई में ५१०, उत्तर प्रदेश में २६२, मध्य प्रदेश में २०१, असम में १८४, पश्चिमी बंगाल में १६१, मैसूर में १२८ तथा राजस्थान में १०३ समितियाँ हैं। अन्य राज्यों में १०० से कम समितियाँ हैं।

सहकारी खेती के मार्ग में कठिनाइयाँ

सहकारिता का सिद्धान्त बहुत ऊँचा है और भारत की खाद्य समस्या और कृषि उपज की वृद्धि के लिये श्लाघनीय प्रतीत होता है। तो भी इसके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से मुख्य बाधाएँ निम्नांकित हैं :—

(क) भारतीय किसान का भूमि के प्रति भारी मोह है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के शब्दों में भारतीय किसान को भूमि पत्नी के समान प्रिय है। कुछ लोगों के अनुसार भूमि के प्रति किसान का सन्तान का सा मोह है। अपनी भूमि पर दूसरे का स्वामित्व उसे असह्य है।

(ख) भूमि भारतीय किसान का जीवनाधार ही नहीं, उसकी सामाजिक मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। भूमि के अनुसार ही ग्रामीण समाज में लोगों को सम्मान प्राप्त होता है तथा सन्तान के विवाह-सम्बन्ध निश्चित होते हैं। अतएव भूमि की मेडबन्दी हटने से वर्ग-संघर्ष का बीजारोपण हो सकता है।

(ग) सहकारी खेती से उत्पादन-वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति सन्देहात्मक है। संसार के किसी भी क्षेत्र में सहकारी कृषि ने उत्पादन-वृद्धि की प्रेरणा नहीं दी। बड़े खेतों में प्रति एकड़ उपज अधिक नहीं होती, बरन् छोटे खेतों में होती है। देश-विदेश के अनुभव से यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है। भारत में पारिवारिक खेती ही श्रेयस्कर एवं सफल हो सकती है।

(ग) भारत में ईमानदार, तपस्वी और निःस्वार्थ जन-सेवकों का भारी अभाव है। बिना ऐसे व्यक्तियों के सहकारिता की सफलता सन्देहात्मक है। आज हमारे गाँव द्वेष-भाव, वैमनस्य, अपराध, स्वार्थ और भुक्तमेवाजी के क्षेत्र बन गये हैं जहाँ सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले योग्य कार्यकर्त्ताओं का मिलना दुर्लभ है।

(घ) सहकारी खेती की सफलता का आधार कृषि का यंत्रीकरण है। यंत्रों के प्रयोग से बेकारी बढेगी जो अग्नि में आहुति देने के समान है। देश में यी ही बेकारों की अपार संख्या है।

(च) वर्तमान ग्रामीण वातावरण और किसान की मनोवृत्ति के फलस्वरूप बल का प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है जो वाछनीय नहीं है। स्वेच्छा से संसार के किसी भी देश में सहकारी खेती सफल नहीं हुई है। भारत में भी ऐसी ही संभावना है।

(छ) संसार के देशों में अथवा भारतीय क्षेत्रों में जहाँ सहकारी कृषि के प्रयोग किए गये हैं वे विफल रहे हैं।

(ज) भारत में कृषि का यंत्रीकरण सफल नहीं हुआ।

(झ) गाँवों की फूट देश में उपयुक्त वातावरण नहीं उपस्थित करती।

उपसंहार

वर्तमान परिस्थितियों में वाछनीय यही है कि सीमित क्षेत्र में सम्मिलित खेती के प्रयोग किये जायें और अनुभव के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। नये तोड़ो, विस्थापित बस्तियों तथा सार्वजनिक भूमि में संयुक्त खेती के प्रयोग किये जायें। सेवा सहकारिताओं द्वारा लोगों को सहकारी खेती के लाभ बताये जायें। आदर्शवाद और भावुकता के स्थान पर व्यावहारिकता को प्रमुखता दी जायें।

“ऐटम और हाइड्रोजन को हिंसा शक्ति का सबसे बड़ा पराक्रम माना जाता है, उसी तरह ग्राम शक्ति से सर्वस्वदान, अहिंसा-शक्ति का सबसे बड़ा पराक्रम माना जायेगा।”

— विनोबा

२—भूदान-यज्ञ

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना
२. अर्थ
३. दार्शनिक आधार
४. भूदान पुण्यों में श्रेष्ठ क्यों ?
५. उद्देश्य
६. प्रारम्भ और प्रगति
७. लाभ
८. आलोचना
९. उपसंहार

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी ७० प्रतिशत जनसंख्या का निर्वाह कृषि पर निर्भर है और हमारी राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन भी कृषि ही है, किन्तु देश की कृषि व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि का असमान वितरण है। एक ओर देश में २०% जनसंख्या ऐसे किसानों की है जिनके पास निजी भूमि नहीं है, वे दूसरों से भूमि लेकर कृषि कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त ५ करोड़ भूमिहीन श्रमिक हैं जो दूसरे लोगों के नौकर रह कर कृषि कार्य करते हैं, उनसे उन्हें केवल मजदूरी मिलती है। दूसरी ओर ५३ लाख भूपति हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, दूसरों से कराते हैं। अनेक बड़े किसान और हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि है और जो दूसरों की सहायता से अपनी भूमि को जोतते हैं। भूदान भूमि के इस असमान वितरण के पुनर्वितरण का एक सात्त्विक प्रयत्न है।

एवं प्रेम का मार्ग है जो लोगों को न्याय बुद्धि जगाकर एवं उनका हृदय परिवर्तन करके सम्पत्ति के न्यायपूर्ण, उचित और समान वितरण की ओर प्रयत्नशील है ।

दार्शनिक आधार

विनोबा जी का कहना है कि हवा, पानी, प्रकाश की भाँति भूमि भगवान की देन है । जैसे पानी नहीं बेचा जाता और हवा की कोई कीमत नहीं कूनी जाती, वैसे ही भूमि खरीदने बेचने के लिए नहीं, बरन् प्रेम से लेन-देन के लिए है । उस पर किसी एक का स्वामित्व सामाजिक पाप है । इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है कि भूपति अपनी भूमि का दान कर दे । भूमिहीन को भूमि देना बंसा ही धर्म है जैसे भूखे को भोजन और व्यासे को पानी देना ।

भूदान केवल पुण्य के लिए नहीं, बरन् दाता की रक्षा के लिए भी जरूरी है । वर्तमान युग में वर्ग-संघर्ष और सामाजिक असन्तोष की जो आंधी चल रही है, उससे यदि भूदान द्वारा बचाव न हुआ तो भूपति की जमीन तो जायेगी ही, वह अपनी इज्जत भी खोयेगा । यदि दाता अपनी जमीन का त्याग करता है तो वह अपनी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है और महान यज्ञ का भागी होता है ।

याचक को स्वजन मान कर दान की क्रिया सरल बना दी गई है । दाता से विनोबा कहते हैं—“भाई, तेरे घर में पाँच बेटे हैं । मैं छठवाँ होकर तेरे घर में प्रगट हुआ हूँ । तू मुझे दरिद्रनारायण की खातिर मेरा हक मुझे वापस कर दे ।” जब परमेश्वर हमारे सामने दरिद्रनारायण का रूप लेकर साक्षात् खड़े हैं और मदद माँग रहे हैं, तो हमें उन्हीं की सेवा करना चाहिए । यही भूदान-यज्ञ का मूल विचार है ।

इस आन्दोलन द्वारा विनोबाजी भूमिदानों, सम्पत्तिदानों और विद्वानों की कर्तव्यपरायणता जगाना चाहते हैं । वे पैसे की प्रतिष्ठा तोड़ कर धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना और संघर्ष व स्पष्टता की प्रतिष्ठा तोड़कर प्रेम की कीमत बढ़ाना चाहते हैं । यह आन्दोलन मर्णादा-शीलता और हकी पर जोर देने की प्रपेक्षा कर्तव्यों पर जोर देता है ।

भूदान का आधार प्रेम और अहिंसा द्वारा लोगों की मानवता जगा कर उनका मत-परिवर्तन और हृदय परिवर्तन है । आज अमीर अपनी अमीरी के कारण जड़ हैं और गरीब अपनी गरीबी के कारण निष्प्राण हैं । दोनों की मनोवृत्ति बदलने की जरूरत है । भूदान यज्ञ दोनों की मालकियत माँगता है । मालकियत के विसर्जन से जहाँ अमीरों का घहंकार टूटेगा, वहाँ गरीबों की दीनता मिटेगी और उनकी अन्तःचेतना जागेगी ।

भूदान पुण्यों में श्रेष्ठ क्यों ?

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी समस्या भूमि की है । यदि वह शान्तिपूर्वक हल की जा सकी तो हम सवार को यह जता सकेंगे कि संसार के बड़े से बड़े प्रश्न शान्ति मार्ग से हमारी इस समस्या की भाँति ही हल हो सकते हैं । इससे ससार का पथ-प्रदर्शन हो सकेगा ।

भूमि उत्पादन का प्रारम्भिक एवं प्रमुख साधन है और उसका दान जीविका साधन देने के समान है। वह स्थायी दान है। याचक को दर-दर माँगने की आवश्यकता नहीं रहती।

यदि लोगो को मुचन खिलायें तो वे भ्रान्सी बनते हैं। भूमि प्राप्त करने वाला उसे परिश्रम से कमायेगा। वह भ्रालसी नहीं बन सकता। उसकी उन्नति होती है।

भूदान में देने वाला घमडी नहीं बनना और न लेने वाला दीन-हीन। देने वाला अपना अहंकार छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर देता है और लेने वाला उसे अपना अधिकार समझ कर प्राप्त करना है।

भारत में गाँव-गाँव के धंधे टूट रहे हैं। लोगो को कुछ आधार जमीन ही है। जमीन की मालकिन मिटाना पुण्यो में सर्वश्रेष्ठ पुण्य है।

एशिया भर में जमीन की माँग है और जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ लोगो के हाथ भूमि रहने से शेष लोग असन्तुष्ट रहते हैं। असन्तोष से हिंसा बढ़ती है। भूदान से अशांति मिटती है। दुनिया हिंसा के भय से बचती है।

विनोबा जी का विश्वास है कि यदि भूमिहीनो में भूमि बँटेगी तो स्वराज्य की किरणें सूर्य की किरणों के समान घर-घर में पहुँचेगी। सम विभाजन के दृष्टि कोण से भी भूदान एक उत्तम पुण्य है।

उद्देश्य

भूदान का मुख्य उद्देश्य देश की भूमि समस्या का समाधान है। भूमि समस्या हल करने के लिए जमींदारी उन्मूलन, चकबन्दी, सहकारी सेती इत्यादि अनेक युक्तियाँ सोची गई हैं और कानून बनाए गये हैं, किन्तु सफलतापूर्वक समस्या हल नहीं हुई। भूदान हृदय परिवर्तन द्वारा भूमि के न्यायपूर्ण वितरण की ओर एक महान प्रयत्न है।

भूदान का सन्देश लोको की न्याय बुद्धि जगाने और उनकी विचार शुद्धि के लिए है। लोगो को न्याय-प्रियता सिखाकर भूदान एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना चाहता है जिसमें पूर्णतः आर्थिक और सामाजिक साम्य हो।

भूदान का एक उद्देश्य गाँव की सभी समस्याओं का हल है। यह गाँव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का एक शान्तिमय मार्ग है। हर गाँव की कुल जमीन गाँव में बँटनी चाहिए, हर गाँव में आमोचोग होने चाहिये, हर गाँव को अपनी आवश्यकताओं की योजना बनानी चाहिए। हर गाँव अपना कार्य अपने ढंग से करेगा। इस भाँति शान्ति जीवन में रामराज्य की भावना का समावेश ही भूदान का लक्ष्य है।

अन्ततोगत्वा, भूदान का उद्देश्य (क) भूमि और सम्पत्ति में व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त करके सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना, (ख) एक शस्त्रहीन एवं शासनहीन समाज का निर्माण, (ग) मताधिकार का अन्त करके सर्व सम्पत्ति द्वारा निर्णय तथा (घ) मद्र भवशा और असहयोग द्वारा सम्मिलित सुरक्षा व्यवस्था करना है।

प्रारम्भ और प्रगति

भूदान का प्रारम्भ आन्ध्र प्रान्त के तेलंगाना क्षेत्र में हुआ। तेलंगाना के लोगो ने अपनी भूमि समस्या हल करने के लिये हिंसा का मार्ग अपनाया। परिणाम यह हुआ कि हजारो की हत्या हुई और हजारो की जमीन छीनी गई। लोगो का आराम से रहना दुश्कर हो गया। एक ओर रात के राजाघो, कम्युनिस्टो की तोड़-फोड़ और मार-घाड़ और दूसरी ओर सरकार का दमन चक्र और इन दोनों के बीच जनता पिस गई। महात्मा गांधी के परम शिष्य विनोबा जी तेलंगाना के लोगो की दुखदर्द कहानी सुनकर उधर जा निकले। उनसे नलगोडा जिले के पोचमपल्ली गांव के हरिजन भाइयो ने ८० एकड़ भूमि की याचना की। विनोबा जी ने अपनी प्रार्थना समा में यह मांग उपस्थित की। तुरन्त श्री रामचन्द्र रेड्डी नामक जमींदार ने उन्हें १०० एकड़ भूमि दान में दे दी। इस प्रकार १८ अप्रैल १९५१ को भूदान यज्ञ का सूत्रपात हुआ। इस दान को विनोबा जी ने भगवान की प्रेरणा का सन्नेत समझकर गांव-गांव पैदल चलकर भूदान मांगना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने तेलंगाना की ५१ दिन की यात्रा की; ५१ गांवो में पड़ाव डाले, वे २०० गांवो में घूमे और दो लाख व्यक्तियों से बातचीत की, इस यात्रा में उन्हें १२,००१ एकड़ भूमि दान में मिली। उन्होंने गांवो के ५०० भगडों का भी निवटारा किया। २७ जून को विनोबा जी अपने पौनार आश्रम पहुँच गए। पंडित नेहरू के निमन्त्रण पर १२ सितम्बर १९५१ को उन्होंने दिल्ली की पदयात्रा प्रारम्भ की। १३ नवम्बर को वे दिल्ली पहुँचे। ६२ दिन की इस पदयात्रा में उन्हें १९,४३६ एकड़ भूमि दान में मिली। २ अक्टूबर को सागर नगर में उन्होंने १९५७ तक षीक करोड़ एकड़ भूमि संचित करने की घोषणा की। १ - अप्रैल १९५२ को सेवापुरी (उ० प्र०) के सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर सर्व सेवा संघ ने २५ लाख एकड़ भूमि आगामी दो वर्ष में प्राप्त करने का संकल्प किया। इस भाँति भूदान का प्रथम चरण समाप्त हुआ।

२३ अक्टूबर १९५० में अपनी बिहार प्रान्त की यात्रा में विनोबा जी ने सम्पत्तिदान का नया आन्दोलन प्रारम्भ किया जो भूदान का द्वितीय चरण माना जा सकता है। भूमि की भाँति सम्पत्ति में भी व्यक्तिगत स्वामित्व न मानकर समाज का स्वामित्व माना जाए और अपनी आवश्यकता से अधिक को दान में दिया जाय। जि हे यज्ञ की भूमि दी जाती है उन्हें हल, बैल, बीज इत्यादि के लिये सम्पत्ति की आवश्यकता भी है।

मई १९५३ में मगरोठा का प्रथम ग्रामदान हुआ। यह भूदान आन्दोलन का तृतीय चरण माना जा सकता है। ग्रामदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण गांव भूमि से निजी स्वामित्व त्यागकर उसे 'ग्राम समाज' को अर्पण कर देता है। ग्राम समा अथवा पंचायत भूमि का जोतने के लिये वितरण करती प्रथमवा सहाकारी होती करानी है। यह गांव के पुनर्निर्माण एवं उसके अन्न व वस्त्र स्वावलंबन का एक नूतन ढंग है।

मार्च १९५३ में शासन मुक्त व शोषण विहीन समाज रचना की घोषणा की गई, अप्रैल १९५४ में प्रथम जीवन-दान प्राप्त हुआ और एक नया अध्याय भूदान

ग्रान्दोलन में जुडा । कालान्तर में धमदान, ताल्लुकदान, सर्वस्वदान इत्यादि अनेक दान-मूलक शब्द इसमें सम्मिलित हुए ।

अप्रैल १९६० तक भूदान में ८०० लाख एकड़ भूमि सात लाख दाताओं से प्राप्त हो चुकी थी । इन नौ वर्ष में विनोबा जी ने ३०,००० मील की पदयात्रा की है । लगभग पाँच हजार सम्पूर्ण गाँव भी दान में प्राप्त हुए हैं । अन्य सम्पत्ति, धमदान, जीवनदान के भी अनेक आदर्श उपस्थित किये गए हैं ।

इस ग्रान्दोलन को सफल बनाने के लिये २० लाख रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकारों से और २२ लाख रुपये की केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई है । लगभग सभी राज्यों में भूदान सम्बन्धी नियम और कानून भी बन चुके हैं । इस भाँति भूदान एक देशव्यापी आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण का ग्रान्दोलन बन गया है ।

लाभ

इस ग्रान्दोलन से अनेक लाभ हुये हैं : (१) अनेक भूमिहीनों की भूमि के रूप में निर्वाह साधन प्राप्त हुए हैं और देश की एक गभीर समस्या का हल निकला है । (२) भूदान ने भूमि के सदुपयोग और उत्पादन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, क्योंकि भूदान में बहूधा परतों और बंजर भूमि ऐसे लोगों को दी गई है जो उसे परिश्रम से कमा सकें । (३) भूमि के स्वामित्व में स्थिरता आई है, क्योंकि दान में मिली भूमि के बेचने और गिरवी रखने का अधिकार नहीं दिया जाता । (४) इस भाँति भूदान ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति सुधार रहा है और उन्हें कर्त्तव्यपरायणता एवं स्वावलम्बन का पाठ पढ़ा रहा है । (५) भूदान से सबसे बड़ा लाभ एक नूतन विचार क्रान्ति को जन्म देता और नैतिकता वृद्धि है । ग्रान्दोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेम वृद्धि है । (६) भूदान अहिंसक क्रान्ति द्वारा एक सर्वोदयी कल्याणकारी समाज की स्थापना करने में रत है । (७) इस ग्रान्दोलन से देश को निष्काम कर्म की शिक्षा मिल रही है । (८) भारत की भूमि समस्या के हल करने के साथ ही यह ग्रान्दोलन विश्व को एक नया संदेश दे रहा है कि कानून और बल प्रयोग के स्थान पर हमारी अनेक समस्याएँ प्रेम, शान्ति और अहिंसा के मार्ग से सहज हल हो सकती हैं । (९) भूदान से खादी, ग्रामोद्योग, नई शिक्षा, सहकारी समितियों एवं पंचायत व्यवस्था को विशेष बल प्राप्त हुआ है । (१०) भूदान जाति भेदों का निरसन चाहता है । वह संसार के सभी लोगों के सुख सृष्टि की कामना करता है ।

आलोचना

भूदान ग्रान्दोलन की कुछ लोगों ने बड़ी आलोचना भी की है । (क) प्राप्त भूमि का वितरण अत्यन्त मन्द गति से हो रहा है । ८० लाख एकड़ भूमि में से अभी तक ८॥ लाख एकड़ अर्थात् १० प्रतिशत का ही वितरण हुआ है । (ख) दान में प्राप्त भूमि का एक बड़ा भाग बंजर और बेकार भूमि बतलाई जाती है । कुछ लोग ६० प्रतिशत और कुछ ९० प्रतिशत ऐसी भूमि बताते हैं । (ग) भारतीय किसान की जीतें

यों ही छोटी हैं। भूदान उनके उपविभाजन और मजदूरों को प्रेरणा देता है। यह शंका निराधार है, क्योंकि जोत की प्रभावशक्ति का ध्यान रखकर ही भूमि का वितरण किया जाता है और सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। (घ) भूमि बहुधा साधनहीन एवं योग्यता रहित व्यक्तियों के अधिकार में चली जाती है जो आवश्यक अनुभव के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते। साधनहीन लोगों के महाजन के चंगुल में फँसने की संभावना रहती है। (ङ) नये किसानों के निचे हल, बैल, बीज आदि साधनों के अभाव में भूमि बेकार पड़ी रहती है और उत्पादन घटता है।

उपसंहार

भूदान आन्दोलन ने देश में एक नई शक्ति और नई विचारधारा को जन्म दिया है जो लोगों में आत्मीयता और प्रेम बढ़ा कर पारस्परिक कलह और द्वेषों को मिटा रहा है। इस मोतिक्वादी युग में भूदान विचार बुद्धि, त्याग-श्रद्धा, सप एवं अहिंसा का एक अद्भुत अस्त्र है। भूदान के द्वारा कानून बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिली है। इससे रचनात्मक कार्यक्रम में लोगों की भास्था बढ़ रही है और उनकी त्रिध्वंसात्मक प्रवृत्ति का निराकरण हो रहा है। ग्रामराज्य और राम-राज्य के आदर्श की ओर यह एक नूतन प्रयोग है जो भारतीय गाँवों के जागरण एवं पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।



"जिस राष्ट्र को अपना अन्न परदेश से लाना पड़ता है, उसकी स्वतन्त्रता हमेशा खतरे में है।"
—काका कालेलकर

३—खाद्यान्न समस्या

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना
२. समस्या का स्वरूप
३. हल की प्रावश्यकता
४. अन्नाभाव के कारण
५. हल करने के प्रयत्न
६. अशोक मेहता समिति
७. कुछ अन्य मुद्दाव
८. उपसंहार

प्रस्तावना

यह हास्यास्पद एवं आश्चर्यजनक बात है कि इस कृषि प्रधान और साधन सम्पन्न देश में लोगों को अन्न-संकट का सामना करना पड़े। द्वितीय युद्ध के वर्षों में इस समस्या का जन्म हुआ जबकि बंगाल के अकाल जैसे संकट भारत पर आए। तब से अनेक प्रयत्नों के उपरान्त भी इस समस्या को हल करने में हम अग्रसर्य रहे हैं और देश को करोड़ों रुपए के खाद्यान्न प्रति वर्ष विदेश से आयात करने पड़ते हैं। खाद्यान्न का अभाव देश में द्वितीय युद्ध से पूर्व भी था, किन्तु वह ग्रामीण क्षेत्र में सीमित था। ग्रामीण जनता के मूक स्वभाव के कारण वह समस्या के रूप में हमें नहीं प्रतीत होता था। खाद्यान्न (मुख्यतः गेहूँ) का षोडा निर्वात और सस्ते मूल्य इस समस्या पर आवरण डाले रहते थे। द्वितीय युद्धकाल में यह कमी नगरों में भी पहुँच गई जहाँ के लोग संगठित होकर बू हल्ला मचाने लगे। अतएव यह समस्या अपना विकराल रूप धारण कर हमारे सम्मुख खड़ी दिखाई दी।

समस्या का स्वरूप

इस समस्या का मुख्य पहलू खाद्यान्न का भौतिक अभाव है। यह अभाव देश

की आवश्यकता के लगभग १०% के बराबर है। देश की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। १९५२ में खाद्यान्न की कमी का अनुमान ४८ लाख टन लगाया गया था। इस कमी की खाद्यान्न के आयात द्वारा पूर्ति की जाती है जो १९४७ और १९५९ के तेरह वर्षों में ७ से ४७ लाख टन तक घटता बढ़ता रहा है और जिसका औसत लगभग २७.३२ लाख टन वार्षिक होता है। १९५९ में ३८ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। यदि देश के सभी लोगों को पर्याप्त भोजन दिया जाए तो यह कमी लगभग ७५ लाख टन होती है, जिसमें धान की कमी ६० लाख टन और दालों की १५ लाख टन है।

खाद्य समस्या का दूसरा पहलू खाद्यान्न के मूल्यों में उत्तरोत्तर होती हुई वृद्धि है जिससे निम्न श्रेणी के लोगों की क्रय-शक्ति क्षीण होती जाती है। १९३९ की अपेक्षा प्रथम योजना के प्रारम्भ (१९५०-५१) तक खाद्यान्न के मूल्य ४२१ प्रतिशत ऊँचे हो गए थे। १९५२-५३ से कुछ गिरावट हुई, किन्तु १९५५ से फिर वृद्धि होती गई। १९५८ का वर्ष इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक महत्त्व का है जबकि मूल्यों में अपूर्व वृद्धि हुई।

इस समस्या का तीसरा पहलू भारतीय जनता के भोजन में पोषक पदार्थों का अभाव है। भारतीय जनसंख्या के केवल ३९% को उपयुक्त भोजन मिलता है, ४१ प्रतिशत को निम्नकोटि का और २० प्रतिशत को प्रति न्यून कोटि का भोजन मिलता है। प्राधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत के प्रति व्यक्ति के उपयुक्त पोषण के लिए २५०० कैलोरी का उपभोग आवश्यक बताया है, किन्तु इस समय हमारे यहाँ का उपभोग स्तर केवल १,८८० कैलोरी है। इंग्लैंड के प्रति व्यक्ति के भोजन में ३२०० कैलोरी, अमेरिका में ३१५०, कनाडा में ३१४० और जापान में २११२ कैलोरी का समावेश होता है। डाक्टर फ्राकोवड ने भारतीय जनता के उपयुक्त पोषक तत्व प्राप्ति के लिए धान के उपभोग में १० प्रतिशत, दालों में २० प्रतिशत, घी-तेल में २५० प्रतिशत, फलों में ५० प्रतिशत, शाको में १०० प्रतिशत और दूध में ३०० प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है।

हल की आवश्यकता

भोजन का सीधा सम्बन्ध मनुष्य के स्वास्थ्य, उसकी कार्यशक्ति एवं कार्यक्षमता से है। उपयुक्त एवं पोषक भोजन मिलने में मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी कार्यक्षमता पर प्रतिबल प्रभाव पड़ता है। दुर्बल व्यक्ति को रोग भी अधिक सताते हैं। कमी-कमी दुर्बलता भयानक रोग और मृत्यु का कारण भी बन जाती है।

अन्नाभाव के कारण देश के कुछ भागों में भुखमरी फैल जाती है और घोर संकट आ जाता है। १९४३ के बंगाल के अकाल में लगभग ३२ लाख लोगों की जानें जाती रहीं।

साधान जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ के लिए कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना अत्यन्त हेम व सज्जाजनक बात है।

अतएव इस समस्या का शीघ्र हल आवश्यक है।

अन्नाभाव के कारण

(क) जनसंख्या वृद्धि—इस समस्या के कारणों में प्रमुख कारण जनसंख्या की अघार वृद्धि है। जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी गति से साधान उत्पादन नहीं बढ़ रहा। सन् १९०० और १९३४ के बीच जनसंख्या में २१% वृद्धि हुई जबकि जोती जाने वाली भूमि में केवल ११% वृद्धि हुई। सन् १९११-१२ और १९४०-४१ की अवधि में जनसंख्या २८% बढ़ी जबकि भूमि का क्षेत्रफल ५% और अन्नोत्पादन ४%। सन् १९११ में प्रति व्यक्ति पीछे कृषि क्षेत्र ०.९० एकड़ था जो सन् १९५१ में केवल ०.६२ एकड़ रह गया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में देखा गया है कि १९२१ और १९५१ के बीच प्रति व्यक्ति पीछे जोते जाने वाले क्षेत्रफल में भारी कमी हो गई है और भूमि पर दिनों दिन भार बढ़ना जा रहा है। गोरखपुर-देवरिया में सन् १९२१ में प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्रफल ०.७४ एकड़ था जो सन् १९५१ में ०.५० एकड़ रह गया। इसी अवधि में गाजीपुर में ०.७३ से ०.५४, वाराणस में ०.९२ से ०.७५, फैजाबाद में ०.६० से ०.४९ तथा बस्ती में ०.६७ से ०.५७ एकड़ रह गया। इसके विपरीत देवरिया में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या सन् १९०१ में ७१.६% थी जो सन् १९५१ में ९३.५% हो गई, बस्ती में ६४.७% से ९०.७%, आजमगढ़ में ५९.४% से ८३.३% तथा गोंडा में ६३.४% से ८६.३% होगई। गोरखपुर में सन् १९२१ में ६२.३% जनसंख्या खेती पर निर्भर रहती थी, किन्तु सन् १९५१ में ८५.७% होगई। १९५०-५१ और सन् १९५५-५६ के पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पीछे साधान का उत्पादन ४.२२ मन से घट कर ४.०७ मन रह गया।

(ख) वर्षा की अनिश्चितता—भारतीय कृषि बहुधा वर्षा पर निर्भर है। वर्षा समय कुसमय होती है और फसलें खराब हो जाती हैं। वर्षा वर्षों के कुछ ही महीनों में सीमित होती है और वह भी सदैव सर्वत्र निश्चित नहीं। अतएव अन्नोत्पादन में भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता रही आती है। १९५०-५१ और १९५५-५६ की अवधि में उत्तर प्रदेश के १४ पूर्वी जिलों में वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण उच्चतम और निम्नतम उत्पादन चावल का १२३९ हजार टन व ६९५ हजार टन, गेहूँ का ६९२ हजार टन व ४७३ हजार टन तथा मक्का का ३५८००० टन व ५४००० टन हुआ अर्थात् प्रतिशत अन्तर क्रमशः ५४, ३७ और १२३ था।

(ग) रबी प्रकोप—कभी-कभी अलिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प अथवा, अन्य रबी प्रकोपों के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं। अले, रबी, कृषि रोग

कोटाणु, टिड्डी इत्यादि से भी फसलें नष्ट होती देखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलो तथा बिहार में बाढ़ माना वर्षा ऋतु की वार्षिक घटना है।

(घ) असंतुलित और पिछड़ी कृषि—भारतीय कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई है। प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। कृषि के असंतुलन के कारण भी पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन संभव नहीं है। मूल्यों के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किसान अपना उच्चतम लाभ देखकर फसलें बोता है। फसलों के संतुलन की कोई व्यवस्था देश में नहीं है। अतएव कभी गन्ना, कभी कपास, कभी तिलहन इत्यादि का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और खाद्यान्न का कम।

(ङ) देश विभाजन—ब्रह्मा के अलग होने और पाकिस्तान बनने से भी खाद्यान्न के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ब्रह्मा के अलग होने से चावल के लिए देश भारी कमी में आ गया। देश विभाजन के उपरान्त भारत में ८१ प्रतिशत जनसंख्या रह गई जबकि भूमि का क्षेत्रफल केवल ७७ प्रतिशत, चावल का ७३ प्रतिशत, गेहूँ का ७० प्रतिशत तथा सिंचाई क्षेत्रफल ७० प्रतिशत ही देश में रहा। इससे खाद्यान्न की स्थिति बड़ी भयानक हो गई।

(च) उपभोक्ता की लाघ्न मनोवृत्ति में परिवर्तन—युद्ध और उपरान्त काल में राशनिंग एवं मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था लागू की गई जिसके अन्तर्गत गेहूँ और चावल निम्न आय-वर्ग को सस्ते मूल्य पर मिलने लगे। इससे उन लोगों को मोटे अन्नो (जो, चना, ज्वार, बाजरा) के स्थान पर गेहूँ और चावल अधिक खाने की आदत पड़ गई। अतएव गेहूँ और चावल की माँग में अपार वृद्धि होती गई है और होनी जा रही है तथा उनका प्रभाव बढ़ना जा रहा है।

(छ) व्यापारी वर्ग की संग्रह प्रवृत्ति एवं मुनाफाखोरी भी देश में कृत्रिम कमी उत्पन्न करने के लिये उत्तरदाई है।

(ज) ग्रामीण जनता का शहरो में अधिकाधिक बसने जाना भी गेहूँ और चावल की माँग बढ़ाकर अन्न में आह्वति का काम करता है।

हल के प्रयत्न

खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक यत्न किये गये हैं। सन् १९४२ में अन्न के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाया गया और अन्न में बड़े-बड़े नगरों में राशनिंग व्यवस्था जारी की गई। साथ ही साथ 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' प्रारम्भ किया गया। बंगाल के अकाल के पश्चात् खाद्यान्न का निर्यात वर्जित घोषित कर दिया गया तथा विदेश से आवश्यकतानुसार अन्न आयात करने की व्यवस्था की गई। राज्य की सरकारों ने किसानों से अन्न मोल लेना प्रारम्भ किया। १९४७ में स्वावलंबन आन्दोलन छेड़ा गया जिसके अनुसार विविध यत्नों द्वारा देश को १९५२ तक स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य अपनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न की उपज बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया और ६५ लाख टन

अधिक अन्न उत्पन्न करने का लक्ष्य अपनाया गया जिसमें अपूर्व सफलता मिली। द्वितीय योजना में १०० लाख टन अधिक अन्न उपजाने का लक्ष्य भी पूरा हो चुका है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०० से १०५ लाख टन अधिक अन्न उपजाने का लक्ष्य रखा गया है और यह आशा की जाती है कि इस योजना के अन्त तक देश अन्न स्वावलम्बन प्राप्त कर लेगा और विदेश से अन्न आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अशोक मेहता समिति

सन् १९५७ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ब्रिटाई गई जिसने निम्नांकित सुझाव दिये : (क) सरकार खुले बाजार में आवश्यकानुसार अन्न के धन-विक्रय की नीति अपनाए, (ख) अन्न का व्यापार सरकार अपने अधिकार में ले, (ग) अन्न के थोक व्यापारियों पर लाइसेंस द्वारा नियंत्रण लगाये जाए, (घ) देश में गेहूँ और चावल के पर्याप्त भण्डार रखे जाए, (ङ) बाहर से अन्न आयात करने की समुचित व्यवस्था की जाए, (च) मोटे अन्नों के उपभोग पर विशेष जोर दिया जाए (छ) मूल्य स्थिर रखने के लिये एक स्थायी संगठन स्थापित किया जाए; (ज) खाद्य मंत्रालय के संगठन में परिवर्तन किए जायें।

कुछ अन्य सुझाव

(क) इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि अन्न का उत्पादन बढ़ाकर ही खाद्य समस्या हल हो सकती है। अन्नोत्पादन के विविध मार्ग अनेक विशेषज्ञों एवं समितियों ने बताया है। सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाना, उत्तम खाद, उन्नति बीज एवं आधुनिक यंत्र किसान को देना, पसलों का समुचित हेर-फेर, फसल बीने के नए ढंग (मूँटी की बुवाई, चावल का जापानी ढंग), संतुलित खेती, पशुओं की नस्ल सुधार, इत्यादि ऐसी युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा उत्पादन वृद्धि संभव है।

(ख) बगर, दलदल युक्त, खादर, तराई, मूज कास आच्छादित भूमि को खेती योग्य बनाकर खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है।

(ग) जनसंख्या पर रोक लगाए बिना समस्या पर काबू पाना कठिन है क्योंकि २% प्रति वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये प्रति वर्ष १० लाख टन अन्न अधिक उत्पन्न होना चाहिए जो असंभव सा ही है।

(घ) सोमी की गेहूँ-बादल के स्थान पर जो, चना, ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटे अन्न तथा फल, तरकारियाँ, धी-दूध अधिक उपभोग करने की आदत डालनी चाहिए। एक बड़ी सोमा तक यह समस्या हमारी मनोवृत्ति से सम्बन्धित है।

(ङ) वितरण व्यवस्था दोष हीन होनी चाहिए।

उपसंहार

यह देश की सभी समस्याओं में सर्वोपरि है। अतः इसे मुलभाने में बिना भेदभाव के किसान, मजदूर, वणिज्य वर्ग, उद्योगपति एवं जन-साधारण सभी के सहयोग की आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारियों का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व है,

वर्षोंकि बिना उनकी लगन और मध्यवसाय के कोई योजना सफल नहीं हो सकती। हम सभी को दृढ़ निश्चय करके खाद्यान्न की कमी को दूर करने के काम में जुट जाना चाहिए। मनुष्य जैसा समर्थ प्राणी क्या नहीं कर सकता? ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोल विशेषज्ञ ने सिद्ध करके दिखाया है कि भूमि का पूर्ण उपयोग करके विश्व की वर्तमान जनसंख्या के चौगुने का पालन-पोषण सहज संभव है। कई देशों के वैज्ञानिकों ने क्लोरेला (Chlorella) नामक एक खाद्य पदार्थ का आविष्कार किया है जिसका प्रति एकड़ उत्पादन आजकल के उत्पादन का बीस गुना हो सकता है। भारत इन आविष्कारों से लाभ उठा सकता है।

आवश्यकता

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन, निम्नकोटि के उत्पादन तथा प्रति एकड़ कम उपज का मुख्य कारण भारतीय किसान का पिछड़े यन्त्रों का प्रयोग ही है। लकड़ी के हल, फावड़े, खुरपी, दगंती इत्यादि परम्परागत उपकरणों की कार्य-क्षमता और कार्य-क्षमता बहुत कम होता है। इससे उत्पादन व्यय बढ़ता है और उपज कम एव बढ़ी होती है। इसी कारण भारतीय किसान अपनी गरीबी के लिए, अपने ऋण मार के लिए, अपने रूढ़वाद एव अज्ञान के लिए जगत प्रसिद्ध है। इसी कारण देश में साधान का अभाव है। आज जब हम देश के आर्थिक विकास की योजनाएँ बना रहे हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि अन्य अग्रगामी राष्ट्रों की भाँति कृषि का भी सुधार करें और अपनी साधान एव औद्योगिक बच्चे माल की कमी को पूरा करें। बिना कृषि के आधुनिकीकरण के हमारी औद्योगिक आधुनिकीकरण की कोई योजनाएँ पूरी नहीं हो सकती।

लाभ

कृषि के यन्त्रीकरण के निम्नांकित मुख्य लाभ बताए जाते हैं —

(क) किसान को भारी-भारी काम और कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा उसे हास-परिहास व मनोरंजन के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि के यन्त्रीकरण से वह बहुत से भारी एवं थकावट उत्पन्न करने वाले काम से बच जाएगा तथा उसे मनोरंजन, हास-परिहास, स्वास्थ्य-सुधार इत्यादि के लिए अवसर मिल सकेगा।

(ख) कृषि में काम आने वाले पशु बहुत-सी उत्पन्न उपज स्वयं खा जाते हैं जिससे मानवी आवश्यकताओं के लिए अनादि की कमी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १,२०,००,००० घोड़े और खच्चर हटा कर ट्रैक्टरों से काम लिए जाने पर ३,३०,००,००० एकड़ भूमि जिस पर उनके लिए चारा उगाया जाता था की बचत हो गई।

(ग) पिछड़े यन्त्रों के स्थान पर आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग से उत्पादन में अपार वृद्धि होगी और हमारी साधान एव औद्योगिक बच्चे माल की कमी अनायास ही दूर हो जाएगी।

(घ) यन्त्रीकरण के उपरान्त उत्पादन की नई-नई रीतियाँ और नए-नए साधन विकसित हो सकेंगे जिनमें कि विचलित जनसंख्या को काम मिल सकेगा।

(ङ) देश के साधनों का पूर्ण उपयोग होगा और देश की गरीबी दूर होगी।

(च) आज भारतीय किसान कृषि कार्य में इसलिए लगा रहता है कि उसे और कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। कृषि के यन्त्रीकरण के उपरान्त अनेक सहायक धन्ये खड़े हो सकेंगे और उन्हें अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने का अवसर मिलेगा।

(छ) भारत में हजारों लाखों एकड़ भूमि ऊसर, बंजर, दलदली अथवा अन्य प्रकार कृषि के अयोग्य है। यन्त्रों के प्रयोग से ऐसी भूमि का कृषिकरण हो सकेगा।

सरकारी नीति

देश की कृषि के पिछड़ेपन एवं खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल की कमी के कारण कृषि उपज बढ़ाने के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी यत्न काम में लाए जा रहे हैं। इन्हीं यत्नों में से एक यत्न भारत सरकार की कृषि के यन्त्रीकरण के प्रति प्रोत्साहित करने की नीति है। इसी कारण भारत सरकार ने कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों एवं डीजल तेल से उद्गादन कर घटाने का निर्दय किया है। कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कर राज्यों की सरकारें उन्नतशैली किसानों को ट्रैक्टर प्रथवा अन्य आधुनिक यन्त्र-उपकरण लेने के निमित्त तकावी ऋण देते हैं। यह सिद्ध होने पर कि कोई ट्रैक्टर बस्तु-खेती के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, उस पर आयात-कर में भी छूट दे दी जाती है। हमारे प्रधान-मंत्री राजगंधान क मूरतगढ़ फार्म की प्रगति से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने सृतीय योजना काल में देश के अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही दस और फार्म खोलने का विचार व्यक्त किया है जहाँ आधुनिक यन्त्रों की सहायता से खेती की जाएगी। देश में ट्रैक्टर बनाने के कारण खेती खोले जाने के प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और १९६० में इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक ट्रैक्टर समिति भी नियुक्त की जा चुकी है। इस नीति भारत सरकार की नीति कृषि-यन्त्रीकरण को पूर्णतः प्रोत्साहन देने की है।

सन् १९५१ में देश में ६ लाख ट्रैक्टर, ६३० लाख सोहे के हल तथा २१ लाख बिजली चालित गन्ना पेलने वाले कोल्हू थे जिनकी संख्या १९५६ तक क्रमशः २१ लाख, १३६७ लाख और २३ लाख हो गई। इन प्रांकड़ों से विदित होता है कि ट्रैक्टरों में १३३%, सोहे के हलो में ४७% तथा कोल्हूओं में १०% की वृद्धि हुई, तो भी देश के कृषि क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग अभी भी लकड़ी के हल और बैल से चलाए जाने वाले कोल्हू पर निर्भर है। ट्रैक्टर कई कारणों से अधिक-प्रयोग में आ रहा है। पंजाब के आर्थिक जांच बोर्ड (Board of Economic Inquiry) के एक हाल के प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि पंजाब में १९५१ में केवल ८५८ ट्रैक्टर थे, किन्तु १९५७ में इनकी संख्या ४१७२ अर्थात् लगभग चार गुनी हो गई। इस प्रगति के निम्नांकित मुख्य कारण बताए गए हैं जो देश के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं : (१) केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों एवं अनेक किसानों ने नई भूमि तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया है ; (२) भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों से भयभीत हो कर अनेक भूस्वामियों ने ट्रैक्टरों की सहायता से अधिक भूमि अपनी जोत में ले ली है ; (३) शिक्षित वर्ग की बढ़ती हुई बेकारी ने अनेक युवकों को ट्रैक्टर द्वारा खेती करने पर बाध्य किया है ; (४) अनेक भू-स्वामियों को कृषि जन्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण ट्रैक्टरों की सहायता से स्वयं खेती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। (५) कुछ क्षेत्रों में श्रम की कमी ने भूपतियों को स्वयं खेती करने के लिए विवश किया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बाँध, नहरें, नलकूप, सड़कें

इत्यादि बनाने की अनेक योजनाओं के कारण अनेक क्षेत्रों में कृषि-धन की भारी कमी हो गई है।

भविष्य

ट्रैक्टर के गत वर्षों में अधिकाधिक प्रयोग होते हुए भी इसके प्रयोग का क्षेत्र सीमित है और यह देश के लिए लोकप्रिय साधन नहीं बन सकता, क्योंकि भारतीय किसान की कगाली, उसकी छोटी जोते एवं उनका बिल्लरापन उसके मार्गों की भारी बाधाएँ हैं। पत्राव के आर्थिक जॉन बोर्ड के प्रोफेसर्स के अनुसार ट्रैक्टर से खेती करने के लिए प्रति एकड़ भूमि के निमित्त किसान को २४१ रु० विनियोग करने पड़ते हैं जबकि वेल की खेती के लिए केवल ११८ रु० अर्थात् ट्रैक्टर की खेती के लिए दुगुने धन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर की खेती के लिए सिंचाई वाली भूमि पर ४७ रु० और बिना सिंचाई भूमि पर ४३ रु० प्रति एकड़ केवल शक्ति के लिए व्यय करने पड़ते हैं। सिंचाई भूमि पर वास्तविक व्यय का अनुमान ट्रैक्टर की खेती का १८१ ५ रु० और वेल की खेती का १५० रु० प्रति एकड़ है। ट्रैक्टर का प्रारम्भिक मूल्य, उसकी मरम्मत एवं संचालन व्यय सभी साधारण भारतीय किसान की हैसियत से बाहर है। इस सब भारी व्यय से यदि आय में अधिक वृद्धि हो जाए तो किसान ऋण लेकर ट्रैक्टर खरीद सकता है और शनः शनः ऋण चुकता कर सकता है, किन्तु आय में व्यय के अनुरूप वृद्धि नहीं होती। सिंचाई की जाने वाली भूमि से प्रति एकड़ ट्रैक्टर की खेती से १२१ रु० शुद्ध आय होती है जबकि वेल की खेती से १२३ रु०। इसी भाँति सिंचाई रहित भूमि से यह आय क्रमशः २० रु० और ७५ रु० है। प्रति एकड़ उपज भी ट्रैक्टर से वेल की अपेक्षा सभी फसलों में अधिक नहीं होती। सिंचाई युक्त भूमि में हल से ट्रैक्टर की अपेक्षा कपास, चना, जौ और मक्का की उपज अधिक होती है। देशी कपास सिंचाई युक्त और सिंचाई हीन दोनों ही प्रकार की भूमि में हल से अधिक होती है। गेहूँ, गन्ना, मक्का, चावल इत्यादि सिंचाई हीन भूमि में हल से ट्रैक्टर की अपेक्षा बहुत अधिक उपज देते हैं। आय, व्यय, उपज इत्यादि सभी बातों को विचार कर यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक धन में ट्रैक्टर से कुछ कमी अवश्य हो जाती है, किंतु खर्च बढ जाने से इस सारी कमी का सर्वथा लोप हो जाता है। अतएव ट्रैक्टर का बड़े पैमाने पर प्रयोग सामंजस्यकारी नहीं है। यही बात कृषि सम्बन्धी अन्य यन्त्रों के लिए सत्य है। अतएव देश में कृषि यन्त्रीकरण करते समय बड़े सोच विचार कर पग बढाना चाहिए।

“सरकारी और निजी क्षेत्रों का पृथक् अस्तित्व नहीं माना जा सकता, वे एक ही शरीर के दो भ्रूणों के समान हैं और इसी भाँति उन्हें मिल-जुल कर काम करना चाहिए।”

—योजना आयोग

५—औद्योगिक नीति

रूप-रेखा

१. औद्योगिक नीति की आवश्यकता ।
२. परतन्त्र भारत में औद्योगिक नीति का अभाव और उसके दुष्परिणाम ।
३. हमारी औद्योगिक नीति का आविर्भाव ।
४. स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति—अप्रैल १९४८ की औद्योगिक नीति की घोषणा :
 - (क) उद्देश्य ।
 - (ख) बड़े उद्योगों का वर्गीकरण ।
 - (ग) छोटे उद्योगों के प्रति दृष्टिकोण ।
 - (घ) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ।
 - (ङ) पूँजी-श्रम के सम्बन्ध ।
 - (च) प्रशासन व्यवस्था ।
 - (छ) विदेशी पूँजी ।
५. औद्योगिक नियन्त्रण एवं नियमन ।
६. संशोधन की आवश्यकता ।
७. १९५६ की नई औद्योगिक नीति :
 - (क) उद्देश्य,
 - (ख) बड़े उद्योगों के तीन वर्ग,

- (ग) लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन,
- (घ) उद्योगों का क्षेत्रीय विनियमन,
- (ङ) उद्योगों का नियन्त्रण नियमन ।
- (च) विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति ।

८. आलोचना

औद्योगिक नीति की आवश्यकता

आज के उद्योग प्रधान युग में प्रत्येक देश की औद्योगिक उन्नति आवश्यक है । बिना किसी निश्चित नीति के यह उन्नति सर्वांगपूर्ण एवं सन्तुलित नहीं हो सकती । इसी कारण आज सभी देशों की अपनी कोई औद्योगिक नीति होती है, जिसके अनुसार सारा औद्योगिक ढाँचा एक पूर्व निश्चित ढाँचे में ढाला जाता है, सरकार और पूँजीपतियों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तथा उद्योगों का क्षेत्रीय विभाजन निर्धारित किया जाता है ।

परन्तु भारत में औद्योगिक नीति का अभाव

अंग्रेजी शासन काल में भारत का प्राचीन औद्योगिक संगठन छिन्न-भिन्न हो गया, किन्तु उसके स्थान पर कोई नया संगठन नहीं स्थापित किया गया । जो कुछ औद्योगीकरण देश में हुआ वह किसी निश्चित नीति के अभाव में अव्यवस्थित ढंग से हुआ । केवल कुछ उपभोग्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग स्थापित हुए, मूल एवं आधारभूत उद्योगों का देश में सर्वथा अभाव बना रहा । एक शताब्दी के औद्योगीकरण के उपरान्त भी देश औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त अवस्था में था । हमें अपनी आवश्यकता की सभी महत्वपूर्ण वस्तुएँ विदेश से आयात करनी पड़ती थी । देश के औद्योगिक साधनों का कोई उपयोग न हो सका ।

औद्योगिक नीति का आविर्भाव

प्रथम विश्व-युद्ध काल में भारत को अपने दुर्बल औद्योगिक ढाँचे के दुष्परिणाम ज्ञात हुए और १९१६ में भारतीय औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई । आयोग के सुझावों तथा तत्सम्बन्धी विचार-विमर्श के उपरान्त १९२१-२२ का तटकर आयोग विधायक गया । अन्त में १९२३ से भेद-भावपूर्ण सरक्षण की नीति अपनाकर कुछ उद्योगों का विदेशी प्रतियोगिता से बचाव किया गया । द्वितीय युद्ध-काल में हमें और भी अधिक अपनी भूल ज्ञात हुई । देश के औद्योगिक ढाँचे में कुछ सुधार करने के विचार से १९४४ में भारत सरकार ने आयोगन एवं विकास विभाग खोला जिसने अप्रैल १९४५ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य प्रकाशित किया और सरकार एवं निजी पूँजीपति का औद्योगिक उत्तरदायित्व बताया । अक्टूबर १९४६ में सलाहकार आयोगन बोर्ड (Advisory Planning Board) और दिसम्बर १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन ने महत्वपूर्ण निर्णय किए जिन्होंने कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की ओर संकेत किया । इसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा नियुक्त आर्थिक कार्यक्रम समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ जिसमें कुछ क्षेत्रों में सभी नए

रहेगी। यदि इस क्षेत्र के किसी उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक नहीं होती है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस क्षेत्र के कुछ उद्योगों को सरकार चलाने भी लगी थी जैसे बिजली, नदी घाटी योजनाएँ, उर्वरक निर्माण, शोध विभाग, इत्यादि।

(४) नियंत्रित उद्योग—कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों का केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में आयोजन और नियमन आवश्यक समझा गया। इस सूची में १८ उद्योगों के नाम लिखे गए जिनमें नमक, मोटर, ट्रेक्टर, मशीनी यन्त्र, रबर, सूती व ऊनी वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज, विमान व समुद्र परिवहन, खनिज इत्यादि सम्मिलित थे।

(ग) लघु एवं कुटीर उद्योग—इस नीति के अनुसार कुटीर और लघु उद्योगों के राष्ट्रीय महत्व पर पूर्ण ध्यान दिया गया। उनके विस्थापितों के पुनर्संस्थापन, स्थानीय साधनों के उपयोग तथा स्थानीय स्वावलम्बन सम्बन्धी महत्व को भली भाँति स्वीकार किया गया। आवश्यक सरकारी संगठन स्थापित करके उनकी अनेक समस्याओं के मुलभूतों का निश्चय किया गया।

(घ) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—बड़े उद्योगों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य देश के उद्योगों का सरकार और उद्योगपति के लिए अलग-अलग उत्तरदायित्व एवं स्वामित्व निर्धारित करना था।

(ङ) पूँजी व श्रम के सम्बन्ध सुधारने के लिए आवश्यक संगठन और व्यवस्था की गई।

(च) प्रशासन संगठन—इस नीति के लागू करने के लिए केन्द्र में, राज्यों में और क्षेत्रों में प्रशासन संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया।

(छ) विदेशी पूँजी—देश के औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी और ज्ञान का उपयोग आवश्यक बताया, उसका महत्व पूर्णतः स्वीकार किया तथा उसके उपयोग के नियम बनाए गए।

इस घोषणा के उपरान्त विदेशी पूँजी हतोत्साहित होती दिखाई दी। अतएव ६ अप्रैल १९४६ को प्रधान मन्त्री ने विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति का खुले शब्दों में स्पष्टीकरण किया कि (१) सरकार विदेशी औद्योगिक संस्थाओं से देश की औद्योगिक संस्थाओं की भाँति ही देश की औद्योगिक नीति के आदर की आशा करती है, किन्तु उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं खड़ी करना चाहती; (२) विदेशी पूँजी को लाभ कमाने के पूर्ण अवसर दिए जाएँगे और उसके देशगमन पर कोई रोक नहीं खड़ी की जाएगी, तथा (३) राष्ट्रीयकरण के समय उन्हें उचित हानिपूर्ति दी जाएगी।

उद्योगों का नियंत्रण और नियमन

भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत एक वर्ग ऐसे आधारभूत

उद्योगों का था जिनका देश हित में सरकारी नियमन आवश्यक था। इसी निर्णय के अनुसार १९५१ का औद्योगिक विकास एवं नियमन कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् और विविध उद्योगों के लिए विकास परिषदें स्थापित की गईं। इस क्षेत्र के उद्योगों का स्थापन, विस्तार, उत्पादन इत्यादि सभी क्रियाएँ एक लाइसेंस समिति की अनुमति द्वारा ही संभव हैं। प्रारम्भ में यह कानून केवल ३७ उद्योगों पर लागू होता था। अब इसकी परिधि के अन्तर्गत १६५ उद्योग आ गए हैं। इस कानून के अन्तर्गत अब उन सभी उद्योगों को सरकारी लाइसेंस लेना आवश्यक है जिनमें १०० अथवा अधिक मजदूर काम करते हैं और जिनकी १० लाख रुपए से अधिक स्थायी सम्पत्ति है।

संशोधन की आवश्यकता

१९४८ की औद्योगिक नीति बनने के उपरांत के वर्षों में देश का आर्थिक विकास तेजी से होता गया। आठ वर्ष की अवधि में देश की अर्थ-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। १९५० में भारत का नया विधान लागू हुआ जिसके अनुसार देशवासियों को कुछ मूल-अधिकार दिए गए जिनमें आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित थे। दूसरे, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी थी और द्वितीय योजना देश के सन्मुख रखनी थी। द्वितीय योजना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने की चर्चा देश भर में चल रही थी। तीसरे, संसद ने समाजवादी समाज की रचना का अन्तिम ध्येय स्वीकार कर लिया था। चौथे, १९४८ की नीति के अनुसार कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न दस वर्ष उपरांत स्पष्ट करना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से देश के लिए एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी।

१९५६ की औद्योगिक नीति

इन्हीं परिवर्तित परिस्थितियों का ध्यान रखकर भारत सरकार ने ३० अप्रैल १९५६ को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस के मुख्य पहलुओं पर नीचे विचार किया जाता है।

(क) उद्देश्य—नई नीति के मुख्य उद्देश्य (१) आर्थिक विकास और औद्योगीकरण की गति बढ़ाना, (२) विशेषतः भारी एवं मशीन निर्माण उद्योगों का विकास, (३) सरकारी क्षेत्र का विस्तार (४) एक विस्तृत एवं उन्नतशील सहकारी क्षेत्र स्थापित करना, (५) काम के साधन बढ़ाना व रहन-सहन ऊँचा उठाना, (६) आय और सम्पत्ति की विषमता मिटाना, तथा निजी एकाधिकार एवं आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोकना, इत्यादि विनाए गए।

(ख) बड़े उद्योगों के तीन वर्ग—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी क्षेत्र को यथा सम्भव विस्तृत करने की नीति अपनाई गई और बड़े उद्योगों के तीन वर्ग किए गए :

आलोचना

यद्यपि देश में इस नीति का स्वागत हुआ है और भारत के औद्योगीकरण में इससे भारी प्रगति भी हुई है, तो भी कई क्षेत्रों में इसकी कड़ी आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह नीति निजी क्षेत्र की उपेक्षा करती है तथा निजी साहस को मदद करती है। वस्तुतः ऐसी लचीली नीति की आवश्यकता थी जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही देश के औद्योगीकरण में पर्याप्त योग देते रहते। उद्योगों का सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभाजन अनावश्यक बताया जाता है, क्योंकि भारत की मुख्य समस्या औद्योगिक विकास और उत्पादन वृद्धि की है न कि स्वामित्व परिवर्तन की। राष्ट्रीयकरण की गति बड़ी तेज और सदेहात्मक है। कुछ लोग भारी मशीनों का निर्माण और अधिक प्रयोग गांधीजी के सिद्धान्तों के विरुद्ध बताते हैं।

“भौतिक सभ्यता की लोहा अधिकतम लाभदायक धातु है, इसका अर्थ सयन्त्र, आँजार एव मशीने है।”

—ऐन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका

६—लोहा एवं इस्पात उद्योग

रूप रेखा

- १ लोहे एवं इस्पात का महत्व
२. उद्योग का प्राचीन स्वरूप
- ३ आधुनिक उद्योग का इतिहास
 - (क) तीन कारखाने
 - (ख) सरक्षण -
 - (ग) द्वितीय युद्ध
 - (घ) १९४५ का विशेषज्ञ दल (Steel Panel)
 - (ङ) तीन नए कारखाने
 - (च) वर्तमान स्थिति एवं उत्पादन
४. उद्योग की समस्याएँ
 - (क) वित्त
 - (ख) प्रशिक्षित व्यक्ति
 - (ग) परिवहन
 - (घ) प्रतिस्पर्धीकरण
 - (ङ) श्रम
 - (च) कच्चा माल
५. भविष्य

लोहे-इस्पात का महत्व

लोहा-इस्पात आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण है। छोटे-बड़े उद्योग, मकान-निर्माण, परिवहन सेवाएँ, बाँध, शक्ति संचय सभी क्षेत्रों में लोहे-इस्पात का प्रयोग

अनिवार्य है। लोहे-इस्पात की आधुनिक सभ्यता का आधार कहे तो कोई प्रतिशयोक्ति न होगी। इस धातु के इस महत्व के कारण ही किसी देश भयवा जाति की प्रगति लोहे-इस्पात के उत्पादन और उपभोग से मानी जाती है। इसी कारण विश्व के सभी देश इसका उत्पादन बढ़ाने के विविध प्रयत्न कर रहे हैं। १९३७ और १९५५ की अवधि में विश्व का इस्पात उत्पादन दूना हो गया।

प्राचीन वैभव

भारत इस्पात के प्राचीनतम उत्पादकों में से है और आज से दो हजार वर्ष पूर्व लोहा-इस्पात उत्पन्न करता था। दिल्ली का लोह-स्तम्भ इसका जीता-जागता प्रमाण है जो ४१५ ईस्वी का बताया जाता है। यह लगभग २३ फीट लम्बा है और इसका व्यास १२॥ इंच से १५॥ इंच तक है। इसकी तोल लगभग ६ टन है। प्रति प्राचीन काल में हूँदराबाद से दमिस्क को इस्पात निर्यात किया जाता था जिससे वहाँ के प्रसिद्ध छुरे और तलवारें बनते थे। भारत इस्पात का प्रयोग भस्त्र-शस्त्रो व यंत्र-उपकरणों के निर्माण तथा सजावट के कामों में करता था। यहाँ की भगरिया और लोहार जातियाँ इस उद्योग के विशेषज्ञ थे। इसके भग्नावशेष अब भी भट्टियों के रूप में मिलते हैं।

विदेशी शासन-काल में अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग का भी पतन हुआ। अब भारत लोहे-इस्पात के उत्पादन में अन्य देशों से अत्यन्त पीछे है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का इस्पात का उत्पादन १०६२ लाख टन, रूस का ४५३ लाख टन, पश्चिमी जर्मनी का २१३ लाख टन, ब्रिटेन का २०१ लाख टन, फ्रांस का १०७ लाख टन तथा भारत का १८ लाख टन है। लोहे का प्रति व्यक्ति पीछे उपभोग संयुक्त राष्ट्र में ३३५ किलोग्राम और विश्व में ३६ किलोग्राम है, जबकि भारत में केवल ६ किलोग्राम है।

आधुनिक उद्योग का इतिहास

सन् १७७७ और १८७५ के बीच बंगाल, बिहार, मद्रास, उत्तर-प्रदेश तथा गुजरात में लकड़ी के कोयले द्वारा लोहा-इस्पात बनाने के अनेक प्रयत्न सरकार और यूरॉपियन लोगों ने किए, किन्तु विफल रहे। १८७५ में बंगाल (अबवा बाराकर) लोहा कम्पनी (Bengal Iron Co) असनसोल और रानीगंज की कोयले की खान के निकट वुल्टी नामक स्थान पर स्थापित हुई। इसने पर्यर के कोयले का प्रयोग प्रारम्भ किया। चार वर्ष उपरान्त यह बन्द हो गई और १८८१ में इसे सरकार ने ले लिया तथा आठ वर्ष तक चलाया। सरकार ने इसे १८८६ में एक नई कम्पनी की बेच दिया जिसका नाम बंगाल लोहा-इस्पात कम्पनी (Bengal Iron & Steel Co) रखा गया। १८९४ में मार्टिन एण्ड क०, कलकत्ता इसके प्रबन्ध अधिकर्ता नियुक्त हुए। प्रथम युद्धकाल में इसे अच्छा प्रवसर मिला और १९१६ में पुनर्संज्ञित होकर इसका नाम बंगाल लोहा कम्पनी (Bengal Iron Co.) रखा गया। १९१८ में हीरापुर में एक नई कम्पनी भारतीय

लोहा-इस्पात कम्पनी (Indian Iron & Steel Co) और वनी जिसके अधिकार प्रथम पुरानी बंगाल लोहा कम्पनी ने ले लिए। भारत में सर्व प्रथम प्राधुनिक ढंग से लोहा-इस्पात बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों कारखानों को है। सन् १९३६ में कुल्टी के कारखाने को भारतीय लोहा-इस्पात कम्पनी ने अपने अधिकार में ले लिया। इस कम्पनी ने १९३७ में इस्पात बनाने के लिए बर्नपुर में बंगाल स्टील कारपोरेशन नामक सहायक कारखाना स्थापित किया। १९५३ में इसे भारतीय लोहा-इस्पात कम्पनी ने अपने अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया।

दूसरा लोहे-इस्पात का कारखाना श्री जमशेदजी नसरवानजी ताता के अवध प्रयत्न से सक्की नामक स्थान पर बिहार में स्थापित हुआ। श्री ताता वम्बई के एक पारसी थे जिन्होंने सूती वस्त्र व्यवसाय में अच्छा लाभ कमाने के उपरान्त १८८२ में लोहे-इस्पात उद्योग के विकास की ओर ध्यान दिया। सरकारी सहयोग के अभाव में उनके प्रयत्न तुरन्त सफल न हुए, किन्तु उन्होंने साहस न छोड़ा। बीस वर्षे उपरान्त जब जॉर्ज हैमिल्टन (George Hamilton) भारत मंत्री हुए तो सरकारी नीति में परिवर्तन आया और ताता को प्रोत्साहित किया गया। अतएव १९०३ में उन्होंने फिर प्रयत्न प्रारम्भ किया। फलस्वरूप १९०८ में जमशेदपुर का कारखाना स्थापित हुआ। इसने १९११ में लोहा और १९१३ में इस्पात बनाना प्रारम्भ किया।

तीसरा लोहे का कारखाना मैसूर सरकार द्वारा १९२० में भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित हुआ। १९३४ में इसके साथ एक इस्पात कारखाना भी चालू कर दिया गया। अतः इसे मैसूर लोहा-इस्पात कारखाना कहा जाता है।

प्रथम विश्व युद्धकाल में ताता कम्पनी को उन्नति करने का अवसर मिला, किन्तु युद्ध के उपरान्त विदेशी प्रतियोगिता के कारण उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। अतएव १९२३ में इसे संरक्षण मिल गया। सरक्षण के उपरान्त उसकी स्थिति में सुधार हुआ। इस्पात का उत्पादन १९२३-२४ में १,६३,००० टन था जो १९२८-२९ में बढ़कर ७,०१,००० टन हो गया। १९२३-२४ में यह कम्पनी देश के इस्पात की माँग के १७.६ प्रतिशत की ही पूर्ति करती थी, किन्तु १९३३-३४ तक यह ७६% माँग की पूर्ति करने लगी।

द्वितीय युद्धकाल में भी उद्योग की संरक्षण मिलता रहा। साथ ही माँग बढ़ने से उत्पादन बढ़ाने और आकार-विस्तार का भी अवसर इस उद्योग को मिला। १९४७ तक इस उद्योग की स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि इसके लिये सरक्षण अनावश्यक बताया गया और उसे समाप्त कर दिया गया। इस मिति २३ वर्ष तक सरक्षण मिलने के उपरान्त इस उद्योग को अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य प्राप्त हुई।

युद्धोत्तर काल में विशेषतः स्वतन्त्रता के उपरान्त, औद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ देश में लोहे-इस्पात की माँग अत्यन्त बढ़ गई और तीनों कारखानों का उत्पादन अत्यन्त सिद्ध होने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनते समय योजना

भाषोग ने इस्पात का उत्पादन देश की मांग के केवल ५०% के बराबर मात्रा और उसमें वृद्धि करने की बात पर विशेष जोर दिया। भूतएव लोहे का उत्पादन १५,७२,००० टन (१९५०-५१) से १९,५०,००० टन (१९५५-५६) और इस्पात का उत्पादन ९,७६,००० टन से १२,८०,००० टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

सन् १९४८ की भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार इस उद्योग की सरकारी क्षेत्र में लेने की घोषणा की गई थी। उत्पादन बढ़ाने के विचार से एक और भारत सरकार ने तत्कालीन उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर बढ़ावा दिया और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में नए कारखाने खोलने के लिए विदेशी उत्पादकों से सम्पर्क स्थापित किया एवं परामर्श लिया। फलस्वरूप १९५५-५६ तक लोहे का उत्पादन देश में बढ़कर १९,१५,४०० टन और इस्पात का १२,८५,७०० टन हो गया। द्वितीय योजना काल में तीन नए इस्पात कारखाने राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) और दुर्गापुर (५० बंगाल) में क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन की सहायता से खोले। इनमें से प्रत्येक का लक्ष्य १० लाख टन इस्पात उत्पन्न करने की क्षमता का है। सन् १९५९ में इन नए कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। तृतीय योजना में एक चौथा इस्पात कारखाना बिहार के बोकरो नगर में और खोला जायेगा। इस समय इस्पात का वार्षिक उत्पादन २६ लाख टन है जो तृतीय योजना के अन्त तक ६९ लाख टन हो जाएगा। भाषा की जाती है कि तृतीय योजना के अन्त तक देश लोहे-इस्पात में स्वावलम्बी ही नहीं हो जाएगा, कुछ लोहा-इस्पात निर्यात भी करने लगेगा।

१९५७ की औद्योगिक गणना के अनुसार देश में इस समय छोटे-बड़े १४७ कारखाने हैं जिनमें १२१ करोड़ रुपए पूँजी (८१ करोड़ ६० मूल और ४० करोड़ ६० चल) लगी हुई है तथा ९० हजार व्यक्ति काम करते हैं जिनमें से ७४००० श्रमिक हैं। इस समय कच्चे लोहे का देश में उत्पादन १२० लाख टन और तैयार लोहे का ८६ लाख टन है। इस्पात का वर्तमान उत्पादन २६ लाख टन है जिस के तृतीय योजना के अन्त तक ६९ लाख टन होने की सम्भवता है।

उद्योग की समस्याएँ

उद्योग की मुख्य समस्याएँ : (क) कच्चे माल, (ख) परिवहन (ग) पूँजी (घ) श्रम तथा (ङ) अभिनवीकरण से सम्बन्धित हैं।

कच्चे माल में खनिज लोहा, कोयला, खनिज लोहक (manganese) मुख्य हैं जो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिज लोहे और लोहक का उत्पादन बढ़ाने के यत्न किए जा रहे हैं। उच्च कोटि के कोयले और तापसह ईंटों (refractories) की कमी उद्योग के लिए विशेष समस्या है। कोयला धोने के कारखाने खोलकर कोयले की कमी दूर की जा रही है।

इस्पात कारखानों के लिए लाखों टन माल और उपकरणों की दुलाई के लिये पर्याप्त रेल सुविधायें प्रदान करना भी एक कठिन समस्या है। द्वितीय योजना में सारी

नई रेल केवल इस्पात कारखानों के क्षेत्र में बनाई गईं। तृतीय योजना में भी यह नीति जारी रहेगी।

इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लेकर पूँजी सम्बन्धी कठिनाई दूर की गई है। और सरकारी क्षेत्र के दोनों कारखानों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता दी है और विश्व बैंक से ऋण भी दिलाए हैं।

श्रम संघर्ष भी उद्योग की एक कठिन समस्या है। श्रमजीवी ऊँची मजदूरी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किन्तु उनकी कार्यक्षमता बंधा गिरती जा रही है। श्रम-कल्याण, निर्वाह निधि (P F) तथा आवास-व्यवस्था द्वारा श्रम-संघर्ष कम किया जा सकता है।

इंजीनियरों और अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों की भारी कमी है जिसे जमशेदपुर, वर्नपुर और भद्रावती के तीन शिक्षण केन्द्रों द्वारा दूर किया जा रहा है।

पुराने कारखानों में अभिनवीकरण की समस्या को शनैः शनैः सुलझाया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एक साव पूँजी जुटाना सम्भव नहीं है।

भविष्य

अभी भारत में अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त लौहा और इस्पात नहीं बनता और बहुत सा माल आयात करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों के पूरी क्षमता तक उत्पादन करने और चौथे कारखाने के चालू होने पर स्थिति सुधर जायगी। आधुनिक युग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर ध्यान दे तो उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा और कुछ ही दिनों में यह उद्योग अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

“सूती वस्त्र-उद्योग भारत का प्राचीन गौरव, भूत व वर्तमान का
दाख्य दुःख, किन्तु सदैव अटूट आशा का साधन रहा है।”

—डॉ० एच० बकन

७—सूती वस्त्र-उद्योग

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना
२. प्राचीन भारत में सूती वस्त्र उद्योग
३. आधुनिक उद्योग की स्थापना और विकास
४. संरक्षण
५. योजना काल में प्रगति
६. वर्तमान स्थिति
७. समस्याएँ ।

प्रस्तावना

विश्व के सूती वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादकों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपरान्त और निर्यातकों में जापान के उपरान्त उसका स्थान है। यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा और सुसंगठित उद्योग है।

इस उद्योग के दो प्रमुख अंग हैं—एक आधुनिक सूती मिल उद्योग और दूसरा परम्परा से चला आने वाला हथकरघा उद्योग। सूती मिल उद्योग का संगठित उद्योगों में और हथकरघा का कुटीर एवं छोटे उद्योगों में देश में सर्वोपरि स्थान है। ये दोनों ही उद्योग देश के गौरव हैं।

प्राचीन भारत में सूती वस्त्र-उद्योग

यह व्यवसाय भारत में अनन्त काल से चला आ रहा है। यह अधिवृत्त रूप से ज्ञात हो चुका है कि भारत इस उद्योग का जन्मदाता है। विलासप्रिय मुगलों से इस उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। फलतः इस उद्योग की अपूर्व उन्नति हुई और विश्व

में इसका गुणगान होने लगा। ढाका, कासिम बाजार और सुनारगाँव की मलमल तथा कारोमएडल तट की छोटी की विश्व भर में भारी माँग और प्रशंसा होने लगी। मेग-स्यनीज, एरियन, स्ट्राबो, बनिवर, टैबनिवर, सरटामसरो, पीटरमडी इत्यादि विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में भारत के इस उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। टैबनिवर ने लिखा है कि एक पीठ रई से भारत में २५० मील लम्बा सूत काता जा सकता था। वस्तुतः भारतीय मलमल और छोटी की खोज में ही ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत प्रागमन हुआ था।

आधुनिक उद्योग की स्थापना और विकास

सन् १८१८ में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई जिसे इस क्षेत्र में एक प्रयोग मात्र समझना चाहिए। इस उद्योग का वास्तविक क्षेत्र बम्बई सिड हुआ जहाँ सन् १८५१ में कादसजी नानाभाई डावर नामक पारसी के प्रयत्न से एक कारखाना स्थापित हुआ जिसने १८५४ में उत्पादन प्रारम्भ किया। सन् १८५६ में रनछौडलाल छोटेलाल के संरक्षण में एक मिल ब्रह्मदावाद में और खुनी। इन प्रयत्नों की सफलता के उपरान्त कुछ ही काल में इस क्षेत्र में अनेक मिलें खुल गईं। इसी समय अमरिका में गृह-युद्ध छिड़ गया और भारतीय रई के व्यापारियों को अपार धन कमाने का अवसर मिला। इस धन से अवसर मिलने पर नई मिलें खोलने का खालब बढना गया और १८७६ तक ४७ मिलें खुल गईं जिनमें दस लाख से ऊपर तकुएँ और ६ हजार से ऊपर कर्षे थे। सन् १८७७ से यह उद्योग देश के अन्तर्गत भागी (नागपुर, वानपुर, शोलापुर, ब्रह्मदावाद) में भी फैलने लगा। जापान, चीन, भ्रव और स्ट्रेट सिटिलवेट को यहाँ से सूत जाने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्ष इस उद्योग के लिए कठिनाई के दिवस थे। तो भी १६०० तक देश में १६३ कारखाने चालू हो गए जिनमें ५० लाख तकुएँ और ४० हजार कर्षे थे। इन कारखानों में १,६१,००० कर्मचारी काम करते थे और १४,५३,००० रई की गाँठें काम आती थीं।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जापान में यह उद्योग उत्तम हो उठा और वहाँ भारतीय सूत जाना बन्द हो गया। जापान अब चीन में भी हमारी प्रतियोगिता करने लगा। अतएव हमारी मिलें अब सूत कातने के साथ-साथ कपडा बुनने लगी। १९०५-०७ के स्वदेशी आन्दोलन से भी इसको प्रेरणा मिली। १९१० तक देश में २६३ मिलें खुल गईं जिनमें ६२ लाख तकुएँ, ८३ हजार कर्षे और २,३४,००० कर्मचारी थे तथा १६,३५,००० रई की गाँठों की खपत होती थी। प्रथम युद्ध के वर्षों में मशीनों के आयात की कठिनाई के कारण नई मिलें तो न खुल सकी, किन्तु पुरानी मिलों को उत्पादन बढाने का अच्छा अवसर मिला क्योंकि विदेशी कपडा आना बन्द हो गया था। युद्ध के उपरान्त भी चार-पाँच वर्ष अचट्टे सिद्ध हुए। सन् १८९६-१९०० में भारतीय मित्रें हमारे वस्त्र की आवश्यकता का केवल ६% की पूर्ति करते थे, २६% की पूर्ति करके के गृह-उद्योग से और शेष ६५% की पूर्ति आयात से होती थी। १९२१-२२ में वे बढ़ें क्रमशः ४२, २६ और ३२ थीं। इसके उपरान्त इस उद्योग की घोर मन्दी के सङ्घट

का सामना करना पडा। १९२५ में स्थिति इतनी दिगड गई कि मिलों को मजदूरी में भारी कटौती करनी पड़ी जिससे मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इस घोर सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने पर उद्योग से उत्पादन-कर उठा लिया गया। तो भी उद्योग की स्थिति में विशेष सुधार न हुआ। अब जापान से भारी प्रतियोगिता आरम्भ होगई। विवश होकर उद्योग की संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी पड़ी।

सरक्षण

उद्योग की माँग पर विचार करने के लिये एक विशेष शुल्क मंडल (Tariff Board) बिठाया गया जिसकी अनुमति के अनुसार १९२७ में उद्योग की संरक्षण दिया गया। यह सरक्षण १९४७ तक चलता रहा। संरक्षण के कारण उद्योग की उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला।

द्वितीय युद्ध के पूर्व तक मिलों की संख्या ३८९ हो गई जबकि १९२६ में केवल ३३४ थी। इसी अवधि में तकुमों की संख्या ८७ लाख से १०१ लाख, करघों की १५९ हजार से २०० हजार और कर्मचारियों की संख्या ३,७४,००० से ४,३०,००० हो गई। इस भाँति मिलों की संख्या में १६.५% तकुमों में १५.४%, करघों में २५.४% तथा कर्मचारियों में १५.२% की वृद्धि हुई। रई की खपत इसी अवधि में २१ लाख गाँठों से बढ़कर ३७ लाख गाँठों हो गई अर्थात् ७४% बढ़ोत्तरी हुई। कपड़े का उत्पादन ९३% अधिक हो गया। मिलों ने उच्चकोटि का मूल्य कातना और कपड़ा बुनना भी प्रारम्भ कर दिया।

द्वितीय युद्धकाल में यद्यपि कच्चे माल और मशीनों के सम्बन्ध में उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पडा, किन्तु तो भी स्वाभाविक और सरकारी संरक्षण के कारण उद्योग उन्नति ही करता रहा। १९४५ तक मिलों की संख्या ४१७ होगई जबकि १९३९ में ३८९ थी। इसी अवधि में तकुमों की संख्या १०१ लाख से १०२ लाख, कर्मचारियों की संख्या ४,४२,००० से ५,१०,००० और रई की खपत ३८ लाख से ४९ लाख गाँठों हो गई। करघों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, यद्यपि चालू करघों की संख्या में ४% वृद्धि होगई थी।

योजना काल में प्रगति

कपड़े की कमी के कारण प्रथम योजना काल में उद्योग का यथाशक्ति विस्तार करने और तरवालीन उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का निश्चय किया गया। विस्तार का ध्येय मुख्यतः कताई विभाग से सम्बन्धित था। कुछ नई इकाइयाँ स्थापित करने और कुछ अलाभकर पुरानी इकाइयों के प्रसार द्वारा विस्तार का कार्य किया जाना था। प्रथम योजना के आरम्भ (अप्रैल १९५१) में मिलों की संख्या ३७८, तकुमों की १०९ लाख, करघों की १,९४,००० थी जो जनवरी १९५६ तक बढ़कर क्रमशः ४१२,१२१ लाख और २,०३,००० होगई। कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ४७० करोड़ गज रखा गया था जो १९५३ तक ही प्राप्त किया जा सका

श्रीर १९५५ तक उत्पादन ५०६४ करोड गज पहुँच गया। सूत के उत्पादन का लक्ष्य १६४ करोड पीड निर्धारित किया गया था जिसे पूर्णतः प्राप्त किया जा सका।

हथकरघा उद्योग के विस्तार की नीति भी अदनाई गई थी। इसका उत्पादन १७० करोड गज के स्थान पर केवल १५० करोड गज हो सका अर्थात् लक्ष्य से कुछ पीछे रह गया। इसी भाँति निर्यात का लक्ष्य १०० करोड गज के स्थान पर केवल ६०४ करोड गज हो सका। देश में कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति पीछे १९५० में ६७ गज से बढ़कर १९५५ तक १५८ गज हो गई। १९५० में एक कार्यकारी दल (Working Party) ने श्रीर १९५४ में कानूनगो समिति ने मिल उद्योग की स्थिति पर श्रीर वर्ष समिति ने हथकरघा उद्योग की स्थिति पर विचार किया तथा सुधार विस्तार के सुझाव दिए।

द्वितीय योजना काल में मिल के कपड़े का उत्पादन ५०० करोड गज श्रीर हथकरघे का २६१ करोड गज हो गया अर्थात् ३४% श्रीर १८६% की वृद्धि हुई। तृतीय योजना के लिए मिल के कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ५८० करोड गज श्रीर हथकरघा के कपड़े का ३५० करोड गज रखा गया है। गत वर्षों में सूती कपड़े का निर्यात विदेशी प्रतियोगिता के कारण गिर गया है। अतः निर्यात का तृतीय योजना का लक्ष्य ८५ करोड गज है।

वर्तमान स्थिति

१९५७ की आँकड़ागिक गणना के अनुसार देश में ५६७ सूती वस्त्र कार्यालय थे जिनमें से २२६ बम्बई में, १२१ मद्रास में, ५१ पंजाब में, २८ उत्तर प्रदेश में, २५ मसूर में श्रीर शेष अन्य राज्यों में थे। उद्योग में ३२८ करोड ६० पूँजी लगी है जिसमें से १३२ करोड ६० स्थायी श्रीर १९६ करोड ६० कार्यशील पूँजी है। इसमें ७८७ लाख व्यक्ति काम करते हैं। वर्तमान उत्पादन ५०० करोड गज कपड़ा तथा १९५ करोड पीड सूत है।

देश में लगभग २० लाख हथकरघे हैं जिनमें से ४,५०,००० आसाम के घरेलू करघे हैं श्रीर शेष १५,५०,००० व्यापारिक करघे हैं जिनका ८० प्रतिशत अर्थात् १२,५०,००० चालू स्थिति में हैं जो २६१ करोड गज कपड़े का उत्पादन करते हैं।

देश में कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग इस समय १७.५ गज है जो तृतीय योजना के अंत तक २०.३ गज हो जाएगा।

यह उद्योग देश को सब उद्योगों से अधिक विदेशी विनिमय देता है, इससे सरकार को उत्पादन कर भी सबसे अधिक प्राप्त होता है तथा यह सब उद्योगों से अधिक काम देने का भी साधन है। लगभग ८ लाख व्यक्तियों को मिल उद्योग श्रीर ५० लाख को हथकरघा उद्योग काम देता है।

समस्याएँ

गत वर्षों में इस उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसकी मुख्य समस्याओं पर विचार कर लेना आवश्यक है।

(१) कच्चा माल—देश विभाजन के कारण रुई की देश में भारी कमी हो गई। बड़े देशों की रुई की स्थिति भी अधिक बिगड़ गई। गत दो योजनाओं में रुई का उत्पादन २९ लाख गांठों से बढ़कर ५४ लाख गांठों हो गया है अर्थात् ८६ प्रतिशत वृद्धि हुई है तो भी अभी बड़े देशों की रुई बड़ी मात्रा में आयात करनी पड़ती है।

(२) अलाभकर इकाइयाँ—देश में लगभग १५० अलाभकर इकाइयाँ हैं जिनमें से कई बन्द पड़ी हैं और कई हानि उठाकर काम कर रही हैं। सूती वस्त्र सलाहकार समिति जिसकी १९५० में स्थापना हुई थी, इस पर ध्यान दे रही है।

(३) माल संचय—अनेक अवसरों पर उद्योग को सरकारी प्रतिबन्धों के कारण माल की बिक्री में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और माल संचित होता रहा है। इससे स्थान और पूँजी की कमी होकर उत्पादन कम हो जाता है। कभी-कभी परिवहन कठिनाइयों के कारण भी माल संचय हो जाता है।

(४) प्रतियोगिता—इस उद्योग की प्रतियोगिता में कृत्रिम रेशम उद्योग खड़ा हो गया है जिसकी उन्नति तीव्र गति से हो रही है। यह नया उद्योग सूती वस्त्रों के अनेक स्थानापन्न वस्त्र उत्पन्न करके इस उद्योग को हानि पहुँचाता है। हमारे इस उद्योग को विदेशी बाजारों में जापान, चीन, हांगकांग, ब्रिटेन आदि देशों से टक्कर लेनी पड़ती है। इनकी प्रतियोगिता के कारण गत दोनों योजनाओं के निर्यात लक्ष्य हमें प्राप्त न हो सके।

(५) अभिनवीकरण—देश के सूती मिलों में बहुधा मशीनें ३५ से ५० वर्ष तक पुरानी हैं जिनकी मरम्मत और धिसावट का व्यय बहुत ऊँचा होता है तथा उत्पादन निम्न कोटि का और ऊँचे मूल्य पर होता है। राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (N I D C.) आर्थिक सहायता देकर इनके आधुनिकीकरण का यत्न कर रही है। निगम ने इस काम के लिये १९५६ में एक कार्यकारी समुदाय (Working Group) भी नियुक्त किया था।

(६) पूँजी का अभाव—देश के लगभग सभी उद्योगों को पूँजी सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश में गत वर्षों में कई वित्तीय संस्थायें खुल गई हैं जो इस कमी की पूर्ति करने का यत्न कर रही हैं।

(७) मिलों और हथकरघा के बीच समन्वय—वाहरी प्रतियोगिता के साथ-साथ इस उद्योग को आन्तरिक प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है। सूती वस्त्र (नियंत्रण) प्रादेश द्वारा भारत सरकार ने मिल उद्योग को अनेक बंधनों में बाँध दिया है जिससे उच्च भारी कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ता, हानि भी उठानी पड़ती है। सूती वस्त्र सलाहकार समिति इन कठिनाइयों को दूर करने में बहुत कुछ सफल हुई है और उसके प्रयत्न जारी हैं।

“भारत ईस का जन्म स्थान है। हमने हजारों वर्षों से इस का उन रूपों में प्रयोग किया है जो सफेद चीनी की अपेक्षा मनुष्य के लिए अधिक पुष्टिकर हैं।”

—प्रो० महेशचन्द्र (धर्म-सन्देश)

८—चीनी उद्योग

रूप-रेखा

१. चीनी का महत्व
२. चीनी उद्योग का महत्व
३. चीनी उद्योग का इतिहास
 - (क) प्राचीन भारत में चीनी उद्योग
 - (ख) आधुनिक उद्योग की स्थापना
 - (ग) संरक्षण
 - (घ) योजना काल।
४. वर्तमान स्थिति
५. समस्याएँ
६. नबिष्ट्य

चीनी का महत्व

चीनी मनुष्य के भोजन का एक आवश्यक पदार्थ है। संतुलित भोजन में इसका विशेष महत्व है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शक्ति देने वाला सबसे सस्ता भोजन भी है। चीनी सभी प्रकार की मिठाइयों का आधार है। यह अन्य कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है जैसे शक्ति अथवा कोहल उद्योग तथा फल संरक्षण इत्यादि।

चीनी उद्योग का महत्व

क्यूबा के उपरान्त भारत चीनी (गुड और खाटसारी समेत) का विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का ३०% गन्ना उत्पादन करता है। यह

भारत का दूसरा संगठित उद्योग है। गन्ने की खेती देश भर में फैले हुए २० लाख किसानों को जीवन निर्वाह का प्रत्यक्ष साधन उपस्थित करती है। चीनी निर्माण उद्योग लगभग १५ लाख कर्मचारियों और ४,००० विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त स्नातकों और स्नातकोत्तर लोगों के निर्वाह का साधन है। १९३४-३५ और १९५४-५५ के बीच वर्ष में इस उद्योग ने १२२ करोड़ रुपए भारत सरकार को उत्पादन-कर के रूप में दिए। बैलगाड़ियों, मोटर टेली, रेलों और घुम्रांकिश कम्पनियों को वर्ष में इससे लाखों टन गन्ना डोने का काम मिलता है। गन्ने की फसल अन्य सभी खाद्यान्नों की अपेक्षा प्रति एकर अधिक कैलोरी उत्पन्न करती है। यह उद्योग उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की अर्थ व्यवस्था का तो जीवन-प्राण है।

इस उद्योग के तीन मुख्य अंग माने जा सकते हैं : (क) गुड़, (ख) खाडसारी, (ग) चीनी-निर्माण।

उद्योग का इतिहास

(क) प्राचीन भारत में चीनी उद्योग—भारत ईस का जन्म-स्थान है। अमन्त काल से यहाँ गन्ने की खेती होती आई है। गुड़, खाडसारी और बूरा अन्य किसी देश में होते थे, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते। वैदिक साहित्य में इसका विवरण मिलता है। ईसा से पूर्व आठवीं शताब्दी में चीनी लोगों ने भारत से गन्ने और उसके उत्पादनों का ज्ञान प्राप्त किया। ६०० ईस्वी में त्साई हेग (Tsaï Heng) नामक चीनी सम्राट् ने चीनी बनाने की क्रिया सीखने के लिए अपने प्रतिनिधि बिहार भेजे थे।

(ख) आधुनिक उद्योग की स्थापना—आधुनिक चीनी उद्योग के स्थापित होने की ठीक-ठीक तिथि अधिकृत रूप में ज्ञात नहीं है। इतना अवश्य कहा जाता है कि यह उद्योग सर्व प्रथम बिहार और उत्तर प्रदेश में १९ वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों अथवा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में स्थापित हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम आधुनिक कारखाना १९०३ में बिहार में खुला। इस समय तक यूरोप और जावा से भारत में चीनी का आयात होने लगा था। इससे चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई और देश के खाडसारी उद्योग को भारी आघात पहुँचा। अनेक उत्तर प्रदेश में १८० खाडसारी के कारखाने बन्द हो गए। ऐसी स्थिति में विदेशी चीनी का आयात बढ़ता गया।

प्रथम विश्व-युद्ध के वर्षों में आयात की कठिनाई के कारण उद्योग की कुछ धक्कर मिली, किन्तु युद्ध के उपरान्त फिर चीनी की कीमतें गिरने लगीं। अतएव इस उद्योग की स्थिति के सुधार और जाँच के उद्देश्य से भारत सरकार ने १९२० में चीनी समिति नियुक्त की। १९२९-३० में देश में चीनी बनाने के २७ कारखाने थे जो ९,९०,००० टन गन्ना प्रति वर्ष पैककर ५०,००० टन चीनी उत्पन्न करते थे। इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। १९२९ में कृषि अनुसंधान परिषद के सुझावों के

अनुसार भारत सरकार ने प्रमुख बोर्ड विठाया। बोर्ड के मुम्भावो के अनुसार १९३२ में उद्योग को १५ वर्ष के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। वस्तुतः भारत के प्राधुनिक चीनी उद्योग का इतिहास संरक्षण के उपरान्त ही आरम्भ हुआ।

(ग) संरक्षण—संरक्षण का इस उद्योग की उन्नति पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। १९३२-३३ में जब इसे संरक्षण दिया गया, देश में ५७ कारखाने जो ३३, ५०,००० टन गन्ना पेल्लर २,६०,००० टन चीनी बनाते थे। १९५५-३६ तक के तीन वर्ष में कारखानों की संख्या १३७ और चीनी का उत्पादन ६,३२,००० टन हो गया अर्थात् क्रमशः १४०% और २२०% की वृद्धि हुई। गन्ने की खपत भी इसी अवधि में दूनी से अधिक हो गई। १९३६-४० तक कारखानों की संख्या में तो विशेष वृद्धि न हुई, किन्तु उत्पादन एक अपूर्व सीमा को पहुँच गया। उस वर्ष चीनी का उत्पादन १२,०७,८०० टन हुआ जो देश को माँग से भी अधिक था। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सरकारों को चीनी के उत्पादन में कमी लाने का कार्य-जम लागू करना पड़ा। इस नीति का वाछनीय प्रभाव पड़ा और १९४१-४२ तक उत्पादन एक निम्नतम सीमा को (७,५१,४०० टन) पहुँच गया। तदुपरान्त चीनी की माँग के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ने लगा और १९४३-४४ तक अपनी प्राचीन उच्चतम सीमा को पहुँच गया और कारखानों की भी संख्या बढ़कर १४४ हो गई। तदुपरान्त प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक इस उद्योग की प्रगति रुकी सी रही।

(घ) पंचवर्षीय योजना काल—प्रथम योजना के प्रारम्भ में देश में १५८ कारखाने थे जिनकी उत्पादन-क्षमता १५ लाख टन थी। इनमें से केवल १३६ कारखाने चालू स्थिति में थे और ११ लाख टन चीनी उत्पादन करते थे। प्रथम योजना के अन्त तक कारखानों की संख्या १६० हो गई जिनकी उत्पादन-क्षमता १७.४ लाख टन थी। इनमें से १४३ चालू स्थिति में थे और उनका वार्षिक उत्पादन १५.६० लाख टन था। १९५४ में ४३ नए कारखाने स्थापित करने के लाइसेंस दे दिए गए और ४२ पुराने कारखानों के विस्तार की भी अनुमति दे दी गई। इन कारखानों के विस्तार के साथ चीनी का उत्पादन १९५५-५६ में १८.६० लाख टन पहुँच गया अर्थात् ८८% वृद्धि हुई। चीनी का उपभोग १९४६-५० में प्रति व्यक्ति पीछे केवल ७ पाँड था जो १९५५-५६ में १२ पाँड अर्थात् ७०% अधिक हो गया।

द्वितीय योजना में उत्पादन क्षमता का लक्ष्य २५ लाख टन और उत्पादन का २२.५ लाख टन रखा गया था जिसे पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। ६६ इकाइयों के विस्तार और ५४ नई इकाइयों के खोलने का भी निश्चय किया गया। तृतीय योजना के लिए उद्योग की उत्पादन-क्षमता और वास्तविक उत्पादन दोनों का लक्ष्य ३० लाख टन है।

वर्तमान स्थिति

१९५७ की औद्योगिक गणना के अनुसार देश में १८७ कारखाने हैं जिनमें से ६८ उत्तर प्रदेश में, ३० बिहार में, २१ बम्बई में, ११ आन्ध्र में और शेष मैसूर,

मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, राजस्थान इत्यादि राज्यों में है। इसमें १२६ करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है जिसमें से ४६ करोड़ रुपए अचल और ८० करोड़ रुपए चल पूंजी है। उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या १४० लाख है। जैसा कि द्वितीय योजना का संक्षेप था वार्षिक उत्पादन २२५ लाख टन पहुँच चुका है। तृतीय योजना के अंत तक यह ३० लाख टन होने की संभावना है। वर्तमान कारखानों की प्रति दिन १७२ लाख टन गन्ना पेरने की क्षमता है। चीनी के कारखानों से प्रति वर्ष लगभग ८ लाख टन शीरा निकलता है जिसका अर्ध उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

समस्याएँ

(क) प्रति एकड़ कम उपज—भारतवर्ष में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अर्ध देशों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत में एक एकर में केवल १४ टन गन्ने की उपज होती है जबकि जावा में ५६ टन, हवाई में ६२ टन, मिस्र में ३० टन, द० अफ्रीका में २१ टन, पीरू में ४१ टन और आस्ट्रेलिया में २१ टन होता है। उत्तम बीज, खाद और अधिक सिंचाई एवं अनुसंधान द्वारा प्रति एकड़ उपज में बहुत कुछ उद्योगों की संभावना है।

(ख) निम्न कोटि का गन्ना—भारतीय गन्ने में चीनी की मात्रा भी अर्ध देशों की अपेक्षा कम बैठती है। आस्ट्रेलिया में १४%, ब्यूवा में १२% जावा में ११.६% हवाई में १०.३% तथा भारत में १०% चीनी की मात्रा निकलती है। अल्पवृक्ष द्वारा इसे भी बढ़ाया जा सकता है।

(ग) उपोत्पादन—चीनी उद्योग से शीरा और छोई पदार्थ बड़ी मात्रा में निकलते हैं। इनका समुचित उपयोग नहीं होता। शीरा से शक्ति अलकोहल और डी० डी० टी० उद्योग तथा छोई से कागज व पट्टा बनाने के उद्योग चलाए जा सकते हैं। इनके समुचित उपयोग से चीनी का मूल्य सस्ता हो सकता है।

(घ) समन्वय का अभाव—इस उद्योग के मुख्य तीन अंग हैं। चीनी, गुड़ और खाडसारी। इन तीनों के समुचित विकास के लिए तीनों का समन्वय आवश्यक है। गुड़ का मूल्य बढ़ने पर चीनी उद्योग को पर्याप्त गन्ना मिलना दुर्लभ हो जाता है। अतएव तीनों उद्योगों के बीच समतुलन और समन्वय की भारी आवश्यकता है।

(ङ) उत्तरी भारत में केन्द्रीयकरण—यह उद्योग अर्ध तक उत्तर प्रदेश और बिहार में ही केन्द्रित रहा है, किन्तु योजना काल में इसे दक्षिण की ओर भी ले जाने का यत्न किया गया है जहाँ इसको अच्छे प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं और इसका कार्य-क्षेत्र भी अधिक है।

(च) ऊँचे कर—इस उद्योग को कई प्रकार के कर देने पड़ते हैं जिनका भार बहुत बढ़ जाता है। उत्पादन कर, गन्ना-उपकर (Cane Cess), बित्रीकर,

प्रायकर इत्यादि कर इस उद्योग को देने पड़ते हैं। गन्ने का मूल्य और चीनी का बिक्री मूल्य भी सरकारी निश्चित कर देती है। इस प्रकार उद्योग का लाभ सीमित हो जाता है।

(छ) पुरानी मशीनों के बदलाव, धीरे के लिए मरम्मत स्थान का अभाव तथा ईंधन की कमी की समस्याएँ भी बटिनाई उपस्थित करती हैं।

भविष्य

चीनी उद्योग भारत का अति प्राचीन उद्योग है। १९३२ से १९५० तक १८ वर्ष सरक्षण में रहकर इस उद्योग ने अच्छी उन्नति की और तदुपरान्त भी यह प्रगति करता चला गया है। यद्यपि इस उद्योग ने सरक्षण में लाभ उठाकर अपना मूल्य स्तर उचित सीमा पर ले जाने का शतन नहीं किया, तो भी जब से सरक्षण उठायी गया है इसने अपनी मूल की समस्या है और आवश्यक सुगार प्रवृत्ति जाग उठी है। अब न केवल हमारे देश की बढ़ती हुई माँग-पूर्ति इस उद्योग से हो रही है, बल्कि कुछ चीनी का हम निर्यात भी करने लगे हैं। इस भाँति यह उद्योग अब आशा-जनक उन्नति कर रहा है और यह उन्नति भविष्य में जारी रहने की संभावना है।

“भारतीय हस्तशिल्प का इतिहास अनीत के उन घुंघले पृष्ठों से प्रारम्भ होता है जब कि प्रथम बार मनुष्य का इतिहास लिखा गया।”
—कमलादेवी चट्टोपाध्याय

६—कुटीर एवं लघु उद्योग

१. परिभाषा ।
२. प्राचीन संभव ।
३. अवनति के कारण ।
४. जीवित रहने के कारण ।
५. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में स्थान एवं महत्त्व ।
६. समस्याएँ ।
७. पंचवर्षीय योजनाएँ एवं प्रगति ।
८. सरकारी नीति ।
९. भविष्य ।

परिभाषा

ग्रामीण उद्योग बहुधा कृषि से सम्बन्धित उद्योग हैं। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय बाजार के लिए स्थानीय कच्चे माल का परिष्करण होता है। इनकी क्रिया-विधि सरल होती है। तेल पेरना, घान कूटना, गुड व खाड बनाना, चमड़ा पकाना, रस्सी बटना, मूडे और टोकरियाँ बनाना तथा जुलाहे, बडई, व लोहार का काम इनमें से विशेष उल्लेखनीय हैं। बर्तन बनाना तथा कपड़े की छार्ई-चढाई इत्यादि शिल्पकलाएँ और अन्य ग्रामीण कुटीर उद्योग भी इनके अन्तर्गत आ जाते हैं।

कुटीर उद्योग वे हैं जो शिल्पी द्वारा अपनी कुटिया अर्थात् निवास-स्थान पर चलाए जाते हैं। इनमें शिल्पी का निजी अथवा पारिवारिक श्रम काम में लिया जाता है; बाहरी श्रम की सहायता नहीं ली जाती। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकते हैं और नागरिक क्षेत्र में भी। नागरिक क्षेत्र में स्थित कुटीर उद्योगों में बिजली अथवा भाप की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस श्रेणी में कुशल कारीगरों के हस्तशिल्प भी सम्मिलित हैं।

लघु उद्योगों से तात्पर्य उन कुटीर और छोटे उद्योगों से है जिनका बारखाने कानून के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक नहीं है। भारत सरकार की वर्तमान परिभाषा के अनुसार इनमें उन सब उद्योगों का समावेश होता है। जिनमें पूँजी की मात्रा ५ लाख रुपये से अधिक न हो। इनमें कर्मचारियों की संख्या अथवा शक्ति के उपयोग इत्यादि बान्ने का कोई विचार नहीं किया जाता। इनमें से कुछ परम्परागत शिल्प-कलाएँ हैं (जैसे कपड़ा बुनना, ताले बनाना, बर्तन बनाना) और कुछ नवीन उद्योग हैं जो बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं (जैसे साइकिल के कल-युग्म बनाना, शक्ति चालित करवा उद्योग)। ऐसे उद्योग आभोग क्षेत्र में भी हो सकते हैं जैसे चादू, कँची, लकड़ी का समान, कृषि उपकरण इत्यादि बनाना।

सामान्यतः इन सब उद्योगों की कुटीर एवं लघु उद्योग कह कर पुकारा जाता है। ये देश के लिए प्राथमिक ही नहीं सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के भी हैं।

प्राचीन वैभव

अति प्राचीन काल से भारत अपने कुटीर एवं चतुर शिल्पियों के लिए जगत प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन भारत में खेती के पूरक और सहायक उद्योगों की कमी नहीं थी। प्रत्येक गाँव में बागीची का एक समुदाय रहना या जिनमें बड़ई, लुहार, कुम्हार, जुनाहे, तेली, मुनार, मोची, दर्जी, धुनिया इत्यादि ग्राम सेवकों के रूप में नाम करते थे। भारतीय नगरों में रहने वाले अनेक शिल्पकार भी अपने कला-वैशय के लिये विश्व-विख्यात थे। ढाका की मलमल, मुँगिदानाद की छोट, बनारसी साड़ियाँ, काश्मीरी शाल तथा हाथी दाँत पर खुदाई का काम, सोने-चाँदी के आभूषण और तारों का काम, तंत्रि और पीतल के बर्तन इत्यादि उत्पादन देश-विदेश में नाम पा चुके थे। इन उद्योगों की बनी वस्तुएँ बड़ी मात्रा में विदेश जाती थीं जिनके बदले में भारत की अपार सोना-चाँदी और अन्य बहुमूल्य पदार्थ मिलते थे और इसी धन संचय के कारण भारत विदेशों में सोने की चिड़िया कहलाता था। ये भारतीय उद्योग उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उत्तमोत्तम अवस्था में रहे, किन्तु तदुपरान्त इनका पतन होन लगा। तब से ये दिनो-दिन गिरते ही चले गए हैं।

पतन के कारण

उन्नीसवीं शताब्दी से इन उद्योगों के पतन के मुख्य कारण निम्नांकित बताए जाते हैं : (क) वैसी राजाओं और नबावों का पतन और उनके संरक्षण का अन्त, (ख) देश में बड़े उद्योगों का स्थापना और उनकी विनाशकारी प्रतिस्पर्धिता, (ग) ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति, (घ) पश्चिमी सभ्यता का आकर्षण एवं लोगों की दक्षिण-दक्षिण तथा रहन सहन में परिवर्तन, (ङ) हमारे शिल्पकारों एवं कारीगरों का अपना अन्धविश्वास, रुढ़िवाद, अज्ञान एवं असंगत ; (च) रेलों और अन्य सौम्यगामी परिवहन के आधुनिक साधनों ने भारतीय गाँवों के प्राथमिक ढाँचे को बदल कर एवं उनके स्वावलम्बन का अन्त करके इन उद्योगों को भारी हानि पहुँचाई।

जीवित रहने के कारण

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन उद्योगों का देश से सर्वथा लोप नहीं हुआ। इनमें से अनेक उद्योग ऐसे हैं जो विषम परिस्थितियों का सामना करते हुये भी हमें अपने प्राचीन वैभव की याद दिलाते हैं और उनमें सजीवता है। आधुनिक वृहत्काय उद्योगों की विनाशकारी प्रतियोगिता का सामना करते हुए वे आज तक जीवित रह सके हैं। इसके मुख्य कारण निम्नांकित हैं (क) हमारी जाति प्रथा ने बश परम्परा के अनुसार बश कौशल को सुरक्षित रखा है, (ख) भारतीय धर्म की प्रगतिशीलता एवं शिल्पियों का पारिवारिक मोह उन्हें अपने पेशे के व्यवसायों से बाहर जाने से रोकता है, (ग) ग्रामीण जनता की बेकारी और अर्द्ध-बेकारी हमारे किसान और शिल्पियों को सहायक उद्योगों के रूप में इन्हें अपने-आपने के लिए बाध्य करती है, (घ) देश में पूँजी का अभाव बड़े उद्योगों के मार्ग में बाधक एव लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, (ङ) हमारे शिल्पियों की निर्धनता और निरक्षरता भी उसे अपने पेशे के व्यवसाय से बँधे रहने के लिए विवश करती है, (च) राष्ट्रीय आंदोलनों और देश प्रेम की भावना ने देशी वस्तुओं का प्रचार किया है, (छ) प्रयोग की परम्परा और उपभोक्ता की रुचि के कारण अनेक देशवासियों मिल के स्थान पर घानी का तेल तथा चीनी के स्थान पर खाड़ का प्रयोग अधिक उत्तम समझते हैं (ज) इनमें से अनेक उद्योगों की बनी हुई वस्तुएँ अपने रंग-रूप, गुण, टिकाऊपन एवं कला के लिये मशीन की वस्तुओं की अपेक्षा उत्तम समझी जाती हैं, (झ) अनेक आंतरिक क्षेत्रों में मशीन की वस्तुओं का प्रवेश नहीं हो सका किंतु स्थानीय उद्योगों की बनी वस्तुएँ उपभोक्ता को सहज सुलभ हैं।

अर्थ-व्यवस्था में स्थान

भारत की अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण एव लघु उद्योगों का विशेष महत्त्व है। भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या का उद्यम कृषि है। कृषि लोगों को वर्ष भर एवं पूरे समय काम नहीं देती। (क) ग्रामीण जनता को पूरा काम देने के एक मात्र साधन ग्रामीण उद्योग हैं जो सहायक उद्यम के रूप में उनके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। (ख) ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी और अर्द्ध-बेकारी को कम करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये लगभग दो करोड़ व्यक्तियों को काम देते हैं। अकेला हथकरघा उद्योग ५० लाख लोगों को काम देता है जो कि देश के सभी बड़े उद्योगों (तनिज, चाय, जूट समेत) के बराबर है। (ग) इन उद्योगों के पतन के कारण देश के ग्रामीण एव नागरिक दोनों क्षेत्रों में हमारे अनेक शिल्पकार, (जुलाहे, मोची, दर्जी, बढई, लुहार) दुर्दिन की यातनाएँ भोग रहे हैं। इन लोगों का पुनःस्थापन और उद्धार पूर्णतः इन परम्परागत उद्योगों के पुनर्जीवन पर निर्भर है। (घ) भारतीय कृषि से जनसंख्या का भार कम करने के लिए भी इन उद्योगों का विशेष महत्त्व है।
की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के एकमात्र साधन यही उद्योग

सभी देश और सभी अर्थशास्त्री इस बात को मुवतकंठ से स्वीकार करते हैं। (घ) हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति, परिवहन, प्रशिक्षित श्रम, पूँजी इत्यादि के अभाव में बड़े उद्योगों के लिये अनुकूल वातावरण एवं परिस्थितियाँ नहीं हैं। वहाँ तो कुटीर-उद्योग ही पनप सकते हैं। ये उद्योग स्थानीय कच्चे माल, पूँजी, श्रम और बाजार के सहारे चलते-फूलते हैं और स्थानीय माँग-पूर्ति की पूर्ण क्षमता रखते हैं। (छ) भारतीय किसान और शिल्पी की दिमादिन गिरती हुई श्रम-शक्ति, बढ़ती हुई बेकारी तथा पतनोन्मुख जीवन-स्तर का एकमात्र इलाज कुटीर और लघु उद्योगों का विकास ही है। (ज) ग्राम सुधार की कोई भी योजना बिना कुटीर उद्योगों के विकास के अधूरी समझी जाएगी। बिना कुटीर उद्योगों के ग्राम सुधार सम्भव नहीं और बिना ग्राम सुधार के देश का उद्धार सम्भव नहीं। (झ) यदि देश में मह्वारी सेती बाछनीय है तो उसके द्वारा विस्थापित एवं बचे हुए श्रम को काम बन के लिये कुटीर उद्योगों का विकास एक आवश्यक कार्यक्रम समझना चाहिये। (ञ) देश की अर्थ-व्यवस्था के विकेंद्रीकरण एवं उसके सन्तुलित तथा सागोपाग विकास के लिये और श्रम के उचित वितरण के विचार से भी कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व है। वस्तुन' छोटे और बड़े उद्योग भारत जैसे विनाल राष्ट्र रूपी हृदय में हृत्स्फार और हृत्कुचन व समान हैं जो अपनी पूरी शक्ति से औद्योगिक दबाव डालकर धन-सम्पदा के रूप में राष्ट्र की श्रम और उत्पादन बढ़ाने के लिये अनिवार्य हैं।

समस्याएँ

इन उद्योगों के पुनर्जीवन और विकास में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से मुख्य ये हैं : (क) उचित मूल्य पर कच्चा माल न मिलना, (ख) पूँजी का अभाव, (ग) शिल्पकारों की अशिक्षा एवं रुढ़िवाद तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, (घ) शैक्षिक ज्ञान का अभाव, (ङ) प्राचीन यंत्र-उपकरणों का प्रयोग, (च) शिल्पियों में सङ्गठन का अभाव, (छ) विन्नी सम्बन्धी कठिनाइयाँ तथा (ज) बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा इत्यादि।

प्रगति

इन उद्योगों के राष्ट्रीय महत्व का ध्यान रखकर स्वतन्त्रता के समय से इन्हें पुनर्जीवित और विकसित करने के अनेक यत्न किये गये हैं। इन्हें केंद्रीय और राज्य की सरकारों ने विविध प्रकार की सहायता द्वारा प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की है। फलतः इस क्षेत्र के पुराने उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ है और अनेक नए उद्योग स्थापित हुये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुरपत दस नूने हुए ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया (१) ग्रामीण तेल उद्योग (धानी), (२) नीम के तेल से साबुन बनाना, (३) घान कूटना, (४) ताड़ से गुड बनाना, (५) गुड और खाँड़ उद्योग, (६) ग्रामीण चमड़ा उद्योग, (७) लोहा का बरत, (८) हाथ से कागज बनाना, (९) मधुमक्खी पालना, तथा (१०) कुटीर दियासलाई उद्योग। इनके अतिरिक्त हथकरघा एवं खादी हस्तशिल्प, रेशम के कीड़े पालना,

मारियल की जटा एवं कई लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता द्वारा बढ़ावा दिया गया। इन सब उद्योगों के निमित्त प्रथम योजना काल में लगभग ३३.६० करोड़ रुपये व्यय किये गये।

इन उद्योगों के संगठन और विकास के लिये ६ संस्थायें स्थापित की गईं :

(१) अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड, (२) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, (३) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, (४) लघु उद्योग बोर्ड, (५) जटा बोर्ड, तथा (६) केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

द्वितीय योजना में इन उद्योगों को और भी अधिक प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दी गई। २०० करोड़ रुपये की धनराशि इनके निमित्त रखी गई जिसमें से लगभग १८० करोड़ रुपये वास्तव में व्यय हो सके। उक्त प्रोत्साहन और सहायता के कारण १९५०-५१ और १९६०-६१ के बीच हथकरघे के काढ़े का उत्पादन ७४२० लाख गज से बढ़कर लगभग २१,२५० लाख गज, खादी का उत्पादन लगभग ७० लाख गज से बढ़कर लगभग ८०० लाख गज और कच्चे रेशम का उत्पादन २० लाख पौंड से बढ़कर लगभग ३७ लाख पौंड हो गया। भवन निर्माण सामग्री, हाथ के औजारों, मिलाई मशीनों, विद्युत् की पंखों और दाईसिकिनों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन लघु उद्योगों की सहायता के लिये सभी राज्यों में लघु उद्योग-सेवा-संस्थानों की स्थापना की गई और ४२ विस्तार-केन्द्र भी खोले गये। लगभग ६० औद्योगिक बस्तियाँ भी स्थापित हो चुकी हैं जिनमें लगभग ७०० छोटे कारखाने हैं।

तृतीय योजना में इन उद्योगों के निमित्त २५० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिसका वितरण इस भाँति है—

	करोड़ रुपये
हथकरघा उद्योग -	३६
खादी और ग्रामीण उद्योग	८२
लघु उद्योग और औद्योगिक बस्तियाँ	१०७
हस्तशिल्प	८
रेशम के कोड़े पालना	७
जटा उद्योग	३
	<hr/>
कुल जोड़	२५०
	<hr/>

तृतीय योजना के अन्त तक हथकरघा वस्त्र उत्पादन २५३ करोड़ गज से २८० करोड़ गज, खादी का उत्पादन ८ करोड़ गज से ७० करोड़ गज तथा रेशम का ३७ लाख पौंड से ५० लाख पौंड हो जाने की सम्भावना है। औद्योगिक बस्तियों की संख्या तृतीय योजना के अन्त तक ३६० हो जायगी।

सरकारी नीति

स्वतन्त्रता के समय से ही भारत ने अपने कुटीर और लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया है और इनके महत्व को समझा है। ६ अप्रैल १९४८ के प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इन उद्योगों के स्थानीय साधनों के उपयोग और भावश्यक उपसामग्री पदार्थों में स्वावलम्बन प्राप्त करने के महत्व को पूर्णतः स्वीकार किया गया था। २० अप्रैल १९५६ के द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इन्हें बड़े पैमाने पर कार्य देने, राष्ट्रीय धन के उचित वितरण तथा पूँजी और कार्यशील सम्बन्धी साधनों के सक्रिय संचालन के महत्वपूर्ण साधन मान लिया गया। १९५४ में भारत सरकार ने पीईएफएचएन की सहायता से इन उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करने के निमित्त एक अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया जिसके सुझावों के अनुसार इनके सङ्गठन सुधार पर विशेष जोर दिया गया और सितम्बर १९५४ में एक नया विभाग खोला जिसके सर्वोच्च पदाधिकारी को लघु उद्योग विकास आयुक्त (Development Commissioner) नाम दिया गया। इसी भाँति प्रथम योजना के अन्तर्गत अपनाई कुटीर और ग्राम्य उद्योगों की नीति के अनुसार १९५२ में हस्तशिल्प बोर्ड, १९५३ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा हथकरघा बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, जूता बोर्ड एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड स्थापित किये गये। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एक सलाहकार संस्था थी। अप्रैल १९५७ में इस उद्योग के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक स्वतन्त्र संस्था और बना दी गई। इस भाँति देश भर में कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिये एक व्यापक सङ्गठन का बाल बिछा दिया गया है जो उनकी उन्नति और विकास की योजनाएँ कार्यान्वित करता है। ये संस्थायें उन उद्योगों को विकास सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण, यंत्र-उपकरणों के निर्माण और सुधार, कच्चे माल जुटाने, निर्मित माल की बिक्री, अनुसंधान व्यवस्था तथा विविध आर्थिक समस्याओं के सुलभाने के भरसक यत्न करती हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड केवल सलाहकार संस्था रह गई जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधीन मानी जाती है। बोर्ड का केन्द्रीय कार्यालय दम्बई में है। बोर्ड का सभापति चार विशेषज्ञ समितियों की सहायता से कार्य करता है। एक कार्यकारिणी समिति, दूसरी प्रशिक्षण समिति, तीसरी अन्वेषण समिति और चौथी आर्थिक समिति है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए कई निदेशालय हैं जो आर्थिक अन्वेषण, प्रचार, अम्बर चर्खा, विकास, ग्राम्य उद्योगों तथा सहकारिता आदि विषयों से सम्बन्धित हैं। बोर्ड के कार्यों के लिए देश को सात क्षेत्रों में बाँट दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक क्षेत्रीय निदेशक भी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक ग्रामोद्योग के लिए एक अलग औद्योगिक सयोजक (Industrial Organiser) नियुक्त किया जाता है जो देश भर में भ्रमण करके तथा स्थिति का अध्ययन करके विविध विकास योजनाएँ बनाता और बोर्ड की मंजूरी के लिये भेजता

है और अन्त में उनकी देख-रेख रखना है तथा पथ-प्रदर्शन भी करता है। संयोजकों का कार्य प्रादर्श प्रदर्शन-उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र खोलना भी है। इस भाँति ग्रामीण उद्योगों के स्थापन एवं पुनरुत्थान के लिए आवश्यक बानावरण बनाया जाता और आवश्यक सहायता एवं सुविधायें दी जाती हैं।

लघु उद्योग विकास प्रायुक्त के अधीन लघु उद्योगों के विकास के लिए एक विशाल संगठन बनाया गया है जिसमें लघु उद्योग बोर्ड के प्रतिरिक्त औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Extension Service) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मुख्य हैं। औद्योगिक विस्तार सेवा के अन्तर्गत चार प्रादेशिक लघु सेवा सस्थान मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, और नई दिल्ली में खोले गए हैं, प्रत्येक राज्य में एक सेवा-संस्थान है, चार शाखा सस्थान और ६६ विस्तार केन्द्र भी चालू हैं। इस सेवा संगठन द्वारा लघु उद्योगपतियों को प्राविधिक परामर्श, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता इत्यादि दी जाती है। सेवा सस्थान के अधीन देश भर में अनेक शिल्पशालाएँ, प्रयोगशालाएँ और प्रदर्शन केन्द्र तथा चलती फिरती प्रदर्शन गाड़ियाँ हैं। सेवा संगठन के अन्तर्गत ही औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की जाती हैं, किराया-रक्य प्रणाली के अनुसार मशीनें खरीदने की व्यवस्था की जाती है तथा सरकारी विभागों से लघु उद्योगों के माल के ऋण के लिए आग्रह किया जाता है।

भविष्य

ग्रामीण और लघु उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था के सतुलित विकास के लिए उनकी उत्पत्ति आवश्यक है। ये काम दिलाने के महत्वपूर्ण साधन ही नहीं, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की एक व्यापक और विकेंद्रित आधार भी प्रदान करते हैं। प्रथम और द्वितीय योजनाओं की भाँति तृतीय और भावी योजनाओं में भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा और तदनुसार इन्हें प्रोत्साहन, प्रेरणा और सहायता दी जाएगी। केन्द्रीय और राज्य-सरकारों की इनके प्रति कल्याणकारी नीति जारी रहेगी। यह आशा की जाती है कि कुछ ही काल में ये उद्योग फिर से अपने खोए हुए प्राचीन वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे।

“अपने विभिन्न रूपों में भारत के ग्रामीण उद्योग देश की आर्थिक संरचना एवं राष्ट्रीय आयोजन के आवश्यक अंग एवं शाश्वत तत्व हैं।”
—योजना आयोग

१०—ग्रामीण उद्योगों का पुनरुत्थान

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना ।
२. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ।
३. समस्याएँ ।
४. प्रशिक्षण ।
५. आर्थिक सहायता ।
६. संगठन ।
७. गहन क्षेत्र योजना ।
८. सरकार द्वारा माल का क्रय ।
९. भविष्य ।

प्रस्तावना

भारत की ८२ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। गाँव के लोगों का मुख्य धंधा खेती है। लेकिन खेती पर इतना अधिक भार है कि वह उन्हें वर्ष भर काम देने में असमर्थ है। गाँवों के अनेक लोग बेकार अथवा अर्द्ध-बेकार हैं। ऐसे लोगों के जीवन-निर्वाह का एकमात्र साधन ग्रामीण उद्योग हैं जो इस समय लगभग दो करोड़ ग्रामीणों को काम देते हैं।

हमारे ये उद्योग भक्ति प्राचीन काल से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और असीसर्वा सताब्दी के प्रारम्भ तक ये अत्यन्त उपतिथील अवस्था में थे। तदुपरान्त कई कारणों से इनका पतन होने लगा। तब से इनका पतन जारी है और आज हमारे ये अनेक शिल्पकार जो अपनी कला के लिये विद्व विरुधात थे बेकार हैं। चूड़ई, तुहार, सुनार, तेली, मोची, दर्जी, नाई, बहार समी निरसहाय अवस्था में हैं।

इनका और भूमिहीन किसान का उद्धार ग्रामीण उद्योगों के पुनरुत्थान से सम्बन्ध है। यही नहीं, सम्पूर्ण ग्राम्य समाज का उत्थान भी इन्हीं उद्योगों के उत्थान पर निर्भर है।

अतएव वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रपिता गांधी ने इन उद्योगों के पुनर्निर्माण की ओर देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने चर्खा, खादी, पशु-पालन तथा अन्य ग्राम उद्योगों को एक राजनैतिक महत्व का प्रश्न बना दिया। उन्होंने अखिल भारतीय चर्खा सघ, अखिल भारतीय कताई सस्था, अखिल-भारतीय ग्राम्य उद्योग सघ स्थापित कर इस ओर प्रयत्न प्रारम्भ किए। क्रमशः यह विषय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बन गया।

स्वतन्त्रता के उपरान्त, भारत सरकार ने इन उद्योगों के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु और ग्रामीण उद्योगों पर ३३.६० करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसमें से खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों पर १५.२० करोड़ व्यय हुआ। द्वितीय योजना में लघु उद्योगों के लिये २०० करोड़ रुपये रखे गये जिसमें से ५५.५० करोड़ रुपये खादी और ग्राम्य उद्योगों के निमित्त थे। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के निमित्त १८ करोड़ रुपये का अनुमान था, जिसका एक अंश गृह उद्योगों में लगाया गया। सामुदायिक विकास योजनाओं पर होने वाले व्यय में से भी ४ करोड़ रुपये की धन-राशि ग्रामीण उद्योगों के निमित्त थी। यह अनुमान लगाया गया है कि लघु और ग्राम्य उद्योगों पर द्वितीय योजना के अन्त तक लगभग १८० करोड़ रुपये व्यय हुए जिनमें से ८०.५० करोड़ रुपये केवल खादी और ग्रामीण उद्योगों पर व्यय हुए। तृतीय योजना में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के निमित्त २५० करोड़ रुपये की धनराशि का अनुमान है जिसमें ८६ करोड़ रुपये खादी और ग्राम्य उद्योगों के लिये हैं।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड

यद्यपि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास का सारा उत्तरदायित्व राज्यों की सरकारों पर है, किन्तु तो भी केन्द्रीय सरकार ने उनके पतनों को प्रोत्साहित करने के विचार से ६ बोर्ड स्थापित किये हैं। ये (१) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (२) (२) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, (३) खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड, (४) लघु उद्योग बोर्ड, (५) जटा बोर्ड, (६) केन्द्रीय रेशम बोर्ड इत्यादि हैं। इनमें से खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड का सम्बन्ध ग्रामीण उद्योगों की उत्थिति और विकास से है। फरवरी १९५३ में बोर्ड की स्थापना हुई थी। बोर्ड ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में खादी, धानी चावल कूटना, गुड़ एवं खांडसारी, चमड़ा एवं दियासलाई इत्यादि १० ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया। द्वितीय योजना में छद्म उद्योग और ले लिये गये। ये उद्योग साबुन बनाना, ताड़ से गुड़ बनाना, कागज बनाना, गृह की मक्खियाँ पालना, बर्तन बनाना

तथा रक्षा उद्योग थे। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य इन उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण, आवश्यक यंत्र-उपकरणों का निर्माण और उपलब्धि, कच्चा माल जुटाना, निर्मित माल की बिक्री का प्रबन्ध करना, अनुसंधान व्यवस्था करना है। प्रत्येक उद्योग की प्राथमिक समस्याओं के अध्ययन का उत्तरदायित्व भी बोर्ड ने अपने ऊपर ले लिया है। प्रारम्भ में बोर्ड केवल परामर्शदात्री संस्था थी, किन्तु कालान्तर में वह स्वायत्त संस्था मान ली गई तथा उसे उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाने और उसके कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक धन देने का भी अधिकार मिल गया। अद्य बोर्ड के उक्त अधिकार अखिल भारतीय ग्राम्य उद्योग आयोग ने ले लिये हैं और बोर्ड पहले के समान केवल परामर्शदात्री संस्था रह गई है।

बोर्ड का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है। बोर्ड का समापति चार विशेषज्ञ समितियों की सहायता से कार्य करता है। एक कार्यकारिणी समिति है, दूसरी का काम प्रशिक्षण, तीसरी का सम्बन्ध अन्वेषण से तथा चौथी का उद्योगों की प्राथमिक समस्याओं से है। बोर्ड अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा अपनी नीति लागू करता है। उसकी सहायता के लिये कई निदेशकों का अपना निदेशालय है। ये निदेशालय प्राथमिक अन्वेषण, प्रचार, अम्बर चर्खा विकास, ग्राम्य उद्योग तथा सहकारिता से सम्बन्धित हैं। बोर्ड के कार्यों के लिये देश को सात क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है।

समस्याये

इन उद्योगों की अनेक समस्याओं में से मुख्य शैक्षिक ज्ञान, पूँजी तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी पथ-प्रदर्शकों का अभाव, बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता एवं माल की बिक्री की कठिनाइयाँ इत्यादि हैं। इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं विविध सुविधाये भी इन उद्योगों को प्रदान की जा रही हैं।

प्रशिक्षण

बोर्ड की स्थायी प्रशिक्षण समिति इस कार्य के लिये उत्तरदायी है और प्रशिक्षण निदेशक की देख-रेख में प्रशिक्षण व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षकों, संयोजकों एवं ग्रामीण शिल्पियों के प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था भी गई है। सामुदायिक विकास क्षेत्रों में इन उद्योगों के विकास के विचार से उस क्षेत्र के प्रसार अधिकारियों (प्रौद्योगिक) एवं ग्राम्यसेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। चार प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रथम दीर्घकालीन एवं गहन प्रशिक्षण है जो ऐसे संयोजकों, प्रशिक्षकों एवं प्रसार अधिकारियों के निमित्त है, जो सामुदायिक विकास क्षेत्रों अथवा खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालयों में काम करते हैं। दूसरे प्रकार का अल्पकालीन प्रशिक्षण है जो क्षेत्रीय ग्रामोद्योग महाविद्यालयों के शैक्षिक सहायकों एवं शिक्षकों को दिया जाता है।

इसमें खादी और ग्रामोद्योगो सम्बन्धी ज्ञान कराया जाता है। तीसरा विशेष गहन प्रशिक्षण है जो ग्राम विशेष के उद्योगो से सम्बन्धित होता है तथा वहाँ के उत्पादन केन्द्रों के निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। चौथा प्रशिक्षण सामयिक पुनरभ्यास पाठ्यक्रम है जो कार्यकर्त्ताओं एवं शिल्पकारों को अन्तिमतम प्रयोगों एवं अन्वेषणों की जानकारी कराने के निमित्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अम्बर-चर्खा सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण सुविधायें भी की गई हैं।

आर्थिक सहायता

नये ग्रामोद्योगो के स्थापन और वर्तमान उद्योगो को प्रोत्साहन देने के विचार से विविध प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रत्यक्ष अर्थ-साहाय्य, अनुदान, बिना व्याज ऋण अथवा व्याज सहित ऋण इत्यादि विविध प्रकार की हो सकती है। नये उद्योग स्थापित करने के लिये पूँजी के रूप में भी सहायता दी जाती है। बच्चा माल मोल लेने, बने माल की बिक्री के लिये अथवा अन्वेषण करने के लिये धन दिया जाता है। उत्पादन मूल्य में कमी करने के लिये भी सहायता दी जाती है, ताकि उद्योग विशेष बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में अपना माल सुविधापूर्वक बेच सके। रेशमी खादी व परमोना पर १० नये पैसे प्रति रुपया तथा अन्य प्रकार की खादी व सिले कपड़ों पर १६ नये पैसे प्रति रुपया छूट दी जाती है। जो लोग निजी प्रयोग के लिये खादी बुनते हैं उन्हें ५ पाने तक अर्थ-सहायता दी जाती है तथा ६ पाई रुपया खादी-उत्पादन अथवा बिक्री केन्द्र को। पानी के तेल पर भी अर्थ-साहाय्य दिया जाता है। सभी उद्योगों के सम्बन्ध में प्रदिशानु पाने वाले विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं।

वैधानिक राज्य बोर्डों अथवा सहकारी समितियों द्वारा सहायता उद्योगों अथवा कारीगरों को वितरित की जाती है। त्रिन राज्यों में वैधानिक बोर्ड हैं उन्हें आर्थिक सहायता सीधी पहुँचाई जाती है, किन्तु जहाँ ये बोर्ड केवल सलाहकार मात्र हैं उन्हें उस राज्य की सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, प्रथम योजना काल में खादी और ग्रामोद्योग पर १६ करोड़ रुपए व्यय किए गए और द्वितीय योजना में ५५.५० करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इसमें से ४ करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार की योजनाओं पर और शेष ५१.५० करोड़ रुपए राज्यों द्वारा उपाई गई योजनाओं में व्यय हुए। इन उद्योगों के निमित्त विशेष निधि स्थापित करने का भी विचार है।

संगठन

प्रत्येक ग्राम्य उद्योग के विकास का पूरा अनुशासित एक आर्थिक संयोजन के हाथ में है। वह देश भर में प्रगति रहना है और उद्योग की अर्थिक एवं सामाजिक पुरी जानकारी प्राप्त करके विकास योजना बनाना है तथा उसे बॉर्ड के अन्तर्गत रखता है। बॉर्ड अपनी कार्यकारिणी की सहायता से इन योजनाओं की अन्वेषण करके उनकी मंजूरी देता है एवं आवश्यक धन की व्यवस्था करता है। योजना बनाने

होने के उपरान्त उसकी देखभाल और पथ-प्रदर्शन भी यही संयोजक करता है। ये संयोजक सिलबकारों को विविध प्रकार की जानकारी और सहायता करते हैं, उन्हें सहकारी समितियाँ बनाने की प्रेरणा देते हैं, उनके माल की बिक्री के सम्बन्ध में परामर्श और पथ-प्रदर्शन करते हैं, उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और प्रतिযোগिताओं में भाग लेने को कहते हैं, उन्हें उत्पादन के नए ढंग एवं यन्त्र प्रयोग करने का परामर्श देते हैं, तथा विकास योजनाओं में उपलब्ध आर्थिक सहायता की सूचना देते हैं। ये आदर्श प्रदर्शन उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र भी खोलते हैं जिन्हें देखकर कारीगर नई विधियाँ एवं नये यन्त्रों का प्रयोग सीख सकें। इस भाँति इन संयोजकों का कार्य ग्रामीण उद्योगों के स्थापन एवं पुनरुत्थान के लिये आवश्यक वातावरण बनाना और सहायता देना है।

गहन क्षेत्र योजना

आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के सिद्धान्त को आधार मानकर बोर्ड ने एक गहन क्षेत्र योजना नामक कार्यक्रम चलाया है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रथम-व्यवस्था का संगठित विकास है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों की देखभाल अथवा अर्द्ध-देखभाल का काम देने के लिए सहायक अथवा वैकल्पिक उद्योगों के रूप में लाया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक विरादरी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र होता है। केन्द्रों में अथ क्षेत्र के निवासियों को ऐसी सुविधा दी जाती है कि वे अपने घर की छोटे-से और तिलहन को तेल में परिवर्तित करा सकें। प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में एक ग्राम विकास मण्डल होता है जो विरादरी केन्द्रों की देख-रेख रखता है। एक क्षेत्र समिति प्रत्येक मण्डल का पथ-प्रदर्शन करती है। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता अथवा ऋण के रूप में आवश्यक धन बोर्ड देता है। यह योजना देश के २१,००० गाँवों में चालू है। १९५५-५६ में ऐसी योजनाएँ चालू की गई थीं। अथ इनकी संख्या २०० ही गई है।

सरकार द्वारा माल का क्रय

ग्राम्य उद्योगों की अनेक समस्याओं में सबसे अधिक कठिन समस्या माल की बिक्री की है। इन उद्योगों का बड़े उद्योगों की भाँति कोई विश्व संगठन नहीं होता। अतएव उपभोक्ता तक पहुँचना उनके लिये कठिन होता है। इस समस्या को सुलभाने के निमित्त बिक्री केन्द्र व दूकानें खोलकर तथा प्रदर्शन केन्द्रों एवं प्रचार द्वारा माल की बिक्री की व्यवस्था की जाती है। साथ ही भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने अपनी आवश्यकता का कुछ माल छोटे अथवा ग्रामीण उद्योगों से लेने का निश्चय कर लिया है। सरकारी, कर्मचारियों की, बस्तियों के, जिल्ह, खादी, का, अधिकाधिक, प्रयोग, किया जाने लगा है जिससे इस उद्योग की अप्रत्यक्ष सहायता और प्रोत्साहन मिलता है। करोड़ों रुपये की खादी प्रतिवर्ष सरकार खरीदती है। केन्द्रीय सरकार चार लाख कम्बल और ५०,००० गज ऊनी कपड़ा प्रतिवर्ष अपने लिये खादी उद्योग से

लेती है। सरकारी विभागों को खादी उपसन्ध करने के लिये सरकार ने एक विशेष निदेशालय स्थापित कर दिया है।

भविष्य

इस भाँति विविध प्रकार की सहायता व प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीण उद्योगों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। फलस्वरूप १९५०-५१ और १९६०-६१ के बीच हथकरघे के कपडे व उत्पादन ७४.२० करोड गज से २१२.५७ करोड गज, खादी का उत्पादन ७० लाख गज से ८०० लाख गज और रेशम का उत्पादन २० लाख पौंड से ३७ लाख पौंड हो गया। तृतीय योजनाकाल में हथकरघे के कपडे का उत्पादन २८० करोड गज, खादी का ७० करोड गज तथा रेशम का ५० लाख पौंड होने की संभावना है। ऐसी उन्नति अन्य उद्योगों में भी हुई है। जो काम गत वर्षों में हो चुका है उसकी जडेँ मजबूत करने के अतिरिक्त तीसरी योजना में कुछ चुने हुये क्षेत्रों में सघन प्रयोग करने और इन उद्योगों के कार्यक्रमों को ग्राम विकास के दूसरे कार्यक्रमों से पूरी तरह समन्वित करने पर जोर दिया गया है। ऐसे व्यापक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं जिनमें गाँवों के शिल्पकारों और कारीगरों की विभिन्न आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रशिक्षण सुविधाएँ, उचित व्याज पर सरल ऋण-व्यवस्था, विस्तार सेवाओं द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता, समरण, बच्चे माल के ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ, बिक्री-केन्द्रों द्वारा माल की बिक्री व्यवस्था तथा उद्योगशालाओं का निर्माण इत्यादि। विशेषतः नए यन्त्रों और बिजली की शक्ति के प्रयोग द्वारा इन उद्योगों को कामयाब बनाने का हमारा लक्ष्य है ताकि ये उद्योग भारत के भावी गाँवों की नवीन आवश्यकताओं की भली भाँति पूर्ति कर सकें और अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त कर सकें।

"अभिनवीकरण को रोचना व आधुनिकीकरण की क्रिया के मार्ग में बाधाएं डालना न केवल अताकिक है, वरन् भारतीय उद्योगों को बरबस अस्थिरता और अवनति की ओर ले जाना है।"

—अन्तर्राष्ट्रीय और प्रायोजन समुदाय ।

११—अभिनवीकरण

रूप-रेखा

१. परिभाषा
२. सिद्धान्त और विधियाँ
३. उद्देश्य
४. साम
५. धम द्वारा विरोध
६. कठिनाइयाँ
७. भारत में आवश्यकता
 - (क) कारण
 - (ख) अनुमतियाँ
८. उपसंहार ।

परिभाषा

अभिनवीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य में नवीनता, विज्ञान, युक्ति अथवा विवेक के समावेश से है। इसका प्रयोग किसी उद्योग में युक्ति, विवेक, विज्ञान अथवा नवीनता लाने के लिए किया जाता है। अतएव समुत्तीकरण, विवेकीकरण, वैज्ञानिकन, नवीनीकरण अथवा नवीकरण इत्यादि शब्द भी इसके पर्यायवाची माने जाते हैं। प्रात्र के वैज्ञानिक युग में अवेज्ञानिक ढंग से सर्गित्त विवेकहीन कोई भी उद्योग उन्नत नहीं हो सकता और न वह उच्च कोटि का उत्पादन ही दे सकता है। अतः अभिनवीकरण आधुनिक उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रतीक है।

सर्व प्रथम इस शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के स्वभाविक कार्यों के लिए युक्तिसंगत कारण जानने के लिए किया गया। सन् १९२४ में जर्मनी में इस शब्द का प्रयोग औद्योगिक पुनर्गठन के लिये किया गया। अन्त में १९२७ में जैनेवा में हुए विश्व आर्थिक सम्मेलन ने इसे एक औद्योगिक क्रान्ति का पद दिया तथा इसकी व्यापक व्याख्या की। इस परिभाषा के अनुसार अभिनवीकरण युक्ति (Technique) और संगठन (Organization) की वे विधियाँ हैं जो श्रम (Effort) और साधनों (material) का अपव्यय कम से कम करने के लिये अपनाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत (क) श्रम का वैज्ञानिक संगठन, (ख) उत्पादन और पदार्थों का प्रतिमानीकरण, (ग) प्रक्रियाओं का सरल करना तथा (घ) परिवहन एवं बिक्री-व्यवस्थाओं में सुधार इत्यादि बातें सम्मिलित हैं। अभिनवीकरण वा सम्बन्ध परम्परागत प्रक्रियाओं के स्थान पर आर्थिक और सामाजिक प्रायोजनाओं के लागू करने और सर्वाङ्गपूर्ण औद्योगिक सुधार से है। १९५६ की कानपुर सूनी वस्त्र उद्योग अभिनवीकरण समिति ने इसका अर्थ विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक सुधार बताया जिसके द्वारा न्यूनतम श्रम और धन व्यय करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। यह सुधार कार्य उद्योग के विविध पट्टुओं मनुष्यों, माल, मशीनों, पूँजी और प्रबन्ध इत्यादि में आवश्यक समझा गया।

सिद्धान्त और विधियाँ

अभिनवीकरण के चार मुख्य रूप हैं :—(क) तकनीकी, (ख) संगठनात्मक, (ग) वित्तीय, तथा (घ) सामाजिक अथवा मानवीय।

यस्तुनः अभिनवीकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है और उद्योग के यंत्रीकरण से इसका धनियुक्त सम्बन्ध है। श्रम की अपेक्षा आधुनिक उद्योग अपने माल के गुण-सुधार और मूल्य कम करने के लिए आधुनिकतम मशीनों का अधिक आश्रय लेता है। उद्योग के यंत्रीकरण के साथ-साथ, विशेषीकरण की गति बढ़ाई जाती है; उत्पादन और माल का प्रतिमानीकरण किया जाता है, उत्पादन प्रिया को अधिकधिक सरल बनाया जाता है और वैज्ञानिक प्रव-घ का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है।

संगठनात्मक अभिनवीकरण के अन्तर्गत दुर्बल इकाइयों को सबल और कार्य कुशल इकाइयों के साथ मिलाकर उद्योग को पुनर्गठित किया जाता है। इससे अस्वरथ प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और उच्च कोटि का उत्पादन होने लगता है। सम्मेलन के द्वारा सभी इकाइयों को आधुनिकतम इकाई बनाया जाता है और अपव्यय कम से कम होने दिया जाता है।

वित्तीय अभिनवीकरण के द्वारा उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है। न तो उद्योग अति पूँजीकरण के दोष से दूषित हो और न कम पूँजी के कारण निम्न कोटि का उत्पादन करता हो। पूँजी के प्रत्येक रूप का पूर्ण उपयोग होता रहना चाहिए। आधुनिकतम क्रियाओं और मशीनों के प्रयोग के लिए उद्योग के पास पर्याप्त धन व्यवस्था आवश्यक है।

अभिनवीकरण एक यात्रिक क्रिया ही नहीं, मानवीय बला भी है। अतएव श्रम की भर्ती में, उसके हटाने में, मजदूरी में, काम के घटों में, उसके बँटवारे में श्रमिक के कल्याण और उसकी सुख-सुविधाओं एवं भावनाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है और इस भाँति पूँजी और श्रम के सम्बन्ध अच्छे किये जाते हैं। समाज हित का ध्यान रख कर उत्पादन किया जाता है। कोई राष्ट्र विरोधी उद्योग अभिनवीकरण का अधिकारी नहीं।

कोई उद्योग अभिनवीकरण की उक्त विधियों में से किसी एक अथवा अधिक को अपना सकता है, सभी का एक साथ समागम आवश्यक नहीं है, यद्यपि वाछनीय है।

उद्देश्य

अभिनवीकरण के मुख्य उद्देश्य : (क) उत्पादन वृद्धि, (ख) माल का गुण सुधार, (ग) उत्पादन व्यय में कमी और (घ) श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार हैं। (ङ) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्योग को विवेकपूर्ण निर्देश और प्रबन्ध के अन्तर्गत संगठित किया जाता है तथा उद्योग की सम्पूर्ण इकाइयों को एक बड़ी इकाई के अंग-प्रत्यंग माना जाता है और उनका पारस्परिक विरोधी भाव समाप्त हो जाता है।

लाभ

अभिनवीकरण से होने वाले मुख्य लाभ निम्नांकित हैं :—

- (क) विशालकाय उत्पादन सम्बन्धी मितव्ययता और लाभ,
- (ख) जीवन-स्तर ऊँचा उठाना,
- (ग) उद्योग की आन्तरिक एवं बाह्य प्रतियोगिता शक्ति बढ़ाना,
- (घ) संघर्ष के कारण हुआकर औद्योगिक वातावरण में स्थिरता स्थापित करना।

ये लाभ समाज के किसी एक वर्ग तक ही सीमित नहीं। इनका स्वस्थ प्रभाव देश और जाति के सभी वर्गों पर पड़ता है। मुख्यतः उद्योगपति, उपभोक्ता और श्रम-जीवी वर्ग को अभिनवीकरण से विशेष लाभ पहुँचता है।

उद्योगपति को अभिनवीकरण का लाभ आर्थिक इकाइयों और प्रतियोगिता के हटने, उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग, अपव्यय कम होने तथा उद्योग के विवेकपूर्ण निर्देश और प्रबन्ध के अन्तर्गत आने से मिलता है। उद्योगपति की सख्त और घन-साधन जुटाने की क्षमता बढ़ जाती है। अभिनवीकरण से श्रमिक वर्ग का कार्य-कौशल बढ़ना है, उसे बकावट कम से कम होती है, उसे पारिश्रमिक अधिक मिलने लगता है तथा वह एक स्वस्थ वातावरण में काम करता है। उसका जीवन-स्तर दिनो-दिन उच्चतर होता चला जाता है। अभिनवीकरण से उपभोक्ता को भी भारी लाभ होता है। उसे सस्ता और उच्चकोटि का माल आवश्यकतानुसार मिलने लगता है तथा उसकी क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। अभिनवीकरण का उद्देश्य उद्योगपति एवं श्रमजीवी को ही लाभ पहुँचाना नहीं है, बरन् देश और समाज को भी गौरवान्वित करना है। अभिनवी-

करण से देश के साधनों का समुचित उपयोगी होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। संगठित औद्योगिक व्यवस्था के कारण अन्वेषण द्वारा नए-नए उत्पादनों और क्रियाओं का आविर्भाव होता है जिससे धन-वैभव और सुख-शान्ति में वृद्धि होती है।

श्रम द्वारा विरोध

यद्यपि अभिनवीकरण से समाज के सभी अंगों को अपार लाभ होते हैं, किन्तु श्रमिक वर्ग की ओर से ऐसी योजनाओं का भारी विरोध होता है। इस विरोध के अनेक कारण हैं (१) बेकारी फैलने का भय, (२) कार्य भार बढ़ने की सम्भावना और फलस्वरूप अधिक थकावट की आशंका तथा (३) अभिनवीकरण से होने वाले लाभों का अनुचित एवं असमान वितरण इत्यादि इस विरोध के मुख्य कारण हैं। अभिनवीकरण की योजनाएँ लागू करते समय उत्तम से उत्तम और आधुनिकतम मशीनें स्थापित की जाती हैं। अतएव अनेक श्रमजीवी काम से हटा दिये जाते हैं। अनेक अलाभकर इकाइयाँ बन्द कर दी जाती हैं जिनमें काम करने वाले कर्मचारी बेकार हो जाते हैं। उत्पादन की माँग के अनुरूप समायोजित करना पड़ता है जिससे काम के साधन बहुधा कम हो जाते हैं। साथ ही कम कार्यकुशल व्यक्तियों को हटा कर उच्च शिक्षा प्राप्त एवं कार्यकुशल कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव तत्कालीन बेकारी होती है। अतएव श्रमिक वर्ग का विरोध स्वाभाविक है। वस्तुतः यह विरोध संकुचित दृष्टिकोण और अदूरदर्शिता का सूचक है, क्योंकि अन्ततोगत्वा अभिनवीकरण से कार्य के साधनों में वृद्धि होती है। उत्पादन सस्ता और उच्च-कोटि का होने एवं उपभोक्ता की श्रम-शक्ति बढ़ने से औद्योगिक प्रसार होता है, अनेक नई इकाइयाँ स्थापित होती हैं, अनेक सहायक उद्योग और सहायक साधनों व सेवाओं का जन्म होता है। इस भाँति अधिकाधिक लोगों को काम मिलता है। गत अनुभव से मशीन कार्य वृद्धि का एक अपूर्व साधन सिद्ध हो चुकी है। ब्रिटेन में शक्ति चालित तकिए व करघों के चालू होने के उपरान्त एक पीढ़ी की अवधि में दस गुने अधिक लोग उस उद्योग में काम करने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ६० वर्ष की अवधि में श्रम-जीवियों की संख्या १८० लाख से बढ़कर ६०० लाख हो गई, १९३९ और १९५३ के बीच वहाँ के निर्माण उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या में ७५% बढ़ोतरी आई।

मशीन के प्रयोग से मनुष्य को अनेक भारी, थकावट पूर्ण और कठिन कार्यों से छुटकारा मिल गया है। जर्मनी में जिस मोटर के बनने में चार महीने लगते थे, नई युक्ति द्वारा उसे केवल तीन सप्ताह में बनाया जाने लगा। ब्रिटेन में जिस मरम्मत के काम में १९२० में २½ महीने लगते थे, १९३० में उसे ४७ घण्टे में किया जाने लगा।

यदि अभिनवीकरण का कार्य-क्रम चढते हुए मूल्यों और बढ़ती हुई माँग के समय लागू किया जाता है तो हटाए गए श्रम को काम में लगाने में कोई कठिनाई

नहीं होती। गिरते हुए मूल्यों और घटती हुई माँग के समय इन योजनाओं को लागू न करने की सावधानी बरतनी आवश्यक है।

कठिनाइयाँ

(क) श्रमिक वर्ग का विरोध अभिनवीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है।
 (ख) धनाभाव दूसरी भारी कठिनाई है। मूल्यवात नई मशीनें और उपकरण लेने के लिए श्रमित धन की आवश्यकता होती है जो सभी उद्योग अथवा इकाइयाँ जुटाने में असमर्थ रहती हैं। हमारे छूट उद्योग के लिए ५० करोड़ रुपए और सूती वस्त्र के लिए ३०० करोड़ रुपए की पूँजी का अभिनवीकरण के निमित्त अनुमान लगाया गया है।
 (ग) एकाधिकार सम्बन्धी दोष तीसरी बड़ी कठिनाई है। सम्मिलित इकाइयों के एकाधिकार स्थापित होने का मज सुदैव बना रहता है। (घ) अभिनवीकरण के लिए उच्च योग्यता और शिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी हमारे देश में भारी कमी है। (ङ) बहूधा कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। अतएव व्यक्तिगत योग्यता और साहस दिखाने के कम अवसर आते हैं। इससे लोगों में प्राण वढ़ने की रुचि कम होती है और प्रन्वेषण मार्ग रकता है। (च) हमारे देश में अनु-संज्ञान सुविधाओं और प्रतिमानीकरण प्रयोगशालाओं का अभाव भी इसके मार्ग की एक बड़ी बाधा है।

भारत में अभिनवीकरण की आवश्यकता

(क) देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को काम देने के लिए अन्य देशों की अपेक्षा भारत की अभिनवीकरण की अधिक आवश्यकता है। पुरानी मशीनों से उत्पादन कम होता है और मूल्य ऊँचा बढ़ जाता है तथा मजदूरी की दर कम हो जाती है। इससे माँग और नय-शक्ति कम होकर उत्पादन और भी कम होता जाता है। इसका अवश्यम्भावी परिणाम गरीबी और बेकारी होता है जिससे छुटकारा पाने का एक मात्र मार्ग अभिनवीकरण है।

(ख) देश में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सर्वमान्य है। इसका एक मात्र साधन उच्च कोटि की मशीनों और उत्पादन क्रियाओं का प्रयोग ही है।

(ग) भारतीय सीमेंट उद्योग ने अभिनवीकरण का सहारा लेकर प्रकृता संगठन सुदृढ़ कर लिया है, किन्तु देश के कई अन्य उद्योग जैसे सूती वस्त्र, छूट, कीयता, लोहा-इस्पात और चीनी इत्यादि, इस दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। विदेशी प्रति-योगिता का सामना करने के लिए उन्हें प्रतियोगी देशों की भाँति ही अभिनवीकरण करना आवश्यक है।

(घ) मन् १९४५ से भारत का विदेशी व्यापार घाटे में है। इस घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे निर्यात पदार्थों में कुछ गिनी छुनी परम्परागत वस्तुएँ ही महत्वपूर्ण हैं। इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उच्च कोटि का सस्ता माल बनना आवश्यक है जो अभिनवीकरण द्वारा ही

संभव है। हमारे सूती वस्त्र और जूट निम्न मात्र, चाय इत्यादि का निर्माण गन्तव्यो में विदेशी प्रतिभोगिता के कारण कम हो गया है।

(क) हमारे कुछ उद्योग मभिनवीकरण मशीनों से काम चला रहे हैं जिससे उत्पादन निम्न कोटि का होता है और उत्पादन खर्च उँचा। सूती वस्त्र उद्योग के कनाई विभाग में ३०% मशीनें १९१० से पहले की और ६५% मशीनें १९२५ से पहले की गयी हुई हैं। उससे बुनाई विभाग में ५९% मशीनें १९१० से पहले की और ७५% मशीनें १९२५ से पूर्व की हैं। वस्त्र उद्योग में समुक्त राष्ट्र में अनुप्रतिष्ठान, फ्रांस में ५२%, इटली में ५१%, रूस में ४१%, प० जर्मनी में २८%, पाकिस्तान में २६%, जापान में १८%, ब्रिटेन में १५%, चीन में १२% करके स्वचालित हैं जबकि भारत में केवल ७%।

(ख) १९५५ में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल तथा जादागो समिति ने मह सुझाव दिया कि भारतीय उद्योगों का मभिनवीकरण वास्तविक ही नहीं आवश्यक है। इस सुझावों के अनुसार उसी वर्ष संसद में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार सूतीवस्त्र और जूट उद्योगों में कुछ शर्तों के साथ मभिनवीकरण की योजना दी गई। सूतीवस्त्र उद्योग समिति १९५८ ने और योजना आयोग ने भी इन उद्योगों के मभिनवीकरण की अनुमति दी है।

उपसंहार

विदेशी बाजारों में बढ़ती हुई प्रतिभोगिता का सामना करने और उच्च कोटि का सस्ता माल बनाने के विचार से देश के सूती वस्त्र, जूट, शोहा-इस्पात, चीनला और चीनी उद्योगों में मभिनवीकरण की निरन्तर आवश्यकता है, किन्तु मभिनवीकरण की योजना लागू करते समय बेकारों का बचाव होना चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड ने कुछ सिद्धान्त बना दिए हैं जिनका पालन करने से बेकारी की मात्रा दूर हो जाती है।

“देश के निजी औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का आज भी बोलवाला है जिसका ७० प्रतिशत सार्वजनिक सीमित दायित्व कम्पनियों पर अधिकार है।”

—पी० एस० लोकनाथन

१२—प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति

रूप-रेखा

१. परिभाषा
२. इतिहास (जन्म और विकास)
३. वर्तमान स्थिति
४. कार्य
 - (क) प्रवर्तक
 - (ख) प्रबन्धकर्ता
 - (ग) वित्तपोषक
 - (घ) ऋण-विक्रय
५. दोष
 - (क) अधिक पारिधमिक
 - (ख) एकाधिकार
 - (ग) अनेक कम्पनियों का प्रबन्ध
 - (घ) एक कम्पनी का धन दूसरी में लगाना
 - (ङ) अंशधारियों और संचालकों पर भाषिपत्य
६. सुधार
 - (क) १९३६ के नियन्त्रण
 - (ख) १९५१ का अध्यादेश
 - (ग) १९५६ का कानून
७. वर्तमान सरकारी नीति
८. मविष्य

परिभाषा

प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति भारतीय विशालकाय उद्योग के प्रबन्ध का एक अनुपम ढंग है। परिमित दायित्व कम्पनियो का प्रबन्ध या तो एक संचालक मण्डल किसी प्रबन्धकर्ता अथवा प्रबन्धकारी संचालक की सहायता से करता है या वह किसी समझौते द्वारा एक प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति करता है। यह प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के प्रबन्ध सम्बन्धी प्रतिनिधि समझे जाते हैं जो समझौते के अनुसार संचालक मण्डल की देख रेख में कम्पनी के सम्पूर्ण प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। यह कोई व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी हो सकते हैं। इनके समझौते के नियमों का कम्पनी के अधिकार पत्र (Memorandum) अथवा अर्तनियमों (Articles) में भी समावेश हो सकता है और अलग किसी सविदे में भी। इन्हें अपना काम बढ़ाया संचालक मण्डल की देख रेख में करना पड़ता है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य देशों में भी कम्पनियों का प्रबन्ध ऐसी सस्थाओं के हाथ में है, किन्तु भारतीय पद्धति उन सबसे सर्वथा भिन्न और विचित्र है जो देश की परिस्थितियों के पूर्णतः अनुकूल है।

जन्म और विकास

भारत में बड़े उद्योगों का आविर्भाव यूरोप के उद्योगपतियों और पूँजीपतियों के द्वारा हुआ। उस समय भारत के लोगों को बड़े उद्योगों के विशाल सगठन का अनुभव नहीं था, यहाँ महाजनी सुविधाय भी विकसित नहीं हुई थी, लोगों में बचत और विनियोग की प्रवृत्ति भी नहीं थी। भारत का लगभग सम्पूर्ण विदेशी व्यापार अंग्रेज और यूरोप के लोगों के हाथ में चला गया था। ब्रिटेन के व्यापारी लोग भारत में ब्रिटिश कम्पनियों अथवा साझेदारी सस्थाओं के प्रतिनिधि होकर आए। इन लोगों को बड़े व्यवसाय के सगठन, प्रवर्तन तथा प्रबन्ध का अच्छा अनुभव था। भारत में आकर इन्होंने यहाँ औद्योगिक विकास-विस्तार के लिए विशाल क्षेत्र देखा। अतएव यहाँ नए-नए उद्योग स्थापित करने लगे। ऐसे किसी व्यक्ति अथवा सस्था ने प्रथम जूट मिल स्थापित किया, तो उसके लिए शक्ति साधन जुटाने के लिए कोयला कम्पनी चालू की और फिर कोयले की दुलाई के निमित्त नीपरिवहन व्यवसाय हाथ में ले लिया। इस भाँति एक ही उद्योगपति विविध उद्योग चलाने लगा।

भारत और ब्रिटेन की दूरी और जलवायु की उष्णता के कारण कुछ ही लोग भारत में रह कर इन उद्योगों को चलाते थे। अतएव प्रवर्तन, वित्तपोषण एवं प्रबन्ध इत्यादि सभी कार्य इन्हें करने पड़ते थे। कभी कुछ ऐसे उद्योगों का भी प्रबन्ध इन्हें करना पड़ता था जिनके ये स्वामी नहीं थे। यही लोग अथवा सस्थाएँ प्रबन्ध अभिकर्ता कहलाएँ। प्रारम्भ में ये बढ़ाया पारिवारिक साझेदारी सस्थाएँ थीं। कालान्तर में कुछ कम्पनियाँ बन गईं और कुछ व्यक्तियों ने इस काम को करने लगे। इन लोगों ने पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बंगाल और आसाम में जूट कार्यालय, चाय उद्योग, कोयला कम्पनियाँ, नीपरिवहन सस्थाएँ तथा चीनी उद्योग प्रारम्भ किये और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गए।

इसी भाँति पश्चिमी क्षेत्र (बम्बई, ग्रहमदाबाद) में भारत के व्यापारी लोगो ने सूती वस्त्र और अन्य उद्योग स्थापित किए और उनके सर्वेसर्वा बन गए। पूर्वी क्षेत्र में यूरोपीय और पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ताओं का एकाधिकार स्थापित हो गया। भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ता बहुधा पारसी, मुसलमान, महरा, भाटिया इत्यादि होते हैं। कालान्तर में मारवाडी लोग भी यामी प्रबन्ध अभिकर्ता बन गए।

१८५० से अब तक भारत में जितने बड़े-बड़े उद्योग (सूती वस्त्र, जूट, चाय, कोयला, लोहा-इस्पात, चीनी, सीमेन्ट) स्थापित हुए हैं उनके प्रवर्तन, संचालन, वित्त-पोषण और प्रबन्ध इत्यादि का सारा श्रेय इन्हीं प्रबन्ध विशेषज्ञों को है। आज विविध प्रतिबन्धों के उपरान्त भी ये देश की लाभदायक सेवा कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

१९५६ में कम्पनी कानून के लागू होने से पूर्व देश में ३,९४४ प्रबन्ध अभिकर्ता थे। ये २९,६२५ कम्पनियों में से ५,०५५ कम्पनियों का प्रबन्ध करते थे अर्थात् प्रत्येक ६ कम्पनियों में से एक कम्पनी इनके प्रबन्ध के अन्तर्गत थी। प्रबन्ध अभिकर्ता लगभग ४८% प्राप्त पूँजी के लिए उत्तरदायी थे। ३९४४ प्रबन्ध अभिकर्ताओं में से २५२२ साम्प्रदायी सहायों थी, १२३८ निजी कम्पनियों और १८४ सार्वजनिक कम्पनियों। इनमें से १७ ऐसे अभिकर्ता थे जिनके नीचे १० अथवा अधिक कम्पनियाँ थीं। पश्चिमी बंगाल में १६०१, बम्बई में ८३५, मद्रास में ४३७ और उत्तर प्रदेश में १९० प्रबन्ध अभिकर्ता थे। शेष अन्य राज्यों में फैले हुए थे।

१९५६ के कानून के लागू होने के उपरान्त यह पद कम आकर्षक रह गया और प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के भाग्य का सूर्य ढलने लगा। १९५६ और १९५९ के बीच तीन वर्षों की अवधि में देश में २९०४ नई कम्पनियाँ बनीं। इनमें से २१९४ कम्पनियों ने संचालक मण्डल द्वारा प्रबन्ध करने का निर्णय किया, ६७४ ने प्रबन्ध संचालक द्वारा और केवल ३६ कम्पनियों ने प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा प्रबन्ध करना उचित समझा। १६ अगस्त १९६० को केवल १३०८ कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथ में था। इस दिन उनकी सहाय केवल ९१९ थी। इनमें से ७७६ अर्थात् ८४% के हाथ में केवल एक-एक कम्पनी का प्रबन्ध था।

कार्य

प्रबन्ध अभिकर्ता एक बड़ा उद्देश्यीय संगठन है जिसके मुख्य कार्य तीन हैं : (क) कम्पनी प्रवर्तन और स्थापन, (ख) वित्तपोषण, तथा (ग) प्रबन्ध, यद्यपि (घ) क्रय-विक्रय और बीमा से सम्बन्धित इनकी सेवायें भी कम महत्व की नहीं हैं।

कम्पनी प्रवर्तन—जितनी देश में नई कम्पनियाँ स्थापित हुई हैं, लगभग ९०% इन्हीं के साहस और परिश्रम से बनीं हैं। इन्हे विविध उद्योगों का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। ये लोग उद्योग के स्थापन की योजना बनाते हैं, इन्जीनियरों, लेखा विशेषज्ञों, व वकीलों से परामर्श लेते हैं, उद्योग का पूँजी सम्बन्धी ढाँचा प्रस्तुत करते हैं, अधिकार पत्र, अग्नियम और उद्देश्य-पत्र लिखाते हैं और सारी कानूनी कार्यवाही करते हैं। पारंपारिक देशों की भाँति भारत में विशेषज्ञ प्रवर्तकों का सर्वथा अभाव है।

अतएव प्रबन्ध अभिकर्ता ही इस काम को करते हैं। मूती वस्त्र, लोहा-इस्पात, लूट, सीमेन्ट, कोयला, बिजली इत्यादि भारत के उद्योगों के स्थापित करने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। यही नहीं हाल के वर्षों में इन्जीनियरी, रसायनिक, मोटर, मशीन निर्माण और अल्पम्यूनियम इत्यादि नए उद्योग भी इन्हीं के साहस और परिश्रम से स्थापित हुए हैं।

विस्तारोपण—प्रबन्ध अभिकर्ता प्रारम्भिक स्थायी पूँजी, कार्यशील पूँजी और वृद्धि-विस्तार व आधुनिकीकरण सम्बन्धी दीर्घकालीन पूँजी उद्योग के लिए जुटाते हैं। वे कम्पनी के अनेक अंश व ऋण-पत्र स्वयं ले लेते हैं अथवा अपने मित्रों और व्यवसाय सहयोगियों को लेने का आग्रह करते हैं। आवश्यकता पडने पर ये कम्पनियों को स्वयं ऋण देते हैं अथवा बैंकों से ढिलाते हैं। जनता अथवा कर्मचारियों से हथपा जमा कराने के लिये भी यही उत्तरदायी हैं। ये प्रारम्भ से अब तक और जीवन भर उद्योग की सभी प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अनेक उद्योगों को इन्होंने संकटकाल में आर्थिक सहायता देकर डूबने से बचाया है।

प्रबन्ध—प्रबन्ध अभिकर्ता वस्तुतः प्रबन्ध विशेषज्ञ होते हैं। अपने लम्बे और विविध अनुभव के कारण ये प्रबन्ध कार्य में बड़े चतुर और सुलझे हुए होते हैं। आधुनिक व्यवसाय की अनेक गुलियों को सुलझाना और कानूनी जटिलताओं को सुविधा में परिवर्तन करना इनके बापों हाथ का खेल है। एक प्रबन्ध अभिकर्ता अनेक कम्पनियों का प्रबन्ध करने में समर्थ है।

विविध सेवाएँ—प्रबन्ध अभिकर्ता उद्योग द्वारा बनाए माल की बिक्री, मशीनों व कच्चे माल के ऋण तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाओं में भी सहायता करते हैं। आवश्यकतानुसार ये आयात-निर्यात कार्य भी कम्पनी के लिये करते हैं।

दोष

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की औद्योगिक सेवाएँ अत्यन्त बहुमूल्य हैं, किन्तु इन्होंने अपने औद्योगिक एकाधिकार का दुरुपयोग भी किया है। प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ से द्वितीय युद्ध के अन्त तक इनके अनेक दोषों की ओर संकेत किया गया। इनके मुख्य दोष निम्नांकित हैं : (क) अधिक पारिश्रमिक—पारिश्रमिक लेने के इनके अनेक ढंग रहे हैं जिनके द्वारा वे उद्योग को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बनाने लगे। कार्यालय का भत्ता, लाभ का एक भाग, मासिक वेतन और क्रय-विक्रय कमीशन इत्यादि इस पारिश्रमिक के विविध ढंग अपनाए गये। १९५६ के कानून के अन्तर्गत उनका पारिश्रमिक वार्षिक लाभ के प्रतिशत के रूप में सीमित कर दिया गया है। (ख) वंश परम्परा द्वारा उद्योग का एकाधिकार, (ग) अंशधारियों और संचालकों पर आधिपत्य, (घ) कम्पनी के धन का दुरुपयोग, (ङ) कम्पनी के स्थान पर निजी हित सर्वोपरि रखना, (च) अन्तर्कम्पनी विनियोग, (छ) मित्रों व सम्बन्धियों को ऋण देना, (ज) कम्पनी के व्यवसाय के साथ प्रतियोगिता करना, (झ) बिना कम्पनी की अनुमति के उसके प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों को दूसरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हस्तान्तरित करना इत्यादि इसके अन्य महत्वपूर्ण दोष हैं।

सुधार

प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के दोष सर्वप्रथम अन्तर्मुद्र काल में लोगों पर प्रगट हुए और उन्हें दूर करने की मांग की जाने लगी। अतएव १९३६ के भारतीय कम्पनी कानून द्वारा उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध और नियन्त्रण लगा दिये गए। इनमें से मुख्य निम्नांकित थे : (क) प्रबन्ध अभिकर्ता का अवधिकाल २० वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया, (ख) दोष प्रमाणित होने पर अशुधारियों को उसे निकाल देने का अधिकार दे दिया गया, (ग) पद (Office) अथवा पारिश्रमिक का दूसरे को सौंपना अथवा हस्तांतरण निषेध घोषित कर दिया गया; (घ) पारिश्रमिक का मुख्य ढंग वार्षिक लाभ का प्रतिशत मान लिया गया, (ङ) केवल उन्हें एक तिहाई संचालकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, (च) कम्पनी द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता अथवा उसके साथियों को ऋण देना अथवा ऋण की गारंटी देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये, (छ) एक कम्पनी से अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत अन्य कम्पनियों को प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा ऋण देना अथवा ठहरा दिया गया, (ज) उन्हें कम्पनी के व्यवसाय में प्रतियोगिता करने का निषेध कर दिया गया।

द्वितीय युद्ध के अभिवृद्धि काल में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने इन प्रतिबन्धों और नियन्त्रणों का उल्लंघन करके अपने अधिकारों का और भी दुरुपयोग किया। अधिक पारिश्रमिक लेने के गुप्त ढङ्ग निकाल लिए। इनके विरुद्ध इतनी शिकायतें आने लगी कि सरकार को समय-समय पर लगभग प्रतिवर्ष कानून में कुछ न कुछ संशोधन करने पड़े और १९५१ में एक अध्यादेश जारी करके इन की शक्तियों, अधिकारों और नियुक्ति पर नए प्रतिबन्ध लगाने पड़े। स्थिति में विशेष सुधार न होते देख कर १९५६ का कानून बनाया गया जिसके अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर भारी प्रतिबन्ध और नियन्त्रण लगा दिए। इनमें से मुख्य निम्नांकित हैं : (क) मूल कानून में इनका अवधिकाल १० से १५ वर्ष तक सीमित कर दिया था, किन्तु १९५६ के एक संशोधन द्वारा इसे ५ से १० वर्ष ही सीमित कर दिया गया है, (ख) प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने का समय निश्चित कर दिया गया है, (ग) नियुक्ति अथवा पुननियुक्ति कम्पनी के अंशधारियों और केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले कर ही संभव है, केन्द्रीय सरकार उन्हीं लोगों की दुवारा नियुक्ति की आज्ञा देगी जिन्हें वह भले आदमी समझती है; (घ) कोई प्रबन्ध अभिकर्ता अब १० से अधिक कम्पनियों का एक साथ प्रबन्ध नहीं कर सकता, (ङ) पद का हस्तांतरण करने के लिए कम्पनी और केन्द्रीय सरकार दोनों की अनुमति आवश्यक है; (च) उन्हें निकाले जाने पर कोई हानि पूर्ति नहीं दी जाती, (छ) उनका पारिश्रमिक अब केवल लाभ का १०% से अधिक नहीं हो सकता तथा यह ४% से १०% तक घटता बढ़ता रहेगा, (ज) प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के लिये देश में क्रय-विक्रय नहीं कर सकते, (झ) दो से अधिक संचालकों की नियुक्ति अब ये नहीं कर सकते; (ञ) अब कोई प्रबन्ध अभिकर्ता वंशपरम्परा के अनुसार

नियुक्त नहीं किया जा सकता। उनके पदत्याग, ऋण लेने अथवा देने, शक्तियों व अधिकारों तथा उनके साधियों पर भी कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए गये हैं। सरकार ने किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय से इस व्यवस्था का सर्वथा अन्त करने का भी अधिकार अपने हाथ में ले लिया है।

सरकारी नीति

प्रबन्ध अभिकर्ताओं के गुण-दोषों पर विचार करके भारत सरकार ने इनका दाने, शनैः अन्त करने की नीति अपनाई है। बैंक और बीमा के क्षेत्र से इस व्यवस्था का अन्त कर दिया गया है। सरकारी कम्पनियों का प्रबन्ध भी प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा नहीं हो सकता। किसी कम्पनी के प्रबन्ध के लिये अब प्रबन्ध अभिकर्ता के साथ-साथ कोई प्रबन्धकर्ता (Manager), सचिव व कोषाध्यक्ष, अथवा प्रबन्ध संचालक नहीं नियुक्त किया जा सकता। अगस्त १९६० से इस पद्धति का अन्त करने की अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि सरकार इसे अभी उपयोगी समझती है।

भविष्य

युद्धोत्तर काल में प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के प्रति भारी विरोध भाव उठ खड़ा हुआ। यहाँ तक कि १९५५ में जब कम्पनी बिल पर संसद में विवाद हो रहा था तो इसका सर्वथा अन्त करने के तर्क उपस्थित किए गए। अन्त में अगस्त १९६० तक इस पर अन्तिम निर्णय स्थगित करने की बात पर समझौता हुआ। अप्रैल १९५६, जब कि नया बानून लागू हुआ, और अगस्त १९६० के बीच इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श होता रहा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय फलित आर्थिक गवेषणा परिषद ने एक खोज की और बताया कि देश की प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति की अभी बड़ी आवश्यकता है। परिषद ने बताया कि यह पद्धति निजी औद्योगिक क्षेत्र की ७०% कम्पनियों पर अभी आधिपत्य रखती है तथा साहस पूँजी संचित करने में इसका बड़ा हाथ है। संभवतः इन्हीं सुझावों के कारण १५ अगस्त १९६० को भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की और इसे कुछ समय के लिये अपना सुधार करने का और भी अवसर दिया है। साथ ही १९६० के कम्पनी कानून में किए गए संशोधनों में इस पर और भी कड़ाई की निगाह रखने की नीति अपनाई गई है। इस भाँति प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति यद्यपि देश के लिये भी आवश्यक एवं लाभदायक है, तो भी इसका भविष्य अभी सन्देह में पड़ा हुआ है। यदि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता अपना रंग-ढङ्ग बदल लेते हैं तो इनकी सेवाओं का देश उपयोग करता रहेगा और यदि वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं तो एक दिन सरकार को विवश होकर उन्हें जयहिन्द कह कर विदा कर देना ही पड़ेगा। यह तो सभी जानते हैं कि देश में इस व्यवस्था का स्थान ग्रहण करने के लिये सचिव एवं कोषाध्यक्ष की एक नई व्यवस्था खड़ी की जा चुकी है और उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

“पूँजी आधुनिक युग में उत्पादन का प्रमुख साधन है, वस्तुतः यह आधुनिक उद्योग का जीवन-रस है।”

१३—औद्योगिक पूँजी

रूप-रेखा

१. पूँजी का महत्व
२. पूँजी के प्रकार
 - (क) स्थायी और अस्थायी पूँजी
 - (ख) दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूँजी
३. पूँजी जुटाने वाली संस्थाएँ
 - (क) परम्परागत संस्थाएँ
 - (ख) नई संस्थाएँ
४. दीर्घकालीन पूँजी की कठिनाई

पूँजी का महत्व

इस पूँजीवादी युग में पूँजी उत्पादन का प्रमुख साधन है। आधुनिक उद्योग के लिए पूँजी प्राण है। कोई उद्योग जितनी ही अधिक आधुनिक ढंग का होगा, उसे उतनी ही अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होगी, यहाँ तक कि रेल उद्योग में पूँजी की मात्रा वार्षिक उत्पादन से पाँच से दस गुनी तक अधिक होनी है। निर्माण उद्योगों के लिए उतनी अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं है जितनी रेलों के लिए, तो भी किसी निर्माण उद्योग की उत्पादन क्रिया जितनी ही अधिक जटिल होगी उसमें उतनी ही अधिक पूँजी लगी होगी। सांख्यिक उद्योग में पूँजी का परिमाण वार्षिक उत्पादन का १२७%, काँच उद्योग में १२०%, कागज उद्योग में १११%, तथा सिमेंट में १०४% है।

पूँजी के प्रकार

वृद्धा, दो, प्रकार की, पूँजी, की, क्रिमी, उद्योग, को, आवश्यकता, होती, है, २. स्थायी, (अथवा अचल) और अस्थायी (अथवा चल)। अस्थायी पूँजी को कार्यशील पूँजी भी

कहते हैं। स्थायी पूँजी स्थायी एवं आवश्यक सम्पत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीनें, यंत्र-उपकरण, फर्नीचर, सड़के, पुल, गाड़ियो तथा प्रयोगशाला-उपकरण इत्यादि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। अस्थायी पूँजी दैनिक व्यव और प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय के लिए होती है। कच्चे माल, भएडार, निर्मित माल, खुले मोजार इत्यादि में लगी पूँजी अथवा वेतन, मजदूरी, मरम्मत इत्यादि के लिए संचित धन अस्थायी पूँजी समझी जाती है। आधुनिक उद्योगों में स्थायी पूँजी की मात्रा अधिक होती है। भिन्न-भिन्न उद्योगों में व भिन्न-भिन्न देशों में स्थायी और अस्थायी पूँजी का अनुपात भिन्न-भिन्न होता है, किन्तु १ : २ का अनुपात सामान्य समझा जाता है।

पूँजी दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन भी हो सकती है। इस सम्बन्ध में सब देशों व सब उद्योगों में एक समान नीति नहीं बरती जाती। तो भी अल्पकालीन पूँजी एक वर्ष तक की अवधि के लिए, मध्यकालीन एक से पाँच वर्ष (कभी कभी ७ वर्ष) तक और दीर्घकालीन ५ से अधिक वर्ष की अवधि के लिए होती है।

आधुनिक उद्योगों में अश्र अथवा ऋण-पत्र निर्गमित करके, ऋण लेकर अथवा निक्षेप (Deposit) प्राप्त कर पूँजी जुटाई जाती है। पूँजी का एक बड़ा भाग अंशों के रूप में संचित किया जाता है। अंश दो प्रकार के होते हैं : साधारण और पूर्वाधिकारी। हमारे देश में साधारण अंश कम मूल्य के होते हैं। अतएव इन्हीं का अधिक प्रचार है।

पूँजी जुटाने वाली संस्थाएँ

(क) परम्परा से चली आने वाली संस्थाएँ—भौद्योगिक क्षेत्र में पूँजी लगाने वाली अनेक संस्थाएँ हैं। इनमें से प्राचीनकाल से चली आने वाली संस्थाएँ : (१) जनता, (२) प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति, (३) वित्तीय संस्थाएँ (बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा विनियोग निगम), (४) केन्द्रीय व राज्यों की सरकारें, (५) विदेशी पूँजीपति, तथा (६) स्वयं भौद्योगिक संस्थाएँ इत्यादि हैं।

जनता—उद्योग-धन्धों को अंश पूँजी का एक बड़ा भाग जनता से मिलता है। बड़े उद्योगों के प्रादि काल में भारतवासियों में उद्योगों में पूँजी लगाने की प्रवृत्ति कम थी। अब ऐसा नहीं है। तो भी गत वर्षों में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के भय से तथा जमींदारी के उन्मूलन के कारण व्यक्तिगत पूँजी हतोत्साहित हो गई है।

प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति—प्रबन्ध अभिकर्ता देश में उद्योगों के प्रमुख प्रवर्तक, प्रबन्धकर्ता और वित्तीय संस्था हैं। ये उद्योगों को न केवल प्रारम्भिक पूँजी देते हैं, बल्कि ऋण के रूप में अतिरिक्त पूँजी भी देते हैं। प्रथम युद्ध के उपरान्त इसमें कुछ ऐसे दोष आ गए कि १९३६ में इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए गए। १९५६ के कम्पनी कानून ने इन पर और भी कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए हैं और इनका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया है। तो भी भौद्योगिक पूँजी में इनका लगभग ५०% योग है और इनका महत्व कम नहीं हुआ।

वित्तीय संस्थायें—भारतीय वारिण्यिक बैंक केवल अल्पकालीन पूँजी देते हैं। कभी-कभी मध्यकालीन पूँजी भी प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन पूँजी अधिक मात्रा में देने में वे असमर्थ हैं, क्योंकि उनका संचित धन बहुधा अल्पकालीन होता है। बीमा कम्पनियों का योग भी पूँजी जुटाने में बहुत कम है। देश में पाश्चात्य देशों की भाँति विनियोग न्यास संस्थाओं का विकास नहीं हुआ। इनकी संख्या देश में बहुत कम है।

केन्द्रीय व राज्यों की सरकारें—यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त से सरकारें उद्योगों को भार्यिक सहायता देने लगी थी, किन्तु यह सहायता बहुत कम थी। द्वितीय युद्ध के उपरान्त के वर्षों में सरकारें विविध प्रकार की भार्यिक सहायता करने लगी हैं। वे ऋण, ऋण की प्रत्याभूति अथवा अनुदान के रूप में उद्योगों को धन देकर पूँजी जुटाने में सहायक होती हैं। वार्यिक आय व्यय में विकास व्यय के नाम से सहायतार्थ दिये जाने वाले धन को दिखाया जाता है।

विदेशी पूँजी—उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के औद्योगीकरण का श्रेय मुख्यतः विदेशी पूँजी को रहा। अब भी विदेशी पूँजी की सहायता से ही औद्योगीकरण की गति बढ़ाई जा रही है।

निजी धन—उद्योगपति स्वयं निजी धन को भी नए उद्योगों के स्थापित करने अथवा स्थापित उद्योगों के प्रसार में लगाते हैं। उद्योगों के लाम का लगभग ४०% प्रतिवर्ष इस भाँति पूँजी के रूप में लगा दिया जाता है।

(ल) नई वित्तीय संस्थायें—युद्धोत्तर काल में देश में बढ़ती हुई औद्योगिक पूँजी की माँग पूर्ति के लिए कई नई संस्थायें खुल गई हैं जो विविध प्रकार के पूँजी संचय करती हैं। इनमें से मुख्य संस्थायें : (१) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (२) राज्य वित्त निगम, (३) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, (४) औद्योगिक साज एवं विनियोग निगम (५) पुनर्वित्त निगम, तथा (६) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इत्यादि हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम—इसकी स्थापना जुलाई १९४८ में हुई थी, इसकी अधिकृत पूँजी १० करोड़ और प्राप्त पूँजी ५ करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देना है। ये ऋण केवल निजी क्षेत्र में काम करने वाली सार्वजनिक कम्पनियों अथवा सहकारी संस्थाओं को दिये जाते हैं। निजी क्षेत्र की व्यक्तिगत कम्पनियाँ, लघु उद्योग अथवा सहकारी उद्योग इसकी परिधि से बाहर हैं। यह निगम ऋण देती है, ऋण की गारन्टी देती है, ऋण पत्र लेती है तथा अशो व ऋण-पत्रों का अभिगोपन भी करती है। आस्थपित भुगतान की गारन्टी करके भी निगम पूँजीगत माल आयात करने में सहायता करती है।

राज्य वित्त निगम—राज्य वित्त निगम कानून १९५१ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक एक वित्त निगम स्थापित करने का निर्देश किया गया था। अब लगभग सभी राज्यों में ऐसी वित्त निगम बन गई हैं। इनकी सेवा उस क्षेत्र को उपलब्ध है

जो कि भारतीय वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इनका उद्देश्य मुख्यतः छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की आर्थिक सहायता करना है। व्यक्तिगत कम्पनियों को भी इनकी सेवा उपलब्ध है। इनके ऋण की उच्चतम सीमा वही है जो भारतीय निगम की निम्नतम सीमा (अर्थात् १० लाख रु०) है।

इन पर राज्य की सरकारों का स्वामित्व है। इन्हें भी ऋण देने, ऋण की गारन्टी देने, ऋण-पत्र लेने, तथा अभिगोपन का अधिकार प्राप्त है। इनकी अधिकृत पूँजी २६ करोड़ रु० और प्राप्त पूँजी १३.३० करोड़ रु० है। प्रत्येक राज्य की सरकार इनकी पूँजी की सीमा निश्चित करती है। यह सीमा ५० लाख रु० और ५ करोड़ रु० के बीच में होनी चाहिये।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम—यह अक्टूबर १९५४ में बनी थी। यह एक निजी कम्पनी है जो भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत बनी है। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ और प्राप्त पूँजी १० लाख रुपये हैं जो पूर्णतः भारत सरकार ने दी है। इसे भारत सरकार अनुदान अथवा ऋण के रूप में आवश्यक धन देती है। अथवा ऋण पत्र निर्गमित करके भी यह धन जुटा सकती है।

इसका उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना है, मुख्यतः यह सरकारी क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करती है। किसी उद्योग के विकास के लिये आवश्यक धन भी देती है। पूँजीगत पदार्थ एवं मशीन-निर्माण की ओर यह विशेष ध्यान देती है।

औद्योगिक साज एवं विनियोग निगम—यह भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत जनवरी १९५५ में बनी थी। इसकी अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रु० और प्राप्त पूँजी ५ करोड़ रु० है। यह नये उद्योगों के स्थापित करने और स्थापित उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देती है। यह अंश पूँजी लेकर, दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण देकर, अंशों का अभिगोपन करके तथा ऋण की गारन्टी देकर उद्योगों की सहायता करती है। आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध सम्बन्धी, तकनीकी तथा प्रशासनात्मक परामर्श भी प्रदान करती है।

पुनर्वित्त निगम—यह जून १९५८ में भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत बनी थी। इसकी अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रु० एवं प्राप्त पूँजी २.५ करोड़ रु० है। इसका मुख्य ध्येय मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मध्यकालीन ऋण तीन से ७ वर्ष तक की अवधि के लिए देना है। निगम उद्योगपतियों को सीधे ऋण नहीं देती, वरन् सदस्य अनुसूचित बैंकों को उनके साधन बढ़ाने के लिये ऋण देती है और ये बैंक उद्योगों को ऋण देते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम—इसकी स्थापना फरवरी १९५५ में हुई थी। यह लघु उद्योगों के विकास के लिये हर प्रकार के यत्न करती है। यह लघु उद्योगों के

लिये किराया-रूप (hire-purchase) सुविधा द्वारा मशीन एवं उपकरण प्राप्त करने में सहायता करती है।

इन नई वित्तीय संस्थाओं के बनने से देश में पूँजी-निर्माण की गति बहुत कुछ बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने की सम्भावना है। तो भी देश में जिस तीव्र गति से औद्योगीकरण की विविध योजनाएँ उठाई गई हैं, उनकी बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिये पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं होती। यहूदा यह देखा गया है कि बड़े और अच्छी साख वाले उद्योगों को आवश्यकतानुसार शीघ्र पूँजी प्राप्त हो जाती है किन्तु छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पूँजी शीघ्र उपलब्ध नहीं हो पाती। उनके लिये अभिगोपन सुविधायें भी सहज सुलभ नहीं। अतएव इस बात की आवश्यकता है कि नई वित्त संस्थाओं के साधनों का विस्तार होना चाहिये और विशेषतः उनकी क्रिया-विधि सम्वन्धी रूकावटों को कम से कम करके उनको अधिक उपयोगी बनाना चाहिए। साथ ही साथ और इसी प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ स्थापित होनी चाहिये। मुख्य कठिनाई दीर्घकालीन पूँजी के प्राप्त करने में उपस्थित होती है। यह कठिनाई नए उद्योगों की प्रारम्भिक पूँजी जुटाने में विशेष होती है। अनेक उद्योग प्रदान पाश्चात्य देशों में औद्योगिक बैंक अथवा अन्य ऐसी विशेष संस्थाएँ हैं जो नए उद्योगों की पूँजी सम्बन्धी कठिनाई को दूर करती हैं। कई देशों में व्याणिज्य बैंक भी औद्योगिक विकास में विविध सहायता देते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जापान अथवा जर्मनी की भाँति भारतीय बैंक भी औद्योगिक विकास में सहायता दें। भारत में औद्योगिक बैंक स्थापित करने के प्रयत्न कई बार विफल हो चुके हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों में वाणिज्य बैंकों को अपना रवेसा बदलने की बात पर विशेष जोर दिया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि भारतीय वाणिज्य बैंक बिना किसी जोखिम के मध्यकालीन ऋण दे सकते हैं, क्योंकि बहुधा वे व्यवहार में अल्पकालीन ऋणों की व्यवधि बढ़ाते रहते हैं। केवल उनको कानूनी रूप देने भर की बात है। विदेशों की भाँति किराया-रूप व्यवस्था द्वारा भी बैंक उद्योगों को सहायता पहुँचा सकते हैं।

“सामाजिक सुरक्षा कोई भार नहीं है, वरन् बुद्धिमत्तापूर्ण विनियोग है, जो जो अन्ततोगत्वा उत्तम लाभाश देती है।”

—बी० धी० गिरी

१४—सामाजिक सुरक्षा

रूप-रेखा

१. अर्थ
२. उद्देश्य
३. प्राचीन रूप
४. आधुनिक स्वरूप
५. पाश्चात्य देशों में सामाजिक सुरक्षा
६. भारत में आवश्यकता
७. भारत में सामाजिक सुरक्षा के यत्न
८. भारत में वर्तमान व्यवस्था
९. आलोचना एवं सुभाव ।

अर्थ

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसे समाज किसी उपयुक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के निमित्त जीवन की ऐसी जोखिमों के विरुद्ध प्रदान करता है जिनसे वे सदैव भयभीत रहते हैं। ये जोखिमों आकस्मिक होती हैं और कम आय एवं न्यून साधनों वाले व्यक्ति बहुधा निजी साधनों एवं दूरदर्शिता से इनके विरुद्ध कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं कर सकते। ये जोखिमों, रोग, प्रमूठि, भ्रंग-भंग, अपाहिजपन, बेकारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि हैं। ये जोखिमों व्यक्ति के आय उपार्जन में बाधा उपस्थित करती हैं और उसके कार्यकौशल को कम करती हैं। अपने आधुनिकतम अर्थ में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सामाजिक सहायता और सामाजिक बोमा दोनों का समावेश होता है। सामाजिक सहायता वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ चन्दा नहीं देना पडना, सारा व्यय सरकार सहन करती है। इसके विपरीत सामाजिक बोमा

वह है जिसमें लाभ पाने वाले को मुक्त चन्दे के रूप में देना पड़ता है। सामाजिक सहायता पूर्णतः समाज का उत्तरदायित्व है, किन्तु सामाजिक बीमा सम्मिलित सहायता का एक ढंग है।

उद्देश्य

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परावनम्बन के दो अवसर अवश्य आते हैं : एक बाल्यकाल और दूसरा वृद्धावस्था। युवावस्था में भी मनुष्य को जीवन की प्राकृतिक जोखिमों के अवसर पर परावनम्बी होना पड़ना है। बाल्यावस्था का प्रथम प्रकृति करती है, किन्तु अन्य अवसरों पर प्रकृति उतनी उदारता नहीं दिखाती। इन्हें अनुदार अवसरों पर सामाजिक सुरक्षा का वरदान काम देता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेकारी, बीमारी, अग-भग इत्यादि सड़कों को पार करना है। रोग के अवसर पर उसके परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध करना तथा सभी अवसरों पर कार्यकर्ता के जीवन स्तर की स्थिरता बनाये रखना एवं उसे न्यूनतम मुम्ब-मुविधाएँ प्रदान करना इसके इलाघनीय क्षेत्र हैं।

प्राचीन रूप

समाज के दुर्बल गंगों के प्रति सदैव से उदारता का सिद्धान्त अपनाया जाता रहा है। संकट काल में बहुधा लोग मितव्ययिता, वचन एवं ऋण द्वारा काम चलाते रहे हैं, किन्तु इनकी सेवा अत्यन्त सीमित होती है। भारत में जाति व्यवस्था एवं समुदाय परिवार के द्वारा संकट काल को पार करना सहज सम्भव था। एक सदस्य के बीमार अथवा बेकार होने पर परिवार के अन्य सदस्यों पर उसके भरण-पोषण का पूरा भार स्वतः ही आ जाता है। जाति-प्राथा के अन्तर्गत भी अनेक सामाजिक सहायता सम्यायें जाति-विरादरी की ओर से खोली जाती हैं। यूरोप के देशों में गिरजावरों और पुजारीयों से अनेक दानगील संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाता रहा। एधियाई देशों में मन्दिर, मसजिद, अमायालय, आश्रम इत्यादि खोले जाने का चलन है। यह व्यवस्था न तो आधुनिक जीवन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त ही है और न आज के दातावरण में उचित ही समझी जाती है। दान पर निर्भरता आज बल मान-हानि अथवा आत्म-गौरव के विच्छेद समझी जाती है।

आधुनिक स्वरूप

आधुनिक युग में राजनीतिक जाग्रति और लोकतन्त्रीय संस्थाओं के विकास के साथ-साथ लोगों में अपने नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति स्वामाजिक चेतना उत्पन्न हुई। लोगों में यह धारणा बढ़नी लगी गई कि राज्य ही वस्तुतः समाज के नैतिक एवं आर्थिक अधिकारों का संरक्षक है। अन्तर्गत धर्म की शोषण से बचना, निस्महाय एवं निर्धनों की रक्षा करना और आर्थिक गगन की मुक्त रखना राज्य का एक न्यायोचित कर्तव्य है। अतएव आधुनिक युग में प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन और उसके कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामाजिक 'सेवाएँ' तथा मुम्ब-मुविधाएँ प्रदान करना राज्य का एक अनिवार्य धर्म माना जाने लगा है।

राज्य के इस उत्तरदायित्व को निभाने के निमित्त दो महत्वपूर्ण संस्थानों का प्राविर्भाव हुआ है — सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा। इन दोनों ने मिल कर एक व्यापक, संतुलित तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा की नींव डाल दी है। सामाजिक सहायता के मुख्य रूप विविध प्रकार की पेशों हैं जो बच्चों, अपाहिणों, वृद्धों, माताओं व अन्य आश्रितों के भरण पोषण, बेकारी सम्बन्धी सहायता, अपाहिणों व विस्थापितों के पुनःस्थापन के लिये दी जाती हैं। सामाजिक बीमा के अन्तर्गत बीमारी, प्रसूति, अंग-भंग, वृद्धावस्था, बेकारी इत्यादि के समय के लिये व्यवस्था की जाती है। कुछ पाश्चात्य देशों में जन्म से मृत्यु तक की सभी जोखिमों सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आती हैं।

पाश्चात्य देशों में सामाजिक सुरक्षा

पाश्चात्य देशों में १६०१ का ब्रिटेन का गरीब रक्षा कानून (Poor Relief Act) सामाजिक सुरक्षा का प्रथम आधुनिक रूप माना जा सकता है। जर्मनी में वस्तुतः सामाजिक सुरक्षा के सिद्धान्त का प्राविर्भाव हुआ जहाँ १८८१ में विलियम प्रथम ने सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अनिवार्य सामाजिक बीमा की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सम्बन्ध में १८८३ और १८८६ के बीच कई कानून भी बने। तदुपरान्त ब्रिटेन, कनाडा, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में भी इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घन (I L O) ने १९१६ में प्रसूति सहाय्य, १९२१, १९२५ व १९३४ में कर्मकार प्रतिकर, १९२७ व १९३६ में रोग बीमा, १९३३ व १९३४ में अंगभंग और वृद्धावस्था तथा १९३४ में बेकारी बीमा से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकार किए। वस्तुतः सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के १९३५ के सामाजिक सुरक्षा कानून में किया गया जिनके अन्तर्गत बेकारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था के विरुद्ध बीमा सम्बन्धी योजनाओं के प्रबन्ध के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापित किया गया। १९३८ में न्यूजीलैंड की प्राय सुरक्षा योजना में, १९४१ में अटलांटिक घोषणा में तथा १९४२ में ब्रिटेन की बोवरिज रिपोर्ट में इस शब्द का प्रयोग किया गया। पुढोत्तर काल में तो यह शब्द सभी देशों में लोकप्रिय हो गया और अब इसका क्षेत्र विश्वव्यापी है।

भारत में आवश्यकता

भारत की अधिकांश जनता कंगाल है और श्रमिक वर्ग की दशा अत्यन्त शोचनीय है। ऐसे साधनहीन श्रमिक वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। हमारे श्रमिक वर्ग की प्रशिक्षण, प्रज्ञान, रुढ़िवाद एवं अमितव्ययता इसे और भी अनिवार्य बना देती है। देश के औद्योगीकरण की अनेक योजनाओं की सफलता औद्योगिक श्रमिकों के कार्यक्षमता पर निर्भर है और श्रमिक वर्ग का कार्यक्षमता सामाजिक सुरक्षा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने भी बेकारी, वृद्धावस्था, रोग तथा अंगभंग के अवसरों के लिए श्रमिक वर्ग के लिए सरकारी सहायता को मान्यता प्रदान की है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के यत्न

श्रमिक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की ओर प्रथम सीमित प्रयत्न भारत में कर्म-कार प्रतिकर कानून १९२३ में बना कर किया गया जिसके अनुसार कर्मकार का अंगभंग हो जाने पर नियोजक (employer) पर उसे प्रतिहर देने का उत्तरदायित्व डाला गया। १९२७ में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के सुझावों पर विचार किया, किन्तु इन्हे कार्यान्वित न किया जा सका। १९२६ और १९४८ के बीच कई राज्यों ने प्रमूक्ति हितकारी कानून बनाये जिनमें से प्रथम कानून १९२६ में बम्बई में बना। द्वितीय युद्ध काल में इस ओर भारत सरकार की विशेष रुचि जाग्रत हुई और १९४०, १९४१ तथा १९४२ में किये गये श्रम-मंत्रियों के सम्मेलनों में इस प्रश्न पर सुविस्तार विचार किया गया तथा एक योजना भी बनाई गई। इस योजना पर विचार करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। उसने स्वास्थ्य बीमा की १९४४ में एक योजना बनाई जिसे कई वर्षों के विचार-विनिमय के उपरान्त कर्मचारी राजकीय बीमा कानून १९४८ के रूप में देश में लागू किया गया। वस्तुतः यही से भारत में सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक इतिहास प्रारम्भ होता है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा बोनस योजना कानून १९४८, कर्मचारी भविष्य निधि कानून १९५२ तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून १९५४ इत्यादि भी इसी ओर किए गए प्रयत्न हैं। १९५७ में भारत सरकार ने मैनन समिति बिठाई जिसने दिसम्बर १९५८ में देश की सुरक्षा व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार के अनेक सुझाव दिए। अतः भारत सरकार अन्य अग्रगामी देशों की भांति ही सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना बनाने का विचार कर रही है।

भारत की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

(क) कर्मकार प्रतिकर कानून—यह कानून १९२३ में बना था। तबसे उसमें १९३३ और १९५६ में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके हैं। यह कानून कर्मकार के काम के समय हताहत हो जाने, उपजीविका से उत्पन्न होने वाली बीमारियों प्रयत्न ऐसे हताहत होने व ऐसी बीमारियों से मृत्यु होने के लिए प्रतिकर की व्यवस्था करता है। यह कानून उन सब कर्मकारों पर लागू होता है जो ४०० रु० प्रतिमास पारिश्रमिक पाते हैं।

(ख) कर्मचारी राजकीय बीमा कानून—यह कानून १९४८ में बना था। यह सभी वर्ष भर काम करने वाले ऐसे कारखानों पर लागू होता है जिनमें शक्ति का प्रयोग होता है तथा जहाँ २० अथवा अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसका लाभ उन सब श्रमिकों एवं लिपिक कर्मचारी वर्ग की मिलता है जिनका मासिक पारिश्रमिक ४०० रु० तक है। इस योजना का प्रशासन कर्मचारी राजकीय बीमा निगम करती है जिसके सभापति भारत सरकार के श्रम मंत्री हैं और जिसमें केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों, उद्योगपति, कर्मचारी, चिकित्सा विभाग तथा संसद इत्यादि के प्रति-

निधि हैं। निगम का काम चलाने के लिए एक कर्मचारी राजकीय बीमा निधि स्थापित की गई है जिसमें उद्योगरति, कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अनुदान से धन एकत्रित किया जाता है। बीमा किए गये कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों को पाँच प्रकार के लाभ प्राप्त हैं :—

(१) बीमारी लाभ—कार्यकर्ता को दैनिक मजदूरी के $\frac{2}{3}$ के बराबर डाक्टर के प्रमाण-पत्र के आधार पर वर्ष भर में अधिक से अधिक ५६ दिन तक हस्पताल दिया जाता है।

(२) चिकित्सा लाभ—बीमारी के दिनों में अस्पताल में अथवा घर पर मुफ्त डाक्टरों की सेवा उपलब्ध होती है।

(३) अंगभंग लाभ—काम के घट्टों में अस्थायी, स्थायी, आंशिक अथवा पूर्णतः अंगभंग होने अथवा रोग लगने के बदले दैनिक मजदूरी के $\frac{2}{3}$ के बराबर प्रति-कर दिया जाता है।

(४) आश्रित लाभ—कर्मचारी के कार्यकाल में हताहत होने से मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को निश्चित दर से प्रतिकर दिया जाता है।

(५) प्रसूति लाभ—प्रसूता को दस सप्ताह के लिए बीमारी की दर से नन्द धन देने की व्यवस्था है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि कानून १९५२—प्रारम्भ में यह ६ बड़े उद्योगों पर लागू किया गया था। अब ३३ और उद्योग इसके अन्तर्गत ले लिए गए हैं जिनमें बगीचा, खनिज, समाचार-पत्र, दियासलाई, मोटर परिवहन, डिस्कट बनाना इत्यादि मुख्य हैं। जो उद्योग कम से कम ३ वर्ष पुराने हैं और जिनमें कर्मचारियों की संख्या ५० अथवा अधिक है उन पर यह कानून लागू होता है। ५०० रु० मासिक पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को $6\frac{1}{2}\%$ चन्दा देना पड़ता है तथा उतना ही धन उद्योगपति देता है।

(घ) कोयला खान भविष्य निधि योजना—यह योजना आंध्र, असम, बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा ५० बंगाल की कोयले की खानों पर लागू होती है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को अपने पारिथमिक का $6\frac{1}{2}\%$ निधि में देना पड़ता है और उतना ही धन उद्योगपति देता है।

(ङ) प्रसूति लाभ—लगभग सभी राज्यों में प्रसूति साहाय्य सम्बन्धी कानून चालू हैं। कुछ राज्यों में ये कानून केवल नियन्त्रित उद्योगों पर लागू होते हैं तथा कुछ में सभी नियमित चलने वाले उद्योगों पर। खान प्रसूति लाभ कानून १९४१, कर्मचारी राजकीय बीमा कानून १९४८ तथा बगीचा उद्योग धम कानून १९५१, तीन केन्द्रीय कानून भी प्रसूति साहाय्य सम्बन्धी नियम लागू करते हैं। देश भर में प्रसूति रक्षा सम्बन्धी समानता लाने के विचार से एक केन्द्रीय कानून पर विचार किया जा रहा है।

आलोचना एवं सुभाब

देश में वर्तमान सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ अत्यन्त सीमित हैं। सारी जनसंख्या की तो वान ही कौन बहे केवल सार औद्योगिक धर्मिक वर्ग को भी ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ लाभ दिए जाते हैं। वे भी जीवन और जगत की कुछ ही जोखिमों तक सीमित हैं। केवल रोग, प्रमूति, अंगभंग, मृत्यु, वृद्धावस्था, बेकारी इत्यादि से आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। सहायता को अवधि बहुधा अल्पकाल होती है। उद्योगपति और धर्मिक दोनों ही पर इसका भार अधिक है। सुरक्षा योजनाओं का प्रवन्ध भी सन्तोषजनक नहीं है।

मैनन समिति ने भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए १९५८ में महत्वपूर्ण सुभाब दिए थे जिन पर विचार हो रहा है और उन सुभाबों के अनुसार देश के लिए एक सर्वाङ्गपूर्ण योजना बनाने के मत्त हो रहे हैं। समिति के विचार में देश की अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम पाश्चात्य देशों के स्तर पर देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कर सकें और न अभी वृषक वर्ग के लिए कोई योजना कार्यान्वित करने की स्थिति में देश है, तो भी समिति ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार के निम्नांकित सुभाब दिए हैं :—

(१) हमारा उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था के सुधार का होना चाहिए और विशेषतः हमें प्रशासन कार्य विधि को सरल करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

(२) सभी योजनाओं का प्रवन्ध एक ही सस्था के अधिकार में होना चाहिए।

(३) उद्योगपतियों के सभी प्रकार के अनुदान एक ही सुगतान में लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(४) कर्मचारी राजकीय बीमा के अन्तर्गत बीमारी की अवधि १३ सप्ताह से बढ़ा कर २६ या २७ सप्ताह कर देनी चाहिए और प्रमूति-साहाय्य की दर में वृद्धि होनी चाहिए।

(५) चिकित्सा स्तर ऊँचा उठाने की बड़ी सुंजाइस है। चिकित्सा सुविधाएँ कर्मचारियों के परिवार को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

(६) भविष्य निधियों को वैधानिक पेंशन योजनाओं में परिवर्तित कर देना चाहिए।

(७) बेकारी बीमा की एक स्थायी योजना बनाई जानी चाहिए।

(८) 'निम्नतम मजदूरी' तुरन्त लागू कर देनी चाहिए।

परिभाषा

उद्योगपतियो, सरकार अथवा अथ सस्याधो द्वारा जो कार्य कर्मकारो के वौद्धिक शारीरिक, नैतिक तथा प्राथमिक लाभ के लिए किये जाते हैं उन्हे अथम-कल्याण कहते हैं। ये कार्य सरकारी नियम व कानून की परिधि के बाहर होते हैं तथा उस समझौते की सीमा के बाहर किये जाते हैं जो कि अथमिक ने अपने स्वामी के साथ किया हो। चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएँ, पोषण (जलपान गृह समेत), विश्राम एवं मनोरजन सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, दिवस धाय घर, शिशु गृह, स्वच्छ मकान, बेतन युक्त छुट्टियाँ सामाजिक बीमा क्षीमारी व प्रसूति योजनायें, भविष्य निधि, अनुग्रह दान (Gratuity) तथा पेंशन इत्यादि अथम कल्याण के अन्तर्गत आती हैं।

अथम कल्याण कार्यों में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उद्योगपति उसे कानून, नियम अथवा समझौते द्वारा करने के लिये बाध्य नहीं होता, केवल वह उसे अपनी इच्छा से अथम की भलाई के लिये करता है, यद्यपि सरकारी विधानों और कल्याण कार्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। सरकारी विधान अथम कल्याण के एक निम्नतम स्तर के सूचक होते हैं किन्तु प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी उद्योगपति उससे कहीं ऊँचा स्तर ले जाते हैं। कभी कभी तो अच्ये उद्योगपतियो द्वारा निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिये ही कानून बनाये जाते हैं। इस भाँति कानून और अथम कल्याण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं विरोधी नहीं।

अथम कल्याण का महत्त्व एवं उद्देश्य

शिक्षा सुविधाएँ, खेल-कूद, मनोरजन इत्यादि अथम कल्याण कार्य कारखाने के भावनात्मक वातावरण में सुधार करके औद्योगिक क्षाति स्थापित करते हैं तथा उद्योगपति के प्रति सद्भाव जाग्रत करते हैं। दूसरे, अच्छे मकान, सहकारी समितियाँ, जलपान गृह रोग व प्रसूति सहायता, भविष्य निधि, अनुग्रह दान, पेंशन इत्यादि कार्य कर्मचारी में उद्योग के प्रति अथमत्व की भावना उत्पन्न करते हैं जिससे अथम अधिक स्थायी और कायकुशल हो जाता है। तीसरे, जलपान गृहों में उत्तम एवं पोषक पदार्थों की व्यवस्था के कारण अथम का स्वास्थ्य सुधार होता है। मनोरजन के साधनों से अनेक कुरोतियाँ दूर होती हैं। चिकित्सा एवं प्रसूति सहायता से कर्मचारी एवं उसके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है तथा प्रसूतिकाओं व बच्चों की मृत्यु संख्या कम होती है। शिक्षा सुविधाओं से कर्मचारियों की बुद्धि का विकास होता है और उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ती है। इस भाँति अथम कल्याण का मुख्य उद्देश्य अथमिक वर्ग के जीवन को स्वस्थ एवं सुखमय बनाना है। यह निर्विवाद है कि सभी कार्य क्षेत्रों में उच्चकोटि का कार्यक्षमता वही कर्मचारी दिला सकते हैं जिनका स्वास्थ्य उत्तम है तथा जो सभी कष्टों से मुक्त हैं और जो उपयुक्त शिक्षण पा चुके हैं जो अच्छे मकानों में रहते हैं एवं जिन्हें उपयुक्त भोजन और वस्त्र प्राप्त हैं।

वगीचा उद्योग धम वदून १९५१ के अन्तर्गत जाने वाले सभी कारखानों के लिये जलपान गृह, स्वच्छ स्थान, विधम गृह, धुलाई व्यवस्था, चिकित्सा सुविधायें और अन्य सभी प्रकार की सुख-सुविधायें दी जाती हैं। श्रमिक वर्ग की गरीबी पर तरस साकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस वर्ग के लिये मकान बनाने की एक योजना चालू की थी जिसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया गया है।

श्रम कल्याण एवं राज्य सरकारें—सन् १९३७-३९ की अवधि में राज्यों में लोकप्रिय मन्त्रित्व स्थापित होने पर राज्य-सरकारें श्रम कल्याण में हस्ति लेने लगी थी। इस कार्य को कालान्तर में भी जारी रखा गया। द्वितीय युद्ध काल में बम्बई और उत्तर प्रदेश सरकारों ने इस कार्य में सीधा हाथ डालना प्रारम्भ किया तथा श्रम कल्याण कार्य किए। वगल भी उनकी देखा-देखी श्रम कल्याण की ओर झुक गया। अब लगभग सभी राज्य सरकारें श्रम कल्याण केन्द्र चला रही हैं। इनका उद्देश्य कर्मचारियों के मनोरंजन, शिक्षा तथा उनकी व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

बम्बई राज्य में सन् १९३९ में आदर्श श्रम कल्याण केन्द्र खोले गए थे। इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़नी चली गई। सन् १९५३ में बम्बई सरकार ने कल्याण सम्बन्धी कार्यों के लिए एक अलग श्रम कल्याण बोर्ड स्थापित कर दिया तथा एक श्रम कल्याण निधि की भी रचना की।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् १९३७ में कानपुर के श्रमिकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के निमित्त एक श्रम विभाग खोला था तथा एक श्रम अधिकारी नियुक्त किया था। युद्ध काल में एक अलग श्रम कल्याण विभाग खोल दिया जो अब समाज कल्याण मन्त्री के अधिकार में चला गया है। इस विभाग का कार्य नए श्रम कल्याण केन्द्र खोलना और चालू केन्द्रों की देख-भाल करते रहना है। दिसम्बर १९५७ से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वृद्धावस्था पेशन योजना चालू कर दी है जिसके अन्तर्गत ७० वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों को पेंशन दी जाती है जिनकी आय का कोई साधन नहीं है और न जिनके पालन-पोषण के लिए कोई उनका सम्बन्धी ही है।

वगल सरकार १९४० तक निजी संस्थाओं को श्रम कल्याण के लिए आर्थिक सहायता देती रही, किन्तु १९४० से श्रम कल्याण केन्द्र खोलने प्रारम्भ कर दिए। अब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, मैसूर, राजस्थान राज्यों में भी अनेक श्रम कल्याण केन्द्र हैं।

स्थानीय संस्थाओं द्वारा—नगरपालिकाएँ तथा महानगरपालिकाएँ नगर के सभी निवासियों के कल्याण की ओर ध्यान देती हैं। उद्योग प्रधान नगरों में श्रम कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर इत्यादि उद्योग प्रधान नगरों की स्थानीय संस्थाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, मकान, मनोरंजन, खेल-कूद, शिशु कल्याण केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था की है।

उद्योगपतियों द्वारा धर्म कल्याण—गत वर्षों में धर्म कल्याण कार्य की ओर उद्योगपतियों ने विशेष रुचि एवं उत्साह दिखाया है। सूतीबस्त्र, जूट, उनी बस्त्र, इन्जिनियरी, सिमेंट, चीनी तथा कागज उद्योगों के इस ओर प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मण सभी सूती मिलों ने योग्य डाक्टरों के अधीन औषधालय खोल दिए हैं, कुछ मिलों में भली भाँति सुसज्जित अस्पताल भी हैं। अनेक सूती मिलों ने प्रसूतिगृह व शिशुगृह भी खोले हैं तथा खेल-कूद, सहकारी समितियाँ, स्कूल, भविष्य निर्धि. अनुग्रह दान इत्यादि की योजनाएँ चलाई हैं। भारतीय जूट मिल संस्था ने कई धर्म कल्याण केन्द्र खोल दिए हैं जहाँ हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बड़ी-बड़ी उनी मिलें भी संगठित रूप से धर्म कल्याण कार्य करती हैं। जिन मिलों में एक हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं ऐसी सभी इन्जिनियरी मिलों ने स्कूल और औषधालय खोले हैं, तथा अनेक इन्जिनियरी कारखानों में जलपान गृह तथा मनोरंजन केन्द्र भी चालू हैं। टाटा लोहा-इस्पात कंपनी ने धर्म कल्याण की संगठित ढंग से विशेष व्यवस्था की है।

धर्म संघ और धर्म कल्याण—दुनाई उद्योग धर्म संघ, अहमदाबाद, रेल कर्मचारी संघ, तथा मजदूर संघ, कानपुर को छोड़कर अन्य धर्म संघों ने धर्म कल्याण कार्य में विशेष रुचि और उत्साह नहीं दिखाया। अहमदाबाद दुनाई उद्योग धर्म संघ अपनी आय का ७०% धर्म कल्याण कार्यों पर खर्च करता है। रेल कर्मचारी संघ ने अनेक सहकारी समितियाँ एवं सामाजिक बीमा योजनाएँ चलाई हैं। कानपुर की मजदूर संघों ने कई वाचनालय, पुस्तकालय, तथा औषधालय खोले हैं।

श्रालोचना एवं सुझाव

भारत में यद्यपि औद्योगीकरण की गति के साथ-साथ धर्म कल्याण कार्य की भी प्रगति होती जा रही है, किन्तु ये कार्य अभी सन्तोषजनक नहीं हैं। न तो सभी उद्योगों में और न एक उद्योग सभी के कारखानों में धर्म कल्याण व्यवस्था है। जहाँ-जहाँ धर्म कल्याण कार्य चालू किए गए हैं उनका कार्य क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। अनेक छोटे उद्योग और छोटी इकाइयाँ ऐसी हैं जहाँ पीने के पानी तक की सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है। जहाँ कानून के अन्तर्गत कोई धर्म कल्याण कार्य अनिवार्य कर दिया गया है वहाँ केवल वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वस्तुतः उसकी भारी उपेक्षा की जाती है। बहुधा हमारे उद्योगपति इस कार्य को धर्म संघ आन्दोलन के शान्त करने का एक साधन मानते हैं तथा अधिकांश वर्ग भी इन कार्यों को सन्देह की दृष्टि से देखता है और उनसे पूरा लाभ नहीं उठाता। धर्म कल्याण कार्यों का वैज्ञानिक महत्त्व, उत्पादन से घनिष्ठ सम्बन्ध एवं औद्योगिक कौशल सम्बन्धी चमत्कार अभी हमारे देशवासियों ने पूरी तरह नहीं समझा। इस ओर हमें शीघ्र ध्यान देना चाहिए तथा धर्म कल्याण कार्य को वैज्ञानिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव उपस्थित किए जाते हैं :—

(१) १९४८ के संशोधनों के अनुसार कारखाना कानून को अपने पूर्ण रूप में लागू करना चाहिए। इसके लिए निरीक्षण सेवा के विस्तार की आवश्यकता है।

(२) कारखाना कानून के सभी नियमों को लागू करने के लिए त्रिदलीय समझौते किए जायें तथा सरकार द्वारा इन समझौतों के पुनर्विचार के लिए आवश्यक संगठन बनाना चाहिए।

(३) किसी औद्योगिक के द्रवती स्थान पर श्रम कल्याण, श्रम सुरक्षा एवं श्रमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक सभ्रहालय खोलना चाहिए।

(४) श्रम कल्याण अधिकारी उन्हीं लोगों को नियुक्त करना चाहिए जिन्हें इस सम्बन्ध में शिक्षण और अनुभव प्राप्त हो।

(५) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को श्रम कल्याण केन्द्रों और तत्सब की शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए।

(६) श्रम कल्याण कार्यों में श्रम का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(७) कोयला और अभ्रक उद्योगों की भांति अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए भी श्रम कल्याण विधियाँ बननी चाहिये।

(८) श्रम कल्याण कार्य केवल आर्थिक लाभ एवं स्वार्थ के दृष्टिकोण से नहीं चलाना चाहिए वरन् इसके ऊँचे उद्देश्यों एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समझना चाहिए।

(९) उद्योगपति, श्रम संघ तथा सरकार सभी को मिलकर उत्साह के साथ इस कार्य में सहयोग करना चाहिए।



“आज की अर्थ-व्यवस्था के युग में औद्योगिक क्षेत्र में मालिक-मजदूर का सम्बन्ध न होकर हिस्सेदार व सहकारी का सम्बन्ध होना चाहिए, तभी हर आर्थिक समस्या को शांतिपूर्वक सुलभाया जा सकता है।”

—पं० जवाहरलाल नेहरू

१६—औद्योगिक प्रवन्ध में श्रम का भाग

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना
२. आशय
३. विचारधारा का प्रादुर्भाव
४. महत्व एवं लाभ
५. भारत में विचारधारा का विकास
६. पाश्चात्य देशों के प्रयत्न
७. भारतीय अनुभव ।

प्रस्तावना

प्राधुनिक युग में श्रम केवल एक निर्जीव पदार्थ नहीं, बल्कि एक चेतन प्राणी माना जाता है जो अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ-साथ आत्म-गौरव, आत्म-सम्मान तथा अपने अधिकारों का भी महत्वाकांक्षी है। इस सिद्धान्त को आज सभी स्वीकार करते हैं और विश्व भर में श्रम के प्रति न्यायोचित नीति अपनाई जा रही है। सभी देशों में श्रम के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के प्रेरक इम नीति उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के यत्न किए जा रहे हैं। श्रम संघर्ष कम करने के अनेक यत्नों में श्रम को औद्योगिक प्रवन्ध में भाग देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश में समाजवादी समाज की आदर्शों के साथ 'औद्योगिक लोकतंत्र' का आदर्श भी जोड़ा जाने लगा है और इस चर्चा का मुख्य केन्द्र बिन्दु श्रम को औद्योगिक प्रवन्ध में भाग देना है।

आशय

धर्म के भाग से तात्पर्य उद्योग के प्रबन्ध एवं नीति निर्धारण में श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से है। उद्योग का प्रबन्ध-प्रशासन एवं नीति-निर्माण केवल उद्योगपति का ही एकाधिकार नहीं, बल्कि उसमें धर्म को भी अधिकार मिलना आवश्यक है। यह सहयोग दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रारम्भिक ढंग धर्म और उद्योगपति के बीच विचार-विनिमय है। धर्म और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन होते रहते हैं अथवा संयुक्त समितियाँ होती हैं जो नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करती रहती है। इस सहयोग का दूसरा ढंग धर्म को उद्योग के स्वामित्व में भागीदार बनाना है। श्रमिक वर्ग सम्बेदार की हैसियत से अपने प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति में भेजता है।

विचारधारा का प्रादुर्भाव

प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त इस विचारधारा का आविर्भाव हुआ। लोकतन्त्रीयवाद को इसका जन्मदाता माना जा सकता है। धर्म-र युद्ध काल में लोकतन्त्रीय शासन की विशेष चर्चा और प्रचार हुआ। आर्थिक राष्ट्रीयता के युग के समाप्त होने के साथ औद्योगिक लोकतन्त्र की भी चर्चा चलने लगी। इस विचारधारा से धर्म और धर्म संघ भी प्रभावित हुए। धर्म सभों ने यह माँग की कि जोस मस्यार्थे धर्म से सम्बन्धित हैं उनके सुलभाने में धर्म का सक्रिय हाथ होना चाहिए। उदार राजनीति, वयस्क मत-धिकार, सार्वभौमिक शिक्षा इत्यादि से इस माँग को बल प्राप्त हुआ। इस विचारधारा को सक्रिय रूप देने का प्रथम श्रेय १९१६ की ब्रिटेन की व्हित्ले (Whitley) समिति को है जिम्मे संयुक्त औद्योगिक परिषदों के स्थापित करने का सुझाव दिया जिनके अन्तर्गत धर्म और स्वामी के समान प्रतिनिधि होंगे तथा जो धर्म एवं प्रबन्ध के पारस्परिक हित के प्रश्नों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया करेगी। युद्धोत्तर-काल में इसी विचारधारा को लेकर अनेक देशों में ऐसे कानून बनाए गये जिनके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को धर्म परिषदें बनाने का आदेश दिया गया। इनके अनेक ऐसी परिषदें होना एक आदर्श औद्योगिक प्रबन्ध का नमूना माना जाने लगा।

महत्त्व एवं लाभ

उद्योग-धर्मों और कारखानों के प्रबन्ध में श्रमिक वर्ग की भाग देना औद्योगिक लोकतन्त्र की दिशा में एक नया कदम है जिसके द्वारा श्रमिकों में उद्योग के प्रति अल्पत्व भाव जाग्रत किया जाता है और इस भाँति उत्पादन बढ़ाया जाता है। सामान्यतः श्रमिक यही समझता है कि वह एक बड़े संगठन का मामूली कल-पत्र मात्र है और उद्योग की सफलता का उसमें ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस निराशावादी विचारधारा का निराकरण करने के लिए ही यह नवोन्नत अणु-धर्म विकसित किया गया है। श्रमिक को उद्योग के प्रबन्ध में भाग मिलने से वह उसे अपना समझने

प्राप्त किया जाएगा तथा सरकारी उद्योग इस प्रोर देश के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करेंगे। इस प्रकार धर्म को प्रबन्ध में भाग देना भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति का एक अंग बन गया। यह द्रष्टव्य कुछ जटिल था। अतएव इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के विचार से भारत सरकार ने सरकार धर्म, प्रोर उद्योग के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल (Study Group) १९५६ में यूरोप भेजा। इसने ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, स्वीडन, जर्मनी, यूगोस्लाविया इत्यादि देशों में भ्रमण किया और १९५७ में अपने सुझाव सरकार के समुख रखे। जुलाई १९५७ में इन सुझावों पर विचार करने के लिए भारतीय धर्म सम्मेलन की एक बैठक हुई जिसने अध्ययन दल के सुझावों की स्वीकार कर लिया तथा कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए। जनवरी १९५८ में धर्म-स्वामी सहयोग विचार गोष्ठी (Seminar) में तथा जून १९५८ में रानीखेत में औद्योगिक कार्यकर्ता पिविर में भी इस प्रश्न पर विचार विनिमय हुआ। इसके देश के सरकारी प्रोर गैर सरकारी उद्योगों में प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इस भाँति यह विचारधारा हमारी राष्ट्रीय नीति प्रोर आगामी औद्योगिक संगठन का एक आवश्यक अंग बन गई है।

पाश्चात्य देशों के प्रयत्न

ब्रिटेन में धर्म को उद्योगों के प्रबन्ध में अधिकार देने के उद्देश्य से प्रथम से द्वितीय युद्ध काल तक कई प्रकार के प्रयोग किए गए। सन् १९४७ से सरकार से प्रेरणा पाकर ऐन्ड्रिक आचार पर संयुक्त सलाहकार समूह (Joint Consultative Machinery) का प्रचार बढ़ता जा रहा है। लाभ-भागोदारी (Profit Sharing) तथा सह-साझेदारी (Co-partnership) द्वारा धर्म स्वामी सहयोग के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। कुछ छुट-पुट उद्योगों ने धर्म के प्रतिनिधि संचालक मण्डल में भी रक्त लिये हैं। सरकारी उद्योगों में वैधानिक नियमों के अन्तर्गत संयुक्त औद्योगिक परिषदें बनाई गई हैं, अन्यथा धर्म को प्रबन्ध में अधिकार देने की नीति स्वीकार नहीं की गई।

कनाडा में धर्म एवं स्वामी सहयोग के सम्बन्ध में ब्रिटेन की परम्पराओं के अनुसार काम किया जाता है। वहाँ संयुक्त उत्पादन समितियों का स्वरूप प्रोर कार्य ऐसे ही हैं जैसे ब्रिटेन में। यद्यपि वे बेबल सलाह देने वाली होती हैं, तो भी उनका कार्य क्षेत्र अति व्यापक है। अनेक औद्योगिक इकाइयाँ अपनी निर्माण-समितियों में नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों, वित्तीय स्थिति तथा लाभ-वितरण इत्यादि बातों पर विचार-विमर्श करती हैं।

फ्रांस में धर्म का सहयोग सरकारी क्षेत्र में समुचित रूप में प्राप्त किया गया है, किन्तु निजी क्षेत्र में धर्म का सक्रिय सहयोग उत्तम नहीं माना जाता। जर्मनी में सह-प्रबन्ध उन सभी कारखानों में अपनाया जाता है जिनमें एक हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं अथवा जिनमें दस लाख मार्क से अधिक पूँजी लगी है। कोपला प्रोर लोहा इस्पात उद्योगों में सह-प्रबन्ध में अधिक वर्ग को समान प्रतिनिधित्व

प्राप्त है। संचालक मण्डल में ११ में से श्रम और स्वामी के पाँच-पाँच प्रतिनिधि होते हैं तथा ग्यारहवाँ सदस्य स्वतन्त्र व्यक्ति होता है। संचालक मण्डल के आधीन तीन सदस्यों का एक प्रबन्धकर्त्ता बोर्ड होता है जिसका एक सदस्य श्रम का प्रतिनिधि होता है तथा संचालक मण्डल के श्रम प्रतिनिधि सदस्यों की अनुमति बिना न उसको नियुक्ति हो सकती और न उसे हटाया ही जा सकता है। संचालक मण्डल के ऊपर एक निरीक्षण परिषद होती है जिनमें भी श्रम के समान प्रतिनिधि होते हैं। यूगोस्लेविया में कारखाने कर्मचारियों के लिये व भूमि किसानों के लिए नारे, के अनुसार श्रमिक वर्ग को कारखानों के प्रबन्ध में कानून द्वारा पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है।

भारतीय अनुभव

भारत में भौद्योगिक विवाद कानून १९४७ के अन्तर्गत निर्माण-समितियाँ (Works Committees) बनाने का विधान है, और १९५६ तक केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में ७४५ ऐसी समितियाँ बन चुकी थी, किन्तु ये समितियाँ सफल नहीं हुई हैं। कुछ उद्योगपतियों ने लाभ-भागोदारी बोनस के प्रयोग किए हैं किन्तु ये भी विफल रहे हैं। इनकी विफलता का मुख्य कारण श्रम अथवा स्वामी की मनोवृत्ति में परिवर्तन का अभाव है। कई सरकारी क्षेत्रों को इकाइयों में श्रम के प्रतिनिधियों को संचालक मण्डल (Board of Directors) में भी स्थान दिया गया है, किन्तु इन प्रयोगों का अनुभव कुछ उत्साहजनक नहीं रहा। वम्बई और मद्रास बन्दरगाह ट्रस्ट कानूनों के अन्तर्गत श्रम के प्रतिनिधियों को संचालक मण्डल में रखने का विधान है, किन्तु इस प्रतिनिधित्व से श्रम के प्रति बन्दरगाह अधिकारियों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न श्रम-स्वामी सम्बन्धों में ही कोई सुधार हुआ है। सिंदरी के खाद के कारखाने, विशाखापत्तनम जहाज घाट और विमान निगमों में भी श्रम के प्रतिनिधियों को अपने संचालक मण्डलों में स्थान दिया है, किन्तु इनका भी अनुभव वैसा ही है जैसा बन्दरगाह अधिकारियों का। इनकी असफलता का कारण यह बताया जाता है कि उच्च स्तर पर ही श्रम प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है और निम्न स्तरों पर इसके कोई प्रयत्न नहीं किए गए। यह कहा जाता है कि जब तक सभी स्तरों पर श्रम का प्रतिनिधित्व न हो उसे कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है।

ऐच्छिक समझौते द्वारा कई उद्योगों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें (Joint Councils of Management) स्थापित की हैं, जिन से कुछ महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ है, किन्तु इमें कोई ठोस सफलता नहीं कहा जा सकता। ताता लोहा-इस्पात कम्पनी ने १९५६ में श्रम सच के साथ एक सम्मिलित समझौता किया जिसके अन्तर्गत निस्तरिय संयुक्त परिषदें (Joint Councils) बनाने का विधान है। ये तीन स्तर प्राथिक, सामाजिक तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रश्नों से सम्बन्धित हैं। इण्डियन अल्यूमिनीयम कम्पनी के बेलर कारखाने, मोदी स्पिनिंग व धीविंग कम्पनी, बंकापारा जूट मिल, बेनी जूट मिल इत्यादि ने भी समझौतों के द्वारा संयुक्त परिषदें बनाई हैं जिन

में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाता है और इस विचार-विमर्श से दोनों पक्षों को लाभ होता है।

यूरोपीय देशों में भ्रमण करने के उपरान्त अध्ययन दल ने १९५७ को अपने प्रतिवेदन में भी ऐसी ही संयुक्त समितियाँ बनाने का सुझाव दिया था जिन्हें कानून का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रश्न पर जुलाई १९५७ में भारतीय थम सम्मेलन ने तथा जनवरी फरवरी १९५८ में थम-स्वामी सहयोग विचार गोष्ठी ने सविस्तार विचार किया था, किन्तु इसे कानूनी रूप देने की बात का भारी विरोध किया गया। उक्त विचार-गोष्ठी ने एक आदर्श-समझौता (Model Agreement) भी स्वीकार किया था। लगभग ४० कारखानों में तदनुसार समझौते द्वारा संयुक्त समितियों के प्रयोग किये जा रहे हैं।

भारत में थम को प्रबन्ध में अधिकार देने की विविध योजनाओं पर अनेक प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों की सफलता पर ही इसका भविष्य निर्भर है जो अभी अनिश्चित सा ही है। पाश्चात्य देशों की भाँति भारतीय थम का बौद्धिक एवं शैलिक विकास अभी नहीं हुआ जिसके अभाव में इन प्रयोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना कम है।

“पैसे की कमी जनता के लिये इतनी भयानक बीमारी नहीं है जितनी कार्य की कमी।”
—महात्मा गाँधी

१७—बेकारी की समस्या

रूप-रेखा

१. परिभाषा ।
२. विश्वव्यापी समस्या ।
३. प्रकार ।
४. स्वरूप ।
५. दुःपरिणाम ।
६. कारण ।
७. समस्या के सुलभाने के यत्न ।
८. सुझाव ।

परिभाषा

काम करने योग्य एवं काम करने के इच्छुक लोगो के लिये आर्थिक अर्थ में कार्य का अभाव ही बेकारी कहलाती है। भ्रंघे, बहरे, लूले, लंगडे, रोगी, बच्चे, वृद्ध अथवा अपाहिज व्यक्ति जो कार्य करने के लिये सर्वथा अयोग्य हैं, बेकार नहीं माने जाते। इसी भाँति भिखारी व साधू-सन्यासी जो काम करने के इच्छुक नहीं हैं वे भी बेकार नहीं समझे जाते। काम के इच्छुक लोगो की संख्या उसकी माँग से अधिक हो तो बेकारी फैलने लगती है। माँग की कमी का कारण लोगो की संख्या का अनि अधिक बढ़ जाना अथवा काम के साधनो में कमी आ जाना अथवा दोनों हो बातें हो हो सकती हैं। भारत में इस समय दोनों ही कारण प्रभावशाली हैं।

विश्वव्यापी समस्या

बेकारी एक विश्वव्यापी समस्या है जिसका पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था से अन्वोन्माथव सम्बन्ध है। युद्ध और अन्य अभिवृद्धि अल्पकाल के लिये इसे दबा सकता है और आर्थिक मन्दी इसे उभार सकती है, किन्तु यह उपस्थित सदैव रहती है।

वी जो १९५१ में १३.७५ लाख, १९५५ में १५.८४ लाख और १९५९ में २४.६८ लाख हो गई। इस भाँति ११ वर्ष में यह लगभग तिगुनी हो गई है। यद्यपि ये आँकड़े पूर्ण नहीं माने जा सकते, क्योंकि सर्वत्र ऐसे केन्द्र नहीं हैं और इनमें नाम लिखाना अनिवार्य नहीं है। इनके कार्य-कौशल में आस्था न रखने वाले अनेक बेकार इनमें नाम लिखाते भी नहीं हैं। तो भी ये आँकड़े एक दृष्टि से बड़े तथ्यपूर्ण हैं। ये निस्सन्देह समस्या की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की ओर संकेत करते हैं।

मध्यम श्रेणी के शिक्षित वर्ग की बेकारी विशेष चिन्ता का विषय है। देश के कालेज और विश्वविद्यालयों से प्रति वर्ष लगभग ३ लाख विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर निकलते हैं जिनमें से ५०% को काम मिल जाता है, किन्तु शेष १½ लाख बेकारों में नाम लिखा लेते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बड़ी संख्या बेकार और अर्द्ध बेकारों की है। योजना आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में बेकारों की संख्या लगभग ५५ लाख है। तृतीय योजना की अवधि में इसमें १०० लाख की ओर वृद्धि होने की संभावना है। इससे भी बड़ी संख्या अर्द्ध बेकारों की है।

इस भाँति यह समस्या अत्यन्त गंभीर है और दिनो-दिन और भी गंभीर होती जा रही है।

दुष्परिणाम

बेकारी के दुष्परिणाम कंगाली, भुखमरी और दुःख है। कंगाली के कारण निम्न जीवन-स्तर, न्यून भोजन-वस्त्र, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, रोग-शोक इत्यादि जीवन को भार बना देते हैं। कभी-कभी कुछ लोग दुखी होकर आत्म-हत्या भी कर लेते हैं। ऐसे लोग आत्म-विश्वास खो बैठते हैं और उनकी हिंसा घृति, पापाचार और अपराध भावना बलवती हो उठती है। वे दूसरों के प्रति द्वेषभाव रखने लगते हैं; उनकी सार्विक प्रवृत्तियाँ दब जाती हैं।

बेकारी से देश को भारी आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है। यदि बेकारों को कार्य मिल सके तो वे अनेक जीवनोपयोगी वस्तुएँ उत्पन्न कर सकते हैं। देश और समाज उनकी योग्यता, कौशल और कार्य-क्षमता में बंचित रहता है। ऐसे लोगों के भरण-पोषण पर देश को बहुत सा धन व्यय करना पड़ता है। ब्रिटेन में बेकारों की संख्या १० लाख मानकर यह अनुमान लगाया गया है कि बेकारी के कारण १०० करोड़ पाँड राष्ट्रीय सम्पत्ति प्रति वर्ष निष्कल हो जाती है।

कारण

देश में युद्धोत्तर काल में इस समस्या के भयानक रूप धारण करने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं :—

- (१) काम के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि;
- (२) छोटे और कुटीर उद्योगों का पतन;

- (३) शिक्षा पद्धति का कार्य-प्रधान होने के स्थान पर सिद्धान्त-प्रधान होना;
- (४) युद्धोत्तर काल में काम के साधनों की कमी;
- (५) सेना से, सरकारी कार्यालयों से और औद्योगिक कारखानों से श्रमिकों की बड़ी मात्रा में छूटनी,
- (६) देश विभाजन एवं शरणाधिकियों का आगमन;
- (७) शारीरिक श्रम के प्रति जन-साधारण का घटता स्पर्ध भाव ।

समस्या के सुलझाने के यत्न

बेकारी दूर करने और कार्य-विस्तार के लिए देश की सरकार विविध प्रयत्न करती रही है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त आर्थिक मन्दी का समय आया था जबकि बेकारी की समस्या भयानक हो उठी थी। ऐसी ही स्थिति की संभावना करके भारत सरकार ने द्वितीय युद्ध समाप्त होते ही १९४५ में एक राष्ट्रीय नियोजन सेवा (National Employment Service) की स्थापना की। इसके अन्तर्गत सर्व प्रथम युद्ध क्षेत्र से निकले हुए सैनिकों के लिए कार्य-व्यवस्था करने के लिए एक मंत्रालय (Directorate General) खोला। इसके अधीन अनेक विभाग खोले गए जिनमें से एक विभाग का सम्बन्ध लोगों को काम दिलाने से था। १९४८ में सेवा नियोजन केन्द्रों की संख्या केवल ७७ थी जो अत्र बढ़ कर २४४ हो गई है। ये संस्थाएँ बेकार लोगों के नाम अपने यहाँ लिखकर रखती हैं और उन्हें यथायोग्य नौकरी दिलाने की व्यवस्था करती हैं। देश विभाजन के उपरान्त शरणाधिकियों को काम देने के लिए विस्थापित मंत्रालय स्थापित किया। सरकार ने काम के साधन बढ़ाने के लिए छोटे और बूटीर उद्योगों के पुनर्जीवन और विकास के विविध यत्न किए हैं। तथा लोगों को व्यावहारिक एवं प्राविधिक शिक्षण देने की भी व्यवस्था की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनने तक यह समस्या विशेष गंभीर नहीं थी, किन्तु १९५३ से यह विशेष भयानक हो गई। अतएव योजना में सशोधन करके १८० करोड़ रुपए इसके निमित्त दिए गए। द्वितीय योजना काल में ६० लाख अधिक लोगों को काम दिया गया। तृतीय योजना का लक्ष्य १५० लाख लोगों को काम दिलाने का है।

गत दस वर्षों में इस समस्या पर काबू पाने के अनेक यत्न किये गये हैं, किन्तु बेकारों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, बरन् और बढ़ती गई है। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में ५३ लाख लोग बेकार थे। तृतीय योजना के प्रारम्भ में २० लाख और लोग द्वितीय योजना काल के बेकार बच रहे और बेकारों की कुल संख्या ८३ लाख होगई। इस गंभीर समस्या को हल करने के अनेक सुभाव दिए जाते हैं, जिनमें निम्नांकित प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं :—

(१) जनसंख्या की रोकथाम—दो प्रतिशत बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार लगभग ३२ लाख नये काम की इच्छा रखने वाले नये व्यक्ति प्रतिवर्ष क्षेत्र में आ जाते

हैं। इतने प्रतिरिक्त लोगों को काम देना सम्भव नहीं। अतएव परिवारिक नियोजन की योजनाओं को तत्परता से लागू करना चाहिये।

(२) शिक्षा पद्धति में सुधार—यद्यपि शिक्षा सुधार की बात सर्वमान्य है और वर्षों से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, कि तु कोई सफल योजना कार्यान्वित नहीं की गई। अब भी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त लोगों का देश में अभाव है। इन्जीनियरो, डाक्टरों, श्रीवरसियरो आमुलिपिको, कम्पाउण्डरो, नर्सों, सर्वेक्षकों, हिसाब रखने वालो इत्यादि की देश में भारो कमी है तथा लिपिका, अध्यापको, थोटर चालको, चपरासियो और अथ शिक्षणहीन लोगो की एक बडो सख्या बेकार फिरकी है। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

(३) कुटीर उद्योगों का विकास—कुटीर उद्योग बेकारी दूर करने के उत्तम साधन माने जाते हैं। इन उद्योगों की समस्याओं को सुलभा कर शीघ्र से शीघ्र इनका विकास विस्तार होना वाञ्छनीय है।

(४) श्रम प्रधान निर्माण कार्य—भवन, स्कूल व सड़कें बनाने, सिंचाई साधन बढ़ाने, जंगल लगाने, भूमि संरक्षण योजनायें चालू करने से अनेक लोगों को काम दिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी कार्य श्रम प्रधान माने जाते हैं।

(५) सामाजिक मनोवृत्ति बदलना—लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति सद्भाव और श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिये। कोई काम करना बुरा नहीं है, बुरा है किसी काम को उठा कर बुरे ढंग से करना। सरकारी नौकरियों के प्रतिरिक्त व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक काम ऐसे हैं जिनमें जीवन निर्वाह और धनोपार्जन की अच्छी सम्भावना है। अनेक लोग कृषि क्षेत्र में काम पा सकते हैं।

(६) छटनी पर प्रतिबन्ध लगाना—भयानक से भयानक बेकारी लोगों को नौकरी से हटाने पर फैलती है। कर्मचारियों की छटनी, उद्योगों की तालाबन्दी इत्यादि बातों पर कानूनी रोक लगा देनी चाहिये।

(७) ग्रामीण प्रवास की रोक—बेकारी के मुख्य अड़े बड़े-बड़े नगर हैं जहाँ गाँवों से आ-आकर लोग बसते जाते हैं। इस ग्रामीण प्रवास को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में काम के साधन बढ़ाने तथा गाँवों में अन्य सुविधाएँ और आकर्षण उत्पन्न करने आवश्यक हैं।

(८) मानव शक्ति नियोजन—अन्य योजनाओं के साथ देश में श्रम शक्ति और मनुष्य बल का भी समुचित आयोजन होना चाहिये। विधिवत योजना बनाकर इस समस्या की गम्भीरता बहुत कुछ कम की जा सकती है।

साधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देकर और अधिक औद्योगिक बस्तियाँ बसा कर भी बेकारी दूर की जा सकती है।

“रेलें वास्तव में देश की जीवन-रेखा हैं जिन पर देश के यात्रियों और सम्पदा का इस प्रकार आवागमन होता रहता है जैसे मानव शरीर में रक्तवाहिनी नाडियों के द्वारा रक्त-प्रवाह होता है।”

—करनलसिंह, अध्यक्ष, रेल बोर्ड।

१८—भारत में रेल परिवहन

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना
२. रेलों का राष्ट्रीय महत्त्व
३. १८५३ से अब तक विकास
४. रेलों के क्षेत्र
५. रेल-वित्त
६. योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति
७. प्रबन्ध-प्रशासन
८. रेलों की कुछ समस्याएँ
 - (क) दुर्घटनाएँ
 - (ख) बिना टिकट यात्रा
 - (ग) यात्रियों को सुख-सुखविधायें।

प्रस्तावना

भारतीय रेल संगठन एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा संगठन है। रेल-मार्ग की कुल लम्बाई पैंतीस हजार मील से ऊपर है। भारतीय रेलों में लगभग १४०० करोड़ रुपए की पूँजी लगी हुई है और लगभग १२ लाख कर्मचारी इनमें काम करते हैं। वे प्रतिवर्ष १५३ करोड़ यात्री और १४५ करोड़ टन माल की दुलाई करती हैं। भारतीय रेलें भारत का सबसे बड़ा सरकारी उद्योग हैं।

रेलों का राष्ट्रीय महत्त्व

रेलों का आगमन से पूर्व भारत छोटे गाँवों और कुटीर उद्योगों का देश था, बम्बई, बलकत्ता जैसे बड़े शहरों का वही नाम न था, उत्पादन बहुधा निजी उपभोग

योजना काल में प्रगति

भारतीय रेलों को द्वितीय विश्व-युद्ध और देश-विभाजन के कारण बहुत क्षति ठगानी पड़ी थी। उसकी पूर्ति पहली योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरी योजना में, रेलों में अपना पचास विकास किया और इन्फ्रा, कोयला, सिमेंट इत्यादि आधारभूत उद्योगों के विकास में सहायता पहुँचाई। १९५०-५१ में रेलों में टोए जाने वाले सामान का कुल परिमाण ९१० लाख टन था। दूसरी योजना के अंत तक यह १६२० लाख टन तक पहुँच गया। १९५०-५१ तक लगभग १२०० मील नई रेलें बनाई गईं १३०० मील-पर ट्रेन्स किया गया और ८८० मील रज-मार्ग विज्ञानी चालित रेलों का ही गया। १९५०-५१ में इन्फ्रा की संख्या ५,२००, सवारी डिब्बों की १६,००० और मान डिब्बों की १,६६,००० थी जो १९२०-२१ तक बडफर क्रमशः १०,६००, २८,६०० तथा २,५४,१०० हो गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेल-यातायात ५,२५० लाख टन की सीमा तक पहुँच जान की संभावना है। इस योजना में रेलों के निमित्त १२०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिसका लगभग एक तिहाई भाग इन्जन और डिब्बों आदि पर व्यय किया जाएगा। योजना की अवधि में १२०० मील रेलें बनाने की व्यवस्था है।

प्रबन्ध-प्रशासन

रेलों के प्रबन्ध-प्रशासन एवं नियंत्रण का सारा भार रेल बोर्ड के ऊपर है जिसकी १९०५ में स्थापना हुई थी। रेल बोर्ड इस समय ५ सदस्यों की संस्था है जिनमें से एक सभापति है जो रेल मन्त्रालय का पदेन सचिव समझा जाता है। दूसरा सदस्य वित्तीय आयुक्त है तथा तीन सामान्य सदस्य हैं जिनमें से प्रत्येक कर्मचारी युद्ध, परिवहन एवं इन्जीनियरी सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

रेलों और जनता के बीच सम्पर्क बनाए रखने और विचार-विमर्श के लिए निम्नांकित समितियाँ बना दी गई हैं : (क) केंद्र में राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार परिषद, (ख) प्रत्येक रेल के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति, (ग) प्रादेशिक रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियाँ तथा (घ) मण्डल (Divisional) सलाहकार समितियाँ।

प्रत्येक रेल-इकाई का सर्वोच्च अधिकारी महाप्रबन्धक कहलाता है। उस रेल के सभी विभागों की देख-रेख, नियंत्रण तथा सूत्रीकरण महाप्रबन्धक का ही उत्तरदायित्व है। प्रत्येक रेल का कार्य विपदा के अनुसार भिन्न-भिन्न अधिकारियों में बाँटा रहता है।

रेलों की कुछ समस्याएँ

रेलों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो उनके लिए रोज-रोज चिंता का विषय बनती रहती हैं और जिनका प्रतिकूल प्रभाव उनके कार्यक्षमता, कार्यक्षमता एवं आय पर पड़ता है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नांकित हैं :—

(क) बिना टिकट यात्रा—प्रतिवर्ष लगभग ६७ लाख यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं, जिनसे लगभग १.५० करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। अनेक ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आते। बिना टिकट यात्रा करने वालों के कारण रेलों की प्रति वर्ष लगभग ५ करोड़ रुपए की हानि सहन करनी पड़ती है।

(ख) दुर्घटनाएँ—दुर्घटनाओं के कारण भी रेलों को भारी हानि सहन करनी पड़ती है। दुर्घटनाओं से तात्पर्य गाड़ियों का पटरी से उतर जाना, गाड़ियों का परस्पर लड़ जाना, गाड़ियों का नदी-नाले में धिर जाना अथवा अन्य प्रकार उनकी टक्कर हो जाना है। इन दुर्घटनाओं से रेल-सम्पत्ति की भारी टूट-फूट और हानि होती है, यात्री हताहत हो जाते हैं अथवा उनकी जर्में बली जाती हैं; बहुत सामान नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। इस सबके लिए रेलों को हानि पूर्ति देनी पड़ती है।

(ग) यात्रियों को सुख-सुविधाएँ देना—यात्री जनता की सुख सुविधाएँ बढ़ाने और रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रेलें सर्वत्र चिन्तित रहती हैं। गत दो योजनाओं में वे ३ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसके निमित्त व्यय करती रही हैं। नमूने के डिब्बे उपलब्ध करना, तृतीय धोखी के डिब्बों में पंखे लगाना, गाड़ियों में और स्टेशनों पर प्रकाश का समुचित प्रबन्ध, शयन-पान व्यवस्था, नए स्टेशन और रेल रुकने के स्थान बनाना, अधिकधिक विश्रामगृह बनवाना, प्लेटफार्मों को ऊँचे कराना, नए टिकट घर खोलना, स्टेशनों पर बिजली का प्रकाश, खान-पान की वस्तुओं का समुचित प्रबन्ध, गाड़ियों और स्टेशनों की सफाई, पीने के पानी का प्रबन्ध, गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के यत्न इत्यादि विषय रेल यात्रा की सुविधा-जनक एवं सुखमय बनाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं।

“सड़के किमी देश की घमनियाँ और शिराएँ हैं जिनके द्वारा प्रत्येक सुधार रूपी रक्त परिभ्रमण होता है।”

—ले० वं.यम

१६—भारतीय सड़क परिवहन

रूप रेखा

१. सड़कों का राष्ट्रीय महत्व
- २ सड़क परिवहन के गुण
- ३ भारत में सड़कों का विकास
- ४ भारत में सड़क परिवहन का विकास
- ५ सड़क विकास योजनाएँ
६. सड़क परिवहन का प्रशासन
- ७ सड़क परिवहन की समस्याएँ
- ८ मविष्य ।

सड़कों का राष्ट्रीय महत्व

सड़कें राष्ट्रीय समृद्धि के विशाल महल की आधार-शिला हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अथ किसी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रयत्न को अपने पूर्ण रूप में फलीभूत होने और आगे बढ़ाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है। भारत के पुनर्जन एव पुनर्निर्माण रूपी गत्यात्मक अभिनय का सड़कें नेत्र बिंदु हैं। किसी राष्ट्र के स्वस्थ वी स्थिर रखने में सड़कों का वही महत्व है जो मनुष्य शरीर में घमनी और शिराओं का। जैसे घमनियाँ और शिराएँ रक्त परिभ्रमण द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं वैसे ही सड़कें राष्ट्रीय जीवन के आवश्यक उपकरणों—माल, मनुष्यों एवं वस्तुओं—को देश के कोने-कोने तक पहुँचाती हैं और उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की क्रियाओं को सफल बनाती हैं। पर्याप्त एवं सुगम सड़कों पर ही राष्ट्र के आर्थिक साधनों का पूर्ण उपयोग संभव है।

सड़क परिवहन के गुण

सड़क परिवहन किसी देश अथवा समाज की आर्थिक एवं मूल आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह अन्य सभी साधनों का आधार स्तम्भ है; यह रेल, जहाज एवं विमान का पूरक है। रेल-सेवा का उपयोग करने से पूर्व हमें मोटर, बैलगाड़ी, इक्का, तांगा रिक्शा, इत्यादि सड़क वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। यही बात नाव-जहाज अथवा विमान सेवा के उपयोग के लिए सत्य है। आज भी सभार के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रेल, नाव, जहाज अथवा विमान का प्रयोग नहीं होता, किन्तु ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं जहाँ किसी न किसी प्रकार की सड़क सेवा उपलब्ध न हो।

सड़क परिवहन का सबसे बड़ा गुण अन्य साधनों की अपेक्षा इस सेवा की लचक है। सेवा की माँग के घटने-बढ़ने के साथ-साथ इस सेवा का सड़क समायोजन सम्भव है। रेल के इंजन अथवा जलवात की भाँति सड़क-वाहन अपने मार्ग से सम्बद्ध नहीं होते। इसका दूसरा गुण इस सेवा की स्वतन्त्रता अर्थात् इच्छानुसार मार्ग अथवा सेवा-परिवर्तन की सुविधा है। एक मार्ग लाभदायक सिद्ध न हो तो दूसरे मार्ग पर और एक यातायात पर्याप्त सिद्ध न हो तो दूसरे प्रकार के यातायात से उसे लाभ-दायक बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन का तीसरा गुण उसकी द्वार-से-द्वार तक पूर्ण सेवा प्रदान करने की क्षमता है। इसके अन्य गुण सेवा का स्थापन, मान की सुरक्षा, समय की बचत, बहुमुखी सेवा इत्यादि हैं।

सड़कों का विकास

भारत के प्राचीन शासक सड़कों के निर्माण और सुधार को लोक-कल्याण कार्य मानते थे तथा इस काम को उत्साह और रुचि के साथ करते थे। अंग्रेजी शासन काल में और मुख्यतः रेल युग में भारतीय सड़कों की उपेक्षा की गई। प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त राजनीतिक जाग्रति व साथ-साथ देश में सड़कों के प्रति भी रुचि उत्पन्न हुई। जनता की भाँग पर विचार करने के लिये १९२७ में जयकर समिति नियुक्त की गई जिसके सुझावों के अनुसार केन्द्रीय सरकार सड़कों के विकास व सुधार में हाथ बटाने लगी और सन् १९२९ में केन्द्रीय सड़क निधि बनाई गई। इस निधि की सहायता से देश की सड़कों का विकास एवं सुधार किया जाने लगा। इस निधि को स्थायी जीवन प्राप्त होने के उपरान्त १९३४ में भारतीय सड़क कांग्रेस नाम की एक अर्द्ध सरकारी संस्था बनाई गई। इस भाँति सड़कों के विकास एवं सुधार का मार्ग खुला। १९२७-२८ में देश में सड़कों की लम्बाई २,०५,००० मील थी और वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं। केन्द्रीय सड़क निधि की सहायता तथा भारतीय सड़क कांग्रेस एवं भारत सरकार के प्रयत्नों से १९३७-३८ तक के दस वर्षों में सड़कों की लम्बाई २,८४,००० मील हो गई, उनका सुधार भी किया गया तथा उन पर अनेक पुल बनवाये गये।

द्वितीय युद्ध काल में सड़कों के और भी अधिक विकास की आवश्यकता हुई। अतएव भारत सरकार ने भारतीय सड़क कांग्रेस की प्रेरणा से दिसम्बर १९४३ में

नागपुर में देश के केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सड़क इंजीनियरों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में देश की आगामी बीस वर्षों की आवश्यकता पर विचार करके सड़क-विकास की एक दस वर्षीय योजना बनाई जिसके अनुसार ४४८ करोड़ रुपए व्यय करके ४ लाख मील लम्बा नया सड़क पथ बनाने का निश्चय किया गया। देश विभाजन के उपरांत इसमें आवश्यक परिवर्तन किये गये और उसे देश की सड़क विकास-नीति का आधार मान लिया गया। तब से देश की सड़को का और भी तीव्रगति से एवं सतुलित विकास हुआ है। अब देश में सड़को की लम्बाई ३,६८,००० मील हो गई है जिसमें से १ ४४ ००० पक्की और २,५४,००० अथ निम्न कोटि की सड़के हैं।

सड़क परिवहन का विकास

सड़क मार्ग से माल और मनुष्यों के आवागमन को सड़क परिवहन कहा जाता है। सड़क मार्ग से टुनाई करने वाले वाहनो में विविध पशुवाहन, मुख्यतः बैलगाड़ी मोटर गाड़ियो तथा बाइसकिलें मुख्य हैं। बैलगाड़ी देश का प्राचीनतम सड़क वाहन है, किंतु यांत्रिक वाहनो ने आवागमन के उपरांत भी प्रामोख्य क्षेत्र के लिए उसका महत्व कम नहीं हुआ। इस समय देश में लगभग ११० लाख बैलगाड़ियाँ हैं जो लगभग १२ ५० करोड़ टन माल और असंख्य यात्रियों की प्रतिवर्ष ढलाई करती हैं। मोटरगाड़ियो एवं बाइसकिलो का चलन बीसवीं सताब्दी में बढ़ता गया है। भारत में प्रथम मोटर गाड़ी १८६८ में आयात की गई। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व देश की सड़को पर ३,०८६ मोटर गाड़ियाँ और २६,००० बाइसकिले चलती थी। द्वितीय युद्ध से पूर्व तक बहुधा मोटरों और बाइसकिलो की माँग आयात से पूरी की जाती थी किंतु उपरांत इनका देश में निर्माण होने लगा। अब आयात बन्द कर दिया है। देश में इस समय लगभग ५ लाख विविध प्रकार की मोटर गाड़ियाँ तथा ६ लाख बाइसकिलें प्रयोग में आती हैं।

मोटर परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ही प्रारम्भ हुआ और इस वेग से हुआ कि आर्थिक मन्दी के वर्षों में यह साधन रेलों को हानि पहुँचाने लगा। रेल मोटर प्रतियोगिता का आशिक हल १९३६ के मोटर वाहन कानून द्वारा सोचा गया। सन् १९४५ में सिद्धांत व्यवहार-सहिता द्वारा मोटर गाड़ियो का कार्य क्षेत्र ७५ मील के अतर्गत सीमित कर दिया गया। १९५० में मोटरवाहन आँच समिति ने मोटर वाहनो के कर घटाने तथा उनके सुधार के अर्थ अनेक सुझाव दिए। १९५५ में परिवहन अध्ययन समुदाय ने मोटर परिवहन की दुर्बलताओं की ओर सकेत किया और उन्हें दूर करने के अनेक सुझाव दिए। १९५६ में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने इस साधन की प्रशासनात्मक व्यवस्था सुधारने के अनेक सुझाव दिये। रेल मोटर प्रतियोगिता का प्रश्न हाल में फिर गम्भीर हो गया है। इस प्रतियोगिता का हल राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के सुझावों के अनुसार किया जायेगा।

सड़क विकास योजनाये

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है देश में सड़को के विकास की प्रथम महत्वपूर्ण योजना १९४३ की नागपुर योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार

को सड़कों के निर्माण व सुधार का उत्तरदायित्व सौंपा गया, सड़कों का विविधत वर्गीकरण किया गया और उनके सतुलित विकास की योजना उपस्थित की गई। इस योजना का कार्यक्रम १९५७ तक पूरा हो चुका था। १९४७ में देश विभाजन और १९५०-५१ में पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ होने के कारण देश की यातायात व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो गये थे और नागपुर योजना देश की बढ़ती हुई माँग के लिये अपर्याप्त समझी गई। अतएव १९५६ में एक नई तीस वार्षिक योजना बनाई गई जिसके अनुसार १९८०-८१ तक देश में सड़कों का सम्बाँध ६,५७,००० मील अर्थात् दुगुनी हो जाएगी। इस पर ५,२०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस योजना के पूरे होने पर देश के विकसित एवं कृषि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सड़क से ४ मील और अल्प सड़क से $1\frac{1}{2}$ मील, अर्द्ध विकसित क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सड़क से ८ मील और अल्प सड़क से ३ मील तथा अशुद्ध विकसित एवं कृषि विहीन क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सड़क से १२ मील और अल्प सड़क से ५ मील से अधिक दूर न रहेगा।

सड़क परिवहन का प्रशासन

राष्ट्रीय सेवाओं का लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीयकरण हो गया है। इन सेवाओं का संचालन वैधानिक सड़क परिवहन निगमों, सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों एवं सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। माल यातायात का एक बड़ा भाग अभी निजी मोटर वाहनों के अधिकार में है। तृतीय योजना के अंत तक इस सेवा के राष्ट्रीयकरण पर योजना आयोग ने रोक लगा दी है। निजी मोटर सेवाओं के समन्वय, निपटन एवं विकास के लिये एक अन्तर्राज्य परिवहन आयोग स्थापित कर दिया गया है। परिवहन के विभिन्न साधनों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीति के बीच समन्वय लाने के लिये भारत सरकार ने परिवहन समन्वय समिति इत्यादि संस्थाओं का संगठन किया है। १९५६ में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने वर्तमान प्रशासनीय संगठन में आमूल परिवर्तन का सुझाव दिया। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक अलग परिवहन मंत्रालय, एक दावा याचिकाकरण और एक परिवहन सलाहकार समिति का संगठन आवश्यक बताया गया है।

सड़क परिवहन की समस्याएँ

देश के विस्तार और उसकी जनसंख्या को देखते हुए सड़क परिवहन की स्थिति सतोपजनक नहीं है। देश की ८२% जनसंख्या एवं विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र की सेवा का भार पूरुगत बेलगाड़ियों पर है जिनका रूप रग और ढाँचा अभी तक वही है जो सदियों पहले था। इसी भाँति देश में प्राधुनिक सड़कों और यांत्रिक वाहनों की स्थिति भी देश की बढ़ती हुई माँग के अनुरूप नहीं है। इस धीमी प्रगति का मुख्य उत्तरदायित्व नीचे वर्णित समस्याओं पर है।

(१) अपर्याप्त एवं बुरी सड़कें—भारत में प्रति वर्तमान क्षेत्र के लिये $\frac{1}{2}$ मील सड़क पथ है, जबकि ब्रिटेन में $2\frac{1}{2}$ मील फ्रांस में ३ मील सयुक्तराष्ट्र में १ मील और लक्का में $\frac{3}{4}$ मील सड़क पथ है। जो कुछ सड़क देश में हैं उसकी लगभग दो तिहाई कच्ची सड़क हैं जो वर्ष भर काम नहीं देती और उन पर पुन भी नहीं है अथवा दुर्बल हैं। हमारी सड़कों की चौड़ाई भी कम है।

(२) अर्थात् मोटर गाड़ियाँ—देश में मोटर गाड़ियों का घनत्व भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। प्रति एक लाख जनसंख्या के लिये यहाँ ८६ मोटरे हैं, जबकि समुक्तराष्ट्र में ३८,०००, कनाडा में २५,०००, आस्ट्रेलिया में २३,०००, ब्रिटेन में ६६००, फ्रांस में १४०० तथा लंका में ६०० मोटरें हैं। अतएव हमारी मोटर चलने योग्य सड़कों की २० से ४० प्रतिशत तक कार्यक्षमता प्रयोग में नहीं आती।

(३) अतएव कर भार—यह अधिकृत रूप से सिद्ध हो चुका है कि भारत में मोटरगाड़ियों पर उच्चतम कर-भार है जो कि संचालन व्यय का २० प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक हो जाता है।

(४) वहन भार सीमायें—मोटर वाहन कानून के अंतर्गत लगाई गई भार-वहन सीमायें वैज्ञानिक नहीं हैं। अतएव देश की मोटर गाड़ियों का पूरा उपयोग नहीं होता है।

(५) प्रतिस्पर्द्धा इकाइयाँ—हमारे देश में मोटर मालिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसके पास एक या दो मोटरें होती हैं। ऐसे छोटे चालक न तो सेवा का उचित स्तर स्थापित कर सकते हैं और न कुशल प्रबन्ध के नभूने ही। प्रातीय सेवा के लिये पांच मोटरों की और अन्तर्प्रान्तीय सेवा के लिये १० मोटरों की प्रतिस्पर्द्धा इकाइयों का सुभाव दिया जाता है।

(६) राष्ट्रीयकरण का भय—सन् १९४७ से अनेक राज्यों ने मोटर सेवा के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई। यद्यपि इसमें उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली, तो भी वे सड़कों पर सरकारी मोटरे लाने की जालायित रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के इस भय के कारण इस व्यवसाय के स्वतन्त्र विकास में भारी बाधा पड़ती है।

(७) साक्ष सुविधाओं का अभाव, (८) राज्यों में असहयोग का अभाव, (९) अनुज्ञापत्र देने की कार्यविधि, (१०) अस्वाभाविक प्रशासन-संगठन, इसकी अन्य समस्यायें हैं।

भविष्य

गत वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि अकेली रेलें देश के बढ़ते हुये यातायात को ले जाने में असमर्थ हैं। उनके विस्तार के लिये देश में पूँजी का भी अभाव है। अतएव सड़क परिवहन का यथाशक्ति विकास करके ही देश की परिवहन सम्बन्धी कमी की पूर्ति की जा सकती है। सड़क परिवहन के विकास-विस्तार के लिये रेलों की अपेक्षा कम पूँजी और विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। अनेक क्षेत्रों में यातायात के घनत्व की कमी के कारण भी रेल-निर्माण लाभकर नहीं है। अतएव सड़क परिवहन के विकास की ओर विशेष ध्यान देना हमारे लिये अनिवार्य हो गया है। देश के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र का विकास सर्वथा सड़क परिवहन के विकास से सम्बद्ध है। इस भाँति विविध पहलुओं से विचार करने के उपरान्त हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय सड़क परिवहन का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

“सिन्धु घाटी में भारतीय सभ्यता के नवप्रभात से लेकर अब तक के लगभग पाँच हजार वर्ष की लम्बी अवधि में भारतीय जहाज परिवहन का उज्ज्वल व तेजस्वी इतिहास रहा है।”

— राधा कुमुद मुकर्जी

२०—भारतीय जहाज परिवहन

रूप-रेखा

- १ राष्ट्रीय महत्व
- २ प्राचीन वैभव
- ३ प्राधुनिक जहाज परिवहन का जन्म एवं विकास
४. परतत्र भारत में धीमी प्रगति के कारण
- ५ स्वतन्त्र भारत की नीति
- ६ १९४७ से प्रगति
- ७ जहाज परिवहन कानून
८. जहाज परिवहन निगम
९. जहाज निर्माण
१०. शिक्षण सुविधायें
११. बन्दरगाह
- १२ समस्यार्यें
- १३ भविष्य ।

राष्ट्रीय महत्व

जहाज परिवहन प्रति प्राचीन एवं आधारभूत व्यवसाय है। प्राधुनिक युग में इसका सैनिक और असेनिक महत्व सभी स्वीकार करते हैं। समुद्र-बल आजकल विजयिनी शक्ति समझा जाता है। विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग तीन चौथाई का परिवहन-जहाजों द्वारा होता है जिसमें वे सब कच्चे पदार्थ भी सम्मिलित हैं जो प्राधुनिक उद्योग के आधार हैं। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ९५ प्रतिशत समुद्र के

मार्ग से ही होता है। समुद्री वेडा माल के विदेशी बाजारों के वितरण के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, वरन् नए बाजार खोजने में भी अद्वितीय है। व्यापारिक असंतुलन को ठीक करने का भी जहाजी उद्योग एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत को इस समय १५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जहाजी भाड़े के रूप में विदेशी जहाजी कम्पनियों को देने पड़ते हैं। विदेशी विनिमय अर्जित करने में जहाजी उद्योग का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। प्राधारभूत उद्योग होने के नाते यह अनेक उद्योगों को जन्म देता है। यह विशाल उद्योग का जन्मदाता, विशेषीकरण का पोषक एवं आधुनिक सभ्यता का जीवन है। यह सभ्यता और संस्कृति के प्रसार एवं अन्तर्राष्ट्रीयकरण का साधन भी है। इन्हीं सेनाओं और विशेषताओं के कारण प्रत्येक देश अपने जहाज व्यवसाय को अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति, राष्ट्रीय नीति का शक्तिशाली यंत्र, अपने व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि का आवश्यक साधन तथा राष्ट्रीय संकटकाल एवं देश-रक्षा का द्वितीय बल समझता है। इसी कारण प्रत्येक देश की सरकार उसे प्रोत्साहन, आश्रय और आर्थिक सहायता देकर बढ़ावा देती है।

प्राचीन वैभव

जहाज-परिवहन और जहाज-निर्माण भारत के प्राचीनतम व्यवसाय है। भारतीय सभ्यता के विकास के साथ-साथ भारतीय इतिहास में इनका भी क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। अंग्रेजी शासन के स्थापित होने के समय तक तीन हजार वर्ष तक भारत विश्व के सामुद्रिक राष्ट्रों में अग्रणी और महान सामुद्रिक शक्ति बना रहा। भारत का व्यापारिक सम्पर्क एशिया के ही नहीं यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ भी था। उस समय भारत का सामुद्रिक महत्व इतना अधिक था कि इतिहासकार इस देश को 'पूर्वी सागरों की रानी' कह कर पुकारते थे। पीगू, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जापान इत्यादि देशों में प्राचीनकाल में भारतीय उपनिवेश थे और दक्षिणी चीन मलाया, प्रायद्वीप, अरब व ईरान के सभी मुख्य नगरों एवं अफ्रीका के सारे पूर्वी तट पर भारत की व्यापारिक बस्तियाँ थीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के प्रारम्भ में भी यह उद्योग समुन्नत अवस्था में था तथा भारतीय कलाकार ब्रिटिश नौकाधिकरण के लिये भी जहाज बनाते रहे। ये जहाज सोहे के जहाजों से कहीं अधिक सुदृढ़, सुन्दर और दीर्घजीवी समझे जाते थे।

आधुनिक जहाज परिवहन का जन्म एवं विकास

ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण अंग्रेजी शासन के सुदृढ़ होने के साथ ही साथ भारत के इस प्राचीन उद्योग के वैभव का सूर्य ढलने लगा और उत्तमसर्वी शताब्दी के मध्य तक यह व्यवसाय लगभग मृतप्रायः हो गया तथा भारतीय व्यापार व भारतीय समुद्री में ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। १८६० और १९२५ के बीच १०२ भारतीय जहाजी कम्पनियाँ बनीं, किन्तु सबकी सब ब्रिटिश एकाधिकार ने समाप्त करदी। केवल १९१९ में बनीं सिंधिया कम्पनी बच रही जो वर्षों तक विदेशी कम्पनियों का सामना करती हुई अपने प्राण

बचा सकी। अतएव भारत में आधुनिक जहाज परिवहन का इतिहास इसी कम्पनी के जन्म और विकास का इतिहास समझना चाहिये। आज भी यह देश के इस व्यवसाय की सबसे शक्तिशाली कम्पनी है।

सन् १९२४ में इस कम्पनी का ब्रिटिश इन्डिया नामक विदेशी कम्पनी के साथ परस्पर सद्भाव बरतने का एक समझौता हो गया था, तो भी विदेशी कम्पनियाँ इसे नीचा दिखाने और हानि पहुँचाने का यत्न करती रहीं। इसी भाँति १९३३ का मोर-समझौता तथा १९३४ का त्रिदलीय समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि १९३६ में भारत का जहाजी बेड़ा १,५०,००० टन था जो १९४५ में केवल आधा अर्थात् ७५,००० टन रह गया।

धीमी प्रगति के कारण

सन् १९१६ और १९४७ के बीच हमारे इस उद्योग की धीमी प्रगति के मुख्य कारण निम्नांकित थे :

- (१) अक्सर उपेक्षा,
- (२) ब्रिटिश पोतचालन की आश्रय,
- (३) भाडा द्वन्द्व युद्ध,
- (४) भारत सरकार की प्रतिज्ञा-भङ्गक एवं उदासीनता पूर्ण नीति, तथा
- (५) आस्यगित फिरोती सिद्धान्त इत्यादि।

स्वतंत्र भारत की नीति

द्वितीय विश्व युद्ध काल की कठिनाइयों और परिवर्तित राजनीति के कारण सन् १९४४ में भारत सरकार ने एक जहाज परिवहन नीति पुनर्निर्माण समिति बिठाई। इस समिति ने स्वतंत्र भारत की जहाज परिवहन नीति का १९४७ के अपने प्रतिवेदन में समावेश किया, जो निम्नांकित थी :

(१) भारतीय व्यापार के सुचारु संचालन के लिये देश को २० लाख टन के जहाजों की आवश्यकता है और इसी लक्ष्य को सामने रख कर हम इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिये।

(२) भारत के कुल समुद्रतटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये रक्षित कर देना चाहिये और सामुद्रिक (विदेशी) व्यापार में भारतीय जहाजों को उपयुक्त भाग मिलना चाहिये।

(३) आगामी पाँच अथवा सात वर्षों में भारतीय जहाजों के लिये (क) भारतीय तटवर्ती व्यापार में शत-प्रतिशत, (ख) निकटवर्ती (पाकिस्तान, ब्रह्मा, लका) व्यापार में ७५%, (ग) दूरवर्ती व्यापार में ३०%, तथा (घ) पूर्वी देशों के व्यापार में ३०% भाग प्राप्त करना चाहिये।

(४) देश के विदेशी व्यापार में भाग लेने वाली जहाजी कम्पनियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये।

(५) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये एक जहाज परिवहन बोर्ड बनाना चाहिये ।

इन लक्ष्यों तथा उक्त नीति को राष्ट्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया और यही सिद्धान्त और यही लक्ष्य हमारी वर्तमान जहाज परिवहन नीति के आधार हैं । इसी नीति के अनुसार अगस्त १९५० में देश के समुद्रतटीय व्यापार को देशी जहाजों के लिये रक्षित कर दिया गया था और अब २० लाख टन के लक्ष्य की ओर देश बढ़ता जा रहा है ।

१९४७ से प्रगति

१९४७ में जहाज परिवहन नीति पुनर्निर्माण समिति के द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार जहाज व्यवसाय की उन्नति एवं विकास के लिये दो बातों की विशेष कमी पाई गई :—

(क) आवश्यक जहाजों की, और

(ख) शिक्षण प्राप्त योग्य व्यक्तियों की ।

एक सम्मेलन बुलाकर इन कमियों को दूर करने के प्रयत्न किये जाने लगे । १९४७ में विशालापत्तनम जहाज घाट खोला गया जहाँ १९४८ से बड़े-बड़े नए जहाज बनने लगे । उसी समय तीन जहाज निगम बनाने का निर्णय किया, १९४८ में शिक्षण व्यवस्था की गई, १९५० में समुद्रतटीय व्यापार के रक्षण की घोषणा की; १९५१ में जहाजी कंपनियों को आर्थिक सहायता देने के विचार से एक विशेष ऋण-व्यवस्था धालू की, १९५८ में जहाज परिवहन कानून में आवश्यक परिवर्तन किये तथा एक विकास निधि का निर्माण किया । एक राष्ट्रीय जहाज परिवहन बोर्ड भी स्थापित कर दिया गया है । विदेशों से नए-पुराने जहाज खरीदे गये हैं । इस भाँति विविध यत्नों द्वारा जहाजी बेड़े का आकार बढ़ाया गया है तथा इस उद्योग की अन्य भाँति प्रगति की गई है ।

१९४६ में भारत में १,२७,००० टन के ४९ जहाज थे । प्रथम योजना के प्रारम्भ में ३,७३,००० टन के ९४ जहाज देश में हो गये जिनमें से २,०६,००० टन के ७१ जहाज समुद्रतटीय व्यापार में और १,६७,००० टन के २३ जहाज विदेशी व्यापार में काम करते थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ लाख टन का लक्ष्य रखा गया किन्तु वस्तुतः देश की जहाजी क्षमता ४,८०,००० टन हो सकी । उस समय जहाजों की संख्या १२६ थी जिनमें से २,४०,००० टन के ९० जहाज समुद्र तट पर और २,४०,००० टन के ३६ जहाज समुद्रपार क्षेत्र में काम करते थे । द्वितीय योजना में ९ लाख टन का लक्ष्य अपनाया जिसे प्राप्त कर लिया गया तथा तटीय जहाजी क्षमता ४,३६,००० टन और समुद्रपार की जहाजी क्षमता ४,६५,००० टन है । तृतीय योजना का लक्ष्य ११ लाख टन का है । वर्तमान जहाजी क्षमता ८१% निजी क्षेत्र में और १९% सरकारी क्षेत्र में है ।

इस भाँति गत दो योजनाओं में इस व्यवसाय में अच्छी उन्नति की है। तो भी हम अपने २० लाख टन के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। अपने विदेशी व्यापार का केवल १०% देशी जहाज से जाते हैं और शेष ९०% विदेशी जहाजों के हाथ में है। विदेशी व्यापार के ५०% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमें अपने विदेशी बड़े की शक्ति पाँच गुनी करनी चाहिये।

जहाज परिवहन कानून

जहाज परिवहन सम्बन्धी विविध नियमों और अनेक कानूनों के स्थान पर सन् १९५८ में भारत सरकार ने केवल एक एणिकपोत कानून बना दिया है। इसके द्वारा एक पोतचालन विकास निधि और राष्ट्रीय पोत-मण्डल की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पोत-मण्डल देश की एक नीति निर्मात्री सर्वोच्च संस्था है।

जहाज परिवहन निगम

१९४७ में भारत सरकार ने सामुद्रिक व्यापार के तीन विभिन्न क्षेत्रों के लिये तीन निगम बनाने का निश्चय किया था। इस निर्णय के अनुसार अब तक दो निगमों की स्थापना हो चुकी है। 'पूर्वी पोतचालन निगम' मार्च १९५० और 'पश्चिमी पोतचालन निगम' जून १९५६ में बने थे। पूर्वी निगम के जहाज भारत-जापान, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सिंगापुर, भारत-पूर्वी अफ्रीका तथा भारत-मसकत मार्गों पर चलते हैं। पश्चिमी निगम की सेवा भारत-ईरान की खाड़ी, भारत-मालासागर, भारत-पोलेड और भारत-रूस मार्गों पर चालू है। तीसरी निगम बनने पर संयुक्त राष्ट्र तथा यूरोप के कुछ देशों को सेवा प्रदान करने की योजना थी, किन्तु अब पूर्वी और पश्चिमी निगमों को एक में मिला दिया गया है।

जहाज निर्माण

देश में समुद्रतटीय व्यापार में काम करने योग्य छोटे जहाज बनाने के कई कारखाने बम्बई, कलकत्ता व कोचीन में हैं। ८,००० टन के प्रथम और भी बड़े जहाज बनाने का १९३७ से पूर्व कोई कारखाना नहीं था। सिंधिया कम्पनी के प्रयत्न से बड़े जहाज बनाने का एक कारखाना १९४७ में विशाखापत्तनम में बना जिसने १९४८ में उत्पादन प्रारम्भ किया। तब से यहाँ प्रतिवर्ष दो जहाज बनकर निकलते रहते हैं। तृतीय योजना में कोचीन में एक दूसरा कारखाना और खोला जाएगा।

शिक्षण सुविधाएँ

गत वर्षों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के भारत सरकार ने भरसक यत्न किये हैं। इस समय चार प्रकार की शिक्षण सुविधाएँ देश में उपलब्ध हैं (१) डफरिन शिक्षण पोत जहाँ नौकातल अधिकारियों को समुद्रगमन से पूर्व का शिक्षण दिया जाता है, (२) सामुद्रिक इंजीनियरी शिक्षण निदेशालय जहाँ सामुद्रिक इंजीनियरों को समुद्रगमन पूर्व का शिक्षण दिया जाता है, (३) नाविक तथा इंजीनियरी कालेज, बम्बई एवं सामुद्रिक इंजीनियरी कालेज, बलकत्ता, जहाँ नौकातल अधिकारियों और सामुद्रिक इंजीनियरों को समुद्रगमन पश्चात् शिक्षण

दिया जाता है, तथा (४) गोदी कर्मचारियों (Ratings) के लिए तीन शिक्षण पोत हैं। (मद्र शिक्षण पोत कलकत्ता में, मेखला शिक्षण पोत विशाखापत्तनम में और नीलकंठी शिक्षण पोत नवलखो स्थान पर सौराष्ट्र में)।

बन्दरगाह

जहाज परिवहन का सुचारु संचालन विकसित बन्दरगाहों और उन पर पर्याप्त स्थान एवं घाट सुविधाओं पर निर्भर है। इस समय देश में ६ बड़े बन्दरगाह हैं : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन और काँधला। इनकी कार्य-क्षमता २८८ लाख टन है : बम्बई, ११८ लाख टन, कलकत्ता ६२ लाख टन, मद्रास २४ लाख टन, कोचीन १८ लाख टन, विशाखापत्तनम २५ लाख टन तथा काँधला ११ लाख टन।

इन बड़े बन्दरगाहों के प्रतिरिक्त देश में लगभग २२५ छोटे बन्दरगाह हैं जिनमें से १५० चालू स्थिति में हैं और शेष सुप्तावस्था में। ये सब मिन कर लगभग ५० लाख टन व्यापार के लिये उत्तरदायी हैं। इनमें से १८ महत्त्व बन्दरगाह हैं और शेष छोटे। इन बन्दरगाहों का प्रबन्ध राज्य की सरकारों के ऊपर है। बन्दरगाहों के विकास कार्यों में केन्द्र और राज्य सरकारों के यत्नों में एकीकरण लाने के विचार से १९५० में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड स्थापित कर दिया था।

समस्याएँ

भारतीय जहाज परिवहन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी मुख्य समस्याएँ निम्नांकित हैं : (१) विदेशी जहाजों की प्रतियोगिता (२) ध्वजा भेदभाव, (३) जहाजों की मूल्य वृद्धि, (४) बढ़ते हुए संचालन व्यय, (५) तडाकपोतो, यात्री पीतो और ट्राम्प जहाजों का अभाव, (६) रेल प्रतियोगिता, (७) अम की अवरोधात्मक नीति, (८) विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ तथा (९) बन्दरगाहों पर स्थानाभाव एवं भीड़-भाड़ और जमघट।

भविष्य

सन् १९४७ से यह व्यवसाय उत्तरोत्तर उन्नति करता गया है। यद्यपि भारतीय जहाजों बेड़ा अभी विश्व के केवल ०.६६% के बराबर है जबकि भारत का विदेशी व्यापार विश्व का १३% है, तो भी हमारे बेड़े का ५५% दस वर्ष से कम अवस्था का है, जबकि विश्व के बेड़े का केवल ४६% ही दस वर्ष से कम आयु का है। जिस गति से हम उन्नति करते हैं वही गति से उन्नति करते रहें जो कि स्वाभाविक है तो कुछ ही काल में भारतीय वणिकपोत अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त कर सकता है।

“मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से विमान परिवहन सबसे नवीनतम, सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला तथा हमारे आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सबसे अधिक क्रान्ति लाने वाला है।”

—केयर एवं विलियम्स

२१—भारतीय विमान परिवहन

रूप-रेखा

१. प्राचीन विमान
२. आधुनिक विमान
३. विमान परिवहन की विशेषताएँ
४. भारत में विकास
५. राष्ट्रीयकरण
६. विमान परिवहन नियम
७. शिक्षण सुविधाएँ
८. उड़ान क्लब
९. हवाई अड्डे
१०. विमान परिवहन सम्झौते
११. भविष्य।

प्राचीन विमान

भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यहाँ प्राचीन काल में विमान द्वारा यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। देवता लोग बहुधा विमान द्वारा ही यात्रा करते थे। अयोध्या के लोक प्रिय राजा राम लंका से पृथ्वी विमान में बैठकर अयोध्या लौटे थे। उनकी सखी सेना भी उसी में बैठकर आई थी। इसमें तत्कालीन विमानों के आकार का भी अनुमान होता है। रामायण में कई स्थानों पर आकाश मार्ग से यात्रा करने का विवरण मिलता है।

गूनाती कषाम्रो मे भी विमान सम्बन्धी सकेत मिलते हैं। एक व्यक्ति ने मोम के पंख लगा कर जेल से भागने का प्रयत्न किया था। परियाँ उड़कर ही एक स्थान से दूसरे स्थान को सदैव जाती थी।

आधुनिक विमान

उन प्राचीन विमानों का अब कुछ भी अवशेष नहीं है। आधुनिक युग में उड़ने की ओर प्रथम प्रयत्न गुम्बारा द्वारा किया गया। जर्मनी के जैपलिन नामक विद्वान ने सर्व प्रथम इस यत्न में सफलता प्राप्त की और लोगों के समुख 'जैपलिन' नाम के विमान का २ जुलाई १९०० को प्रदर्शन किया। इसकी चाल २० मील प्रति घण्टा थी। जर्मनी की देखा-देखी अन्य देशों की भी इस ओर रुचि बढ़ी और बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में अनेक विमान बनाए गए। १७ दिसम्बर १९०३ को राइट ब्रादर्स ने प्रथम शक्ति-चालित विमान का आदर्श उपस्थित किया। १९१० में जर्मनी में विमानों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। धीरे-धीरे विश्व भर में इनका प्रचार हो गया और अब विमान डाक, माल और यात्री ले जाने के अतिरिक्त सेना का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।

विमान परिवहन की विशेषताएँ

विमान परिवहन एक नवीनतम साधन है जिसका गत चालीस वर्षों में ही विशेष विकास हुआ है। अब इसका महत्व दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है। इस महत्व वृद्धि के कारण इसके निराले गुण हैं।

(१) अधिक चाल इसका सबसे बड़ा गुण है। इसकी साधारण चाल रेल मोटर की चाल से दस गुनी है। १४००-१५०० मील प्रतिघण्टा की चाल से चलने वाले विमान सप्ताह में हैं। इनकी चाल दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। हाल में एक राकेट विमान ने २६५० मील की चाल प्राप्त कर ली है। (२) भौगोलिक बाधाओं का निराकरण इसका दूसरा बड़ा गुण है। बर, पर्वत, रेगिस्तान, दलदल, नदी, नाले, बर्फीले प्रदेश, समुद्र इत्यादि विमान के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते। (३) बहुमूल्य एवं सकटकालीन वस्तुओं के परिवहन, (४) औद्योगिक विकेन्द्रीकरण, (५) औद्योगिक प्रबन्ध, (६) व्यापारिक विकास-विस्तार, (७) सैनिक सेवा, (८) शांति स्थापन, तथा (९) स्वास्थ्य, कृषि व वन रक्षा के दृष्टिकोण से भी विमान की सेवा अद्वितीय है।

भारत में विमान परिवहन का विकास

अद्यपि प्रयोगात्मक उड़ानें १९११ में ली जाने लगी थी, किन्तु आधुनिक विमान परिवहन का वास्तविक आरम्भ भारत में सन् १९२७ में हुआ जब कि भारत सरकार ने अपने नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की। तभी से यहाँ हवाई भ्रमों बनने लगे और सरकारी सहायता से उड़ान क्लब स्थापित होने लगे। १९२९ में ब्रिटेन, फ्रांस तथा हॉलैंड की साम्राज्य वायु-सेवा के आगमन पर यहाँ अनुसूचित विमान

सेवा का प्रथम बार आविर्भाव हुआ। आगामी दस वर्ष में देश में तीन विमान कम्पनियाँ बनी जो डाक और यात्री ले जाने लगी। इनमें से एयरसर्विसेज आफ इण्डिया नामक कम्पनी जो १९३६ में बनी थी १९३९ में बन्द हो गई। इस भाँति द्वितीय युद्ध से पूर्व केवल दो कम्पनियाँ विमान सेवा दे रही थी। प्रथम ताता सन्स लिमिटेड थी जो १९३२ में बनी थी और दूसरी इण्डियन नेशनल एयरवेज लि० थी जो १९३३ में बनी थी। ये भारतीय कम्पनियाँ साम्राज्य वायु सेवा के केवल एक उपाग के समान थी। उनका स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था।

द्वितीय युद्ध काल में इन कम्पनियों को अच्छा अवसर मिला। ये देश-रक्षा और सरकारी काम में लग गईं। अधिक मार्गों पर एवं अधिक घनत्व के साथ उनके विमान चलने लगे। युद्ध सम्बन्धी कई विशेष कार्य भी उन्हें सौंपे गए, दक्षिणी अरब वायु मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया, इराक को सेना, अस्त्र-सस्त्र, एवं अन्य युद्ध सम्बन्धी सामग्री भिजवाई गई; ब्रह्मा से शरणार्थियों को मंगाया गया इत्यादि। इन सेवाओं के बदले भारत सरकार ने उन्हें अच्छा पारिश्रमिक दिया जिससे कम्पनियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो गई। १९३९ और १९४५ के बीच उड़ाने १७ लाख से ३३ लाख, यात्री ३५ हजार से २४ हजार तथा माल यातायात ९८ हजार पौंड से बढ़कर ८५ लाख पौंड हो गया। इस भाँति युद्ध काल में भारतीय कम्पनियों को अपनी स्थिति सुधारने, अनुभव प्राप्त करने, नए जहाज चलाने और विमान चालकों और अन्य लोगों को शिक्षा देने का स्वर्ण अवसर मिला। इससे उनका कार्य कौशल बढ़ा और मान वृद्धि भी हुई। अब यह व्यवसाय बड़ा आकर्षक एवं लाभ कर माना जाने लगा।

युद्धोत्तर काल में विमान सेवा पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक समझ कर जुलाई १९४६ में विमान परिवहन लाइसेन्स बोर्ड की स्थापना की गई। १९४७ के प्रारम्भ तक इस बोर्ड ने २१ कम्पनियों को लाइसेन्स दे दिए, यद्यपि देश में ४ से अधिक कम्पनियों के लिए काम नहीं था। देश विभाजन के कारण कुछ दिन इन्हे काम मिलता रहा, किन्तु तदुपरान्त इन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति गिरने लगी। अप्रैल १९४९ में सरकार ने डाक का वायु महसूल बन्द कर दिया, मार्च १९४९ में तेल के प्रायात कर में ६ आने गैलन छूट दे दी जिसे कालान्तर में बढ़ाकर ९ आने गैलन कर दिया तथा कम्पनियों को ४० लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देने लगी। तो भी स्थिति गिरती ही गई और सरकार को एक जाँच समिति नियुक्त करनी पड़ी।

राष्ट्रीयकरण

फरवरी १९५० में भारत सरकार ने विमान परिवहन जाँच समिति विठाई जिसने सितम्बर में अपने सुझाव उपस्थित करते हुए विमान कम्पनियों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के कारणों पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीयकरण के गुण-दोषों पर सविस्तार विचार किया। समिति के सुझावों पर लगभग दो वर्ष तक गम्भीरतापूर्वक विचार होना रहा। जनवरी १९५१ में भारत सरकार द्वारा बुलाए गए एक विमान चालकों

के सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ तथा १९५२ में योजना आयोग ने भी इस प्रश्न पर सविस्तार विचार किया। अन्त में जून १९५३ में विमान परिवहन निगम कानून बनाकर विमान सेवा के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। इसके मुख्य लाभ निम्नांकित बताए गए - (१) कार्य-केन्द्रों, साज-सज्जा तथा कर्मचारी वर्ग का अधिकतम उपयोग, (२) देश-रक्षा एवं सकृत्कालीन प्रयोग, (३) उच्च कोटि की एवं सस्ती-सेवा, (४) दूरदर्शितापूर्ण नीति-निर्माण, (५) नए आविष्कारों से लाभ उठाना, (६) स्थायी व्यय में कमी इत्यादि।

विमान परिवहन निगम

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त विमान सेवा-संचालन के लिए दो निगम स्थापित की गईं। एक भारतीय विमान परिवहन निगम और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय विमान निगम। प्रथम देश के अन्तर्गत और द्वितीय देश के बाहर सेवा प्रदान करती है। प्रथम का मुख्यालय नई दिल्ली और द्वितीय का बम्बई है। भारतीय विमान निगम बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली केन्द्रों से अपनी सेवा संचालित करती है। दोनों निगम स्वायत्त संस्थाएँ हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में काम करती हैं। दोनों के बीच एकीकरण स्थापित करने के लिए विमान परिवहन परिषद की स्थापना की गई है। प्रत्येक निगम की एक-एक सलाहकार समिति तथा एक-एक ध्रम समिति है। अन्तर्राष्ट्रीय विमान निगम १९ देशों को विमान सेवा से जोड़ती है।

शिक्षण सुविधाएँ

इलाहाबाद (बमरोली) में विमान सेवा सम्बन्धी विविध प्रकार के अधिकारियों को शिक्षण देने का केन्द्र है जहाँ विमान चालक, विमान इन्जिनियर, हवाई भट्टे अधिकारी, नियंत्रण संचालक, अग्नि संचालक, रेडियो संचालक, रेडियो-शिल्पी, तथा चालक शिक्षक इत्यादि पदाधिकारियों के लिए शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ से प्रति वर्ष लगभग ३०० शिक्षार्थी शिक्षण पाकर निकालते हैं।

उड़ान क्लब

देश में १६ सरकारी सहायता प्राप्त उड़ान क्लब हैं। इनके प्रतिरिक्त पूना, बंगलौर और इलाहाबाद में तीन सरकारी उप-उड़ान केन्द्र (Gliding Centres) और नई दिल्ली व पिलानी में दो सरकारी सहायता प्राप्त उप-उड़ान केन्द्र और हैं। इन केन्द्रों में भी विमान चालकों को शिक्षण सुविधाएँ प्राप्त हैं।

हवाई भट्टे

भारत सरकार का नागरिक उड्डयन विभाग ८५ हवाई भट्टों का नियंत्रण और संचालन करता है। इनमें से तीन, बम्बई (शान्ताक्रूज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली (पालम) अन्तर्राष्ट्रीय भट्टे हैं और शेष राष्ट्रीय। हल्द्वानी (उ० प्र०), तुलीहल (मनीपुर), रक्सौल (बिहार), जोगबनी (बिहार) और बिहाला (प० बंगाल) पाँच नए भट्टे और बन रहे हैं।

विमान परिवहन समझौते

अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, संथा, मिश्र, फ्रांस, इटली, जापान, लेबनान, नीदरलैंड, पाकिस्तान, फिलिप्पाइन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इराक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस के साथ भारत के विमान परिवहन सम्बन्धी समझौते हो चुके हैं।

भविष्य

विमान इस युग का एक विलक्षण साधन है। इसका प्रयोग दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश के लिए उसकी सेवा का लाभदायक उपयोग संभव है। भारत आज अपने पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। इस राजनीतिक, प्रायिक एवं सामाजिक पुनर्गठन के महान कार्य को सफल बनाने के लिए विमान-सेवा का बहुमुखी प्रयोग संभव है। अतएव इस देश में उसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। भारत के भविष्य के बनाने में विमान की निम्नांकित सेवाएँ लाभदायक हैं : (१) सोना, चाँदी, सरकारी ऋण पत्र इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं का परिवहन, (२) वायदा व्यापार बढ़ाने में, (३) संकटकालीन (बाढ़, अकाल, भूचाल, रोग, भू-गतन) वस्तुओं का परिवहन, (४) भौद्योगिक प्रवन्ध, (५) ताजे फलों का व्यापार-विस्तार, (६) सर्वेक्षण, तथा (७) आन्तरिक शान्ति।

विमान का प्रयोग फसलों के रोग निवारण, टिट्टी से बचाव, वन रक्षा, स्वास्थ्य सुधार के लिए भी किया जा सकता है।

इस समय विमान सेवा की ६०% भाग यात्री यातायात से प्राप्त होती है। अतएव विमानों का निर्माण केवल यात्री यातायात को सुख-सुविधाओं का ध्यान रख कर किया जाता है। अब ऐसे विमान बनाने का यत्न किया जा रहा है जो केवल माल से जायेंगे। यह आशा की जाती है कि १९६१ में ऐसे विमान बन कर चलने लगेंगे और माल का विमान भाड़ा लगभग ४०% कम हो जाएगा। भाड़े में ४०% कमी से माल की मात्रा में ३०० से ५००% की वृद्धि की संभावना है। ऐसे विमानों के बनने से वह माल जो अब महीने में उपभोक्ता अथवा विक्रेता के पास पहुँचता है कुछ दिनों में ही पहुँचने लगेगा। फुटकर विक्रेताओं को तब बहुत कम माल संचय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक सप्ताह की विक्री से अधिक माल भण्डारों में भरने की आवश्यकता न रहेगी। नाशवान पदार्थों का बाजार हज़ारों मील के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाएगा। भारतीय ग्राम विमान द्वारा ब्रिटेन जाने भी लगे हैं। उन्हें हम नए जहाजों से और अधिक मात्रा में यूरोप और अमेरिका की राजधानियों के नगरों में नियमित रूप में भेजने लगेंगे। कुछ अत्यन्त कोमल यंत्र-उपकरण होते हैं जिनके रेल अथवा जहाज से भेजने के लिए बड़े कीमती संवेष्टन की आवश्यकता होती है। नए विमानों से इन यंत्रों को सस्ते संवेष्टन द्वारा भेजा जा सकेगा। यह उद्योगपति के लिए भारी सुविधा की बात होगी।

५. सामाजिक सेवाएँ
 - (क) शिक्षा प्रसार
 - (ख) स्वास्थ्य सुधार
६. योजना की प्रगति
 - (क) प्रथम योजना
 - (ख) द्वितीय योजना
 - (ग) तृतीय योजना के द्येय ।

नियोजन का आविर्भाव

प्राथमिक नियोजन का जन्मदाता रूस है । राजनैतिक क्रान्ति में सफल होने के उपरान्त रूस ने प्राथमिक क्रान्ति की ओर पग बढ़ाया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने प्राथमिक विकास का पंचवर्षीय कार्यक्रम उठाया । इस कार्यक्रम में उ-हे अपूर्व सफलता प्राप्त हुई । प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम के सफल होने के उपरान्त कालान्तर में ऐसे ही पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाये । अब तक वहाँ ७ पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जा चुकी हैं, यद्यपि अन्तिम योजना की अवधि ५ वर्ष के स्थान पर ७ वर्ष करदी गई है ।

घोर प्राथमिक मंदी के वर्षों में रूस की उत्पादन वृद्धि और प्राथमिक सफलता ने पूँजीवादी देशों को आश्चर्य में डाल दिया । अतएव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एवं अन्य पूँजीवादी देशों ने प्राथमिक नियोजन के पंचवर्षीय कार्यक्रम के प्रयोग किये । यद्यपि पूँजीवादी देशों ने ये कार्यक्रम उतने सफल नहीं हुये जितने रूस के । तो भी पंचवर्षीय योजना प्राथमिक विकास का एक सार्वभौमिक साधन माना जाने लगा ।

भारत जैसे परतत्र एवं पिछड़े हुये देश का भी इस ओर ध्यान गया । अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सत्यावधान में १९३८ में राष्ट्रीय नियोजन समिति नियुक्त हुई जिसने देश के साधनों का पूर्ण उपयोग करने नियोजित प्राथमिक विकास पर जोर दिया । द्वितीय विश्व युद्ध-काल में भारत सरकार ने कई पुनर्निर्माण समितियाँ बनाईं और जुलाई १९४४ में एक नियोजन विभाग (Department of Planning) की स्थापना की । इन्हीं वर्षों में कई गैर सरकारी योजनाएँ भी बनाई गईं जिनमें से चम्बई योजना, जन-योजना एवं गांधी योजना विशेष उल्लेखनीय हैं ।

उपर्युक्त योजनाएँ युद्धोत्तर कालीन पुनर्निर्माण के निमित्त बनाई गई थी । देश के स्वतन्त्र होने के उपरान्त हमारा ध्यान देश के दीर्घकालीन विकास की ओर गया । इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ जिसमें देश के दीर्घकालीन विकास का मार्ग बतलाया । मार्च १९५० में भारत सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) की नियुक्ति की जिसे देश के साधनों के पूर्ण और संतुलित प्रयोग द्वारा योजना बनाने का काम सौंपा गया । योजना आयोग ने जुलाई

लक्ष्य की प्राप्ति है। ये लक्ष्य राष्ट्रीय भाव, प्रति व्यक्ति भाव और भार्यिक संतुलन से सम्बन्धित हैं।

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमने अनुमान लगाया था कि सन् १९७१-७२ तक हमारी राष्ट्रीय भाव दुगुनी हो जायेगी, किन्तु द्वितीय योजना में हमारा यह लक्ष्य सन् १९६७-६८ तक प्राप्त होने की सम्भावना बताई गई।

(ख) इसी भांति प्रथम योजना में सन् १९७७-७८ तक प्रति व्यक्ति भाव दुगुनी होने का अनुमान लगाया गया था। द्वितीय योजना में उसे सन् १९७३-७४ तक ही प्राप्त कर लेने की सम्भावना बताई गई।

(ग) देश की अर्थ व्यवस्था को संतुलित रूप देने के विचार से हमने सन् १९७५-७६ तक राष्ट्रीय भाव में कृषि का अनुपात १९-७० से घटा कर ६०% करने का लक्ष्य अपनाया है। इस भांति हम अपनी राष्ट्रीय और व्यक्तिगत भाव को उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएंगे और साथ-साथ देश वासियों का जीवन स्तर ऊँचा होता चला जायेगा।

विकास व्यवस्था एवं पूर्वाधिकार

ऊपर बताये गये उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि लोगों का उपभोग्य-स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाये। इसके लिये निरन्तर उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता है। इस विकास व्यवस्था को इस भांति हमें आयोजित करना है कि देश की अर्थ-व्यवस्था तीव्रता से आगे बढ़ते हुये स्वावलम्बन और स्वतन्त्र विकास की स्थिति प्राप्त कर सके। इसके लिये निम्नांकित बातें आवश्यक हैं।

(क) विनियोग दर—विनियोग की दर उत्तरोत्तर ऊँची होती जानी चाहिये। प्रथम योजना काल में पूँजी विनियोग की दर ५ प्रतिशत से बढ़कर ७ प्रतिशत हो गई। द्वितीय योजना के अन्त में इसे ११%, तृतीय के अन्त में १४%, चतुर्थ के अन्त में १६% और पंचम योजना के अन्त में १७% तक बढ़ा लेने का अनुमान है।

(ख) मूल एवं भारी उद्योग—प्रगतिशील विकास के लिये यह आवश्यक है कि इस्पात, कोयला, शक्ति एवं मशीन निर्माण इत्यादि आधार-भूत उद्योगों को दृढता के साथ स्थापित किया जाय। इन उद्योगों की उन्नति और विकास के बिना हमारे देश के समुचित औद्योगीकरण के स्वप्न पूरे नहीं हो सकते।

(ग) कृषि—जिन क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों के उपयोग से अधिकतम उन्नति सम्भव है, उन क्षेत्रों में पूर्णतम भौतिक विकास की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास, स्थानीय साधनों और ग्रामीण जनता के अधिकधिक उपयोग से सम्बद्ध है। वर्तमान स्थिति में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन सर्वोपरि प्रश्न है। साथ-साथ हमें कृषि के विविधीकरण और गहन कृषि की ओर भी ध्यान देना है। खाद्यान्न के उत्पादन के अतिरिक्त देश के पशुधन की उन्नति, दुग्ध पदार्थों का उत्पादन

समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाया। प्रथम योजना के प्रारम्भ से द्वितीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में ४२%, प्रति व्यक्ति आय में २०%; प्रति व्यक्ति उपभोग में १६%, कृषि उत्पादन में ४०%, औद्योगिक उत्पादन में ५१% की वृद्धि हुई। लोहे-इस्पात के उत्पादन में ६३%, मशीनों के उत्पादन में ४००%, रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में २०० प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई। अनेक उद्योगों का विस्तार किया गया और कई नये उद्योग स्थापित किये गये। देश की अर्थ-व्यवस्था विकास क्रम के पथ पर दृढ़ता के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है।

तृतीय योजना द्वितीय की अपेक्षा लगभग दुगुनी बनाई गई है और इसमें पहले से अधिक सफलता की भी सम्भावना है। आगामी योजनाएँ भी इसी भाँति बड़ा रूप धारण करती जाएँगी।

- (१) "तीसरी पंचवर्षीय योजना, हमारे बुनियादी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के क्षेत्र में एक कठिन परिस्थिति की परिचायक है।" —बी० टी० कृष्णमाचारी
- (२) "तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि देश आत्म-चालित ढंग से प्रगति करने के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाए। मूलतः प्रगति को आत्म-चालित बनाने का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में वचत और पूंजी-विनियोग की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि राष्ट्र की आय में निरन्तर और अधिकाधिक वृद्धि होती चली जाए।" —योजना आयोग

२३— तृतीय पंचवर्षीय योजना

रूप-रेखा

१. प्रथम पंचवर्षीय योजना
 - (क) उद्देश्य
 - (ख) व्यय
 - (ग) सफलता
 - (घ) विफलता
२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
 - (क) उद्देश्य
 - (ख) व्यय
 - (ग) सफलता
 - (घ) विफलता
३. तृतीय पंचवर्षीय योजना
 - (क) उद्देश्य
 - (ख) व्यय

(ग) साधन

(घ) विकास कार्य और लक्ष्य

मार्च १९५० में योजना आयोग की नियुक्ति के उपरान्त भारतवर्ष में पंच-वर्षीय योजनाओं का आविर्भाव हुआ। अब तक दो पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और तृतीय योजना का कार्यकम बनाया जा चुका है। इस योजना को समझने के लिये प्रथम और द्वितीय योजनाओं की पृष्ठ भूमि, उद्देश्य, लक्ष्य एवं प्रगति इत्यादि समझ लेना आवश्यक है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

१ अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च १९५६ तक प्रथम योजना की अवधि मानी गई है। यद्यपि इसका कार्यकम १ अप्रैल १९५१ से प्रारम्भ हो गया था, किन्तु योजना का प्रारूप (Draft) जुलाई १९५१ में और अन्तिम स्वरूप दिसम्बर १९५२ में प्रकाशित हुआ।

उद्देश्य—(१) इस योजना का मुख्य उद्देश्य युद्ध और देश-विभाजन जनित असंतुलन को मिटाकर देश की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। इसी कारण इस योजना को पुनर्स्थापन योजना (Rehabilitation Plan) कहा जाता है।

(२) देश का बहुमुखी एवं संतुलित विकास करना और एक विकास-क्रम को जन्म देना इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य था। विकास द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार आवश्यक समझा गया।

(३) देश के सामने उस समय अनेक समस्याएँ थीं। जिनमें खाद्य, वस्त्र, मुद्रा स्फीति, औद्योगिक कच्चे माल, व्यापारिक घाटे इत्यादि उल्लेखनीय हैं। विस्थापितों की समस्या और औद्योगिक क्षमता के उपयोग की समस्या भी कम महत्व की नहीं थीं।

ध्यय—योजना के मूल अनुमान के अनुसार २०६६ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया था जिसे कालान्तर में बढ़ाकर २३५६ करोड़ रुपये करना पड़ा। यह अनुमान केवल सरकारी क्षेत्र के थे। सरकारी क्षेत्र में वास्तविक व्यय १९६० करोड़ रुपये हुआ। व्यक्तिगत क्षेत्र में १८०० करोड़ रुपये के विनियोग का अनुमान लगाया गया है। इस भाँति ३७६० करोड़ रुपये इस योजना पर व्यय हुये।

सफलता—इस अवधि में राष्ट्रीय आय में १८% और प्रति व्यक्ति आय में ११% की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन १९% और औद्योगिक उत्पादन ४०% अधिक हो सका। खाद्यान्न में उत्पादन में ३०%, रई में ३७.३% और जूट के उत्पादन में २८% की बढ़ोत्तरी आई। खाद्य, वस्त्र, मुद्रा स्फीति औद्योगिक कच्चे माल एवं विस्थापितों की समस्याओं पर देश धावू बन सका। अर्द्ध-प्रयुक्त औद्योगिक क्षमता का भी अधिकतम उपयोग किया गया। देश में आघातभूत उद्योगों की नींव पड़ी।

सफलता—द्वितीय योजना काल में देश की राष्ट्रीय आय २०% और प्रति व्यक्ति आय ६% बढ़ी, कृषि उत्पादन २१% अधिक हो गया; खाद्यान्न के उत्पादन में २५% और अन्य कृषि जन्य पदार्थों के उत्पादन में १६% की वृद्धि आई गई। औद्योगिक उत्पादन ३३% अधिक हो गया। मशीनों का उत्पादन ११५% अधिक हो गया। देश में कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों की नींव पड़ी। सरकारी क्षेत्र में राउर केला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई और उन्होंने उत्पादन प्रारम्भ किया। राची के निकट हतिपा नामक स्थान पर भारी मशीनें बनाने के कारखाने और भोपाल में बिजली के बड़े कारखाने की नींव पड़ी। कोयला धोने के दो कारखाने (दुम्दा और भोपू डीह) और देश का दूसरा डी० डी० टी० का कारखाना (मन्दाये) एवं लोन नए खाद बनाने के कारखाने खोले गये। एक दर्शन यन्त्रों के शीशे बनाने का कारखाना नैनी में खोला गया जिसे अब दुर्गापुर ले जाया गया है।

विफलता—द्वितीय योजना के प्रारम्भ में ही कुछ लोगों ने इसे आशावादी योजना कहा था। अनुभव से यह बात पूर्णतः सिद्ध हो गई। सन् १९५८ में विदेशी विनिमय, विदेशी सहायता और अन्य अनेक कारणों से योजना में दो बार संशोधन करने पड़े और केवल (Core) योजना के मूल भाग को पूर्ण करने का निश्चय किया गया। इसी वर्ष खाद्यान्न के भाव एक आश्चर्यजनक सीमा तक चढ़ गये। इसका कारण आवश्यकता से अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उपयोग बताया गया। हमारी खाद्य समस्या, बेकारी की समस्या और मकानों की समस्या भयानक रूप धारण करके हमारे सामने आ खड़ी हुई। परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी देश के विकास कार्यों में बाधा उपस्थित करने लगी। देश में कई आवश्यक वस्तुओं (लोहा इस्पात, सीमेन्ट, चीनी, वस्त्र) का अभाव हमें खलने लगा। ग्रामीण वातावरण अत्यन्त दूषित हो गया, हिंसा, अपराध, भ्रम, चोरी-डकैती बढ़ते दिखाई दिए। प्रशासन कार्य ढीला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार युक्त बताया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने में देश को अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा तो भी अपनी समस्याओं के साथ उलझने और उन्हें यथाशक्ति सुलझाने की शक्ति हमें प्राप्त हुई। उलझनों के बीच साहस के साथ आगे बढ़ने का हमें अनुभव हुआ। इसी साहस और अनुभव से प्रेरणा लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना को द्वितीय की अपेक्षा ड्योढ़ी बनाने का हमने निश्चय किया। इसका प्रारम्भ १ अप्रैल सन् १९६१ से हुआ और ३१ मार्च सन् १९६६ को यह समाप्त होगी।

उद्देश्य—(१) द्वितीय योजना की भांति ५% प्रति वर्ष अर्थात् योजना काल में २५% राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना इसका प्रथम उद्देश्य है।

(२) खाद्यान्न के उत्पादन में स्वावलम्बन की स्थिति प्राप्त करने की आशा की गई है। कृषि उत्पादन में ऐसी सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जायेगा कि देश की औद्योगिक कच्चे माल की मांग पूर्ति होने के उपरान्त देश की निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके।

(३) औद्योगीकरण सम्बन्धी योजनाओं को इन योजना में वही महत्त्व दिया जायगा जो उन्हें द्वितीय योजना में दिया गया। इस्पात, शक्ति एवं ईंधन उद्योगों का यथासम्भव विस्तार किया जायगा। मशीन निर्माण उद्योग की इस भांति उत्पत्ति और विकास किया जायगा कि भाग्यो १० वर्ष में देश के औद्योगीकरण की मांग देश के उत्पादन से ही पूरी की जा सके।

(४) कार्य के साधनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करके देश को जन-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने का यत्न किया जायगा।

(५) आर्थिक शक्ति के समान विनरग्न द्वारा आय और सम्पत्ति सम्बन्धी विषमता दूर की जायगी और समाजवाद की ओर देश को आगे बढ़ाया जायगा।

व्यय—इस अवधि में १०,४०० करोड़ रुपए के विनियोग व्यय का अनुमान लगाया गया है। ६३०० करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में और ४,१०० करोड़ रुपए गैर-सरकारी क्षेत्र में खर्च होंगे। सरकारी क्षेत्र में कुल ७५०० करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है जिसमें से १२०० करोड़ रुपए विकास व्यय के हैं और ६३०० करोड़ रुपए विनियोग के। दोनों क्षेत्रों के विनियोग व्यय का विषयानुसार वितरण निम्न भांति होगा :

क्रम संख्या	विषय	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	कुल	कुल का प्रतिशत
		करोड़रुपये	करोड़रुपये	करोड़रुपये	
१	कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास	१३१०	८००	२११०	२०
२	शक्ति	१०१२	५०	१०६२	१०
३	उद्योग (छोटे-बड़े) व खनिज	१६७०	१३२५	२९९५	२९
४	परिवहन व संवहन	१४८६	२५०	१७३६	१७
५	सामाजिक सेवाएँ	६२२	१०७५	१६९७	१६
६	अन्य	२००	६००	८००	८
	कुल जोड़	६,३००	४,१००	१०,४००	१००

साधन—सरकारी क्षेत्र का अनुमानित व्यय निम्न साधनों से जुटाया जायगा :

करोड़ रुपये

(१) वर्तमान करों से आय

५५०

(२) रेलों का अनुदान

१००

(३) अन्य सरकारी उद्योगों का लाभ	४५०
(४) सार्वजनिक ऋण	८००
(५) अल्प बचत	६००
(६) निर्वाह निधि (P. F.) अन्य पूंजीगत आय	५४०
(७) अतिरिक्त कर और लाभ	१७१०
(८) विदेशी सहायता	२२००
(९) घाटे की वित्त व्यवस्था	५५०
कुल जोड़	७५००

विकास-कार्य और लक्ष्य—देश की माँग और छाषणों की उपलब्धि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विकास लक्ष्य नीचे दिए जाते हैं।

उत्पादन और विकास के लक्ष्य

वस्तु	इकाई	१९६०-६१	१९६५-६६	प्रतिशत वृद्धि
१. खाद्यान्न	लाख टन	७६०	१०००	३१.५
२. कपास	लाख गॉटें	५१	७०	३७.२
३. चीनी (गुड़)	लाख टन	८०	१००	२५.०
४. तिलहन	लाख टन	७१	९८	३८.०
५. बिजली	लाख किलोवाट	५७	१२७	१२३
६. कच्चा लोहा	लाख टन	१०७	३००	१८०
७. कोयला	„ „	५४६	९७०	७६
८. इस्पात	„ „	३५	९२	१६३
९. अल्यूमिनियम	हजार टन	१८.५	८०	३३२
१०. मशीनों यंत्र	मूल्य लाख रु०	५५०	३०००	४४५
११. मोटर गाड़ियाँ	हजार	५६५	१००	८७
१२. सूती वस्त्र	करोड़ गज	५१३	५८०	१३

योजना में छोटे-बड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यद्यपि कृषि क्षेत्र को भी भुलाया नहीं जाएगा। सभी आवश्यक उद्योगों (इस्पात, कोयला, बिजली) का प्रसार किया जाएगा और अनेक नए उद्योग स्थापित किए जायेंगे। दो नए बिजली की भारी मशीनें बनाने के कारखाने, दो कोयला घरे के कारखाने, एक इस्पात का

कारखाना, एक जहाज बनाने का कारखाना इत्यादि का समावेश योजना में किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक खाद का कारखाना, प्रत्येक जिले में एक दुग्धशाला (Dairy farm) तथा सभी गाँवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना के अन्त तक पहुँच जाएगा। खनिज तेल के अन्वेषण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। थर्मामीटर, घड़ियाँ, मोटर साइकिलें बनाने के उद्योग प्रथम बार देश में स्थापित किए जायेंगे।

तृतीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय १६००० करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय ३८५ रु० हो जाएगी। प्रथम योजना के प्रारम्भ की अपेक्षा कृषि उत्पादन में १७५% और औद्योगिक उत्पादन में ३२९% की वृद्धि हो जाएगी।



“सामुदायिक योजनाएँ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ कल्याण-कारी शासन की ओर जिसका हमने बीडा उठाया है स्वतंत्रता के समय से सबसे बड़ी देन हैं।”
—ऐस० के० डे

२४-सामुदायिक विकास योजनाएँ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ

रूप-रेखा

१. ग्राम सुधार की आवश्यकता
२. योजनाओं का अर्थ एवं उद्देश्य
३. योजना का स्वरूप एवं संगठन
४. कार्यक्रम
५. प्रारम्भ और प्रगति
६. आलोचना ।

ग्राम सुधार की आवश्यकता

भारत गाँवों का देश है। यहाँ की ८२% जन-संख्या गाँवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र खालान्न और अन्य जीवनोपयोगी पदार्थ ही नहीं देते, औद्योगिक कचरे माल के भी प्रधान उद्गम हैं।

हमारे इन गाँवों की दशा अत्यन्त सोचनीय है। कृषि उपज प्रति न्यून है। लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। वैगनस्प, ईर्ष्या-द्वेष, मुकद्दमेबाजी, रुढ़िवाद और अन्य सामाजिक कुरीतियों के वे ग्रहें बन गये हैं। सारा ग्रामीण जीवन अभाव, कंगाली, निराशा, निरुत्साह से परिपूर्ण है और चारों ओर उदासीनता छाई हुई है।

यदि हमे अपने देश की उन्नति बाछनीय है तो ग्रामीण जीवन का सुधार उसकी पहली सीढ़ी है। १३% जन संख्या के सुधार मात्र से हमारा देश समृद्ध और समुन्नत नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करके हमारी अर्थ-व्यवस्था संतुलित रूप धारण नहीं कर सकती। वस्तुतः भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।

योजनाओं का अर्थ एवं उद्देश्य

सामुदायिक विकास योजनाएँ ग्रामीण समुदाय के बहुमुखी विकास की योजनाएँ हैं। ग्रामीण जीवन के किसी एक पहलू के सुधार से ग्राम सुधार सम्भव नहीं। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य सभी पहलुओं के सुधार द्वारा ही ग्रामीण जीवन में आशा का संचार सम्भव है। केवल आर्थिक पहलू ही सब कुछ नहीं है। हमें ग्राम समाज में आत्म-सम्मान और स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करके ग्रामीण जीवन में महत्वाकांक्षा और उत्साह उत्पन्न करना है। कृषि सुधार के साथ-साथ परिवहन, उद्योग, आवास व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन इत्यादि की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार का सर्वाङ्ग पूर्ण एवं सतुलित विकास इन योजनाओं का मुख्य ध्येय है।

एक ओर उत्पादन वृद्धि और कार्य के साधन उपलब्ध करके ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना इन योजनाओं का उद्देश्य है तो दूसरी ओर उनमें स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास, आत्म-सम्मान और आशा का संचार करके उन्हें देश के सभ्य नागरिक बनाना है। यह तभी सम्भव है जबकि ग्रामीण जीवन की सामाजिक कुरीतियों, अन्ध-विश्वास, छुड़वा, भाग्यवाद हटाकर उनमें जाग्रति उत्पन्न की जाय और राजनैतिक अधिकार देकर उन्हें उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाया जाय। इसके लिये शिक्षा प्रसार और आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

योजना का स्वरूप एवं संगठन

योजनाओं का कार्यक्रम लागू करने के लिये सौ गाँवों की एक इकाई मान ली जाती है जिसमें लगभग १५० वर्गमील क्षेत्रफल और ६०-७० हजार आबादी आजाती है। इसे विकास खण्ड कहा जाता है। खण्ड पंचायत समिति इसका कार्यक्रम बनाने के लिये उत्तरदायी है। समिति के सदस्य निर्वाचित सरपंच होते हैं। इस समिति की देख रेख में एक खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) और ८ विस्तार अधिकारी (Extension Officers) कार्य करते हैं। ये अधिकारी प्रबन्ध प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं। प्रत्येक अधिकारी किसी विशेष विषय (कृषि, सहकारिता, पशु पालन, इत्यादि) का विशेषज्ञ होता है। प्रत्येक १० गाँवों के समूह में एक ग्राम सेवक (V. L. W.) होता है। यह बहुउद्देशीय विस्तार प्रतिनिधि माना जाता है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती है जिसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इनमें खण्ड पंचायत समिति के अध्यक्ष और उस जिले के लोक सभा एवं विधान मंडल के सदस्य सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक राज्य में विकास आयुक्त सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। उसकी सहायता के लिये राज्य विकास समिति होती है जिसका कि सभापतिस्व उस राज्य का मुख्य मंत्री करता है। केन्द्र में सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय पर इन योजनाओं का पूर्ण उत्तरदायित्व है। नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक केन्द्रीय समिति होती

है जिसका महापतिव्य प्रधान मंत्री करते हैं। योजना आयोग के सदस्य साध एवं कृषि विभाग और सामुदायिक व सहकारिता के मंत्री इसके सदस्य होते हैं।

कार्यक्रम

बहुउद्देशीय योजनाये होने के नाते इनका बहुमुखी कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। भाषिक उत्थान के साथ-साथ प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण और सामाजिक जागृति भी इन योजनाओं का उद्देश्य है। कृषि विकास एवं उत्पादन वृद्धि इन योजनाओं का प्रथम लक्ष्य है। भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था, उत्तम बीज, आधुनिक यंत्र एवं उर्वरक, अच्छा नस्ल के पशु, फसल रक्षा इत्यादि द्वारा कृषि सुधार की व्यवस्था की जाती है। भारतीय कृषि किमान को वर्ष भर कार्य नहीं दे पाती और उसके चिये आवर्तक आय का साधन भी नहीं है। अतएव किसान को खाली समय के लिये काम देने और वेकारों के जीवन निर्वाह के साधन उपस्थित करने के विचार से आभीष्ट उद्योगों के पुनर्जीवन एवं विकास की व्यवस्था की जाती है। गाँवों में आधुनिक जीवन की मुख सुविधाओं के अभाव का मुख्य कारण परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है। इस कमी को पूरा करने के निमित्त सड़क निर्माण एवं सुधार की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाता है। इस कार्य में लोगों के श्रमदान से बड़ी सहायता मिलती है। ग्राम्य समाज का पिछड़ापन मुख्यतः प्रशिक्षा के कारण है। एक ओर प्रौढ़ शिक्षा द्वारा लोगों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है, दूसरी ओर शिक्षा के प्रसार एवं निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ औद्योगिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की सफाई पर भी विशेष जोर दिया जाता है। गलियों और नालियों की नियमित स्वच्छता, कूड़ा-कचरा ढालने की उचित व्यवस्था और शौचालय इत्यादि का प्रबन्ध इस सम्बन्ध में आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि हमारे गाँवों में मकानों का अभाव नहीं है किन्तु वहाँ की आवास व्यवस्था बैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य-वर्धक नहीं है। अतएव कुछ नमूने के मकान बनवाकर एवं लोगों को आवश्यक प्राविधिक परामर्श देकर स्वास्थ्यप्रद मकान बनाने का प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान की जाती है। ऐसे स्वस्थ वातावरण में रहने से लोगों की अनेक रोगों से बहुत कुछ मुक्ति मिल सकेगी। तो भी उनके स्वास्थ्य सुधार के निमित्त चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। प्रसूति साहाय्य पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि इससे हमारे गाँव सर्वथा वंचित हैं। समाज कल्याण को व्यवस्था भी इस कार्य-क्रम का एक अंग है। मेने और प्रदर्शिनियों द्वारा सामाजिक सम्पर्क बढ़ाने तथा रेडियो और चलचित्र द्वारा मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। खेल-कूद, गोष्ठी, प्रसाठे इत्यादि भी चालू किये जाते हैं।

प्रारम्भ और प्रगति

सन् १९२६ में राजकीय कृषि आयोग ने ग्राम सुधार की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और ग्राम्य पथ प्रदर्शक नियुक्त करने की बात कही थी।

सन् १९५० में तटवर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारत के लिये विस्तार सेवाओं की बात कही। योजना आयोग के बनने पर ग्राम सुधार और कृषि विकास के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया गया। जुलाई सन् १९५१ में प्रकाशित प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में योजना आयोग ने ग्रामीण विस्तार सेवाओं के प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का संतुलित विकास कड़ा गया। फरवरी सन् १९५२ में अधिक अग्र उपजाओ जाँच समिति ने ग्रामीण जीवन के सुधार के निमित्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अथवा ब्रिटेन के समान विस्तार अथवा सलाहकारी सेवाएँ चालू करने का सुझाव दिया। इसी समय (जनवरी सन् १९५२) भारत और अमेरिका के बीच एक प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत ग्राम विकास के लिये अमरीकी सरकार ५०० लाख डालर की सहायता इस शर्त पर देने को सहमत हो गई कि भारत सरकार भी उतना ही धन लगाये। इटावा अग्रगामी, गोरखपुर देवरिया, निलोखेरी, बम्बई सर्वोदय, इत्यादि योजनाओं और फिरका विकास कार्यक्रम (मद्रास) इत्यादि प्रयोगों की सफलता से भारत सरकार अत्यन्त प्रभावित हुई और वह उन्हें ग्राम सुधार की आदर्श व्यवस्था समझने लगी। फलतः उक्त अमरीकी समझौते के अनुसार एवं अमरीकी विशेषज्ञों की सहायता से भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में ५५ केन्द्र चुने जिनमें ग्राम सुधार का कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया गया। इसी कार्यक्रम को सामुदायिक योजनाओं का नाम दिया गया।

यह कार्यक्रम २ अक्टूबर सन् १९५२ में चुने हुये ५५ केन्द्रों में चालू किया गया। इसके अन्तर्गत ५०० वर्ग मील क्षेत्रफल, ३०० गाँव और २ लाख जनसंख्या सम्मिलित थी। प्रथम योजना के अन्तर्गत इसका प्रसार १२०० विकास खण्डों (६०० सामुदायिक विकास योजनाओं और ३०० राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं) में फैल गया जिससे १ लाख २३ हजार गाँव और ८ करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई। सन् १९५६ के अन्तर्गत यह संदेश २७०० खण्डों में पहुँच गया जिससे ३ लाख ६० हजार गाँवों और १८ करोड़ जनसंख्या को लाभ पहुँचा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार अक्टूबर सन् १९६३ तक भारत के सभी गाँवों को इन नये प्रयोगों का लाभ मिलने लगेगा।

श्रालोचना

यद्यपि सामुदायिक विकास योजनाएँ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ देश के विस्तृत क्षेत्र और तीन चौथाई जनसंख्या में जागृति उत्पन्न करने का कार्यक्रम है और उसे इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हुई है, तो भी इस कार्यक्रम की बड़ी श्रालोचना की गई है। इन योजनाओं से जितनी हम आशा करते हैं उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई। अनेक लोगों का कहना है कि ये योजनाएँ केवल कागजी कार्यक्रम हैं और लोगों में स्फूर्ति और आशा का संचार नहीं कर पाईं। जितना इस विषय पर धन खर्च किया जा रहा है उतना लाभ देश को नहीं हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य मन्तव्य कृषि उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीण जनता की आय वृद्धि करना और उनकी कंगाली दूर करना

है। योजनाओं के मूल्यांकन प्रतिवेदनों (Evaluation Reports) में बताया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में ये योजनाएँ विफल रही हैं। इस विफलता का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव, आवश्यक सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धि तथा जनता की अपेक्षा बताया जाता है। साथमें मूल्यांकन प्रतिवेदन में बताया गया है कि १८ म से १४ खण्डों (Blocks) में सिंचाई सुविधाएँ अपर्याप्त पाई गईं। उत्तम बीज और खाद भी अपर्याप्त बताये गये। पसल सम्बन्धी रोग एवं कीड़े और भूमि के कटान भी गम्भीर समस्याएँ बताई गईं। बीज, खाद, कीटाणुनाशक कृषि-यन्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के वितरण सभ्यता में सुधार के लिये बहुत कुछ सम्भावना है। कभी-कभी वितरण में देरी की शिकायतें भी की गई हैं। कई वस्तुओं का वितरण अभी तक राज्य सरकारों के विभागों के हाथ में है। यह एक सामान्य दोषारोपण है कि योजनाओं का लाभ केवल धनी-मानी और प्रभावशाली लोगों को ही प्राप्त है। भूमि हीन किसानों अथवा अन्य गरीब जनता को इनसे कोई लाभ नहीं पहुँचा। वस्तुतः इन योजनाओं का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वावलम्बन, आत्मसम्मान और नृत्व की भावना जागृत करना है। ऐसी कोई जागृति लोगों में उत्पन्न नहीं हुई। यह कहा जाता है कि ग्राम सेवक स्वयं वहाँ के नेता बन गये हैं और ग्रामीण जनता इस अधिकार से वंचित रहखी गई है। इन योजनाओं की विफलता का एक बड़ा कारण खण्ड में काम करने वाले कर्मचारियों में कार्य-कौशल की कमी बताई जाती है। लगभग २५% कर्मचारी ऐसे बताये जाते हैं जो अपने काम को करने के अयोग्य हैं अथवा उसे उपेक्षित भाव से करते हैं। खण्ड विकास अधिकारियों और खण्ड विस्तार कर्मचारियों में परस्पर समन्वय की भावना भी नहीं है। सहकारी समितियों को योजनाओं से प्रोत्साहन नहीं मिला और न पचायतों का ही विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। ग्रामीण जनता बहुधा इस कार्यक्रम को अपेक्षा की दृष्टि से देखती है और उसे केवल एक सरकारी कार्य कम समझती है। शिक्षा प्रसार भी प्रासाजनक नहीं हो सका।

“१९६६ के लगभग जब कि भारत की जनसंख्या ४५ करोड़ की सीमा को लाँघ कर आगे बढ़ जाएगी, उसकी अनियन्त्रित वृद्धि को रोकने के सम्पूर्ण प्रयत्न विफल हो जायेंगे।”

—जनगणना महारजिस्ट्रार

२५—जनसंख्या की समस्या

रूप-रेखा

१. समस्या का स्वरूप :
 - (क) भौतिक वृद्धि
 - (ख) प्रतिशत बढ़ोतरी
 - (ग) घनत्व
२. जनसंख्या से सम्बन्धित आर्थिक समस्यायें
३. वृद्धि के कारण
४. रोक-थाम की आवश्यकता
५. रोकने के प्रयत्न
६. परिवार नियोजन
७. जनसंख्या वृद्धि रोकने के अन्य सुझाव ।

समस्या का स्वरूप

भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। १९६१ की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ४३.८० करोड़ है तथा गत दशक में उसमें २१.५% वृद्धि हुई है।

भौतिक वृद्धि—बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ की जनसंख्या केवल २४ करोड़ थी। गत ६० वर्ष में उसमें ८४% की वृद्धि हो गई है। इस शताब्दी के प्रथम तीन दशक में केवल ३.७० करोड़ की वृद्धि हुई, किन्तु इसके उपरान्त तीन दशक में १६.३० करोड़ की वृद्धि हुई। यह अनुमान लगाया गया है कि १९७६ तक भारत की जनसंख्या ५६.८० करोड़ हो जाएगी अर्थात् १९५१ और १९७६ के बीच की २५

वर्ष की अवधि में वह २०.६० करोड़ बढ़ जायेगी। इस भाँति देश की जनसंख्या उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़ती जा रही है।

इस वृद्धि के अनुमान भी बहुत ही ठीक नहीं उत्तरते। द्वितीय योजना बनाते समय १९५६ में ३८.४० करोड़ का अनुमान लगाया गया था और १९६१ में ४०.८० करोड़, १९६६ में ४३.४० करोड़, १९७१ में ४६.५ करोड़ तथा १९७६ में ५० करोड़ की संभावना की गई थी, किन्तु केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन द्वारा हाल के अनुमानों के अनुसार १९६१ में ४३.१० करोड़, १९६६ में ४८ करोड़, १९७१ में ५२.८० करोड़ तथा १९७६ में ५६.८० करोड़ संख्या सूती गई है। १९६१ की जनगणना के उपलब्ध आँकड़ों से ये अनुमान गलत सिद्ध हो चुके हैं।

प्रतिशत बढ़ोतरी—भारत की जनसंख्या की भौतिक वृद्धि ही अधिकाधिक नहीं है, उसकी प्रतिशत बढ़ोतरी भी उत्तरात्तर बढ़ती जाती है। १९०१-१९११ के दशक में प्रतिशत वृद्धि ५, १९२१-२१ में ११, १९३१-४१ में १४.३, १९४१-५१ में १३.४ तथा १९५१-६१ में २१.५ रही। यह वृद्धि दर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है।

घनत्व—भारत में जनसंख्या का घनत्व अन्य कुछ प्रधान एवं ऐसे ही विस्तृत देशों की अपेक्षा अधिक है। भारत में प्रति वर्ग मील घनत्व २८७ है जबकि चीन में १२३, हिन्देशिया में १०८, फ्रांस में १६३, संयुक्त राष्ट्र में ५०, ब्राजील में १५ तथा आस्ट्रेलिया व कनाडा में प्रत्येक का केवल ३ है।

सम्बन्धित आर्थिक समस्याएँ

हमारी जनसंख्या की इस असाधारण वृद्धि के आर्थिक प्रभाव भी बड़े असाधारण होने स्वाभाविक हैं। देश में खाद्यान्न का अभाव, बेकारी, अशिक्षा इत्यादि सब जनसंख्या के ही परिणाम हैं।

खाद्यान्न अभाव

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की खाद्यान्न समस्या अति गंभीर है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के अथक् प्रयत्नों के उपरान्त भी हमें देश की खाद्यान्न की कमी पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष तीस-पैंतीस लाख टन अन्न वा आयात करना पड़ता है। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में लगाए अनुमान अब गलत सिद्ध हो गए हैं और तृतीय, चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजनाओं की जनसंख्या की अनुमानित अधिक बढ़ोतरी के लिए क्रमशः २.३ करोड़, ४.६ करोड़ तथा ६.३ करोड़ अधिक व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करना होगा।

बेकारी

जनसंख्या की अपार वृद्धि का कारण ही देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या है। सन् १९५६ के योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार देश में ५३ लाख लोग बेकार थे और एक करोड़ और नए द्वितीय योजना काल में धर्मिक वर्ग में

सम्मिलित हो जायेंगे। द्वितीय योजना में ८० लाख लोगों को अधिक काम देने की व्यवस्था की गई, किन्तु वास्तुतः केवल ६५ लाख लोगों को काम दिया जा सका अर्थात् १५ लाख नए व्यक्ति और बेकार हो गए। इसी भाँति तृतीय योजना में १ करोड़ ५० लाख नए श्रमिक बढ जाने की संभावना है जिनमें से केवल १ करोड़ ४० लाख को काम दिया जा सकेगा अर्थात् १० लाख और नए लोग बेकार हो जायेंगे। इस भाँति काम के साधनों से जनसंख्या की गति अधिक होने से देकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

भूमि पर अधिक भार

काम के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या के अधिक बढ़ने के कारण लोगों को खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो कि देश का परम्परागत व्यवसाय है। इससे भूमि पर भार दिन प्रति वृद्धता ही जाता है। १९११ में प्रति व्यक्ति पीछे ०.६० एकर कृषि क्षेत्र था जो १९५१ में केवल ०.६० एकर रह गया। दो पंचवर्षीय योजनाओं के उपरान्त भी हमारी जनसंख्या का ७२% पूर्णतः कृषि पर निर्भर है।

इसी भाँति निम्न जीवन-स्तर, प्रति व्यक्ति न्यून आय, निरक्षरता, जीवन-काल की कम अवधि, अकुशल उत्पादन इत्यादि समस्यायें भी जनसंख्या से सम्बन्धित हैं।

वृद्धि के कारण

देश की जनसंख्या की तीव्र गति के अनेक कारणों में से मुख्य निम्नांकित हैं :
 (१) भारत में विवाह एक सामाजिक आवश्यकता माना जाता है और सभी स्त्री-पुरुष विवाह करते हैं। (२) विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति माना जाता है। (३) बहुपत्नीय प्रवृत्ति में विवाह करने की रूढ़ि और ग्रन्थविद्वास लोगों में फैला हुआ है। (४) लोगों की बंगाली भी जनसंख्या की वृद्धि का एक सर्वमान्य कारण है। निम्न आय के वर्गों में जीवन स्तर के गिरने का भय नहीं होना। अतएव अधिक सताने होती हैं। (५) देश का जलवायु प्रजनन क्षमता बढ़ाने का मूल कारण है जिसके कारण बहु-विवाह, बाल-विवाह आदि कुप्रथायें प्रचलित हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में योग देती हैं। (६) हमारे यहाँ अशिक्षित मानव जनसंख्या के अनेक देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। (७) लोगों की निरक्षरता उन्हें मृतति निरोध के साधनों से अनभिज्ञ रखती है। (८) इस देश में स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। उन्हें घर के बाहर बहुत कम निकलने और मनोरंजन का कम अवसर मिलता है।

जनसंख्या के रोकने की आवश्यकता

(१) यह निर्विवाद है कि भारत की जनसंख्या १९२१ के उपरान्त जिस गति से बढ़नी गई है उस गति से पाच पदार्थ नहीं बढ़ सके और प्रसिद्ध विद्वान् मात्स का सिद्धान्त देश में लागू होता स्पष्ट दिखाई देता है। १९४३ में बंगाल में भीषण भूकाल पड़ा और तदुपरान्त भी कई बार कई क्षेत्रों में संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो

चुकी है। इस प्रकार के संकट से बचने का एकमात्र साधन जनसंख्या की रोक थाम है। (१) न केवल हम अपने भरण-पोषण के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, पौष्टिक दृष्टि से भी हमारा भोजन अत्यन्त अनुपयुक्त है जिससे दिनों दिन लोगो का स्वास्थ्य-स्तर गिरता जाता है, कार्यक्षमता कम होता जाता है, तथा आयु कम होती जाती है। देश के स्वास्थ्य-स्तर को उठाने के लिये जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। (२) देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तथा लोगों की न्यून-शक्ति बढ़ाने, शिक्षा प्रचार तथा जीवन स्तर उठाने के विचार से भी जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक बताया जा रहा है। (४) देश की बेकारी तथा बगाली दूर करने के लिये भी सीमित जनसंख्या पर जोर दिया जाता है। १९५१ की जनगणना के समय ही जनसंख्या अधिकारी (Registrar General) ने यह सलाह दी थी कि साधनों के विचार से उत्पादन वृद्धि के सभी आर्थिक यत्नो को काम में लेकर भी ४५ करोड़ से अधिक जनसंख्या का उपयुक्त भरण-पोषण करने में देश असमर्थ रहेगा और उन्होंने वृत्तिम उपायो द्वारा जनसंख्या की रोक पर जोर दिया था। तत्कालीन अनुमानों के अनुसार यह सीमा १९६६ तक पहुँचने वाली थी, किन्तु १९६१ की जनगणना के अनुसार वह ४४ करोड़ हो चुकी है अर्थात् उक्त संकट की घटी बजने के निकट पहुँच गई है और हमें सचेत हो जाना है।

जनसंख्या को रोकने के प्रयत्न

१९४३ के बंगाल के अकाल ने जनसंख्या के सम्बन्ध में हमारी प्रसिद्धि खोल दी थी और तभी से हम उसे तथा उससे सम्बन्धित अनेक आर्थिक समस्याओं पर कायू पाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्नशील रहे हैं। बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए शारदा एक्ट पहले ही बन चुका था जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम आयु वाले लड़के और १४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह एक कानूनी अपराध ठहराया गया। इस कानून में कई कमी हैं। वह केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है। अतएव वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा है।

स्वतंत्रता के उपरान्त देश के आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजन का प्रादुर्भाव हुआ। आर्थिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू जनसंख्या का नियंत्रण माना गया। अतएव प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही सन्तति निरोध एवं सीमित जनसंख्या के प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा इसका एकमात्र माग परिवार नियोजन बताया गया। अब परिवार-नियोजन आर्थिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और देश भर में फैल चुका है।

परिवार नियोजन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की ठीक ठीक जानकारी, प्रजनन शक्ति का पूर्ण ज्ञान और उसके नियमन के साधन, जनता में सम्बन्धित जानकारी बढ़ाने तथा परिवार नियोजन सेवा व सलाह को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों

बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा तथा देव-रेल का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता, तथा भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दाल-विवाह, बटु-विवाह, बेजोड़ विवाह इत्यादि कुप्रथाओं का अन्त करना चाहिए। स्त्री-शिक्षा के प्रसार द्वारा एवं स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता देकर भी जनसंख्या की समस्या पर बहुत कुछ रोक लगाई जा सकती है। सामान्य शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार एवं सन्तति निरोध साधनों के प्रचार द्वारा भी समस्या मुलभाने में सहायता मिलेगी। इस समस्या का वास्तविक हल आवश्यक सामाजिक वातावरण बनाने और सन्तति निरोध के सरल एवं सफल साधनों के प्रचार द्वारा ही सम्भव है।

“घाटा-वित्त आधुनिक युग में पिछड़ेपन का आवश्यक उपचार माना जाता है।”

२६-घाटे की वित्त-व्यवस्था

रूप-रेखा

१. परिभाषा
२. आवश्यकता
- ३ घाटा-वित्त के ढंग
- ४ घाटा-वित्त का महत्व एवं उद्देश्य
- ५ नियन्त्रण की आवश्यकता
६. भारतीय योजनाओं के अन्तर्गत घाटा-वित्त
- ७ उपसंहार।

परिभाषा

सरकार द्वारा आय से अधिक व्यय करने को घाटा-वित्त कहते हैं। सरकार अपनी आय के लिए नागरिकों पर कर लगाती है, जनता से ऋण लेती है, निक्षेप प्राप्त करती है। इन सधनों से प्राप्त राशि से अधिक यदि सरकार व्यय करे तो सरकार का बजट ‘घाटे का बजट’ कहा जाता है। इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है, अधिक मुद्रा निर्गमित करती है अथवा केन्द्रीय बैंक की निक्षेप-निधि का उपयोग करती है। इसी क्रिया को घाटे की वित्त-व्यवस्था कहा जाता है। इस भाँति घाटा-वित्त सरकारी व्यय का वह भाग है जो सरकार की मुद्रा-सृजन शक्ति के द्वारा किया जाता है। यदि सरकार जान-बूझकर किसी उद्देश्य से अपनी आय से अधिक व्यय करे और उस घाटे की पूर्ति किसी ऐसे ढंग से करे जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़े तो उसे ही घाटे की वित्त-व्यवस्था कहा जाता है। अतएव घाटा-वित्त के दो मूल तत्त्व माने जाते हैं - (१) सरकार जान-बूझकर अपनी आय से अधिक व्यय करे; (२) इस घाटे को पूर्ति इस प्रकार की जाय कि देश में मुद्रा अथवा साख अथवा दोनों का प्रसार हो।

यह घाटा केवल राजस्व खाते से सम्बन्धित होना आवश्यक नहीं है, इसमें पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित होना चाहिए तथा ये राजस्व व पूँजी के व्यवहार केन्द्रीय और राज्य सभी सरकारों के होने चाहिये।

सामान्यतः सरकारी बजट के घाटे को पूरे करने के कई ढंग हैं जैसे नए कर लगाकर, पुराने करों में बदोतरी करके, नागरिकों, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर, किन्तु इन सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ होती हैं। उस सीमा से आगे बढ़ जाने से देश में पूँजी-निर्माण कम हो जाता है, लोगों की कर-भय समता क्षीण हो जाती है और निजी 'उद्योग-व्यापार' शिथिल होने लगते हैं। विदेशी ऋण भी सीमित मात्रा में ही लिए जा सकते हैं। अतएव सरकार घाटा पूरा करने के ऐसे ढंग अपनाती है जिनसे उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं का बचाव हो सके। इनमें अपने संचित कोष में से खर्च करना, केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा अधिव मुद्रा निर्गमन कराना इत्यादि हो रहे जाते हैं। इन्हीं साधनों के उपयोग द्वारा घाटा-पूर्ति करना घाटे की वित्त-व्यवस्था मानी जाती है।

आवश्यकता

प्राचीन अर्थशास्त्री संतुलित सरकारी बजट के पक्षपाती थे, किन्तु युद्ध, प्राथमिक मन्दी, प्रायोजन इत्यादि ऐसे विशेष अवसर सरकार के सामने आ उपस्थित हुए जबकि संतुलित बजट रखना असम्भव हो गया और सरकार को आय से अधिक व्यय करने के लिए विवश होना पड़ा।

और प्राथमिक मन्दी के वर्षों में उद्योग-व्यापार शिथिल पड़ जाते हैं, मूल्य-स्तर गिर जाते हैं, बेकारी फैल जाती है, गरीबी और प्राथमिक संकट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार नए-नए निर्माण, विनियोग और कल्याण कार्यों का संचालन करने के लिए अपनी आय से अधिक व्यय करती है। इससे कार्य के साधन बढ़ जाते हैं, बेकारी दूर होती है तथा उद्योग-व्यापार में जान आती है। इस भाँति मुद्रा प्रसार होकर मूल्य-स्तर ऊँचे होते हैं तथा मन्दी दूर होती है।

युद्ध काल में युद्ध सम्बन्धी कार्यों, देशरक्षा उद्योगों एवं अन्य प्रकार अपार धन व्यय करना पड़ता है और उसकी पूर्ति मुद्रा प्रसार द्वारा ही की जाती है अर्थात् घाटा-वित्त की शरण लेनी पड़ती है।

प्रायोजित अर्थ व्यवस्था की पूर्ति के लिए सरकार को साधनों के समुचित उपयोग, कार्य वृद्धि, औद्योगीकरण तथा विविध निर्माण कार्यों के लिए प्रसाधारण व्यय करना पड़ता है। इसके लिए मुद्रा और साख दोनों का सृजन करना पड़ता है अर्थात् घाटे की वित्त-व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

घाटा-वित्त के विविध ढंग

सरकारी बजट के घाटे की पूर्ति के विविध ढंगों में निम्नांकित मुख्य हैं :

(१) विदेशी सहायता अथवा विदेशों से ऋण लेना, (२) अल्प वचत का परिचालन, (३)

देश के अन्तर्गत जनता से ऋण लेना; (४) सरकार को संघिन रोकड़ी राशि का प्रयोग; (५) केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण-कोष का प्रयोग; (६) पौंड पावने के प्रयोग द्वारा; (७) सरकारी ऋण-पत्र बेचकर; (८) केन्द्रीय बैंक द्वारा नई मुद्रा चालू करके अर्थात् बिना स्वर्ण-सचप के नए नोट छापना इत्यादि ।

घाटा-वित्त के उद्देश्य

घाटा-वित्त प्राच्युतिक युग में पिछड़ेपन का आवश्यक उपचार माना जाता है । पिछड़े देशों की गरीबी, बेकारी, निम्न जीवन, अशिक्षा, बीमारी इत्यादि दूर करने के लिए अमित धन की आवश्यकता होती है । इतना धन बचत अथवा परम्परागत आय के साधनों से जुटा लेना सम्भव नहीं होता अतएव घाटा-वित्त की सहायता लेनी पड़ती है । अनेक देशों की गरीबी साधनों के अभाव के कारण नहीं होती, बल्कि साधनों के दोहन न होने के कारण होती है । घाटा-वित्त इन मुशुकत साधना के दोहन एवं उपयोग का मार्ग खोल देना है और साधनों का बड़ी मात्रा में एक साथ उपयोग किया जा सकता है । आयोजन आज के युग में विकास का एक वैज्ञानिक ढंग माना जाता है । घाटा-वित्त आयोजित अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग माना जाता है । औद्योगीकरण की नई-नई योजनाएँ चलाने, बाँध बाँधने, नहरें, सड़कें, रेलों व पुल बनाने, स्कूल, कॉलेज, विश्व-विद्यालय, अस्पताल इत्यादि स्थापित करने के लिए एक साथ अमित धन की आवश्यकता की प्राथिक पूर्ति घाटा-वित्त से की जाती है ।

ऐसा करने से बड़े पैमाने पर आर्थिक सम्पत्ति का निर्माण होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, काम के साधन बढ़ते हैं, विनियोग की दर ऊँची होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा बढ़ती है और विविध प्रकार से विकास होने लगता है ।

घाटा-वित्त किसी संकट काल से पार उतरने का भी साधन है । आर्थिक मन्दी व युद्ध के समय देश का संकट निवारण करने में इसकी अपार सेवा का उपयोग सर्वत्र किया जाता है ।

नियंत्रण की आवश्यकता

यद्यपि घाटा-वित्त आर्थिक विकास का एक अमोघ अस्त्र है, तो भी इसका उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है । असंयमित एवं अनियंत्रित घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है जिसके दुष्परिणामों से कौन परिचित नहीं है ? जब तक बढ़ाई गई मुद्रा की मात्रा के समकक्ष माल बन कर बाजार में नहीं आजाता तब तक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं ; लोगों की शक्ति कम हो जाती है ; बचत एवं विनियोग की क्षमता कम हो जाती है । घाटा-वित्त के इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए इसका प्रयोग सावधानी से करना होता है । इस के लिए बहुत निम्नांकित उपचार किए जाते हैं :

(१) भोजन-अस्त्र आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं की माँग और पूर्ति के असन्तुलन को दूर करने के विचार से उनका उत्पादन बढ़ाया जाता है, आयात अथवा उधार द्वारा

उनका संभित बोध बनाया जाता है, उन्हें निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है, उनका उपभोग पर नियंत्रण लगाया जाता है और आवश्यकता हो तो राशनिंग व्यवस्था चालू की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं के व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले सकती है।

(२) कर पद्धति में आवश्यक राशोधन किए जाते हैं। ये राशोधन ऐसे होते हैं कि लोग के अनावश्यक एवं विलासी उपभोग सीमित हो और सरकारी बोध में अधिकधिक धन आए।

(३) घाटा-वित्त के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए साख-नियंत्रण भी आवश्यक होता है। मुद्रा-स्फीति का लक्षण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि ही नहीं, साख वृद्धि भी है। अतएव साख की आवश्यक मात्रा, दर व दिशा पर भी नियंत्रण लगाया जाता है। यह नियंत्रण कन्द्रीय बैंक लगाता है जो दश व अन्व-बैंक की नीति का पथ प्रदर्शक है।

(४) आयात-निर्यात का सतुलन बनाए रखने के विचार से विनिमय नियंत्रण भी आवश्यक होते हैं। ऐसे कदम किए जाते हैं कि विदेशी विनिमय का उपयोग बेचल विकास कार्यों अथवा जीवनोपयोगी उपभोग्य पदार्थों के आयात के लिए ही किया जाता है।

(५) विदेशी सहायता प्राप्त कर तथा ऐसी परियोजनाओं की प्राथमिकता देकर जिनके परिणाम शीघ्र मिलने लगे भी घाटा वित्त के दुष्प्रभावों को रोका जाता है।

भारतीय योजनाएँ और घाटा वित्त

प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने आयोजन के लिए घाटा वित्त का महत्व स्वीकार कर लिया था और २६० करोड़ रुपए घाटा-वित्त व्यवस्था का अनुमान लगाया था। योजना के अन्त तक ४२० करोड़ रुपए घाटा वित्त का विकास के लिए प्रयोग किया गया जो योजना के कुल सरकारी व्यय का २१% था। इस अवधि में देश के पास पौड पावने का पर्याप्त कोष था जिसका तुल्य कर प्रयोग किया गया। अतः इस घाटे-वित्त से देश की अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के प्रभाव दिखाई न दिए। इस समय तक देश की बहुत सी औद्योगिक क्षमता भी अप्रयुक्त थी जिसके उपयोग ने भी मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभाव रोकने में सहायता दी।

द्वितीय योजना प्रथम से लगभग दूनी बड़ी बनाई गई। उसे अधिक साधनों की आवश्यकता हुई। अतएव १२०० करोड़ रुपए घाटे-वित्त द्वारा व्यय करने का निश्चय किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग २०० करोड़ रुपए पौड पावने कोष से मिल जायेंगे और शेष १००० करोड़ रुपए से मुद्रा निर्माण करना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्ष में ६१७ करोड़ रुपए (प्रथम वर्ष १२६ क० ६०, द्वितीय वर्ष ४६४ क० ६० तथा तृतीय वर्ष २१५ क० ६०) के

घाटे वित्त का प्रयोग विधा गया। यह सुरक्षा सीमा से बाहर था। अतएव देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के अनुभव दिव्यार्थ देन लगे। पीछे पावने का बड़ी मात्रा में प्रयोग करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कौप की साख सुविधाओं के उपरान्त भी देश में वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ने लगे, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, औद्योगिक उत्पादन की गति शिथिल होने लगी। अतएव आगामी वर्षों में घाटा-वित्त का कम प्रयोग करने का निश्चय किया गया। द्वितीय योजना काल में इस साधन से ११७५ करोड़ रुपए व्यय किए गए।

द्वितीय योजना के कटु अनुभव के उपरान्त देश तृतीय योजना में उस सीमा तक घाटा-वित्त प्रयोग करने के लिए अग्रमर्थ था। अतएव तृतीय योजना में केवल ५५० करोड़ रुपए के घाटा-वित्त का अनुमान लगाया गया है। इन सीमा के निर्धारित करने में यह विचार किया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में मोटो के चलन में ३३% की वृद्धि से मूल्यों पर विशेष दबाव नहीं पड़ेगा।

उपसंहार

घाटे की वित्त-व्यवस्था का सुरक्षित परिमाण निश्चय करने की कोई निश्चित विधि नहीं है। इस प्रसंग में, प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के दोनों ढंगों अर्थात् बजट के माध्यम और बैंको द्वारा ऋण-ग्रहण पर एक साथ विचार करना उचित है। घाटे की वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय समय-समय पर आर्थिक परिस्थितियों की जांच करके ही किया जाना चाहिए। यह बहूत कुछ इस बात पर निर्भर है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई—विशेषतः कृषि के क्षेत्र में—और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों पर कहां तक काबू पाया गया। वस्तुतः घाटा-वित्त एक उत्तम विकास साधन है, किन्तु इसके उपयोग में चतुराई और दूरदर्शिता की अनीव आवश्यकता है।

“समाज के माध्यम से ही भारत में ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है, जिसका प्रत्येक सदस्य प्राथमिक आवश्यकताओं के अभाव से मुक्त हो।”

—पं० जवाहरलाल नेहरू

२७—समाजवादी समाजगठन

रूप रेखा

१. अर्थ ।
२. मूल तत्त्व ।
३. पाश्चात्य और भारतीय प्रादशों में अन्तर ।
४. आवश्यकता ।
५. उद्देश्य ।
६. औद्योगीकरण ।
७. सामाजिक शक्ति ।
८. आयोजन द्वारा प्राप्ति ।
९. भारत में प्रगति ।

अर्थ

विश्व में तीन वाद प्रचलित हैं - (१) सामन्तवाद, (२) समाजवाद एवं (३) पूँजीवाद। सामन्तवादी व्यवस्था में बड़े-बड़े भूपतिपते, जमींदारों एवं राजकुमारों का बोलबाला होता है। समाज के अन्य भ्रम बहुधा निर्बल, दुर्बल और सुच्छ समझे जाते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े-बड़े कारखाने नहीं होते। उत्पादन कुटीर उद्योगों में ही होता है।

पूँजीवादी व्यवस्था में बड़े-बड़े कारखाने होते हैं जिनमें प्राधुनिक मशीनों से काम होता है। इन कारखानों पर घनी वर्ग का अधिकार होता है जिसे पूँजीपति अथवा उद्योगपति कहते हैं। उद्योग और व्यापार में इन्हीं का घन लगा रहता है और समाज की अधिकांश सम्पत्ति पर इन्हीं का अधिकार होता है, यद्यपि वे स्वयं काम

नही करते । समाज के अन्व वर्ग (मजदूर और किसान) गरीब एवं तुच्छ समझे जाते हैं ।

समाजवाद इन दोनों से भिन्न है । ऐसे समाज में ऊँच-नीच अथवा धनी-निर्धन का भेदभाव नहीं होता । विशेषाधिकारों पर किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होता, उनका सभी में वितरण होता है । भूमि और उद्योग पर समाज का अधिकार माना जाता है । सभी लोग सार्वजनिक हित साधन के लिये कार्य करते हैं । सम्मिलित प्रयास का परिणाम सभी को मिलता है और सभी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । ऐसे समाज में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होता । सभी को उन्नति के समान अवसर उपलब्ध होते हैं । धन सम्पत्ति और आय का न्यायपूर्ण वितरण होता है ।

समाजवाद के भी दो रूप हैं । एक क्रान्तिकारी समाजवाद जिसे बहुधा साम्यवाद कहा जाता है और जो हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास करता है । ऐसा समाजवाद रूस, चीन, पूर्वी यूरोप, उत्तरी कारिबा इत्यादि में है । दूसरा वैधानिक समाजवाद है जिसमें शान्तिमय एवं वैधानिक मार्ग से क्रान्ति की जाती है । इसे बहुधा राजकीय समाजवाद कहा जाता है ।

भारत में समाजवाद से तात्पर्य वैधानिक समाजवाद से है । हम शान्ति और अहिंसा के वैधानिक मार्ग से सामाजिक क्रान्ति के पक्ष में हैं । यह एक ऐसा आर्थिक संगठन होगा जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधन सरकार के अधिकार में रहेंगे तथा उद्योग-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो जायगा । औद्योगिक प्रबन्ध श्रमिक वर्ग की सहायता से किया जायगा । ऐसे समाज की रचना में उत्पादन वृद्धि, आयोजित अर्थ-व्यवस्था, पूर्ण काम, न्यायपूर्ण वितरण, विपत्ता निवारण, समान अवसर इत्यादि आदर्शों की कल्पना की गई है ।

भारत में जिस समाजवादी समाज की कल्पना की गई है उसका अभिप्राय यह नहीं है कि आर्थिक क्षेत्र में सभी नए काम केवल सरकार ही प्रारम्भ करेगी । वस्तुतः राष्ट्रीय विकास में निजी उद्योगपतियों का भी महत्वपूर्ण भाग माना गया है, कि तु निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय योजना में अन्तर्निहित अनुशासन और सिद्धान्तों का मानना और सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग करना आवश्यक होगा । निजी क्षेत्र से तात्पर्य बड़ी-बड़ी संगठित औद्योगिक इकाइयों से ही नहीं, बरन् करोड़ों किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और छोटे-छोटे उद्योगपतियों से भी है । सरकारी क्षेत्र और सामाजिक भावना से अनुप्राणित निजी क्षेत्र मिल कर एक भव्य सहकारी जीवन की नींव डाल सकते हैं । सभी उद्योगों को, चाहे वे सरकारी हों या निजी, देश द्वारा स्वीकार किए गए आधारभूत आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में लोक हित की कसौटी पर खरा उतरना होता है ।

मूल तत्त्व

भारतीय समाजवादी समाजगठन के मूल तत्त्वों का समावेश भारतीय संविधान,

वादी समाज की प्रमुख आवश्यकता उद्योग-धन्धों का समाजीकरण माना जाता है। १९५४ के संसद के धोर १९५५ के ब्रावडी प्रस्ताव के उपरान्त तदनुसार औद्योगिक नीति में परिवर्तन आवश्यक था। अतएव १९५६ की औद्योगिक नीति घोषणा की गई, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य देश-रक्षा सम्बन्धी उद्योग, अणुशक्ति, लोहा-इस्पात, भारी मशीनें, कोयला इत्यादि १७ उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया है, अल्पमूल्य-निषम, मशीनी पत्र, उर्वरक, कृत्रिम रबड़ इत्यादि १२ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने निजी साहस की सहायता से चलाने का निश्चय किया है, किन्तु जिनका उत्तरोत्तर उत्तरदायित्व सरकार लेती जाएगी, केवल कुछ कम महत्व के बड़े और छोटे उद्योग ही पूंजीपतियों के लिये छोड़े गए हैं। इन पर भी सरकारी नियन्त्रण रहेगा।

समाजवाद एवं सामाजिक क्रान्ति

समाजवादी समाज की स्थापना के लिये पुनर्गठन ही आवश्यक नहीं है, सामाजिक क्रान्ति भी अनिवार्य है, क्योंकि इस आदर्श के अर्थात् सामाजिक न्याय, समान पद, समान अधिकार और विषमता निवारण इत्यादि सिद्धान्त निहित हैं। अतएव देश में १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों को इस सम्बन्ध में विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर देश में निरपेक्ष शासन स्थापित किया गया और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। स्त्रियों को प्राथमिक स्वतन्त्रता देने के विचार से एक कानून बना दिया गया है तथा उनके कल्याण की व्यवस्था की गई है। हमारी योजनाओं में शिशु-कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्पृश्यता कानूनी अपराध मान लिया गया है। पिछड़ी जातियों के अग्रगण्य के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस भाँति देश में भारी सामाजिक क्रान्ति हो रही है।

समाजवाद और आयोजन

समाजवादी समाज के मुख्य लक्ष्यों में उत्पादन वृद्धि -प्रायपूर्ण वितरण, विषमता एवं बेकारी निवारण इत्यादि हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति देश के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम अपना कर किया गया है। आयोजन की गति-विधि इस भाँति समायोजित की गई है कि देश शनै-शनै इन उद्देश्यों को प्राप्त करता जाए। गत दस वर्ष में राष्ट्रीय आय में ४२%, प्रति व्यक्ति आय में २०%, कृषि उत्पादन में ४०% तथा औद्योगिक उत्पादन में ५१% की वृद्धि हुई है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उचित वितरण की ओर भी ध्यान दिया गया है और देश की विषमता दूर होती जा रही है। कर-व्यवस्था के सुधार से, बचत की भावना जाग्रत करके इस ओर देश आगे बढ़ रहा है। आयोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी पूर्णतः नियंत्रण में ले लिया गया है।

भारत में प्रगति

समाजवादी समाज की विचारधारा को व्यावहारिक रूप देने का प्रथम प्रयत्न

‘सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥’

(सब सुखी हों, दुखी कोई न हो,

सब निरोगी हों और सब सज्जन हों)

२८—सर्वोदय

रूपरेखा

१. अर्थ
२. मूल सिद्धान्त एवं गुण
३. आर्थिक-व्यवस्था
४. समाज-व्यवस्था
५. राजनैतिक व्यवस्था
६. सर्वोदय सम्मेलन
७. कार्यक्रम
८. उपसंहार ।

अर्थ

सर्वोदय शब्द का अर्थ सबका उदय, सबका उत्कर्ष तथा सबका विकास है । यह सिद्धान्त भारत का पुरातन आदर्श माना गया है जो निम्नलिखित श्लोक में निहित है :

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥

महात्मा गांधी के मतानुसार सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज-व्यवस्था है जिसका आधार सर्वव्यापी प्रेम है । इस व्यवस्था में राजा-रंक, हिन्दू-मुसलमान, छूत-अछूत, बाले-गोरे, सन्त-असन्त सबके लिये स्थान है । किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन, शोषण या विनाश नहीं किया जायेगा । इस समाज-व्यवस्था में सब धरावर के सदस्य होंगे, सबको उनके परिश्रम की पैदावार में हिस्सा मिलेगा, बलवान दुर्बलो की रक्षा

प्राथमिक व्यवस्था

सर्वोदय का आदर्श प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर है। इनके अन्तर्गत "सबे भूमि गोपाल की" मानी जाती है। भूमि अर्थात् उत्पादन के आधारभूत साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य अन्वयात्पूर्ण है। सभी राष्ट्र की सम्पत्ति मानी जानी चाहिये अथवा उन पर राज्य का नियन्त्रण हो। वह स्वार्थपरता एवं निजी लाभ के लिये नहीं, बरन् मानव-जाति के लिए चलाए जाने चाहिए। उनका हेतु लाभ के स्थान पर प्रेम होना चाहिए। इस व्यवस्था में उत्पादन का स्वल्प समाज की जरूरत से निश्चित होगा, न कि व्यक्ति की सनक अथवा लालच से। यह व्यवस्था सम्पत्ति में संरक्षकता का सिद्धान्त स्वीकार करती है जिससे समाज की वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्था में बदल जाती है। यह व्यवस्था व्यवसाय की स्पर्धा में विश्वास नहीं करती जो धनी की अधिक धनी और निर्धन को अधिक निर्धन बनाने के लिए उत्तरदायी है।

सर्वोदय वस्तुतः न्याय का अर्थशास्त्र है। लोग जितना न्याय करना और सदाचारी बनना सीखेंगे उतने ही वे सुखी एवं सम्पन्न होंगे। सर्वोदय कहता है कि जो अर्थशास्त्र केवल धन की पूजा करना सिखाता है और कमजोरों को हानि पहुँचा कर सबको धन जमा करने देता है, वह झूठा और भ्रान्तक अर्थशास्त्र है। वह मृत्यु का दूत है। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय की हिमायत करता है। जैसे पिता के तमाम कमाऊ बेटों की कमाई परिवार के सम्मिलित कोष में जाती है, ठीक वैसे ही उसकी अधिकांश कमाई राज्य की भलाई में काम आनी चाहिये। यह व्यवस्था आय की समानता प्रतिपादित करती है। वकालत का पेशा करने का यह मतलब नहीं कि एक देहाती बड़ई की मजदूरी से उसे ज्यादा मजदूरी मिले। इसके अन्तर्गत भंगियों, डाक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे लोगों को दिन भर के प्रामाणिक काम की एकसी मजदूरी मिलेगी। मजदूर की योग्यता उसका आधार होगा। सबके पास इतनी सम्पत्ति हो जिससे वे अपनी प्राकृतिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। यह आय और सम्पत्ति की समानता उद्योग-धन्धों के विकेन्द्रीकरण द्वारा सम्भव है। उद्योग-धन्धों के केन्द्रीयकरण से गरीब की गरीबी और अमीर की अमीरी बढ़ती है। इस व्यवस्था के अनुपायी अहिंसा के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। अतएव अहिंसक धन्धे ही चला सकते हैं। अहिंसक धन्धा बड़ा बतया गया है जो बुनियादी तौर पर हिंसा से मुक्त हो और जिसमें दूसरों का शोषण अथवा ईर्ष्या न हो। दस्तकारियों में शोषण और गुलामी की गुंजाइश नहीं होती। यह व्यवस्था यंत्रों के विकेन्द्रीकरण वृद्धि को विरोधी है। उसमें केवल सीधे-सादे मनुष्य का समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। हमें यह देखना होगा कि मशीन मनुष्य को बिल्कुल पगु न बना दे। इसमें पूँजी और श्रम के सम्बन्ध अच्छे रहते हैं। यदि पूँजी ताकत है, तो श्रम भी ताकत है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।

समाज-व्यवस्था

सर्वोदय समाज एक मर्यादित समाज होगा। इसमें अहिंसा मनुष्य का एक सामाजिक गुण माना गया है, वह केवल व्यक्तिगत सदगुरा नहीं है। मनुष्य मुख्यतः एक सामाजिक प्राणी है। उसे अनिश्चित व्यक्तिवाद को त्याग कर व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और सामाजिक संयम के बीच के रास्ते पर चलना सीखना होगा। सामाजिक संयम को चुप्पी से मानना व्यक्ति और समाज दोनों को समृद्ध करता है। सर्वोदय समाज में अस्पृश्यता के लिये स्थान नहीं है, यद्यपि उसमें सच्चे धर्म में वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा की गई है। इस समाज में अन्तर्जातीय विवाह और ज्ञान-भान व्यक्तिगत प्रश्न माने गये हैं, उनका सर्वथा निषेध नहीं किया गया। स्त्री अहिंसा और प्रेम का अवतार मानी गई है और पुरुष के समान ही उसे अधिकार दिये गये हैं। पत्नी-पति की जीवन-सागनी और सहायक है तथा उसे अपना मार्ग चुनने की पति के समान ही स्वतन्त्रता है। विवाह धार्मिक संस्कार माना गया है तथा विवाहित जीवन में संयम का पालन आवश्यक बताया गया है। बाल-विषवाभों के विवाह को सामाजिक स्वीकृति दी गई है। गर्भ-निरोध को अनावश्यक कहा गया है। जोर-रसा का धर्म सभी जीवों की रक्षा और पशुओं के प्रति अहिंसा भाव से लिया गया है। इस भाँति सर्वोदय समाज एक अहिंसक, प्रेमपूर्ण एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना से भोत-भोत समाज है। उसमें मनुष्यमात्र के ही नहीं बल्कि प्राणीमात्र के बन्धुत्व का प्राग्रह किया गया है।

राजनैतिक-व्यवस्था

सर्वोदय में राज्य-सत्ता का स्थान लोक-सत्ता से लेती है। सच्चा लोकतन्त्र वह है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता जनता के हाथ में हो। यह गांधीजी के रामराज्य की कल्पना है जिसमें लोकमत ही सर्वोपरि माना जाता है और सभी निर्णय सर्व-सम्मति से होते हैं। उसमें अल्पमत की उपेक्षा नहीं की जाती। चरित्र बल इस सत्ता का आधार है। ऐसा समाज अनिश्चित गाँवों का बना होगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग का नहीं, बरन् लहरों की तरह एक के बाद एक की शकल में होगा। इसका केन्द्र व्यक्ति होगा। व्यक्ति गाँव के लिये और गाँव ग्राम समूह के लिये मर-मिटने को हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह अन्त में सारा समाज ऐसे व्यक्तियों का बन जाएगा जो अहंकार में घाकर कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि सदा विनीत रहेंगे। इस भाँति सेना और पुलिस की आवश्यकता सर्वथा मिट जाती है। राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं आत्म-नियमन कर लेता है और राजनैतिक सत्ता की आवश्यकता सर्वथा समाप्त हो जाती है।

लोक-शक्ति ही इस शासन-व्यवस्था का मूलाधार है जिसे न द्रव्य का भरोसा है, न हिमा का और न कानून का। उसका एकमात्र संबन्ध विचार शासन है। मनुष्य के स्वाभाविक प्रेम और सद्भाव की शक्ति का सामाजिक रूप ही विचार-शासन अथवा लोक शक्ति है।

सर्वोदय सम्मेलन

महात्मा गांधी ने सर्वोदय के इस दर्शन को जन्म दिया। विनोबा भावे इसे आज विकसित कर रहे हैं। भूदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान, साधनदान, बुद्धिदान, धर्मदान आदि प्रक्रियाएँ सर्वोदय विचार-प्रचार के ही सन्निय रूप हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साम्प्रदायिक दंगों की आग देश में भड़क उठी। देश में एक अद्भुत वातावरण उत्पन्न हो गया। कुछ लोग गांधी जी की हिन्दू-मुसलिम एकता की नीति की खुलकर निन्दा करने लगे और इनके परिणाम स्वरूप ३० जनवरी १९४८ को एक कट्टर पक्षी हिन्दू ने गांधी जी की गोली मार दी। गांधी जी की छाया देश से उठ गई। इन कठिन परिस्थितियों में सेवा ग्राम आश्रम में पं० जवाहरलाल नेहरू, विनोबा आदि प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में यह सोचने के लिए कि "बापूजी की छत्र छाया हमारे ऊपर से उठ गई है, अब आगे क्या कार्यक्रम होगा?" एक सभा हुई। यह प्रथम सर्वोदय सम्मेलन था। दूसरा सर्वोदय-सम्मेलन इन्दौर के पास राऊ नामक ग्राम में हुआ। सन् १९५० में एक सर्वोदय-समाज की स्थापना हुई। इससे पूर्व कांग्रेस के सदस्य ही इन सम्मेलनों में एकत्रित होते थे। प्रथम कोई सर्वोदय समाज नहीं था। तीसरा सर्वोदय-सम्मेलन ८ अप्रैल से ११ अप्रैल तक १९५१ में शिवरामपल्ली में हुआ। १८ अप्रैल १९५१ का दिन इतिहास का चिरस्मरणीय पृष्ठ रहेगा। इस दिन प्रथम भूदान हुआ। अब अन्त विनोबा ने सारे देश में पैदल घूम-घूमकर भूदान यज्ञ आन्दोलन छेड़ दिया। चौथा सर्वोदय-सम्मेलन १३ अप्रैल १९५२ को सेवापुरी में हुआ। इस सम्मेलन में सर्व सेवा संध ने २५ लाख एकड़ भूदान प्राप्त करने का सक्लष किया। मार्च १९५३ में चांडील में पाँचवाँ सर्वोदय सम्मेलन हुआ जिसमें शासन मुक्त, शोषण विहीन समाज रचना की घोषणा की गई। अप्रैल १९५४ के बोध गया छठे सर्वोदय सम्मेलन में प्रथम जीवन दान हुआ। मार्च १९५५ के जगन्नाथपुरी के सातवें सम्मेलन में प्रथम ग्रामदान हुआ। आठवें सर्वोदय सम्मेलन में मई १९५६ में कांचीपुरम् ग्रामोदय की कल्पना सामने आई, नवम्बर १९५६ में तत्रमुक्ति और निधिमुक्ति का महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, मई १९५७ में कालडी में नवाँ सर्वोदय-सम्मेलन हुआ और जुलाई १९५७ में गाँव-गाँव में शान्ति-सेना प्रस्थापित करने का नया विचार सूझा। दसवाँ सर्वोदय-सम्मेलन ३० मई से १ जून तक १९५८ में पडर-पुर में हुआ और २५ जून को सर्वोदय-पान के प्रयोग का श्रीगणेश हुआ। इस प्रकार समय-समय पर सर्वोदय गंगा में विभिन्न विचाररूपी धाराएँ मिलती चली गई हैं। अब सर्वोदय-सम्मेलन सर्वोदय विचार-प्रचार का एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जिसमें हजारों गांधीवादी एवं सर्व सेवा संध के सदस्य एकत्रित होते हैं और सर्वोदय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

सर्वोदय कार्यक्रम

सर्वोदय का मुख्य मार्ग विचार-प्रचार द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन और मत परिवर्तन है। इसके लिए गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम चुना गया है। इस कार्य-

रम के मुख्य विषय जानीय एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्यनिषेध, खादी, ग्रामोद्योग, गाँव की सफाई, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, स्त्रियाँ, आरोग्य निषमों की शिक्षा, प्रांतीय भाषाएँ, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, विज्ञान, मजदूर, आदिवासी, कुष्ठरोगी, विद्यार्थी और पशु-मुधार इत्यादि हैं। यह सूची केवल मार्ग दर्शक है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनुष्य मात्र ही नहीं जीव मात्र की सेवा करना तथा सामाजिक समानता उत्पन्न करना है।

उपसंहार

सर्वोदय का ध्येय एक वर्ग-विहीन, जाति-विहीन, शोषण-विहीन और शासन-विहीन समाज की स्थापना करना है। यह कोरा आदर्श ही नहीं पूर्णतः व्यावहारिक है। अन्तर्राष्ट्रीय संघ एवं अन्य विश्व संगठन इसी सन्देश के समर्थक हैं। सर्वोदय मानवीय विभूति के विज्ञान में विश्वास करता है। घर में, परिवार में हम जिस प्रेम से रहते हैं, दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं तथा हर व्यक्ति की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम सारे विश्व का, मानव मान का, प्राणीमात्र का ध्यान रखेंगे। इस आदर्श व्यवस्था में कोई किसी का शत्रु नहीं, सभी सामान्य ध्येय के लिए अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। सब पढ़ लिख सकते हैं। रोग और बीमारी कम से कम होती है, संयम अधिक से अधिक। कोई दरिद्र नहीं होता। मजदूरों को सदैव काम मिल जाता है। ऐसे समाज में जुआ, दारादलोरी, दुराचार, वर्ग-द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। धनवान अपना धन बुद्धिमानों और उपयोगी ढंग पर खर्च करते हैं। ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं होता। “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना हमारी रंग-रंग में भिद जाती है।

“बिना विज्ञापन के राष्ट्र के १७०० दैनिक, ६००० साप्ताहिक एवं ६०० मासिक पत्र-पत्रिकाओं की जीवन-नैया भंवर म पड जाएगी। रेडियो और टेलीविजन के सम्बन्ध में यह और भी सत्य है जिनकी आय का एक मात्र साधन विज्ञापन ही है।”

—एल्सवर्थ बेकर

२६—विज्ञापन तथा उसकी उपयोगिता

रूप-रेखा

१. परिभाषा
२. उद्देश्य
३. विज्ञापन के लाभ
४. विज्ञापन के दोष व सीमाएँ
५. विज्ञापन के माध्यम
 - (क) समाचार पत्र,
 - (ख) बाह्य विज्ञापन
 - (ग) डाक द्वारा
 - (घ) ग्रन्थ साधन
६. आधुनिक विज्ञापन की उपयोगिता।

परिभाषा

किसी वस्तु अथवा सेवा की धन व्यय करके ऐसी जानकारी कराना जिससे उनकी माँग उत्पन्न हो अथवा बढे, जिससे वे बिकें अथवा उनके बिकने में सहायता मिले, और जिससे लोगों के ऐसे विचार बनें जो उन्हें एक निश्चित रूप में सोचने अथवा काम करने के लिए प्रेरित करें, विज्ञापन कहलाता है। किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाना अथवा उसके बाजार का विस्तार करना इसका मूल उद्देश्य है। व्यापारिक जगत की प्रतियोगिता इसकी जननी है तथा उत्पादन की विविधता इसका जनक।

वाज़ार विम्भार क माय-नाय दिन प्रति दिन इसका प्रचार दहना जा रहा है और प्रच इसने एक विज्ञान एव कला का रूप धारण कर लिया है ।

उद्देश्य

व्यापारिक क्षेत्र म विज्ञापन के तीन मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं :—(क) नवीन वस्तु अथवा सेवा की जानकारी कराना और इस भाँति उसकी माँग उत्पन्न करना, (ख) उसकी माँग बढ़ाना तथा (ग) उसकी माँग को स्थिर बनाए रखना । आधुनिक जगत म विज्ञापन व्यापारिक आवश्यकता ही नहीं है, बरन् राजनीतिक, सामाजिक एव जीवन के अन्य क्षेत्रों म भी उपयोगी माना जाता है । यहाँ तक कि स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय इत्यादि शिक्षा संस्थाओं को भी विज्ञापन की गरण लेनी पड़ती है । लोकतंत्रीय आयोगन की सफलता भी प्रभावपूर्ण प्रचार पर निर्भर है ।

विज्ञापन के लाभ

विज्ञापन से उत्पादक, उपभोक्ता एवं समाज के अन्य वर्गों को भी लाभ होता है । संक्षेप म ये लाभ निम्नांकित हैं :—

(क) उत्पादक को लाभ—(१) माल अथवा वस्तु की माँग उत्पन्न होनी और बढ़ती है जिससे बिक्री बढ़ कर बिक्रेता का लाभ बढ़ता है ।

(२) बड़ी माँग-शक्ति के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है जो सस्ता होता है, क्योंकि प्रति इकाई व्यय कम पड़ता है ।

(३) विज्ञापन से व्यापारी की स्थािति बनती है ।

(४) अस्वस्थ प्रतियोगिता पर काबू पाने का विज्ञापन अदभुत अस्त्र है ।

(५) वस्तु अथवा माल का विक्रय क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि नये-नये दुकानदार उसे बेचने के लिए लालायित होते हैं ।

(६) विज्ञापित वस्तुओं की माँग बनो रहने से व्यापार मे सुरक्षा का भाव बना रहता है ।

(७) ग्राहकों को बनाए रखने का काम भी विज्ञापन का ही है ।

(ख) व्यापार-व्यवसाय की नैकनामी के कारण योग्य कर्मचारी आकर्षित किए जा सकते हैं ।

(ग) उपभोक्ता को लाभ :—(१) नवीन वस्तुओं की जानकारी होती है, (२) मध्यम कम हो जाते हैं; (३) उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर माल मिल सकता है, (४) वस्तुओं के मूल्य स्थायी हो जाते हैं, (५) सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होना उपभोक्ता के उच्च जीवन स्तर का कारण है, (६) उपभोक्ता वृद्धिमत्ता एवं मित्रव्ययता मे व्यय करता है, (७) वस्तु व माल के गुण तथा उपयोग म विश्वास जम जाता है, (८) मूल्य की जानकारी हो जाती है, (९) सोदा करने मे अधिक समय नष्ट नहीं करना पड़ता ।

(ग) अन्य लाभ :—(१) विज्ञापन अनेक कलाकारों, कारीगरों, लेखकों इत्यादि के जीवन-निर्वाह का साधन है; (२) समाचार-पत्रों की भाय का प्रमुख साधन

है, (३) उपभोक्ता को समाचार पत्र सस्ते मिलने लगते हैं, (४) अर्द्धे विज्ञापन लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं, (५) नवीन योजनाओं की जानकारी सहज समभव है, (६) विक्रय-कर्त्ता का काम सरल हो जाता है, (७) कर्मचारी अपने बनाए माल की दिनों से गौरवान्वित होते हैं, (८) फुटकर दुकानदारों को माल बेचने में सुविधा हो जाती है।

विज्ञापन के माध्यम

आधुनिक विज्ञापन के अनेक साधन और माध्यम हैं जिन्हें हम सामान्यतः चार वर्गों में बाँट सकते हैं - (१) पत्र-पत्रिकाओं द्वारा, (२) बाह्य विज्ञापन, (३) डाक द्वारा विज्ञापन और (४) अन्य साधन।

पत्र-पत्रिकाएँ—पत्र-पत्रिकाओं की श्राव का विज्ञापन एक मुख्य साधन है और उनकी सफलता नियमित विज्ञापन प्राप्त करने पर निर्भर है। व्यापारी वर्ग भी पत्र-पत्रिकाओं के विज्ञापन को एक सरल एवं सस्ता ढंग समझते हैं। ये विज्ञापन दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्धमासिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही तथा वार्षिक पत्र-पत्रिकाओं में किए जाते हैं। दैनिक पत्रों के विज्ञापन का प्रभाव अल्पकालीन होता है, किन्तु सामा-यिक पत्रिकाओं के विज्ञापन का प्रभाव दीर्घकालीन होता है।

बाह्य विज्ञापन (Mural Advertising)—बाह्य विज्ञापन का अर्थ दीवारों पर किए जाने वाले विज्ञापन से है, किन्तु आजकल इस श्रेणी में इस्तहार चिपकाना अथवा बाँटना, बस, ट्राम, रेलगाड़ी द्वारा विज्ञापन, विजली द्वारा सजावट, विमान द्वारा घुएँ से लिखना, डायरी, पेंसिल, कलम, स्याहीखोला इत्यादि पर विज्ञापन लिख कर बाँटना, सचित्र बोर्ड लगाना इत्यादि सभी आते हैं।

बाह्य विज्ञापन समाचार-पत्रीय विज्ञापनों के पूरक हैं अर्थात् जिन विज्ञापनों को पत्र-पत्रिकाओं में दिया जा चुका है उनका स्मरण कराने अथवा उनकी ओर व्यस्त व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये विज्ञापन किए जाते हैं। इनसे वस्तुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनता है, उनकी विशेषताएँ जनता के सामने आती हैं तथा मिलने के स्थान की जानकारी होती है।

डाक द्वारा विज्ञापन (Mail Advertising)—आधुनिक युग में डाक सुविधायें अधिक लोकप्रिय हो गई हैं और यह विज्ञापन का एक प्रभावशाली माध्यम बन गई हैं। परिपत्र, मूल्य सूची, विवरण पत्र, स्मरण पत्र इत्यादि ग्राहकों अथवा सम्भावित ग्राहकों के पास भेजे जाते हैं। जुने हुए व्यक्तियों पर प्रभाव डालने का यह उत्तम साधन है। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और उन्हें स्थायी बनाया जा सकता है।

अन्य साधन—विज्ञापन के अन्य साधनों में विषय से सम्बन्धित विशेष पत्रिकाएँ अथवा मुष्पत्र, मेले व प्रदर्शिनियाँ, सिनेमा, चल-चित्र, रेडियो, नमूने, प्रतिनिधियों द्वारा सम्पर्क, उपहार इत्यादि हैं।

विज्ञापन के दोष व सीमायें—प्राजकाल विज्ञापन का इतना चलन हो गया है कि बिना विज्ञापन के माल को बिक्री असम्भव सी हो गई है। अच्छे से अच्छा माल भी बिना विज्ञापन के बेचना दुर्लभ है। अतएव सभी उत्पादकों एवं विक्रेताओं को विज्ञापन पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। अनेक छोटे व्यापारी-व्यवसाईं दिवालिया तक हो जाते हैं। इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और उपभोक्ता की क्रय-शक्ति कम होती है। वस्तु की माँग कम हो जाती है। नए-नए विज्ञापन मनुष्य के मन में असन्तोष की भावना जागृत करते हैं, क्योंकि सभी वस्तुएँ खरीद लेना सम्भव नहीं है। प्राजकाल अनेक प्रकार के झूठे विज्ञापन होने लगे हैं जो भोले-भाले लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। उपभोक्ता के मन में अनेक धार विज्ञापन अनिश्चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं और कभी-कभी उन्हें अनावश्यक वस्तुओं पर धन खर्च करना पड़ता है। कुछ वस्तुएँ मनुष्य के मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। विज्ञापन मकानों व दीवारों को गन्दा कर देते हैं। चिल्ला-चिल्ला कर विज्ञापन करने वाले लोगों की शान्ति भंग करने में कुछ उठा नहीं रखते। विज्ञापन को प्रधिकता लोगों के मन में अरुचि उत्पन्न करके उनका विश्वास सर्वथा हटा देती है। एक बार विज्ञापन करने से काम नहीं बनता। उसे बार-बार करते रहना आवश्यक है।

आधुनिक विज्ञापन के उपयोग

इन सब दोषों और सीमाओं के होते हुए भी विज्ञापन आज के व्यापार-व्यवसाय का एक आवश्यक अंग माना जाता है और उसका प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। (क) वाणिज्य निर्माता—विज्ञापन को आधुनिक युग का वाणिज्य निर्माता (Business builder) कहा जाता है। ब्रिटेन में देश की राष्ट्रीय आय का २% और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४% विज्ञापन व्यय है। इंग्लैंड का एक सिगरेट निर्माता अपने नये नमूने अथवा नई छाप (Brand) की जानकारी कराने पर २०,००,००० पाँड (२६७ करोड़ रुपए) खर्च कर देता है। इसी भाँति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक बड़ी सिगरेट कम्पनी १,४०,००,००० पाँड से १,५०,००,००० पाँड (२० करोड़ रुपए) प्रारम्भिक विज्ञापन पर खर्च करने को प्रस्तुत रहती है। इस अमित व्यय के पीछे नए विज्ञापन की व्यापार-व्यवसाय जमाने की अनुपम शक्ति ही काम करती है। (ख) माँग सृष्टा (Demand creator)—विज्ञापन में माँग उत्पन्न करने की अपार क्षमता है। माल के गुण, स्वभाव, उपयोग, मूल्य, रंग-रूप इत्यादि की बिना जानकारी के माँग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, विशेषतः आज के विश्वव्यापी बाजार में। आज से ठीक सौ वर्ष पूर्व १८६० में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपना औद्योगीकरण प्रारम्भ कर रहा था और जब विज्ञापन अपनी बाल्यावस्था में ही था संयुक्त राष्ट्र विज्ञापन पर १,००,००,००० पाँड व्यय करता था और उसका राष्ट्रीय उत्पादन ५,००,००,००,००० पाँड था। आज सौ वर्ष उपरान्त संयुक्त राष्ट्र का विज्ञापन व्यय ११,००,००,००,००० पाँड और राष्ट्रीय उत्पादन ५,००,०००,०००,००० पाँड है अर्थात् विज्ञापन में ११०० गुनी वृद्धि हो गई है और

राष्ट्रीय उत्पादन में १०० गुनी। राष्ट्रीय उपज से भी विज्ञापन की ११ गुनी अधिक वृद्धि विज्ञापन के माँग बढ़ाने सम्बन्धी चमत्कार की ओर संकेत करती है। विश्व-व्यापी बाजार का निर्माण विज्ञापन ने ही किया है, क्योंकि माँग उत्पन्न करना आज की प्रतियोगी प्रणाली की एक मुख्य क्रिया है। (ग) आयोजित उत्पादन एवं उपयोग का संगी (Essential adjunct to planned production and consumption)—जैसे दोषपूर्ण मुद्रा उत्तम मुद्रा को प्रयोग से हटा देती है, वैसे ही उपभोग्य पदार्थों में उत्तम पदार्थ दोषपूर्ण पदार्थों को उपभोग से हटा देते हैं। उपभोग्य पदार्थों का विज्ञापन सहायक है। अच्छा विज्ञापन धुरे विज्ञापन को हटाने में सफल होता है। अच्छा विज्ञापन अच्छे माल का ही हो सकता है। उपभोग्य क्षेत्र में गुण ही प्रधान है। इसी कारण भाजकल व्यापार चिन्हों और छापों में लोगों की अधिकाधिक भावना और विश्वास बढ़ता जा रहा है। वे किसी छाप का माल इसी लिए लेते हैं कि उन्हें उसके गुण का विश्वास हो जाता है। इस भाँति विज्ञापन माल के उत्तम नमूने और प्रतिमान स्थापित करने का एक साधन बन गया है। जो व्यापारी-व्यवसायी दोषपूर्ण माल से लोगों को धोखे में डालते रहते हैं वे या तो बाजार से सर्वथा निकल जाते हैं या वे अपने माल का गुण सुधार करने को विवश हो जाते हैं।

अच्छा विज्ञापन स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करता है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। इस स्वस्थ प्रतियोगिता से उत्पादक को नई क्रिया, नया कच्चा माल, नए रूपांकण, नए रूप-रंग की प्रेरणा मिलती है ताकि उसका माल अधिक आकर्षक हो सके। इस गुण सुधार का लाभ उपभोक्ता को उच्च कीटि के माल और सस्ते मूल्य के रूप में मिलता है। इस भाँति विज्ञापन आयोजित उत्पादन एवं उपभोग का सहयोगी माना जाता है। (घ) रचनात्मक कला (Creative art)—आज के युग में विज्ञापन को एक वैज्ञानिक तथा रचनात्मक कला माना जाता है। इसे व्यापारिक प्रबन्ध का एक यंत्र माना जाता है और मनोविज्ञान, अंक शास्त्र, बाजार सर्वेक्षण इत्यादि व्यापारिक प्रबन्ध सम्बन्धी सभी प्रकार के विश्लेषणों से इसे विभूषित किया जाता है। आज के विज्ञापन-विशेषज्ञ बाजारों, माध्यमों, अपीलो, प्रतिलिपियों, स्थापन स्थान, उत्पादन क्रिया इत्यादि के विषय में संभवतः वैज्ञानिकों से अधिक जानकारी रखते हैं। इस भाँति वे विश्व की सुन्दर से सुन्दर रचना के श्रेय के भागी हैं। (ङ) बिक्री यंत्र (Tool of Market)—विज्ञापन आधुनिक विक्रय-कला का यंत्र है। इसका मुख्य ध्येय माल की बिक्री है। बिक्री की सफलता माल, वस्तु प्रथवा सेवा का आकार-प्रकार, रूप-रंग एवं मूल्य जानना आवश्यक है। केवल ऊपरी जानकारी से भी काम नहीं चलता, माल का उपभोक्ता के साथ सम्बन्ध साठ होना चाहिए। उपभोक्ता का माल के रूप, रंग, आकार, प्रकार, मूल्य, सुगन्ध, चमक, ऊपरी दिखावट इत्यादि के सम्बन्ध में क्या विचार है? ये बातें विज्ञापन में और अन्ततोगत्वा बिक्री में बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

“वस्तुतः सुखी वही है जिसने जीवन बीमा जैसी वैज्ञानिक वचत योजनाओं द्वारा अपनी अर्थ-व्यवस्था आयोजित की हो।”

—कैलाशनाथ काटजू

३०—जीवन बीमा निगम

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना ।

(क) जीवन बीमा का संक्षिप्त इतिहास ।

(ख) जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण ।

२. जीवन-बीमा निगम का संगठन ।

३. जीवन-बीमा योजनाएँ ।

४. बीमा कार्य की प्रगति ।

५. कर्मचारी वर्ग एवं शिक्षण ।

६. विनियोग नीति ।

७. आलोचना ।

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में जीवन बीमा का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में ‘योगक्षेम’ शब्द का इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। आधुनिक जीवन-बीमा प्रणाली यहाँ इंग्लैण्ड और यूरोप से आई जहाँ सोलहवीं शताब्दी में उसका जन्म हुआ। भारत में प्रथम जीवन बीमा करने वाली ओरियण्टल जीवन बीमा कम्पनी थी जो १८१८ में कलकत्ता में बनी थी। १८७० तक कुल लगभग १५ कम्पनियाँ बन गईं जिनमें से सात भारतीय और आठ विदेशी थीं। ये कम्पनियाँ केवल यूरोप के लोगो का बीमा करती थीं। भारत के लोगो के बीमा के लिए उन्हें अतिरिक्त धन देना पड़ता था। १८०१ में बम्बई म्यूचुअल जीवन बीमा कम्पनी और १८७४ में ओरियण्टल गवर्नमेंट सिवयोरिटी जीवन बीमा कम्पनी और इनोंने भारतीय लोगो से अतिरिक्त धन

वनाने के दृष्टिकोण से कई प्रकार की योजनाएँ चालू की गई हैं जिनमें से मुख्य निम्नांकित हैं :—

(१) सम्पूर्ण जीवन बीमा, (२) वृत्ति बीमा (Endowment), (३) संयुक्त जीवन वृत्ति बीमा, (४) अस्थायी बीमा, (५) पारिवारिक धाय बीमा, (६) शुद्ध वृत्ति बीमा तथा त्रिगुणित वृत्ति बीमा, (७) विविध लाभ गारंटी बीमा, (८) परिवर्तनीय प्राजीवन बीमा, (९) शिशु पालिसियाँ, (१०) जनता पालिसी, (११) केतन बचत योजना, (१२) समुदाय बीमा योजना, (१३) वार्षिक वृत्ति।

निगम के बीमा सम्बन्धी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वृत्ति बीमा (Endowment) सबसे अधिक लोकप्रिय बीमा है जिसका भाग कुल बीमित मूल्य का लगभग ७०% है। संयुक्त बीमा का भाग १९५८ में १०%, सम्पूर्ण जीवन बीमा का ८%, शिशु बीमा का ५% तथा शेष ७% अन्य पालिसियों का था। विविध रुचि-स्वभाव के लोगों की माँग के अनुसार निगम नई-नई बीमा योजनाएँ चालू करती है।

बीमा कार्य की प्रगति

१९२९ से भारतीय बीमा सम्बन्धी पूर्ण आँकड़े उपलब्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है कि १९२९ में २९ करोड़ रुपये के मूल्य की १,४३,००० पालिसियाँ चालू थीं। १९३९ तक पालिसियों की संख्या लगभग ३ लाख और उनका मूल्य ४७ करोड़ रुपये हो गया तथा इसमें उपरोक्त वृद्धि होती रही। सन् १९५१ तक पालिसियों की संख्या ५-३६ लाख तथा उनका मूल्य १४८ करोड़ रुपये अर्थात् १९२९ की अपेक्षा पाँच गुने से ऊँचा हो गया। गत वर्षों की प्रगति के आँकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	पालिसियों की संख्या (लाख)	बीमा का मूल्य (करोड़ रु०)	सूचक अंक (१९२९=१००)
१९५१	५.३६	१४७.८६	५१७
१९५५	७.९६	२४०.५१	८४१
१९५६	५.४९	१८७.६९	६५६
१९५७	७.९५	२८१.९०	९८५
१९५८	९.३६	३४३.९७	११९९
१९५९	११.५१	४२८.९४	१४९९

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकरण के तुरन्त उपरान्त बीमा मूल्य कम हो गया था, किन्तु तुरन्त वह कमी पूरी हो नहीं करली गई, वरन् उल्टे घाने

तीव्र गति से वृद्धि होती चली गई। प्रत्येक पालिसी के प्रोसत मूल्य में भी बढोतरी हुई। १९५५ में प्रति पालिसी मूल्य ३२०० रु० था जो १९५७ में ३५७५ रु० और १९५८ में ३६६६ रु० हो गया। निगम के व्यवसाय की इस तीव्र वृद्धि के कारण नए कार्यालय खोलना तथा नई योजनाएँ (जन्त पालिसी), संयुक्त जीवन बीमा, वेतन वचत योजना इत्यादि चालू करना है।

कर्मचारी वर्ग एवं शिक्षण

निगम के ऊपर से नीचे तक सम्पूर्ण कार्यकर्ताओं को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : (क) प्रशासन कर्मचारी वर्ग तथा (ख) क्षेत्र अधिकारी (Field Officers)। निगम के कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग ३५००० है। निगम के कार्य-विस्तार के साथ गत वर्षों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई है।

अपने कर्मचारियों की योग्यता और कार्य-क्षमता बढ़ाने के निमित्त निगम ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिक्षा देने की व्यवस्था की है। दफतरी में काम करने वाले सभी नए-पुराने कर्मचारियों के शिक्षण के लिए प्रदेशीक केन्द्र में शिक्षण व्यवस्था की गई है। उच्च अधिकारियों के शिक्षण के लिए नागपुर में एक कालेज खोल दिया गया है।

विनियोग नीति

जीवन बीमा व्यवसाय में बड़ी मात्रा में धन संचय होना स्वभाविक है और उस व्यवसाय की सफलता उस धन के उत्पादक विनियोग में है।

जीवन बीमा निगम कानून द्वारा निगम को अपने बचे धन का विनियोग करने के लिए एक सलाहकार समिति की सहायता लेने का अधिकार है। निगम की विनियोग नीति निर्धारित करने वाली यही समिति है और इस सम्बन्ध में निगम स्वतन्त्र है, उस पर १९३८ के कानून की धाराएँ लागू नहीं होती। १९५७ के निगम के विनियोग का विवरण निम्नांकित है :

	करोड़ रु०	कुल का प्रतिशत
१. सरकारी ऋण-पत्र	२६०.६१	७०
२. कम्पनियों के अंश व ऋण-पत्र	६९.१४	१८
३. बंधक भूमि	१३.८६	३
४. मकान	२१.३८	५
५. अन्य	१६.९१	४
	३८१.९०	१००
जोड़		

श्रालोचना

गत वर्षों में निगम ने अपनी सेवा का स्तर उच्चतर करने एवं भारतीय जनता को अधिकधिक संरक्षण देने में कोई बात उठा नहीं रखी। उसने कई नई योजनाएँ (जनता पालिसी, सामुदायिक बीमा, देतन वचत योजना, सयुक्त जीवन पालिसी) चालू की हैं जिनसे समाज के विविध अंगों में लाभ उठाया है। निगम ने अपने संचित धन को राष्ट्रीय महत्व के आधारभूत उद्योगों में लगाकर देश में औद्योगीकरण की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। उसने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भी अपार धन दिया है। निगम ने नए-नए कार्यालय ऐसे स्थानों में खोलकर जहाँ पहले कभी नहीं खोले गए थे बीमा के संदेश को अधिक लोकप्रिय एवं व्यापक बनाने का भरसक यत्न किया है। निगम ने उचाई एजेंट नियुक्त करके ग्रामीण जनता से उचाई के प्रश्न को सरल कर दिया है। निगम ने अपने नित्री लक्ष्य निर्धारित किये हैं और पंचवर्षीय योजना बनाई है। यह योजना १९५६ में प्रारम्भ हुई जिसमें प्रथम वर्ष का नये काम का लक्ष्य १००० करोड़ रुपये रखा गया था जिसे प्राप्त करने में निगम को पूरी-पूरी सफलता मिली। इस भाँति निगम नित प्रति लोकप्रिय होती जा रही है और उसका सेवा क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। तो भी हमें उसे और भी विस्तृत करने के प्रयत्न जारी रखने चाहिये। हमारा उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार तक बीमा का संदेश पहुँचाने का होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि निगम को ८ करोड़ पालिसियाँ चालू करनी चाहियें, किन्तु अभी तक केवल ७० लाख पालिसियाँ ही दी गई हैं अर्थात् निगम के कार्य में दस-ग्यारह गुनी वृद्धि की अभी आवश्यकता है। इस आदर्श स्थिति तक पहुँचने के लिए आवश्यकता है कि निगम के प्रति जहाँ भी उँगवी उठाई जाती हो उन दोषों को दूर किया जाए।

निगम के प्रति एक दोषारोपण यह किया जाता है कि वह एक महान वित्तीय संगठन को आदर्श प्राथमिक सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं चला रही और न वह वर्तमान निहित-सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने में ही सफल हुई है। बहुधा अस्वाभाविक लक्ष्य नियत कर दिए जाते हैं और अकुशल प्रबन्ध, बढ़ते हुए व्यय तथा अन्य अस्वाभाविक ढंगों से इन्हें प्राप्त करने के यत्न किए जाते हैं जिनसे जनता की करोड़ों की वचत यो ही व्यर्थ वह जाती है। निगम के कार्य का समुचित फेलाव भी नहीं होता और वर्ष भर के बीमा कार्य का एक बड़ा भाग वर्ष के अन्तिम दो महीने में ही पूरा होता है। यह कार्य में देरी होने का सूचक अंक है। प्रस्तावों को पूरा करने में असाधारण देरी होती है।

इस बात की आवश्यकता है कि बीमा के संदेश को ग्रामीण क्षेत्र में अधिक ले जाया जाए जहाँ लोगों में वचत की भावना कम है और जो कुछ भावना है उसके लिए उपयुक्त साधन नहीं हैं इसके लिए जनता पालियों को और भी अधिक सफल बनाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले मेलों और प्रदर्शिनियों में प्रचार कार्य

बढ़ाना चाहिए। तभी यह संभव है, क्योंकि इन मेलों में करोड़ों ग्रामीण इकट्ठे होते हैं जहाँ सहज प्रचार संभव है। हाल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए निगम ने एक डाक्टर-हीन योजना (Non medical Scheme) चालू की है। इसे आगे बढ़ाने की निता त आवश्यकता है। निगम को सर्वेक्षण को धीरे विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी क्षेत्रों मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण सर्वेक्षण करा कर उचित आंकड़े संकलित करने में कोई देरी न करनी चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक योजना बनाने के लिए पूर्ण एवं अधिकृत आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं।

“खाद्यभाव के उपरान्त मकानों के अभाव की समस्या इस समय भारत की एक भयानक समस्या बन गई है।”

—एत० डी० पुनेकर

३१—मकानों की समस्या

रूपरेखा

- १ मकानों का महत्व
- २ समस्या का स्वरूप
- ३ कमी के कारण
- ४ सरकारी हस्तक्षेप
- ५ सरकारी संगठन
- ६ मकान निर्माण की प्रगति
- ७ विविध योजनाएँ
 - (क) औद्योगिक आवास
 - (ख) निम्न आय वर्ग
 - (ग) मध्य वर्ग
 - (घ) धनी वस्तियाँ एवं हरिजन आवास
 - (ङ) विस्थापित वर्ग
 - (च) बगीचा उद्योग
 - (छ) सरकारी कर्मचारी
 - (ज) ग्रामीण क्षेत्र
- ८ उपसंहार ।

महत्व

भोजन और वस्त्र के उपरान्त मनुष्य की तीसरी अनिवार्य आवश्यकता मकान है। आवास-व्यवस्था का मनुष्य के स्वास्थ्य और सुख से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सुन्दर और स्वच्छ निवास स्थान का मनुष्य को कार्य-शक्ति, कार्य-कौशल और कार्य-क्षमता

पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्योग, व्यवसाय और प्रशासन व्यवस्था के लिये आवास व्यवस्था लगभग अनिवार्य है।

समस्या का स्वरूप

श्रव से कुछ दिन पूर्व तक हमारे देश में आवास व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के लगभग सभी पहलुओं की अपेक्षा की जाती रही है। बहुधा नगरो का भी अन्वयस्थित विरासत हुआ है। इस समय हमारी मकानों की समस्या का दो रूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के अभाव की समस्या नहीं है। सभी ग्राम्य वासी मकान मालिक होते हैं चाहे मकान पत्ता हो चाहे कच्चा अथवा केवल फूस की भीड़। इसका विपरीत नगरो में बहुधा लोग किरायेदार हैं। नगरो की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण किराये के मकान मिलना भी दुर्लभ हो गया है और मकान किराये अनेक लोगों की देय शक्ति का बाहर हो गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ में देश के नगरो में २५ लाख मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया था। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में यह कमी बढ़कर ५३ लाख हो गई। इस समय स्थिति इतनी ही अधिक बिगड़ी हुई बताई जाती है जितनी कि यह प्रथम योजना काल में बिगड़ गई थी अर्थात् द्वितीय योजना के अन्त में योजना का प्रारम्भ की अपेक्षा मकानों की कमी दुगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। तृतीय योजना का प्रारम्भ में केवल नगरो में ७८ लाख मकानों की कमी आई है। इस भाँति हमारी मकानों की समस्या का भयानक रूप बड़े नगरों में दिखाई देता है जहाँ जनसंख्या का भारी जमघट हो गया है और आज का सभ्य और शिष्ट नागरिक बजारों की भाँति पड़ाव डाल पड़ा दिखाई देता है।

कमी के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के समय से सभी औद्योगिक देशों में मकानों की समस्या भयानक हो गई है। भारत में इसके भयानक रूप धारण करने का कारण जनसंख्या की अपार वृद्धि है। गाँव की अपेक्षा बड़े नगरो की जनसंख्या और भी तेजी से बढ़ रही है। घनी माँसी, महत्वाकांक्षी और शान्तिप्रिय लोग गाँव छोड़कर नगरो में बसते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी, कार्य के साधना और आधुनिक जीवन की सुख सुविधाओं का अभाव तथा नगरो का औद्योगीकरण एवं आकर्षण इस प्रवास का मुख्य कारण हैं। द्वितीय युद्ध और उसके उपरान्त के वर्षों में, विशेषतः योजना काल में औद्योगीकरण का कारण नगरो की जनसंख्या विशेष तेजी से बढ़नी गई है। देश विभागों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई शरणार्थी समस्या ने भी मकानों की कमी को बढ़ाने में बड़ा योग नहीं दिया। भवन निर्माण सामग्री का अभाव और ऊँचे मूल्य तथा किराया नियंत्रण कानून भी इस समस्या की प्रज्वलित ज्वाला में आहुति देते रहे हैं। अतएव मकानों की बढ़ती हुई माँग से भवन-निर्माण की गति लगभग १६% पीछे रह गई है। १९५४ में लिये गये आँकड़ों से ज्ञात हुआ है कि गत दशक में कानपुर नगर में जनसंख्या ६६% बढ़ी किंतु मकान व्यवस्था में

केवल ७% वृद्धि हुई। इलाहाबाद के सम्बन्धित घाँकड़े ३५% और १०%, बनारस के ३४% और २%, आगरा के ४५% और ११ प्रतिशत तथा लखनऊ के २८ प्रतिशत और ७½ प्रतिशत थे।

सरकारी हस्तक्षेप

इस समस्या का मुख्य पहलू मकानों के मूल्य अथवा उनके किराये का लोगों को भ्राय से सम्बन्ध स्थापित करना है। भारतवर्ष में एक बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो अपनी आर्थिक भ्राय से मकान निर्माण के लिये कुछ भी बचाने में असमर्थ हैं। विनियोग के दृष्टिकोण से भवन-निर्माण आकर्षक विषय नहीं है। जो कुछ पूँजी मकान निर्माण के लिये पूँजीपतियों द्वारा लगाई जाती है उससे उच्चवर्ग के लोगों के लिये भले ही कोठियाँ खड़ी हो जायँ, निम्न श्रेणी के लोगों को इससे कोई सुविधा नहीं होती। ऐसी स्थिति में और विशेषतः लोक-कल्याण शासन, समाजवादी समाज और संतुलित आयोजन इत्यादि उद्देश्यों के परिपालन के लिये इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया। हमारे देश में सरकार का ध्येय जनसंख्या के अनुपात में मकानों की वृद्धि करना, वास्तविक लागत व्यय पर लोगों को मकान उपलब्ध करना अथवा ऐसे किराये पर मकान देना है जो अधिकतर लोगों की देय शक्ति के अनुकूल हो। सरकार ऐसे लोगों के लिये आवास व्यवस्था करना चाहती है जिनकी आर्थिक स्थिति भवन निर्माण के लिये अनुकूल नहीं है। ऐसे लोगों को बचत की प्रेरणा प्रदान की जाती है और बचाये हुये धन को मकान बनाने के लिये लगाने को लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार विविध प्रकार की सहायता भी प्रदान करती है। सरकार की ओर से मकान बनाकर उचित किराये पर उठाये जाते हैं। भवन-निर्माण के लिये आर्थिक सहायता और ऋण भी दिये जाते हैं। कर सम्बन्धी छूट देकर भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकारी संगठन

मकानों की भारी कमी देखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष संगठन स्थापित करने का निश्चय किया और मई १९५२ में निर्माण, आवास तथा पूँजी मंत्रालय की स्थापना की। १९५४ में राष्ट्रीय निर्माण संस्था (National Buildings Organisation) जिसका उद्देश्य अनुसंधान और सम्बन्ध द्वारा भवन-निर्माण व्यय में कमी करना तथा लोगों को आवश्यक सूचना देना है। इस संगठन का मुख्य अंग राष्ट्रीय निर्माण परिषद् है। इसी वर्ष एक केन्द्रीय ग्रामीण संगठन (Central Rural Cell) की भी स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यक सहायता और परामर्श प्रदान करना है।

भवन निर्माण की प्रगति

देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आदिमार्ग के साथ-साथ नगरों में मकानों

की कमी दूर करने के दल किये जाने लगे। इस योजना में श्रमिक वर्ग, निम्न आय क लोग और बिस्थापितों के लिये समुचित आवास व्यवस्था की योजनाएँ चालू की गईं। योजना की अवधि में ६३ करोड़ रुपये लगाकर ७ लाख ४० हजार मकान सरकारी क्षेत्र में बनाये गये जिनमें से ७७ हजार श्रमिक वर्ग के लिये ४० हजार निम्न आय के लोगों के लिये, ३ लाख २३ हजार शरणार्थियों के लिये और ३ लाख मकान सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये। व्यक्तिगत क्षेत्र में इसी अवधि में ७ लाख ५० हजार मकानों का निर्माण हुआ। इस भाँति प्रथम योजना काल में १४ लाख ९० हजार नये मकान भारतीय नगरों में बने।

द्वितीय योजना में १२० करोड़ रुपये मकान निर्माण के लिये योजना आयोग ने रखे। यह अनुमान लगाया गया था कि कुल मिलाकर १ हजार करोड़ रुपये भारत सरकार, राज्य की सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तिगत पूँजीपतियों द्वारा इस काम में लगाये जा सकेंगे तथा योजना के अन्तर्गत १२ लाख और व्यक्तिगत प्रयत्नों से १० लाख अर्थात् २२ लाख मकान इस योजना की अवधि में बन जाएँगे। द्वितीय योजना में सरकारी कर्मचारियों, ग्रामवासियों, धनी वस्तियों में रहने वाले लोगों, हरिजनों, बगीचा उद्योगों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजनाएँ चालू की गईं। द्वितीय योजना के १९५८ में संशोधन करते समय अनुमानित धन राशि १२० करोड़ रुपये से घटाकर ८४ करोड़ रुपये करदी थी जिसमें से ५६ करोड़ रुपये व्यय किए गए। रिजर्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार शहरों में मकान बनवाने में प्रथम योजना काल में कुल ५०० करोड़ रुपये और दूसरी योजना काल में ६०० करोड़ रुपये व्यय किए गए। तीसरी योजना में १२० करोड़ रुपये रखे गए हैं, किन्तु कुल १२०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

विविध योजनाएँ

(क) औद्योगिक आवास (Industrial Housing)—प्रथम और द्वितीय योजना के अन्तर्गत चालू की गईं भवन निर्माण योजनाओं में यह पहली योजना है जिसे सितम्बर १९५२ में कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिये चालू किया गया था। इसके अन्तर्गत फ़ैक्टरी कानून और खान कानून के अन्तर्गत आने वाले सभी श्रमिक सम्मिलित हैं। इस योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य की सरकारों अथवा आवास बोर्डों को मकानों की लागत का ५०% ऋण और ५०% आर्थिक सहायता के रूप में देती है। इसी भाँति उद्योगपतियों को ३७% ऋण और २५% आर्थिक सहायता तथा श्रम जीवियों की सहकारी समितियों को ५०% ऋण और २५% आर्थिक सहायता देती है। प्रथम योजना काल में इस सुविधा से लाभ उठाकर ७७ हजार मकान बने और द्वितीय योजना में १ लाख ४२ हजार।

(ख) निम्न आय वर्ग—यह कार्यक्रम नवम्बर १९५४ में राज्य की सरकारों को ऋण देने के सम्बन्ध में चालू किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को भवन

निर्माण के लिये ऋण देना है जिनकी आय ६,००० रु० वार्षिक अथवा ५०० रु० मासिक से अधिक नहीं होती। राज्य की सरकारें यह ऋण ५.३% व्याज पर ३० वर्ष की अवधि के लिये ऐसी आय वाले व्यक्तियों अथवा उनकी सहकारी समितियों को देती हैं। ऋण की अधिकतम सीमा मकान और भूमि के मूल्य का ८० प्रतिशत अथवा ८ हजार रुपए प्रति मकान है। प्रथम योजना काल में इस सुविधा से लाभ उठाकर ४० हजार मकान बनाये गये तथा द्वितीय योजना काल में ६८ हजार मकान।

(ग) मध्यम वर्ग—वर्षों मध्यम वर्ग के लिए प्रथम योजना काल में ही कोई कार्यक्रम बनाने का विचार था, किन्तु कई कारणों से कोई सक्रिय कदम न उठाया जा सका। जीवन बीमा क राष्ट्रीयकरण के कारण यह योजना कई वर्ष तक यो ही पड़ी रही। फरवरी सन् १९५६ में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम की सहायता से इसे अन्तिम रूप दिया। इसके अन्तर्गत ६,००१ रुपए से १२,००० रुपए तक की वार्षिक आय के लोगों को ५।१ प्रतिशत व्याज की दर से २५ वर्ष के लिये ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

(घ) घनी बस्तियाँ एवं हरिजन आवास—यह योजना ५ मई १९५६ में बनाई गई थी। इसके अन्तर्गत घनी बस्तियों में रहने वालों और हरिजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य की सरकारों अथवा स्थानीय संस्थाओं को २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की है। मकान की लागत का शेष २५ प्रतिशत राज्य की सरकार अथवा स्थानीय संस्था को अपनी ओर से देने की व्यवस्था करनी आवश्यक समझी गई। इस योजना से बड़ी लोग लाभ उठा सकते हैं जिनकी आय बम्बई और कलकत्ता में २५० रुपया मासिक और अन्यत्र १७५ रुपए मासिक से अधिक न हो। द्वितीय योजना काल में १,१०,००० मकान बनने की सम्भावना की गई।

(ङ) विस्थापित लोग—विस्थापित लोगों के बसाने और उन्हें काम देने की योजनाएँ देश विभाजन के फलस्वरूप चालू की गई थी। प्रथम योजना में इस काम के लिए १३६ करोड़ रुपए खर्चे गए थे जिसमें से ६५ करोड़ रुपए भवन-निर्माण में खर्च हुए। द्वितीय योजना में इस विषय पर ६० करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया था। अनेक बड़े नगरों में विस्थापितों के लिए बस्तियाँ बसाई गई हैं और कई नये नगर भी इन लोगों के बसाए गए हैं। दण्डकारण्य योजना की सफलता के साथ-साथ विस्थापितों के बसाने की समस्या लगभग पूर्णतः हल हो जायेगी।

(च) बगोचा उद्योग—इस वर्ग के लोगों के लिए अप्रैल १९५६ में आवास व्यवस्था का कार्यक्रम बनाया गया था। प्रारम्भ में मकान के मूल्य के ८० प्रतिशत के बराबर अथवा उत्तरी भारत में २,००० रुपए तक और दक्षिणी भारत में १,६०० रु० तक ऋण रूप में बगोचा उद्योग में काम करने वाले लोगों को दिए जा सकते थे। अगस्त १९५७ में उपर्युक्त सीमाएँ बढ़ाकर क्रमशः २४०० रु० और १९२० रुपए तक बढ़ी गईं। द्वितीय योजना काल में ११,००० मकान बनने की सम्भावना की गई।

(घ) सरकारी कर्मचारी—केन्द्रीय और राज्य की सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था करना एक सामान्य प्रथा समझी जाती है। आवश्यक सेवाओं (रेल और देश रक्षा विभागों) और छोटे नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। युद्धोपरान्त काल में इस और विशेष ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना काल में विभिन्न सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए लगभग ३ लाख मकान बनवाये। द्वितीय योजना में विभिन्न सरकारों ने ५ लाख ७६ हजार मकानों की व्यवस्था की। इनके अतिरिक्त १ लाख ७७ हजार मकान खनिज उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए भी केन्द्रीय सरकार की ओर से बनवाए गए।

(ज) ग्रामीण क्षेत्र—प्रथम योजना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम न बनाया जा सका, तो भी देश के विभिन्न भागों में १८ हजार आदर्श मकान बनवाए गए और १५ हजार मकानों का सुधार किया गया। यह व्यवस्था सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत की गई। द्वितीय योजना में अक्टूबर १९५७ में ग्राम सुधार कार्य के आवश्यक अंग के रूप में एक योजना बनाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक सहायता प्रदान करना तथा मकानों का सुधार करना है। सुधार व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि १० वर्ष के अन्तर्गत सारे गाँवों के मकानों का पुनर्निर्माण हो सके। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा लागत व्यय के ५० प्रतिशत अथवा १५०० रुपए प्रति मकान ऋण के रूप में सीमित होगी। यह ऋण व्यक्तियों अथवा सहकारी समितियों को २० वर्ष के लिये दिये जायेंगे। द्वितीय योजना में ५,००० ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाएँ कुछ चुने हुए गाँवों में चालू की गईं। इन पर ५ करोड़ रुपए व्यय करके १ लाख २० हजार मकान बनाए गए।

इन योजनाओं की प्रगति प्रत्यन्त धीमी है। बहुधा आर्थिक सहायता अथवा ऋण व्यवस्था ऐसी हैं जिनकी या तो लोगों को जानकारी नहीं है या तो उनकी शर्तें कठोर हैं। जिसे निम्न वर्ग ठहराया गया है वह वास्तव में मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग व्यावहारिक दृष्टि से उच्च वर्ग। यद्यपि आर्थिक सहायता भवन निर्माण के लिए आवश्यक है किन्तु केवल धन से मकान नहीं बन सकते। धन से भी अधिक आवश्यक ईंटें, सिमेंट, लोहा, चूना और अन्य सामग्री हैं जिसके मूल्य प्रत्यन्त ऊँचे हो गये हैं और उनका मिलना भी दुर्लभ हो गया है। भवन निर्माण की प्रगति में स्थानीय संस्थाओं के कानून भी एक भारी बाधाएँ हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने से ही भवन निर्माण की उचित प्रगति सम्भव है।

‘ जो विकासशील अर्थ-व्यवस्था अपने साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, उसे इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है कि वह विशिष्ट यत्र सामग्री, धातुएँ और कल-पुर्जें आदि का अधिकाधिक मात्रा में विदेशों से आयात करे, परन्तु वह उनका मूल्य कुछ समय तक अपने निर्यात-व्यापार की कमाई द्वारा नहीं चुका पाती। इस परिस्थिति में विदेशी साधनों की आवश्यकता पड़ना अवश्यम्भावी है। इस तरह की सहायता भारत के आर्थिक विकास में गति लाने में काफी समर्थ सिद्ध हुई है और उसकी जितनी भी कीमत आँकी जाए, कम है।’

—योजना आयोग

३२—विदेशी पूँजी

रूप-रेखा

१. विदेशी पूँजी का महत्व ।
२. विदेशी पूँजी के प्रकार ।
३. विदेशी पूँजी का आगमन ।
४. विदेशी पूँजी की मात्रा ।
५. विदेशी पूँजी के लाभ ।
६. दोष ।
७. सरकारी नीति ।
८. उपसंहार ।

महत्व

उत्पादन का पूँजी से सीधा सम्बन्ध है। आज के पूँजीवादी युग में उत्पादन के साधनों में पूँजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक विशालकाय व्यवसाय को न केवल यन्त्र उपकरणों तथा चल-प्रचल सम्पत्ति के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों (भूमि, श्रम, संगठन) के जुटाने के लिये भी

पूँजी प्रप्रेक्षित है। किसी औद्योगिक संगठन की उत्पादन-सामर्थ्य पूँजी के सरल, नियमित और सशक्त प्रवाह पर निर्भर है।

पूँजी के प्रकार

पूँजी दो प्रकार की हो सकती है, देशी और विदेशी। मुद्द एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिये स्वदेशी पूँजी ही वाञ्छनीय है। जिन अ विकसित देशों में पर्याप्त स्वदेशी पूँजी उपलब्ध नहीं, वहाँ विदेशी पूँजी का उपयोग कर लेने में कोई आपत्ति नहीं। प्रायः के विश्व व-घुसव और विश्व सहयोग के युग में रुस और संयुक्त राष्ट्र जैसे धनी देशों को छोड़कर कोई विरला ही राष्ट्र ऐसा होगा जहाँ थोड़ी-बहुत मात्रा में विदेशी पूँजी न लगी हो।

प्रयोग के दृष्टिकोण से भी पूँजी के दो रूप हो सकते हैं; स्थायी पूँजी और अस्थायी अर्थात् कार्यशील पूँजी। यहाँ पर हमारा मन्तव्य केवल स्थायी दीर्घकालीन पूँजी की समस्या पर विचार करना है।

विदेशी पूँजी का आगमन

यूरोपीय जातियों के आगमन के साथ-साथ भारत में विदेशी पूँजी का पदार्पण हुआ। तब से १८ वीं शताब्दी के अन्त तक वणिज्य पूँजी का प्राधान्य रहा। सन् १५०० में सर्वप्रथम पुर्तगाल वालो ने अपनी पूँजी लगाकर कालीकट में एक कोठी खोली। उसके लगभग एक शताब्दी उपरान्त अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। उसी समय डच और फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापारिक कोठियाँ बनाईं। ये सभी जातियाँ केवल व्यापारी की हैसियत से अपना रुपया भारत में लगाती रहीं।

धीरे-धीरे ये व्यापारी उद्योगपति बन गये और इन्होंने बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने प्रारम्भ किये। चाय, कढ़वा, और रान के सेतों में काम प्रारम्भ किया; रेलों, सड़कों और गहरों के निर्माण में अपनी पूँजी लगाई, कोयले की खानें खोदने लगे, सन और रुई के वस्त्र बुनने के कार्यालय, बैंक तथा बीमा के व्यवसाय प्रारम्भ किये। इस भाँति देश में आधुनिक उद्योगों का जन्म हुआ और इस काल में लगी हुई विदेशी पूँजी औद्योगिक पूँजी कहलाई। यह स्थिति सन् १९१४ तक बनी रही।

प्रथम मुद्द के उपरान्त भारत ने औद्योगिक संरक्षण की नीति अपना कर विदेशी पूँजी का आगमन सीमित कर दिया, तो भी देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण विदेशी पूँजी का अधिकाधिक प्रयोग होता रहा। इस युग में अत्यन्त रूप में बढ़वा विदेशी पूँजी का सचय हुआ। स्वतन्त्रता के समय तक इस सम्बन्ध में हमारी कोई स्थायी नीति नहीं थी। स्वतन्त्र भारत में किसी स्थायी नीति का निर्धारण आवश्यक था। अतएव इस प्रश्न को लेकर एक भारी वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। यद्यपि इस समय भारत सरकार द्वारा एक निश्चित नीति घोषित की जा चुकी है, तो भी यह वाद-विवाद सर्वथा शान्त नहीं हुआ है।

(३) औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में जोखिम का अर्थ अधिक होना है। यह सम्भव है कि प्रारम्भिक जोखिम विदेशी पूँजी उठाये और स्थापित उद्योगों को देशवासी प्राप्त कर लें। भारत में यही हो रहा है। सभी नये उद्योग विदेशी सहायता से स्थापित किये जा रहे हैं जिन्हें निश्चित अवधि के उपरान्त भारत सरकार अथवा भारतवासी ले लेंगे।

(४) यह पूँजी बहूरा समुन्नत और समृद्ध देशों से आती है जो अपने साथ उन्नतता की नई विधायक, नई मशीनें और नए कारखाने लेकर आती है। इनके प्रवेश से देश को प्रारंभ लाभ होना स्वाभाविक है।

(५) विदेशी पूँजी के साथ-साथ प्रतियोगिता वृद्धि होती है जो कि देश के उद्योगों को चौकन्ना रखने और उन्नतता के ऊँचे ढंग अपनाते के लिए बाध्य करती है।

(६) इससे देश में स्थायी सम्पत्तियों की सृष्टि होती है तथा काम के साधन बढ़ते हैं।

(७) अधिकसिद्ध देशों के विकास का एक मात्र श्रेय विदेशी पूँजी को ही है क्योंकि बिना पूँजी के साधनों का उपयोग सम्भव नहीं।

दोष

(१) विदेशी पूँजी का सबसे अधिक भयानक रूप राजनैतिक क्षेत्र में दिखाई देना है। विदेशी पूँजी के साथ विदेशी प्रभुत्व और प्रभाव अवश्यम्भावी है। व्यापार के पीछे-पीछे ध्वजा चलती है अर्थात् अधिक प्रभुत्व के साथ-साथ राजनैतिक प्रभुत्व स्वाभाविक है। अंग्रेजी शासन काल में हम इसके कड़वे फल चख चुके हैं।

(२) विदेशी पूँजी की सहायता से देश के प्राकृतिक साधनों का दोहन और विकास बहूरा विदेशियों के लिए ही अधिक लाभदायक सिद्ध होना है। परिस्थितियों का स्वाभाविक ज्ञान न होने के कारण विकास की गतिविधि उचित दिशा में नहीं हो पाती।

(३) इससे देश के युवकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी अवसर प्राप्त नहीं होते और देश के उद्योग-धन्धों का संचालन एवं प्रबन्ध सर्वथा विदेशियों के हाथ में रहता है।

(४) रक्षा तथा आधारभूत उद्योगों में विदेशी पूँजी का विनियोग भयानक समझा जाता है।

(५) देशी पूँजी के द्वारा देश में पूँजी निर्माण की गति बढ़नी है क्योंकि उद्योगों से प्राप्त लाभ भी बहूरा पूँजी बन जाते हैं। इससे देश की औद्योगिक परिधि उत्तरोत्तर चौड़ी होनी चनी जाती है। विदेशी पूँजी के लाभ बहूरा विदेश चले जाते

हैं और देश इस व्यापारिक शीघ्रोगीकरण में बचिन रह जाता है। सन् १९२५ में विदेशी कम्पनियों को २५ दगाड नए लाभ हूपा तिसर ते केवल १० करोड रुपए देश में रहे।

सरकारी नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा करते समय भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इस घोषणा से विदेशी पूँजी का भविष्य अज्ञान मन हो गया और विदेशी पूँजी प्रत्याह्वित हो गई। इससे देश की आत्मनिर्भरता का आशय बनने में बाधा उपस्थित होन लगी। अतएव अगस्त १९४६ में भारत सरकार ने अपनी विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति की इस भाँति घोषणा की —

(क) सामान्य औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन करने में देशी और विदेशी औद्योगिक सहयोगों में कोई भेदभाव नहीं रखना जायगा।

(ख) विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों का ध्यान में रख कर विदेशी पूँजी द्वारा कमाए हुए लाभ का विदेश भेजने के लिए आवश्यक सुविधाओं प्रदान की जायेंगी और पूँजी का स्वदेश गमन पर कोई रोक नहीं लगाई जायगी।

(ग) उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय उचित हानिपूर्ति के उपरांत ही सरकार ऐसे उद्योगों को अपने स्वामित्व में लेगी।

उक्त नीति को भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का एक अंग मान लिया है और उनके कार्यान्वयन करने के लिए विदेशी पूँजी का पूर्णतः स्वागत किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा हमें पूँजीगत माल, औद्योगिक विशेषज्ञों और विदेशी एक्सचेंज अधिकारों के उपयोग करने के अवसर मिलते हैं।

उपसंहार

विद्यमाने कट्टर अनुभव का ध्यान रखते हुए विदेशी पूँजी के विनियोग के सम्बन्ध में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। केवल ऐसे क्षेत्रों में विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनमें कि विदेशी पूँजी के कारण किसी प्रकार के मजदूरी की आर्जना न हो। देश तथा सम्बन्धी और आवाहनभूत उद्योगों में विदेशी पूँजी का विनियोग वाञ्छनीय नहीं है। नैतिक दृष्टि से इस सिद्धान्त को मानते हुये भी हमने इसका उल्लंघन किया है। हमारे लोह-इस्पात के नए कारखाने विदेशी सहायता से स्थापित हुए हैं। तो भी हमें इसे एक अलगकालीन व्यवस्था मानकर उससे शीघ्र छुटकारा पाने का यत्न करना चाहिए।

विदेशी पूँजी स्वीकार करते समय ऐसी शर्तें लगानी आवश्यक हैं जिनके द्वारा विदेशी पूँजी देश में आए किन्तु विदेशी प्रमुख देश में न जाए। इस सम्बन्ध में विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से अर्थों के रूप में विदेशी पूँजी का विनिर्देश बाध्यता बसाया जाता है। ऋण रूप में विदेशी पूँजी का आगमन बुरा नहीं माना जाता, किन्तु यह श्रेष्ठ विदेशी सरकारों अथवा महत्वपूर्ण संस्थाओं (विश्व बैंक, आयात-निर्गत बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम) से ही लिए जाने चाहिये।

हाल के वर्षों में विदेशी पूँजी का भारत में बढ़ता साम्प्रदायी के रूप में आगमन हुआ है। यह साम्प्रदायी की प्रथा बाध्यता है, किन्तु इस साम्प्रदायी से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले लेनी चाहिए। नगरीयों को शर्तों में देश के युवकों को प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था प्रचलन कर लेनी चाहिए।

गत वर्षों में विदेशी पूँजी की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई है। इस बात की आवश्यकता है कि विदेशी पूँजी का विनिर्देश देशी पूँजी के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए होना चाहिए न कि उसके ह्रास के लिए। देश की स्वावलम्बन की नीति प्रपनानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी पूँजी के विनिर्देश हमारी देशी शक्ति के बाहर न चला जाय।

संक्षेपिका लेखन एवं अपठित

विषय-प्रवेश

किसी भाषा की सामान्य जानकारी का एक प्रचलित ढंग उस भाषा में लेख लिखने एवं अपठित का अभ्यास है। अपठित से तात्पर्य पाठ्य पुस्तक के प्रतिरिक्त स्थान से लिए हुए वक्तव्य, लेख अथवा अवतरण से है। इस अवतरण के अध्ययन से ज्ञानवृद्धि के बहुधा चार मार्ग हैं : (क) अवतरण का सारांश (Summary) लिखना, (ख) उसकी संक्षेपिका लिखना, (ग) पारिभाषिक शब्दों अथवा शब्द-समूहों का अर्थ अथवा भावार्थ लिखना, एवं (घ) अवतरण के अनुसार कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना। इन चारों क्रियाओं में संक्षेपिका लिखने की क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन है और सबसे अधिक अभ्यास की अपेक्षा करती है। अतएव सभी परीक्षाओं में संक्षेपिका को विशेष महत्व दिया जाता है। इस पुस्तक में विद्यार्थी वर्ग की इस आवश्यकता को दृष्टिगोचर करके ही संक्षेपिका की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और उसके अभ्यास का मार्ग भी बताया गया है।

संक्षेपिका की परिभाषा

संक्षेपिका किसी मूल विषय, वक्तव्य, विवरण, लेख अथवा अवतरण का सार-गर्भित संक्षिप्त रूप है। यह विस्तृत विवरण को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की एक कला है। इसका मुख्य उद्देश्य विषय को अधिक स्पष्ट, बोधगम्य, सहज ग्राह्य बना कर श्रम और समय की बचत है। वस्तुतः यह मुद्रण यंत्र और टंकन यंत्र की भाँति ही प्राधुनिक युग का एक श्रम संचक यंत्र है। संक्षेपिका पाठक को मूल विषय का कम प्रयास और कम समय में ज्ञान कराने का एक साधन है। संक्षेपिका लिखते समय मूल अवतरण की काट-छाँट उसी सावधानी से की जाती है जिस सावधानी से एक चतुर माली उपवन की लताओं की काट-छाँट करके उन्हें अधिक सुन्दर, आकर्षक और उपयोगी बनाना है।

संक्षेपिका अपने छोटे रूप में भी उसी भाँति पूर्ण और स्पष्ट होती है जैसे किसी बड़े चित्र का छोटा रूप जिसमें मूल चित्र की सभी रेखाएँ और सभी हाव-भाव विद्यमान रहते हैं। उद्यान का माली किसी आवश्यक लता-पल्लव से हाथ नहीं लगाता, केवल अनावश्यक पर कँची चलाता है। उसी भाँति संक्षेपिका लेखक का कर्तव्य है। आवश्यक तर्क और विचार निकाले नहीं जाते और अनावश्यक भाव छोड़े नहीं जाते।

किसी अवतरण का सारांश लिखने और संक्षेपिका बनाने में अन्तर है। सारांश बनाने में मूल विषय के वाक्य विन्यास, क्रम, शैली, विचारधारा, तर्क इत्यादि को बहुधा

अपने मूल रूप में ही प्रस्तुत करना होता है और अधिक से-अधिक मूल लेख के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। संक्षेपिका में ऐसा नहीं है। संक्षेपिका में बिखरे हुए भावों को क्रमबद्धता के साथ एक सूत्र में बाँध कर इस भाँति प्रस्तुत करना होता है कि विषय शीघ्र और कम प्रयास से समझ में आ सके। कोई विचार, भाव अथवा तर्क मूल लेख में किसी कारणवश दबे रह गए हो जिनकी वजह से विषय स्पष्ट न होता हो, तो संक्षेपिका में उन्हें उभार देना चाहिए। इसके विपरीत यदि मूल विषय में कोई तर्क अथवा विचार दुहराए तिहराए गए हो तो संक्षेपिका में उन्हें दुहराने तिहराने की आवश्यकता नहीं है। किसी बात को दुहराना संक्षेपिका का भारी दोष माना जाता है। सारांश लिखते समय लेखक अथवा वक्ता द्वारा कही गई प्रत्येक बात और प्रत्येक तर्क को ग्रहण किया जाता है, किन्तु संक्षेपिका में केवल आवश्यक बातों और तर्कों को सम्मिलित किया जाता है, अनावश्यक बातों को छोड़ दिया जाता है। सारांश सदैव एक सा लिखा जाता है, किन्तु संक्षेपिका अक्सर और उद्देश्य के अनुसार बदल सकती है।

संक्षेपिका और लेख में भी अंतर है। लेख लिखते समय लेखक प्रवाच विषय के पक्ष-विपक्ष के तर्कों का उल्लेख करने, उनकी आलोचना और काट-छाँट में स्वतन्त्र है। संक्षेपिका लिखने में लेखक के विचारों की आलोचना करने, उनके समर्थन अथवा त्याग की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। लेख लिखते समय कोई व्यक्ति निजी विचार व्यक्त करने में भी स्वतन्त्र है, किन्तु संक्षेपिका में उसे यह स्वतन्त्रता भी प्राप्त नहीं है। उसे उसी परिधि के अंतर्गत रहना है जो सीमा मूल लेखक ने बाँध दी है। उसे पूर्ण भक्ति भाव प्रदानाना आवश्यक है। संक्षेपिका लेखक सदैव मूल लेखक का अनुसरण करता है और उसकी विचारधारा के प्रति भक्ति-भाव धरता है।

किसी लेख में रूपक, उपमा, विशेषण, प्रश्न-वाचक, विस्मयादि बोधक, उदाहरण और अलङ्कृत भाषा के लिए पूर्ण स्थान होता है, किन्तु संक्षेपिका में नहीं। संक्षेपिका में किसी बात को न तो घुमा-फिरा कर कहने का अवसर है और न अलङ्कृत भाषा का।

संक्षेपिका के मुख्य गुण

संक्षेपिका का सौंदर्य निम्नांकित गुणों पर निर्भर है। किसी संक्षेपिका में जितने ही अधिक ये गुण होंगे, वह उतनी ही अच्छी समझी जाएगी और अपनी उद्देश्य पूर्ति में वह उतनी ही अधिक सफल होगी।

(१) स्पष्टता—संक्षेपिका लेखक अथवा वक्ता के विचारों का शुद्ध और सच्चा विवरण होना चाहिए और उसे सर्वथा वही विचार व्यवक्त करना चाहिए जिसे कहने का मूल लेखक अथवा वक्ता का उद्देश्य था।

(२) सुबोधता—संक्षेपिका में दुर्ग्रह शब्दों अथवा वाक्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अस्पष्टता संक्षेपिका का सबसे बड़ा दोष है। संक्षेपिका इतनी सुबोध और सुस्पष्ट भाषा में लिखी-जानी चाहिए कि पाठक उसे जिना प्रयास समझ सके।

(३) सक्षिप्तता—संक्षेपिका का सबसे बड़ा गुण उसका सक्षिप्त रूप है, किन्तु यह रूप अक्सर और उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। सामान्यतः संक्षेपिका

अपने मूल आकार के एक तिहाई के बराबर होनी चाहिए, किंतु यह अवतरण की प्रकृति पर निर्भर है। कोई अवतरण इतने सारगर्भित हो सकते हैं कि उनका एक तिहाई कर देना भी कठिन होता है और कोई इतने सारहीन कि उनका दसवाँ रूप सहज प्रस्तुत किया जा सकता है।

(४) पूर्णता—सक्षिप्त होने के साथ-साथ संक्षेपिका में पूर्णता का गुण होना आवश्यक है। कोई आवश्यक विचार और तर्क छूटना नहीं चाहिए और अनावश्यक तर्क प्रथवा विचार उसमें आना नहीं चाहिए किन्तु वह स्वतः पूर्ण अवश्य होनी चाहिए।

(५) क्रमागत विवरण—यह आवश्यक नहीं कि संक्षेपिका लेखक मूल अवतरण के क्रम का ही पालन करे। उसे अपना निजी क्रम अपनाने की आवश्यकता है। इस क्रम के अपनाने में उसे विचारों और तर्कों के महत्व का ध्यान रखना पड़ता है। महत्वपूर्ण विचारों और तर्कों को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। संक्षेपिका एक क्रमबद्ध विवरण उपस्थित करती है।

संक्षेपिका का महत्व

संक्षेपिका आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। यह आधुनिक युग के अन्य अनेक क्रम सचक्र पत्रों और युक्तियों में से एक है। बड़े से बड़े राजकीय अधिकारी से लेकर सामान्य कर्मचारी तक और प्रकाशक परिषद से लेकर विद्यार्थी तक के लिए इसका ज्ञान अपेक्षित है।

राज के लोकतंत्रीय शासन में एक के ऊपर दूसरे-तीसरे अधिकारी होते हैं और वे त्रीहृत शासन का मूलाधार से उच्च पदाधिकारी और उनकी कार्य पटुता ही होती है। इन पदाधिकारियों और उप-पदाधिकारियों की कार्य पटुता और क्षमता अधीन अधिकारियों के संक्षेपिका-लेखन के ज्ञान पर निर्भर है। यदि अधीन अधिकारी विचारणीय विषय को थोड़े से थोड़े क्षणों में उच्च पदाधिकारियों के सम्मुख रखने में समर्थ हैं तो अन्तिम निर्णय में कोई देर न लगेगी। इसके विपरीत यदि अधीन अधिकारी संक्षेपिका के ज्ञाता नहीं हैं तो उच्च पदाधिकारी का बहुत सा प्रमूल्य समय अनावश्यक विवरणों, लेख-प्रलेखों, पत्र-प्रपत्रों इत्यादि के पढ़ने में व्यर्थ जाएगा और निर्णय में देरी होगी।

राज के व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र भी विश्व-व्यापी है। बहुधा सीदे, सविदे और समभूते पत्र-व्यवहार द्वारा होते हैं। आधुनिक उद्योग-व्यवसाय का प्रतीक संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियाँ हैं जिनके भागीदार देश-विदेश में फैले रहते हैं। व्यापार-व्यवसाय के संबन्धक व प्रबन्धकर्ता को इनसे पत्र-व्यवहार द्वारा ही सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। प्रबन्धकर्ता उस विस्तृत पत्र-व्यवहार को अधीन अधिकारियों की सहायता से शीघ्र समझने और निर्णय करने की क्षमता ग्रहण करता है। ये अधीन अधिकारी सम्बन्ध लेख-प्रलेखों और पत्र-प्रपत्रों को संक्षिप्त करके उच्च-

अधिकारियों का समय और श्रम बचाते हैं और व्यापार-व्यवसाय की गति बढ़ाते हैं।

लोकमत के निर्माता सम्पादक एवं सम्वाददाता तथा ज्ञान-विज्ञान के प्रतीक शिक्षक व शिक्षार्थी की सफलता भी संक्षेपिका के ज्ञान पर बहुत सीमा तक निर्भर है। सम्पादक बिना संक्षेपिका के ज्ञान के विस्तृत विवरणों और वस्तुताओं को सीमित स्थान में व्यक्त करने में असमर्थ रहेगा। इसी भाँति अध्यापक एवं विद्यार्थी का अध्ययन भी बिना संक्षेपिका की जानकारी के सीमित रहेगा।

संक्षेपिका का आकार

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है संक्षेपिका का आकार उसके उद्देश्य और अवतरण के प्रकार पर निर्भर है। संक्षेपिका का आकार मूल लेख अथवा वस्तुता का एक-तिहाई, एक-चौथाई, अथवा और भी कम हो सकता है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं बंधी जा सकती और न कोई निश्चित नियम ही बनाया जा सकता है। विषय के अनुसार कोई अवतरण इतने सारगर्भित हो सकते हैं कि उन्हें अपने मूल आकार के आधे के बराबर भी कठिनाई से किया जा सके और कोई अवतरण इतने सारहीन हो सकते हैं कि उन्हें अपने मूल आकार के दसवें के बराबर भी सहज किया जा सकता है। विद्यार्थियों को इस संबंध में निर्देशानुसार काम करना चाहिए। सामान्यतः परीक्षा में कोई शब्द संख्या अथवा सीमा निश्चित कर दी जाती है। इस सीमा अथवा शब्द संख्या का उन्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि शब्द संख्या ८० माँगी गई हो तो विद्यार्थी अधिक से अधिक ८५ शब्द और कम से कम ७५ शब्द लिख सकता है। इस सीमा के बाहर उसे कदापि न जाना चाहिए। यदि कोई शब्द-संख्या अथवा सीमा न बताई गई हो अथवा जहाँ विद्यार्थी को निर्णय करने में संदेह हो वहाँ उसे विषय को अपने मूल आकार के एक-तिहाई के बराबर छोटा कर देना चाहिए।

संक्षेपिका लिखने की विधि

संक्षेपिका प्रायः दो प्रकार की हो सकती है :

(क) कम शब्द लेख-प्रलेखों की संक्षेपिका जैसे वस्तुता, प्रस्ताव, लेख, वाञ्छा-सूचना अथवा इनका कोई अवतरण।

(ख) पत्र-व्यवहार की संक्षेपिका जिन्में व्यापारिक और सरकारी दोनों प्रकार के पत्र हो सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य प्रथम प्रकार की संक्षेपिका लिखने का है। कमशब्द विवरण की संक्षेपिका लिखने के लिए निम्नांकित विधि अपनाई जा सकती है :—

संक्षेपिका लिखने के लिए प्रस्तुत अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और उसके मूल विषय एवं भावार्थ को समझने का यत्न करना चाहिए। एक बार पढ़ने से भाव समझ में न आये तो दो-तीन बार पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय पारिभाषिक एवं सांकेतिक शब्दों एवं शब्द-समूहों को रेखांकित करते जाना चाहिए अथवा अलग कागज पर लिखते जाना चाहिए।

रेखांकित साकेतिक शब्दों अथवा वाक्यों को एक बार पढ़ कर उनका क्रमबद्ध कर लेना चाहिए और क्रमबद्ध करने के उपरान्त संक्षेपिका का एक प्रारूप (draft) बना लेना चाहिए। प्रारूप बनाने के उपरान्त मूल अवतरण पर एक बार और दृष्टि डाल कर यह देख लेना चाहिए कि कोई तर्क अथवा बात छूट तो नहीं गई।

अब प्रारूप की भाषा और वाक्यों की व्याकरण के नियमों के अनुसार ठीक कर लेना चाहिए। साथ-साथ उसका आकार भी देख लेना चाहिए कि वह बताई गई सीमा के अनुसार है अथवा नहीं। यदि आकार बड़ा हो तो वाक्यों को काट-छाँट कर आवश्यकतानुसार उसे छोटा कर लेना चाहिए। यदि आकार छोटा हो तो उसमें आवश्यक बातें जोड़ लेनी चाहिए।

इतना करने के उपरान्त वाछनीय ढंग की संक्षेपिका बन जाएगी। संक्षेपिका बनाते समय निम्नांकित नियमों का ध्यान रखना चाहिए :—

- (१) अवतरण को एक या दो बार सावधानी से पढ़िए।
- (२) उसकी महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करते जाइए अथवा अलग लिखते जाइए।
- (३) एक बार उन रेखांकित शब्दों अथवा शब्द समूहों को तथा अवतरण को फिर पढ़ जाइए।
- (४) संक्षेपिका का एक प्रारूप बना डालिए।
- (५) प्रत्येक संक्षेपिका को उपयुक्त शीर्षक देना आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है। शीर्षक छोटे से छोटा और ऐसे साकेतिक शब्दों का बना हुआ होना चाहिए कि अवतरण का मुख्य भाव उससे तुरन्त स्पष्ट हो जाए।
- (६) प्रारूप को व्याकरण के नियमानुकूल सुधारिए और उसमें आवश्यक विराम व अर्द्ध-विराम भी लगा दीजिए।
- (७) संक्षेपिका सदैव अन्य पुरुष में और भूतकाल में लिखी जानी चाहिए।
- (८) संक्षेपिका में अपने निजी विचार व्यक्त न कीजिए।
- (९) गद्यात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। संक्षेपिका में विशेषण, प्रसन्नवाचक विस्मयादि बोधक, उपमा, रूपक, अलंकार, दृष्टान्त, इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। भाषा को अलंघित करने के सभी प्रयत्न संक्षेपिका में वर्जित हैं।
- (१०) यदि किसी अवतरण में धाँकड़ों का प्रयोग किया गया है तो उन्हें पूर्णाङ्कों (१०, १००, १०००० इत्यादि) अथवा प्रतिशत में बदल दीजिए ताकि पाठक के लिए वे शीघ्र ग्राह्य हो सकें।

उदाहरण १

कलकत्ते के चोर बाजार की भाँति चोर बाजार शहर के किसी बाजार या मुहल्ले का नाम नहीं है, जिसको आप सहज में तलाश ले और न वह किनारी बाजार या चाँदनी चौक का सा खुला बाजार है, जहाँ ले जाकर ताँगा या टैक्सी वाला आपको लडा कर दे। वह भगवान की भाँति हर एक बाजार में व्याप्त है और साधारण चर्म चक्षुओं से देखने वालों को कहीं भी नहीं है। चोर बाजार उसे इसलिए नहीं कहते हैं कि उसमें नय-विषय करने वाले चोरी का माल बेचते और खरीदते हैं। वह माल प्रायः सरकार की आज्ञा से खरीदा हुआ होता है। खरीददार को धोका-धड़ी से माल नहीं दिया जाता। सोते में उसके घर में संध नहीं लगाई जाती, न उसके भ्रतज्ञाने में गाँठ काटी जाती है। जितनी सावधानी के साथ माल-बायदाद का ब्यनामा लिखा जाता है, उससे भी अधिक चेतनता के साथ चोर-बाजार का सौदा होता है। बचने वाले और खरीददार भी साधारण जनता की दृष्टि में धर्मरक्षा, साहब और साख वाले समझे जाते हैं, फिर यह चोर बाजार क्यों कहलाता है ?

चोर बाजार यह इसलिए कहलाता है कि उसका माल खरीदा तो प्रायः सरकार की आज्ञा से, कि तु बेचा जाता है सरकार की निश्चित की हुई दर के प्रतिभूल और सरकार की जानकारी से बाहर। इसका खुले आम सौदा होते हुए भी इसमें थोड़ी-बहुत गुप-चुप का सा वातावरण रहता है; कीमत की या तो रसीद नहीं दी जाती और यदि दी भी जाती है तो उचित दामों की। उचित दामों के ऊपर के दाम बढ़े खाते जाते हैं। खेल खतम और पैसा हजम। गरज बायली होती है और गरज वाला खुशी-खुशी उल्टे उल्टरे से मुँड जाता है। जिस काम को सबके सामने न कर सके, जिसके करने को सबके सामने न स्वीकार कर सके और जो बिना अधिकार किया जाय, वही चोरी का काम कहलाता है, इसलिए इस तरह के सौदे का नाम चोर-बाजार पडा।

(व्यापार कानून)

प्रश्न

- (१) काले पदों का अर्थ समझाइए।
- (२) इस अवतरण को उपयुक्त शीर्षक दीजिए और उसकी संक्षेपिका बनाइए।
- (३) चोर बाजार जिसे कहते हैं और इसका यह नाम क्यों पडा ?

उत्तर

प्रश्न १—

चोर बाजार

चोर बाजार किसी शहर के बाजार, मुहल्ले अथवा गली का नाम नहीं है। वह सब शहरों तथा सब नियंत्रित बाजारों में व्याप्त है। चोर बाजार में चोरी के माल का नय-विषय नहीं होता और न याहक के साथ कोई धोखा ही किया जाता है। पूर्ण चेतनता के साथ इस बाजार में सौदा होता है। तो भी यह चोर बाजार इसलिए

कहलाता है कि यह सोदा सरकारी नियमों के विरुद्ध एवं निश्चित दर के प्रतिभूल होता है। क्रेता को या तो कीमत की रसीद नहीं दी जाती है और यदि दी जाती है तो जाली। दूसरों से छिपाकर यह सोदा किया जाता है। इसलिए ऐसे सोदे को चोर बाजार कहते हैं, क्योंकि छिपकर किए जाने वाला काम ही चोरी का काम कहलाता है।

प्रश्न २—

वह भगवान की भाँति.....कहीं भी नहीं है—चोर बाजार किसी बाजार विशेष का नाम नहीं है, किन्तु वह सर्वव्यापी भगवान की भाँति सभी नियन्त्रित बाजारों में विद्यमान है जिसे केवल जानकार व्यक्ति ही पहचान सकते हैं।

थोड़ी-बहुत गुप-सुप का सा वातावरण रहता है—यद्यपि चोर बाजार में माल का सोदा खुले प्राम होता है, तो भी उसमें माल के मूल्य अथवा रसीद की बात दूसरों से छिपा कर की जाती है।

खेत खतम और पंसा हजम—चोर बाजार से माल खरीदने वाला व्यक्ति अपनी माँग पूर्ति के स्वार्थवश जान-बूझ कर सरकार की निश्चित की गई दर से अधिक मूल्य देता है। इस दर से अधिक दिए हुए पैसे का उसे कोई हिसाब अथवा रसीद नहीं दी जाती जिसका उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। इस व्यवहार के लेन-देन के उपरान्त वह इस बात को सिद्ध करने में सर्वथा असमर्थ है कि उसने माल का अधिक मूल्य चुकाया है और बात वही समाप्त हो जाती है।

गरज बावली होती है.....मुँड़ जाता है—स्वार्थवश मनुष्य दुकानदार के चंगुल में फँस जाता है और उसे मनमाना मूल्य देने पर उतारू हो जाता है। इस भाँति वह अकारण हानि सहन करता है जिसके सम्बन्ध में वह किसी से उचित-अनुचित की चर्चा भी नहीं कर सकता।

उहटे उस्तरे से मुँड़ जाता है—जान-बूझ कर हानि सहन करता है।

प्रश्न ३—

चोर बाजार किसी बाजार विशेष को नहीं कहते। यह बाजार सभी नियन्त्रित बाजारों में उपस्थित रहता है। जिन वस्तुओं की मात्रा देशकी आवश्यकता-पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती और उनके मूल्यों में अपार वृद्धि होने लगती है। उनके मूल्य अथवा क्रय-विक्रय पर सरकार नियन्त्रण लगा देती है। ऐसी वस्तुओं अथवा माल को सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर सरकारी नियमों के अनुसार बेचा जा सकता है। ये वस्तुएँ बहुधा सीमित मात्रा में ही दी जाती हैं। जिस मनुष्य को अधिक की आवश्यकता होती है वह बहुधा उसे अधिक मूल्य देकर सरकारी दर और नियमों का उल्लंघन करके खरीदता है। इस प्रकार के क्रय-विक्रय को चोर बाजार कहते हैं।

दूसरों से छिप कर किए जाने वाले काम को चोरी का काम कहते हैं और इस माल का क्रय-विक्रय दूसरों से छिपकर किया जाता है। अतएव इसका नाम भी चोर बाजार पड़ गया है।

उदाहरण २

भारत में जनसंख्या की समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उनके मत को जानने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में जाँच की जाए। इस सम्बन्ध में बलकत्ते के स्वास्थ्य विभाग की एक संस्था ने इस दिशा में अपनी उपयोगी कदम बढ़ाया है। यह जाँच बलकत्ते के दो क्षेत्रों में की गई। एक में उच्चतर मध्यवर्गीय लोगों की बस्ती थी और दूसरे में भुसलमानों की। पहले क्षेत्र में १,०६७ पुरुष जाँच के लिये चुने गए। इनमें १,०१७ व्यक्तियों में ८६६ लोगों से सम्पर्क स्थापित किया गया, जिनमें ५८१ प्रतिशत लोगों ने परिवार में सीमित संख्या में बालकों की आकांक्षा की। ५६ ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि जितनी भी सम्भव संतानें हों, उतनी ही, ६० ऐसे व्यक्ति थे जो परिवार की सीमा निर्धारण के विपरीत थे।

सामाजिक सुधार और आर्थिक दृष्टि दोनों दृष्टिकोणों से यह जाँच बड़े महत्व की है। विदेशों में आर्थिक और सामाजिक जाँच के लिये अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, पर भारत में अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रथम बार सार्वजनिक प्रयत्न हुआ है। इस जाँच में जो लोग सीमित संख्या में बालक चाहते थे, उन्होंने २६ की माँग की, पर आमतौर पर उनमें से किसी ने दो-तीन बालकों से अधिक की माँग नहीं की।

इस प्रकार ६६ प्रतिशत लोगों ने सीमित परिवार की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि बच्चा को उपयुक्त शिक्षा देने और जीवन निर्वाह का स्तर न गिरने देने और लड़कियों के विवाह-व्यय की दृष्टि से कम से कम संतानों का होना उचित है।

इस जाँच में एक बात यह भी सामने आई कि बालकों की उत्पत्ति में समय का भी अन्तर होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जब प्रश्न पूछे गये तो लोगों ने तीन साल का अन्तर आवश्यक बताया। इस सम्बन्ध में अधिकांश लोग ने आमतौर पर अपनी सहमति प्रकट की। ६८६ व्यक्तियों में से ६२८ व्यक्तियों ने यह भी वचन दिया कि वे पारिवारिक नियोजन का समाज में आम प्रचार करेंगे। (सम्पन्न)

प्रश्न

- (१) उपयुक्त शीर्षक देते हुए उक्त प्रवचन की ६० शब्दों में सल्लेषिका बनाइये।
- (२) पारिवारिक नियोजन की आवश्यकता समझाइये।

उत्तर

प्रश्न १—

पारिवारिक नियोजन

भारतीय जनसंख्या की समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और जनमत जानने के विचार से बलकत्ते के स्वास्थ्य विभाग ने एक तथ्यपूर्ण जाँच की है

जो समाज सुधार और आर्थिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता लगना है कि ६६ प्रतिशत लोग सीमित परिवार के पक्ष में हैं। वे दो-तीन से अधिक बालक नहीं चाहते और बालकों की उत्पत्ति में भी ३ वर्ष का अन्तर आवश्यक समझते हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या ने पारिवारिक नियोजन का समाज में प्रचार करने का भी वचन दिया है। (६३)

प्रश्न २—

बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने और जीवन-निर्वाह का स्तर न गिरने में तथा लड़कियों के विवाह व्यय की दृष्टि से कम से कम मन्ताना का होना उचित है।

भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि उसके लिए आवश्यक भरण-पोषण पदार्थ और खाद्यान्न उपलब्ध करना हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया है और हमारा जीवन-स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। अतएव देश को आगे बढ़ाने के विचार से और उन्हें सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए पारिवारिक नियोजन की नितान्त आवश्यकता है।

उदाहरण ३

चाय की खेती एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न प्रकार में होती है। विभाजन के पूर्व देश में चाय की खेती के कुल क्षेत्र ६,५५८ थे। आसाम में १,१२८ खेतों की ४४,०२८ एकड़ भूमि थी, जिसके अनुसार प्रत्येक खेत का औसत क्षेत्रफल २६० एकड़ था, किन्तु बंगाल में ४१३ खेतों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ५१५ एकड़ था। ट्रावनकोर में २२० खेतों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ३५१ एकड़ और मैसूर के १५ बगीचों में प्रत्येक का औसत क्षेत्रफल २६७ एकड़ था। इससे अतिरिक्त चाय कोचीन विहार, उत्तर-प्रदेश और मद्रास में भी पैदा होती है। यहाँ का क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है, जो क्रमशः १८६, १५५, १७४ और ३७ एकड़ है। पंजाब भी चाय की खेती में अछूता नहीं रहा। वहाँ भी विभाजन के पूर्व ४ एकड़ में खेती होती थी। विभाजन का परिणाम बंगाल और आसाम पर पड़ा। उन प्रदेशों में चाय की पैदावार बढ़ गई, पर अन्य सब प्रदेशों में चाय की खेती पूर्ववत् होती है। चाय के जिस क्षेत्रफल का हमने यहाँ उल्लेख किया है उसमें वास्तविक खेती होती है, किन्तु इसके अतिरिक्त चाय के उत्पादकों के पास और भी भूमि है, जिसका उपयोग खेती में नहीं होता।

चाय के उत्पादन के सम्बन्ध में सन् १९४६-५० के उपरान्त के कोई-कोई प्रबन्ध उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९४६ तक विभिन्न राज्यों में चाय का उत्पादन निम्नलिखित था। इससे प्रकट होगा विभाजन के परिणामस्वरूप आसाम का सिल-

हट प्रदेश और बंगाल का कुछ भाग पाकिस्तान में जाने पर उत्पादन में वितनी क्षति हुई।

(उत्पादन १००० पीड में)

राज्य	१९४२	१९४८	१९४९
आसाम	३,०८,८७९	३,११,०८९	३,१४,३५७
प० बंगाल	१,५२,९९९	१,५०,२३८	१,६६,१३६
द० भारत	९५,१५३	१,०१,४०६	९५,६१६
उ० भारत	४,९२७	३,३३३	३,१२३
बिहार	२,१०१	१,९८९	२,१२३
त्रिपुरा	अप्राप्य	३,७५२	३,६७५

इससे यह प्रकट होता है कि चाय के उत्पादन का जो भी क्षेत्र आसाम और बंगाल का पाकिस्तान में गया, उससे कहीं अधिक उपज बढ़ाने में देश आगे बढ़ा। सन् १९४८ में विभाजित बंगाल और आसाम में चाय की प्रायः अधिक उपज हुई। (सम्पदा)

प्रश्न

(१) उपयुक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक दीजिए तथा उसकी लगभग ९० शब्दों में सुवोध संक्षेपिका बनाइए।

उत्तर

प्रश्न १—

चाय की खेती

चाय की खेती भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल में होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही में आसाम सर्वोपरि है, किन्तु पश्चिमी बंगाल के खेत आसाम से भी बड़े हैं। अन्य उत्पादकों में त्रावनकोर, मैसूर, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा उल्लेखनीय हैं। देश-विभाजन का आसाम और बंगाल की खेती पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा, किन्तु शीघ्र ही वहाँ चाय का उत्पादन पहले से भी अधिक हो गया जैसा सन् १९४८ और १९४९ के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े बतलाते हैं। देश के कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। (९३)

उदाहरण ४

ग्रेट ब्रिटेन का आर्थिक सकट एक देशीय सकट नहीं है। यह स्टैलिंग-क्षेत्र तक भी सीमित नहीं। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न आर्थिक सङ्कटों में से यह चौथा सङ्कट है। आर्थिक सङ्कट का चक्र लगभग प्रति दो वर्षों के बाद आ रहा है। अमेरिकी मदद, मार्शल योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता और अवमूल्यन द्वारा तीन सङ्कटों को ब्रिटेन ने पार किया। पहला सङ्कट युद्ध-जन्य महाविनाश के कारण पुनर्निर्माण के निमित्त था। दूसरा, स्टैलिंग के रूपान्तर होने में

कठिनाई होने के कारण आया। तीसरा, डालर-सङ्कट निर्यात और उत्पादन की कमी के कारण आया, परन्तु यह चौथा सङ्कट प्रथम मन्त्री श्री रिचार्ड बटलर के अनुसार पिछले संकटों से बड़ा है। पार्लियामेंट में इस सङ्कट का परिचय देते समय उन्होंने कहा था—“आज हमारे सामने साधारण भुगतान की समस्या है। सन् १९४९ के समान यह मुख्यतः केवल स्टलिंग-क्षेत्र और डालर क्षेत्र के बीच ही नहीं है। अकेला ग्रेट ब्रिटेन ही घाटे में नहीं, स्टलिंग-क्षेत्र के अन्य बहुत से देश, जो पहले पर्याप्त वचत के देश थे, घाटे में जा रहे हैं, फलतः सम्पूर्ण स्टलिंग क्षेत्र समस्त विश्व के प्रति घाटे में है। यह एक दम स्वर्ण-महानिधि में कमी होने से प्रतिलक्षित हो गया है। आज पहले जैसा दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा के बीच दृश्यमान विभेद नहीं रहा है। वस्तुतः सब विदेशी मुद्राएँ दुर्लभ हो गई हैं। स्टलिंग-क्षेत्र और डालर-क्षेत्र के बीच की व्यापारिक भुगतान की समस्या हमारे लिए आज एक विकट रोक्ड़ भुगतान की समस्या हो रही है और हमें संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के साथ निर्यात व्यापार और बढ़ाना चाहिए। वर्तमान सङ्कट में स्टलिंग-क्षेत्र में बाहर के शेष ससार के साथ घाटा कम महत्वपूर्ण नहीं और वह भी प्रभावशाली उपाय योजना की अपेक्षा रखता है।”

(Agra, B Com, Part I, 1953)

प्रश्न

- (१) उपर्युक्त का अपने शब्दों में संक्षेप दीजिए।
- (२) काले भागों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर

प्रश्न १—

ब्रिटेन का आर्थिक संकट

युद्धोपरांत काल में ब्रिटेन पर प्रति दो वर्ष बाद एक आर्थिक संकट आ रहा है और अब तक उस पर चार संकट आ चुके हैं। पहला संकट युद्ध-जन्य विध्वंस से उत्पन्न हुई पुनर्निर्माण की समस्या के द्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रिटेन ने अमेरिकी सहायता से पार किया। दूसरा संकट स्टलिंग के रूपान्तर की कठिनाई के कारण आया, जिसे उसने मार्शल योजना के अन्तर्गत मिली आर्थिक सहायता से पार किया तथा तीसरे डालर-संकट को अवमूल्यन द्वारा पार किया। यह चौथा और पिछले तीनों संकटों से भयानक संकट व्यापारिक भुगतान का संकट है, जिसे टालने का एक मात्र उपाय निर्यात वृद्धि है, विशेषतः दुर्लभ मुद्रा राष्ट्रों अमेरिका और कनाडा के साथ। यह संकट अकेले ब्रिटेन का ही नहीं, सम्पूर्ण स्टलिंग-क्षेत्र का संकट है, अतः इसे टालने के लिए सभी स्टलिंग राष्ट्रों के सम्मिलित प्रयत्न आवश्यक हैं।

प्रश्न २—

युद्ध-जन्य महाविनाश के कारण पुनर्निर्माण के निमित्त या—द्वितीय महायुद्ध से ब्रिटेन का इतना विध्वंस हुआ कि उसके पुनर्निर्माण की समस्या ने ब्रिटेन के सम्मुख एक भारी आर्थिक संकट उपस्थित कर दिया।

पर्याप्त वस्तु के देश—व देश जिनका निर्यात व्यापार आयात व्यापार से अधिक हो अथवा जिनका विदेशी व्यापार पक्ष में हो ।

सम्पूर्ण स्टालिंग क्षेत्र समस्त विश्व के प्रति घाटे में है—युद्धोपरान्त काल में सभी स्टालिंग क्षेत्रों का व्यापार विपक्ष में हो गया । सन् १९४६ में व्यापारिक भ्रुगतान का समस्या केवल डालर राष्ट्रों के साथ थी, किन्तु अब विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ स्टालिंग क्षेत्र के देशों का व्यापार विपक्ष में होगया है ।

स्वर्ण महानिधि में कमी होने से प्रतिरक्षित हो गया है—सम्पूर्ण स्टालिंग राष्ट्रों का व्यापारिक विपक्ष में जाने का प्रमाण उन देशों में स्वर्ण के रक्षित कोष में कमी होना है ।

दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा के बीच द्वयमान विभेद नहीं रहा है—कुछ काल पूर्व विश्व के राष्ट्र दो वर्गों में बँट गए थे—दुर्लभ मुद्रा, अर्थात् डालर राष्ट्र और सुलभ मुद्रा, अर्थात् स्टालिंग राष्ट्र । इसका कारण यह था कि डालर राष्ट्रों के साथ स्टालिंग राष्ट्रों का व्यापार कम था । अब यह भेद भाव मिट गया है और सारे स्टालिंग क्षेत्र के देश अन्य सभी देशों के प्रति घाटे में पहुँच गए हैं ।

वर्तमान संकट में योजना की अपेक्षा रखता है—व्यापारिक घाटे सम्बन्धी वर्तमान आर्थिक संकट स्टालिंग राष्ट्रों के लिए एक भयानक संकट है और बिना किसी व्यावहारिक योजना के इसे पार करना कठिन है ।

उदाहरण ५

आर्थिक उन्नति की प्रगति अथवा सरकारी व्यय और पूँजी निर्माण पर निर्भर रहती है । पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग सप्ताश सरकार स्वयं व्यय करती है और इतना ही पूँजी-निर्माण (प्राइवेट तथा सरकारी) में लगता है । एशियाई तथा सुदूर-पूर्वी देशों में इन दोनों मदों पर मुश्किल से इतनी राष्ट्रीय आय व्यय होती है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को रोक सकें । बर्हा प्रामोण क्षेत्रों में अम दान की सम्भावना है । तब भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय-आय-वृद्धि का ४०-५०% सरकार द्वारा व्यय किया जाय । इसके दो उपाय हैं—अधिक कर और द्रव्य निर्गमन । अर्द्ध-विकसित और बेकारी वाले देशों में सरकारी व्यय के कारण बेकार पड़े साधन काम आते हैं । यदि साथ ही उपभोग-पदार्थों की वृद्धि न हुई तो मुद्रा-स्फीति की स्थिति प्रगट होती है । ऐसा अनुमान है कि शिक्षा तथा कुटीर-उद्योगों तथा किसानों की कार्य-प्रणाली में सुधार पर कुछ व्यय करने से ही खाद्य तथा कुटीर-उद्योग पदार्थों की पर्याप्त वृद्धि शीघ्र होती है । फेक्टरियाँ के लिए पूँजी तथा यन्त्रों पर द्रव्य व्यय करने पर भी अन्त में उपभोग-पदार्थों की वृद्धि हाती है । स्मरण रहे कि उत्पादक और अनुत्पादक मदों में द्रव्य उपयोग के कारण होने वाली मुद्रा स्फीतियों में भिन्नता है । मुद्रा-स्फीति और अधिक राष्ट्रीय उत्पादन का सयाग श्रेयस्कर है । जिन क्षेत्रों में प्रतिरिक्त-द्रव्य पहुँचाना उनमें से यदि उपभोग वस्तुओं की आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई तो कर-पद्धति द्वारा प्रतिरिक्त

द्रव्य को खींच लेना चाहिए, तभी मूल्य नहीं बढ़ेगा। यदि अधिक वस्तु या कर द्वारा प्रतिरिक्त द्रव्य निष्क्रिय नहीं बना दिया जाता तो बड़े मूल्य-नियन्त्रण द्वारा भी मूल्य स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है। कुछ मुद्रा स्फीति से देश में प्राइवेट पूँजी-बिनियोग को प्रोत्साहन मिलता है, पर तु यदि आयात का बड़ा नियन्त्रण न किया और निर्यात-पदार्थों का देश में ही उपयोग बढ़ने से न रोका गया तो मुद्रा स्फीति का भुगतान की बाकी पर प्रति कुप्रभाव पड़ेगा, अत आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने वाली योजनाएँ वाछनीय हैं। (Agra, B Corn, Part I, 1954)

प्रश्न

- (१) उपर्युक्त वा अपने शब्दों में संक्षेप दीजिए।
- (२) काले भागों की व्याख्या कीजिये।

उत्तर

प्रश्न १— एशियाई देशों का आर्थिक विकास

किमी देश की आर्थिक उन्नति अत्यंत सरकारी व्यय और पूँजी निर्माण पर निर्भर है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का सप्ताश भाग इन दोनों मदों पर व्यय होता है, कि तु एशियाई तथा सुदूर पूर्व के अविश्वसित देशों में बहुत कम। इन देशों के समुचित विकास के लिए वस्तुन भ्रमदान के प्रतिरिक्त, उनकी राष्ट्रीय आय का ४०-५०% इन मदों में व्यय होना चाहिए। द्रव्य निर्गमन और अधिक करों द्वारा ही इतना अधिक व्यय सम्भव है। सरकारी व्यय और पूँजी निर्माण से अदोहित साधन काम आते हैं और उत्पादन दृढता है। सरकारी और गैर सरकारी पूँजीगत व्यय के साथ-साथ आनुपातिक उत्पादन वृद्धि नहीं होती तो मुद्रा स्फीति अवश्यम्भावी है, जिसके विपत्त प्रभावों से बचने के दो मार्ग हैं कर-वृद्धि और बड़े मूल्य नियन्त्रण। इनके द्वारा प्रतिरिक्त द्रव्य को निष्क्रिय बना दिया जाता है। मुद्रा स्फीति पर बाधू पाने के लिए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने वाली योजनाएँ भी वाछनीय हैं अथवा भुगतान की बाकी पर समका विपत्त प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न २— राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय—किमी देश के सम्पूर्ण साधनों का मूल्य।

ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमदान की सम्भावना—एशियाई और अन्य पूर्वी देशों में बिना मजूरी लिए ही जनता सार्वजनिक कार्यों में सहयोग देती है, जिससे बहुत कुछ आर्थिक विकास सम्भव है। कार्य करने वाले अपने भ्रम का प्रतिफल न लेकर उमे दान स्वरूप सरकार को सौंप देते हैं।

उत्पादक और अनुत्पादक—विप्रता है—उत्पादक कार्यों के लिए चलाए जाने वाले और अनुत्पादक कार्यों में लगाये जाने वाले द्रव्य में अन्तर है। उत्पादक कार्यों के लिए मुद्रा प्रसार श्रेयस्कर है, अनुत्पादक कार्यों के लिए नहीं।

स्वाभाविकता का लोप हो गया है। राज के जीवन में प्राकृतिक सम्पर्क तनिक भी नहीं रहा तथा अत्यधिक कृत्रिमता आ गई है, इसलिए उसे नास्तिक युग कहा गया है।

जैसे मानव मानने की बात ही ग्यारी हो उठी—पूँजीवादी युग में अधिकार शक्ति इनकी बढ़ गई कि पूँजीपति वर्ग धमजीवी वर्ग को मनुष्य मानने में भी हिचकिचाने लगा, भूमि इत्यादि अन्य उत्पादन के साधनों की भाँति वह उसे एक अचेतन साधन मात्र समझने लगा।

स्वनिर्घंत्रित वेदनापूर्ण एवं दुःखद मृत्यु—राज के समाज में पूँजीपति और धमजीवी वर्गों के पारस्परिक संघर्ष ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया है कि अत्याचार पीड़ित मानव दुःखद मौत की इच्छा करने लगा है। निम्न वर्ग अपने जीवन से इतना नग्न आ गया है कि इस जीवन से वह मरना अच्छा समझने लगा है।

भूदान, धर्मदान, धनदान आदि आन्दोलन—राज के समाज की विषमता को दूर करने के लिए विनोबा भावे ने भूमि, धर्म और धन के दान द्वारा समता लाने का मार्ग सुझाया है। जिनके पास अधिक भूमि अथवा सम्पत्ति है वे उसका एक अंश उधे दें जिनके पास उनका अभाव है तो सामाजिक विषमता दूर होकर निम्न वर्ग का कल्याण हो सकता है। यह प्रेम और त्याग का मार्ग है, दमन और अत्याचार का नहीं।

तत्सदृश जीवन—कृत्रिम एवं आडम्बरपूर्ण जीवन, सादा और स्वाभाविक जीवन के विपरीत जीवन।

उदाहरण ७

शोषण की प्रवृत्ति राज समाज में सर्वत्र है। उत्पादक-धर्म की प्रतिष्ठा समाज में नहीं है। किसान और मजदूर भी धर्म इसलिए नहीं करते कि वे धर्मनिष्ठ हैं। वे लाचार हैं, इसलिए वे धर्म करते हैं। गरीब भी सग्रह की आकाशा के शिकार हैं। वे देखते हैं कि यहाँ गुनाहो और बीमारी पर लोग जीते हैं, उनमें रोजी वमाते हैं और धमीर बनने हैं। ऐसे अनुत्पादक व्यवसायों की सेवा के रूप में अर्वागट रखना चाहिए, परन्तु ऐसा हो इसमें पहले जन-समूह का, जो अधिकांशतः गरीबों का समूह है, हृदय-परिवर्तन कर देना चाहिए। मुट्ठी भर धमीरों को छाटना मुश्किल नहीं है, परन्तु उनके बाद छोटे-बड़े गरीब रहेंगे। उनको एक सतह पर लाना अति कठिन होगा, इसलिए धमी से छोटे-बड़े सभी शोषकों को बदलना अनिवार्य है।

गरीबी और धमीगी की जड़ नष्ट करनी ही पड़ेगी इस हेतु जमीन का बँटवारा पहला कदम है। कारखानों का बँटवारा तो हो नहीं सकता है। उन पर केवल समाज का स्वामित्व स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में स्वेच्छापूर्वक दान और बँटवारा अपेक्षित है। सह-जीवन के सिद्धान्त की यही मीग है। यही भारतीय योग है, जो किसी भी "वाद" से उत्तम है। तोड़ने की प्रवृत्ति जोड़ना श्रेष्ठ है।

क्या पंचवर्षीय योजनाकार इन बातों में विश्वास करते हैं? वे प्राणधारभूत बड़ी मात्रा के उद्योगों और बहुमुखी योजनाओं के आधार पर रोजगार और रहन-सहन का

स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी मात्रा के तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया जायेगा। अर्थशास्त्री उनकी इस उत्पादन क्षमता की ओर उंगली उठाते हैं। जन-प्रतिनिधि कहता है—इनका मंहगा माल कौन खरीदेगा? विशेषज्ञ और जनता दोनों ही सह-जीवन के सिद्धान्त को नहीं समझते; वे इस ओर ध्यान नहीं देते। जनता का ध्यान इस ओर खींचना सरल है। यही विभिन्न दान-प्रादोलनों का कार्य-क्षेत्र प्रारम्भ होना है। (Agra, B Com, Part I, 1956)

प्रश्न

(क) उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेप लगभग ७५ शब्दों में दीजिए।

(ख) काले भागों का अर्थ तथा महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

प्रश्न (क)— सह-जीवन

आज के समाज में उत्पादक श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। यह मनो-वृत्ति सारे सामाजिक शोषण का कारण है। हृदय-परिवर्तन द्वारा इसे बदलना सह-जीवन का श्लाघनीय उद्देश्य है और भूमि का समान वितरण तथा कारखानों का सामाजिक स्वामित्व इसके मुख्य साधन हैं, किन्तु ग्रामीर-गरीबी को पूर्णतः मिटाने के लिए सभी छोटे-बड़े शोषकों का हृदय-परिवर्तन वाञ्छनीय है। आज के भूदान, श्रम-दान आदि आन्दोलनों तथा पंचवर्षीय योजना का यह वास्तविक क्षेत्र है। (७२)

प्रश्न (ख)—

उत्पादक श्रम की प्रतिष्ठा—किसान-मजदूर जो प्रत्यक्षतः धन उत्पन्न करके समाज की सेवा करते हैं, उनकी सेवा की समाज में इतनी प्रतिष्ठा नहीं, जितनी वकील, डाक्टर इत्यादि, अप्रत्यक्ष सेवा करने वालों की है। वस्तुतः किसान-मजदूरों की सेवा अधिक आवश्यक सेवा है, अतएव इस वर्ग के लोगों का समाज में अधिक आदर होना चाहिए।

गरीब भी सग्रह की आकांक्षा के शिकार हैं—धन-सचय के इच्छुक ग्रामीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं और अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए उन्हें सताते हैं। जिन वस्तुओं के लिए गरीब तरसते हैं, उन्हीं का ग्रामीर लोग सग्रह करते हैं तथा सामाजिक कुरीतियों को जन्म देते हैं। सग्रह न हो तो चोरी-डकैती और बर्ग-सघर्ष भी न रहे।

जहाँ गुनाहो और बीमारी पर लोग जीते हैं—समाज के अनेक लोग (वकील, डाक्टर) गरीबों की गरीबी और बीमारों की बीमारी को अपने निर्वाह और ग्रामीरों का साधन बना लेते हैं। यदि समाज-सेवा के उद्देश्य से वकील-डाक्टर उचित महनताना लें तो न इतनी बीमारी बढ़े और न मुकद्दमेबाजी और अपराध। गरीबी के कारण लोग बीमार पड़ते हैं और अपराध करते हैं। अपराध से मुकद्दमेबाजी बढ़ती है

और मुकद्दमेवाजी के लिए गरीब लोग धन कमाने के अनुचित मार्ग अपनाते हैं। एक बार इस जाल में फँस कर छुटकारा मिलना कठिन हो जाता है।

छोटे-बड़े गरीब—अमीर-गरीब के भेद-भाव को समूल नाश करने से ही सामाजिक समता स्थापित हो सकती है। इसके लिए उत्पादन के साधनों और धन का सारे समाज में समान वितरण आवश्यक है, अर्थात् सभी लोगों की आय एक स्तर पर आ जानी चाहिए अन्यथा छोटे-बड़े का कुछ भी भेद-भाव बना रहा तो वर्ग-संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता।

सह-जीवन के सिद्धान्त—मिलकर रहने अथवा सहकारी जीवन का आधार-भूत सिद्धान्त यही है कि प्रेम और अहिंसा द्वारा लोगों का हृदय-परिवर्तन किया जाए, अर्थात् स्वेच्छापूर्वक धनी और पूँजीपति अपनी धन-सम्पदा के दान और बँटवारे के लिए प्रस्तुत हो जायें। कानून द्वारा उनमें यह न कराया जाय।

जो किसी भी “वाद” से उत्तम है—सह-जीवन अथवा प्रेम और अहिंसा का यह मार्ग संसार में प्रचलित सभीवादों, अर्थात् साम्यवाद, समाजवाद इत्यादि से उत्तम है, क्योंकि इस मार्ग का प्रभाव स्थायी होगा।

अर्थशास्त्री उनकी कम उत्पादन-क्षमता की ओर उँगली उठाते हैं—राज के अनेक अर्थशास्त्रियों का मन है कि छोटी माना के तथा कुटीर उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बड़े पैमाने के उद्योगों की उत्पादन क्षमता से कम होती है, अतएव राज के विशाल उद्योगों के युग में इन उद्योगों का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः सन्तुलित अर्थव्यवस्था और पूर्ण कार्य इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका महत्व राज भी कम नहीं है। भारत जैसे देश के लिए इनका और भी अधिक महत्व है, अतएव आर्थिक विकास की योजना में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।



अभ्यास ?

वन-महोत्सव शब्द का उच्चारण करते ही आँखों के सामने देश के प्राकृतिक शौन्दर्य का एक सजीव चित्र खिंच जाता है। देश के पहाड़, जंगल, नदियाँ सब उन्मत्त होकर नाचते दूदते दृष्टिगोचर होते हैं। वन-महोत्सव का अर्थ है कि वन में स्थित जड़, चैनन जो भी हैं, इस उत्सव में सम्मिलित हों। हमारे प्राचीन ग्रन्थ और काव्यों में वनों की बड़ी महिमा बताई गई है और काव्य के काव्य वनों की प्राकृतिक छटा और उसके शौन्दर्य की चर्चा से भरे पड़े हैं। ऊँचे से ऊँचे जितने काव्य लिखे गये हैं, उनकी पृष्ठभूमि कोई न कोई जंगल या हरे-भरे पहाड़ या ऐसी नदी, जिसके दोनों ओर सुन्दर और सघन वृक्षावलिर्वा हों, से ही मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने वनश्री को स्थायी रूप से जीवित रखने के लिए धार्मिक रूप दे दिया था। किसी भी हरे वृक्ष को काटना महापाप माना जाता था। प्रत्येक शुभ कार्य पर सुन्दर छाया वाले और फल वाले वृक्षों को लगाना एवं पुनीत कर्तव्य समझा जाता था। वनों के नाम महान्त

उन्हे पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उस दिन पटना में राज्यपाल महोदय ने भी इस देवी को पुरस्कार प्रदान किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसने राज्यपाल महोदय माननीय दिवाकर जी को एव जनेऊ दिया, छोटी इलाइची के छिलके के भीतर बन्द करके, उस समय वे उस 'भेट' को समझ न सके। भाई का पुरस्कार राजम था—उसकी अभिव्यक्ति हुई विश्वास के रूप में। बहन का उपहार नारीत्व की गौरव गरिमा के रूप में ध्वनित ही कर रह गया, भारतीय काव्य की आत्मा के रूप में। सात्विक उपहार, जनेऊ का धागा राली वा सागा।

कल्पना का दानव उस जनऊ के सम्बन्ध में रग पर रग भरता जा रहा है—कैसा था, वह जनेऊ ? लाल, पीला, शुभ्र ? उसकी बारीकी की ओर भी मन खिच रहा है और भारत के उस कालखण्ड की ओर ध्यान आकषित हो रहा है, जब मुगल बादशाह की अलहड बहन या बेटी, उसके सामने ढाका की मलमल पहनकर निकली थी। उसमें सज्जा की छीन्क थी, योवन सौन्दर्य और वैभव-विलास का प्रदर्शन था। वह दूसरे के हाथ की कती-बुनी थी। यहाँ मिथिला की नारी, सलज्ज, सकरुण मूर्ति, सामने जनेऊ भेंट कर रही थी।

कनिष्क के समय के एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी—भारतवर्ष रोम से प्रति वर्ष साठे पाँच करोड़ रुपये का सोना खींच लेता है और यह कीमत हमें अपनी विलासिता और अपनी शिबियों की देनी पड़ती है। एक दूसरे रोमन लेखक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा है कि वे भारतवर्ष से आने वाली 'बुनी हुई हवा के जाले' पहनकर अपना सौन्दर्य दिखाती थीं। उस सौन्दर्य की आँकी भी मानस लोचन के सम्मुख खिच आती है। रोमन सौन्दर्य, भारतीय वस्त्र। उसकी प्रतिविद्या के रूप में जैसे कोई यूनानी मूर्तिकार किसी मिनर्वा की मूर्ति, यक्षिणी के रूप में गांधारी ढाँचे में, भारतवर्ष में बैठकर बनाने का प्रयास करे।

और आज का अभाव—अन्न-वस्त्र का अभाव। फिर भी हमारी कला में सजीवता है। मिथिला की एक बेटी ने घंटे भर में ३५० नम्बर का १३० गज सूत कातकर चमत्कार किया।

एक और विज्ञान अपने समस्त वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ खडा है—एटम-हाइड्रोजन बम लेकर। एक और दर्शनवेत्ता मैथिल स्मृतिवारों की लडकी इस युद्ध, विनाश और कोलाहल से परिपूर्ण म खादी का महीन जनेऊ लिए मानो कह रही है—

सन्तोष और साव भर्मजता के साथ साथ मनुष्य का गृह उद्योग में ही कल्याण है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं—कोकटी धोती, पट्टा का साग, साधारण वस्त्र एव भोजन, लिफ्टक पाउडर नहीं। भावतरल तन तटस्थ का लावण्य है—इसके सिवा और सब निथ्या है—माया-परिग्रह, जजाल।

(सम्भवा)

प्रश्न

- (१) उपयुक्त गद्यांश की संक्षेपिका लिखिए।
- (२) काले पदों का भावार्थ समझाइए।
- (३) मुगलकाल की गलगल और मिथिला की नारी के अनेक म कौनसा अन्तर आप पाते हैं ?

अभ्यास ३

हाल के वर्षों में भारत के वस्त्र-उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की है। अब भारत न केवल अपनी कपड़े की माँग स्वयं ही पूरी कर सगने की स्थिति में है, बल्कि वह अपनी कपड़ा मिलों द्वारा निर्मित कपड़ा बहुत बड़े परिमाण में विदेशों की भी भेज रहा है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को भारी समर्थ करना पडा है। स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रगति के साथ स्वदेशी की भावना का विकास हुआ और उसने भारतीय वस्त्र उद्योग को पनपाने में बहुत सहायता दी। यह दयनीय स्थिति अब नहीं रही, जब बरोडो रूप के मूल्य का कपड़ा प्रति वर्ष विदेशों से आकर भारत में खपता था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अन्न और वस्त्र के मामले में देश को स्वावलम्बी होने की शिक्षा दी थी और उसने उस शिक्षा को कार्य रूप में सारर दिया।

किन्तु आज की दुनिया में कोई भी देश अन्य देशों की भाँति आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भी अलग-अलग नहीं रह सकता। प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों की निर्यात करना पडता है और जब वह निर्यात करता है तो वह दूसरे देशों के माल के लिए अपना दर्वाजा बिल्कुल बंद नहीं कर सकता। किसी भी देश की अपनी आवश्यकता का माल विदेशों से आयात करने में तो कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि वह ऐसे आयात का स्वागत करता है, किन्तु अपने निर्यात के हित में उसे अपने वहाँ ऐसे माल के आयात की अनुमति और सुविधा देनी पडती है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं होता, कि तु जिसका निर्यात करने में दूसरे देशों की रुचि होती है। आदान-प्रदान व्यापार का मूलभूत आधार होता है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिक लाभ का ध्यान रखना ही पडता है।

(हिन्दुस्तान)

प्रश्न

- (१) इस अवतरण को संक्षिप्त कीजिए।
- (२) आदान-प्रदान व्यापार का मूलभूत आधार क्यों है ?

अभ्यास ४

शायद ही कोई देश कच्ची सामग्रियों के लिए सतारव्यापी माँग के कारण उत्पन्न हुई मुद्रा स्फीति की प्रचल शक्तियों से बच सगा होगा, जो सन् १९५० में

कोरियाई युद्ध लड़ने के बाद पैदा हुई थी। यद्यपि इस प्रभाव ने व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न रूप धारण किए हैं फिर भी देशों को दो विस्तृत समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले में मुख्यतः कच्ची सामग्रियों के उत्पादक और दूसरे में मुख्यतः वस्तु निर्माता देश सम्मिलित हैं। पहले समूह के बारे में यह कहा जा सकता है कि कच्ची सामग्रियों के मूल्य परिवर्तन आमदनियों में सीधे ही प्रकट हो जाते हैं। फलस्वरूप मुद्रा स्फीति या मुद्रा संकोच जल्दी सामने आते हैं। दूसरे समूह के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आयात की गई कच्ची सामग्रियों की लागत के परिवर्तन तैयार माल के मूल्यों में इतनी शीघ्रता से प्रकट नहीं होते, क्योंकि कच्ची सामग्रियों से चीज तैयार करने में समय लगता है। यहाँ मुद्रा स्फीति या मुद्रा संकोच बहुत धीरे-धीरे सामने आते हैं। तैयार निर्माता की कीमत भी आयात की गई कच्ची सामग्रियों की पहले से ऊँची या नीची कीमतों को बहुत समय बाद प्रकट करती है। भारत का स्थान प्रथम और दूसरे समूह में समान रूप में है। वह कच्ची तथा निर्मित सामग्रियों का निर्यात करता है और उसके आयात में अधिकतर मशीनें, मोटोरे, अन्न और अन्य तैयार चीज सम्मिलित होती हैं। कीमतों और अन्य सम्बन्धित बातों की गति केवल यही प्रकट नहीं करती कि इन शक्तियों ने देश पर कैसा प्रभाव डाला बल्कि भारत का निर्यातों के लिए प्राप्त किये गये औसत मूल्यों की धीमी वृद्धि के कारण पर भी प्रकाश डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अनन्तर मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये भारत सरकार ने जो प्रयास किए, उन्हें केवल आंशिक सफलता ही मिली।

(विशाल भारत)

प्रश्न

- (१) इस अवतरण को संक्षिप्त कीजिए।
- (२) काले पत्ते का भावार्थ समझाइए।
- (३) मुद्रा-स्फीति और मुद्रा संकुचन से क्या अभिप्राय है ?

अभ्यास ५

राज की समस्त आर्थिक बुराइयों की एक दवा आर्थिक योजनाय है। आर्थिक योजनाओं के महत्व का दर्शन सारबिन महोदय निम्नलिखित शब्दों में करते हैं —

योजना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रगति में ऊपर नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करती है। एक योजनाय अर्थ प्रणाली की परिभाषा साधारण शब्दों में इस प्रकार की जा सकती है—आर्थिक संगठन की वह योजना जिसमें व्यक्तिगत और विभिन्न उत्पादन की इकाइयों संगठित इकाइयों की एक समूह सम्मिलित जाती है जिनका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत जनता की आवश्यकताओं को पूरक सन्तुष्टि के लिए सत्र प्रकार के उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना होता है। इसके आवश्यक तक्षण है कि समूह की समस्त उत्पादक इकाइयाँ एक दूसरे की आश्रित रहती हैं रहन सहन में स्तर और बढ़ती हुई उत्पादन

प्रणाली की प्रगतिशीलता का सन्तुलन होता है और एक सयोजक केन्द्र का अस्तित्व होता है, जो कि इस प्रकार की प्रणाली को चेतन रूप में राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदत्त लक्ष्य की ओर बढ़ाता है।

स्पष्टतः आर्थिक योजना मुक्त व्यवसाय और नियमित समुक्त पूँजीवाद से आर्थिक पथ प्रदर्शन के विषय में भी भिन्न है। प्रत्येक उत्पत्ति की इकाई को स्वयं विधान बनाने का अधिकार न देकर, योजना उनसे एक सर्वमान्य आर्थिक उद्देश्य पूर्ति के सम्बन्ध में सहयोग की आशा रखती है। संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के कामों का नियन्त्रण अधिकतर प्रतिबन्ध और असम्बन्धित विधानों द्वारा होने देने के स्थान पर योजना सम्बन्धित कार्य तथा एक लक्ष्य की प्रणाली का पालन चाहती है।

उन्नीसवीं शताब्दी की मुक्त व्यवसाय की नीतिप्राकृतिक नियमानुसार देवी-पथ प्रदर्शन के आम्पात्मवाद पर आधारित थी। बीसवीं शताब्दी की योजना-नीति दार्शनिकता पर आधारित है जो अन्वेषण और रचनात्मक दूरदर्शिता द्वारा क्रमबद्ध आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मनुष्य की शक्ति पर विद्वान् रखती है।” (विशाल भारत)

प्रश्न

- (१) “प्राज्ञ की समस्त आर्थिक सुराह्या की दवा आर्थिक योजनाये है।”
कैसे ? कारण सहित समझाइए।
- (२) काले पदों का अर्थ समझाइए।
- (३) उपयुक्त शीर्षक देते हुए उक्त अवतरण का लगभग १०० शब्दों में सक्षिप्तीकरण कीजिए।

अभ्यास ६

विदेशी पूँजी की सहायता से देश के प्राकृतिक साधनों का दोहन और विकास बढ़ाया विदेशियों के लिए ही अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। आपारभूत एवं राष्ट्र रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में विदेशी पूँजी का विनियोग और भी भयानक होता है। विदेशी पूँजी के विनियोग से देश के युवकों का प्रशिक्षण सम्पन्न की अवसर प्राप्त नहीं होता। देश के उद्योग धंधों का संचालन एवं प्रवर्धन सर्वथा विदेशियों के हाथ में रहता है। विदेशी लोगों को देश की वास्तविक परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनके पथ प्रदर्शन की दिशा बहुत गलत हो सकती है। औद्योगीकरण का सत्रमे पहला परिणाम आत्म निर्भरता होता है। अथवा लाभ संचय इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि पूँजी लगाने की कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। यह लाभ ही पूँजी बन जाते हैं। और ज्यों-ज्यों इन लाभों की परिधि विस्तृत होती जाती है त्यों त्यों औद्योगीकरण का क्षेत्र भी चौड़ा होता चला जाता है। साथ ही व्यापार एवं व्यवसाय सम्पन्न भी अनूभव और ज्ञान में भी वृद्धि होनी जाती है जो औद्योगीकरण के लिए अत्यंत

आवश्यक है किन्तु हमारे देश में अंग्रेजी सरकार ने जो औद्योगीकरण किया उससे उन दोनों में से एक भी समस्या की पूर्ति नहीं हुई। विदेशी पूंजी का सबसे भयानक स्वरूप हम राजनैतिक क्षेत्र में मिलता है 'व्यापार के पीछे-पीछे ध्वजा चलती है' कहावत का हमें समारंभ कई दशा में चरितार्थ हात दिया है और हम इसका बड़ा बटु अनुभव हो चुका है। आर्थिक प्रभुत्व के साथ-साथ राजनैतिक प्रभुत्व अवश्यम्भावी है।
(Agra, B Com I, 1957)

प्रश्न

- (क) उपर्युक्त गद्यांश का मस्यौदा लगभग ७५ शब्दों में दीजिये।
(ख) काले शब्दा का अर्थ मोटाहट्टण संक्षिप्त रूप से अपने शब्दों में समझाइये।

अभ्यास ७

संसार की अस्त-व्यस्त वास्तविकताओं के साथ साथ नैतिक गुणों की संगति लगाना कठिन है। तत्तु कुछ लोग धर्म का सहारा लेते हैं। कुछ लोग विज्ञान को सदाचार का निर्णायक मानते हैं। कुछ लोग उनको ही सदाचार मानते हैं जो समाज के बार-बार के अनुभव में ठीक लगता है और कुछ लोग नैतिक गुणों को सर्वथा व्यर्थ तथा सभी आदर्शों को निरर्थक एवं दम्भपूर्ण बनाते हैं। पिछले दो विश्वयुद्धों ने प्ररक्षा का भय बढ़ा दिया है। बड़े झूठे भी चिन्ता युक्तों में भी दोलने लगे हैं। युद्ध-काल की दूरता नागरिक जीवन में चली आयी है। यद्यपि आदर्श-परायणता, साहस और सहयोग की भावनाओं को भी बढ़ावा मिला है, युद्ध और उसके सम्बद्ध घटनाओं ने सदाचार के पुनर्विकास का काम बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक सफलताओं से बहुचरी सामाजिक समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं। बड़े कारखानों की कार्य-स्थिति बेव्यक्त-उत्तरदायित्व की भावना को कम करती है। कारीगर की अपनी कुशलता का अस्तिमान तथा आत्म संतोष कुण्ठित हो जाता है। एक और सुखी व समृद्ध जीवन विज्ञान के भौतिक साधन प्रचुर हो गए हैं। दूसरी ओर हम पुरस्कार का समय आत्म-चिन्तन, आत्म-विकास तथा समाज-सेवा के कार्यों में अधिक नहीं लगाते हैं। पश्चिमी देशों और बड़े शहरों में मित्र-मंडली व्यवस्था पड़ोसी की चौपाल का स्थान बनब और नाचघर ले रहे हैं। टेलीफोन के कारण मुट्ठी भर घाट के लिये पड़ोसी के घर की व्यवस्था परचूनियों की दूकान पाम लगती है। मोटरकार मेलझोल के दापरे को मुहल्ले और गाँव की सीमा के बाहर ल जाते हैं। हमारा अकृत्रिम निजी सम्बन्ध कृत्रिम तथा अनिजी बनता जाता है। परिवार में माता-पिता का नियंत्रण शिथिल होना जाता है। उर है कि वे यह समझ लें कि बालक को रास्ता दिखाने की उनकी जिम्मेवारी भी समाप्त हो गई। जीवन का सामना स्वयं करने से पूर्व बालकों के लिये आवश्यक अर्थ उदाहरण, निर्देश, नियंत्रण, सुरक्षा और प्रेम की पूर्ति खतरे में है। विज्ञान, नाटक तथा विनोद का प्रभाव स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध पर पड़ता है। संसार

के राष्ट्रो के आपसी तीव्र विरोध का मूल कारण आचार सम्बन्धी यह प्रश्न है कि मानव-व्यवहार का आदर्श क्या होना चाहिये ? संसार के मतभेद का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का आन्तरिक मतभेद है । आज वे संसार में स्वतन्त्रता की रक्षा नैतिक और आत्मिक गुणों के विकास की समस्या है । शिक्षक ही इसका एकमात्र सुधारक है ।

(Agra, B Com I, 1958)

प्रश्न

- (क) उल्लिखित गद्यांश का सक्षेप लगभग ६० शब्दों में दीजिए ।
(ख) काले पदों की विवेचना कीजिए ।

अभ्यास ८

प्रत्येक किसान उत्पादन कार्य के लिये अपनी भूमि का स्वैधानुसार उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र है । जब तक वह भूमि को भली भाँति जोतता बोता है तब तक भूमि पर उसका ही अधिकार रहे । उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने धन का पूरी तरह से फल भोग सकेगा । भूमि पर उसका अधिकार काश्तकारी बानून के आधार पर ही अथवा उसे इच्छानुसार भू-स्वामित्व के अधिकार खरीदने की स्वतन्त्रता हो । ऐसा होने पर किसानों की भूमि पर अधिकार करने की लालसा पूरी हो सकती है । देशों के भिन्न-भिन्न भागों के लिये लाभकर खातों के क्षेत्र निर्धारित किये जायें और इस बात का प्रयत्न हो कि अधिक से अधिक किसानों के पास ऐसे खाते हों । सभी किसानों का खाता सम्भवनः लाभकर होना चाहिये, अर्थात् उसका क्षेत्र १० एकड़ से कम नहीं होना चाहिये । १० एकड़ से कम होने पर उत्तराधिकारियों में उसका बंटवारा किसी भी दशा में नहीं किया जाय, क्योंकि इससे एक नई समस्या खड़ी हो जावेगी । जब खाता १० एकड़ के लगभग हो तो उसका स्वत्व अनेक उत्तराधिकारियों में किम प्रकार हस्तान्तरित किया जाय, यह प्रश्न उपस्थित होना है, क्योंकि यदि खाता सबसे बड़े लड़के को मिलना है, तो शेष के साथ अन्याय होता है, इसलिये इस समस्या का हमको सामना करना ही है अन्यथा भूमि के विभाजन से राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को ही बल मिलता है, जो समाज के लिये अत्यन्त घातक है । इस सम्बन्ध में यही किया जा सकता है कि भूमि-सम्बन्धी उत्तराधिकार काश्तकारी नियमों के आधार पर इस प्रकार निश्चित हो कि १० एकड़ से कम के टुकड़े न हो सकें और उत्तराधिकारी, जिसे खाता प्राप्त हो, अपने से छोटे उत्तराधिकारियों के पूर्ण बचस्क होने तक उनके भरण-पोषण तथा शिक्षा के लिये पूरी तरह उत्तरदायी हो । किसी भी व्यक्ति को ३० एकड़ से अधिक भूमि को अपने अधिकार में रखने की आज्ञा न हो । जिनके पास इससे अधिक भूमि हो उसकी अतिरिक्त भूमि अलाभकर खातेवालों को दे दी जाय । इसके अलावा गाँवों में बेकार पड़ी हुई भूमि भी इन्हीं अलाभकर खातेवालों में बाँट दी जाय । इतना होने पर भी बहुत से अलाभकर खातेवालों तथा भूमिरहित मजदूरों की समस्या शेष रह ही जायेगी,

जिसका हल होना आवश्यक है। इसनिय ग्रामों में कुटीर धंधों का अधिक विकास किया जाय जिससे यह रोग बेकार समय में काम करते जीवितों उपार्जित कर सकतया अपनी आय बढ़ा सक। गाँव की जा सख्या तथा खातो ही भूमि के प्रतिरिक्त शेष सभी भूमि पर गाँव समाज का अधिकार हो, जिसका निर्माण प्रत्येक गाँव में होना चाहिये। गाँव समाज को अपने सदस्यों के रहन सहन का स्तर उन्नत करने के लिये सभी प्रकार के कार्य करने चाहिये। गाँव से मालगुजारी एकत्र करके सरकार को उसके भुगतान करने के लिये भी ग्राम मन्त्र ही उत्तरदायी हो।

(Agric Com I 1959)

प्रश्न

- (क) उपयुक्त गद्यांश का संक्षेप लगभग ७५ शब्दों में दीजिये।
 (ख) काले भाषों की संक्षिप्त रूप से अपने शब्दों में समझाइय।

अभ्यास ९

छोटी छोटी वस्तुओं में रहने और अधिकांश अपने लिए या स्थानिक उपयोग के लिये छोटे छोटे यंत्रों पर उत्पादन करने की लोग विज्ञान की सुई की पीछे पसोडना कह सकते हैं। लोग समझते हैं विज्ञान एक बड़े पैमाने पर केन्द्रित उत्पादन और मनुष्यों की धनी धनी वस्तुओं अनिवार्य रूप से साथ साथ रहेगी। इससे अधिन बेमानी बात और क्या हो सकता है? विज्ञान दो तरह का है (१) शुद्ध विज्ञान, (२) उपयोगी विज्ञान। मैं केवल शुद्ध विज्ञान की ही विज्ञान कहूँगा दूसरा तो यंत्रकला है। फिर विज्ञान का उपयोग स्वतः विज्ञान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज की प्रवृत्ति और मठन पर निर्भर करता है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना स्वयं कमाने वालों के लिए लाभदायक था, इसलिए यंत्र कला ने उस विशिष्ट प्रकार के उत्पादन का मार्ग प्रपन्नाया। समाज में पैसा कमाने वाले पूँजीपतियों का प्रभाव था इसलिये उनके मन की बात होने ही वाली थी। सरकारों ने भी अपने पादशों की शिता न करते हुए केन्द्रित और बड़े पैमाने पर उत्पादन को पसंद किया। क्योंकि युद्ध करने के लिये अथवा प्राप्त चाहे तो संरक्षण के लिये भी यह सकते हैं उसकी आवश्यकता थी। इसलिए भी उसका महत्व था कि उसके द्वारा सारी आर्थिक और इसलिये राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में केन्द्रित हो गयी थी। इस प्रकार सरकारों और मुनाफाखोरी ने मिलकर आधुनिक समाज के मरमासुर को पदा किया है। बेकारे विज्ञान का इस मामले में कोई हाथ नहीं था। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का धन चलता तो वे उत्पादन और विनाय के बहुत से इंजनों को जिनके निर्माण में उनके अनुभव धन से सहायता मिली है अकनाचूर कथे प्रसन्न होते किंतु समाज ने यदि सत्ता मुनाफा और युद्ध के लक्ष्यों को न प्रपन्नाकर शांति सद्भावना, सहकार स्वतः प्रथम और बहुत्व के लक्ष्यों को प्रपन्नाया होता तो निश्चित ही यंत्र कला का सद्गुरुत्व विकास करने में विज्ञान का उतना ही उपयोग हुआ होता। वह विज्ञान

की भवति नहीं कही जाती, बल्कि विनाश के बदले निर्माण की दिशा में उसकी प्रगति ही कही जाती। यह बता देना चाहिए कि आणविक शक्ति ने उत्पादन के व्यापक वितरण और लघु-उद्योगों के विकास को पहले की अपेक्षा अधिक सम्भव कर दिया है।

(Agra, B Com I, 1960)

प्रश्न

- (क) उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेप लगभग ७५ शब्दों में दीजिए और एक उचित शीर्षक भी।
- (ख) काले भागों को संक्षिप्त रूप से अपने शब्दों में समझाइए।

अभ्यास १०

इसमें सन्देह नहीं कि सयुक्त कृषि के समर्थक जिस आदर्श तब पहुंचना चाहते हैं वह बहुत प्रशंसनीय है। सयुक्त कृषि के आलोचक भी इस आदर्श से सहमत हैं। वे भी परस्पर सहयोग और सहकारिता को अवाञ्छनीय नहीं मानते, कि तु उनकी यह दृष्टि सम्मति है कि सयुक्त कृषि के रूप में सहकारिता किसी तरह भी व्यावहारिक नहीं है। उनके तर्कों पर अभी तक हमें सन्देह है, गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर तर्कभास तथा दृढ़ भाषा द्वारा उन्हें चुप कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस आन्दोलन और प्रत्यान्दोलन में जो कुछ दोनों ओर से कहा जा रहा है, उस पर यदि शान्त मस्तिष्क से विचार करें तो, प्रतीत होगा कि मूल प्रश्न जिस पर मतभेद हैं, निम्नलिखित हैं —

आलोचकों की धारणा यह है कि किसान का अपनी भूमि के प्रति जो मोह है, उसके कारण वह अपनी भूमि पर किसी दूसरे को खेती नहीं करने देगा। श्री राजाजी के शब्दों में किसान अपनी भूमि से पत्नी की तरह प्रेम करता है। वह स्वयं भले ही अपने किसी साथी को सहयोग के लिए बुलाए और बदले में उसको भी सहयोग दे दे, एक नियंत्रण और नियम के नीचे अपने जिस किसी पड़ोसी को अपने खेत पर हल जोतने नहीं देगा। दूसरे वह अपने खेत पर बहुस्वामित्व को सहन नहीं करेगा। जात पाँठ, बिरादरी और पारिवारिक झगड़ों से भी वह आज ठपर उठ जाए, इसकी भी बहुत कम सम्भावना है। आलोचकों की तीसरी मुख्य धारणा यह है कि आज तो वह अपने खेत का स्वतंत्र रूप से स्वामी है, जब चाहता है और जो चाहता है और जैसे चाहता है, अपने खेत में हल जोतता, फल बोता और अपने बाल बच्चों का सहयोग लेता है। वह अपने लाभालाभ को देखकर अपनी बुद्धिपूर्वक यथाशक्ति परिश्रम करता है कि तु सयुक्त कृषि के बाद वह मजदूर भर रह जाएगा, जिस सहकारी समिति के कर्मचारी उसके परिश्रम के अनुसार वेतन देगे। आज भी लोकतंत्र राज्यों में वह सरकारी कर्मचारियों, विधान सभाओं के सदस्यों और मंत्रियों से आत्मीयता स्थापित

नहीं कर पाना, यद्यपि वे उसके ही बोझों से बूने जाते हैं। संयुक्त कृषि का अर्थ है कारखानों की भांति कृषि का भी केन्द्रीयकरण व उद्योगीकरण।

संयुक्त कृषि चालू करने से पूर्व इन तीनों आपत्तियों का निरसन करना होगा। भारतीय किसान को प्रोत्साहित करने और सहकार की भावना उत्पन्न करने के लिए तपस्वी, ईमानदार, निस्वार्थ जनसेवकों की आवश्यकता है, जो गाँव गाँव में घूमकर किसानों के हृदय में स्वार्थ व धन-पराए की भावना को निकाल सकें। क्या आज के भ्रष्टाचार और स्वार्थ के युग में ऐसे निस्वार्थ कर्मचारी तैयार हो सकेगें ? इन प्रश्नों के उत्तर पर संयुक्त कृषि का भविष्य निर्भर है। यदि इसका उत्तर 'हाँ' में है तो संयुक्त कृषि सफल होगी और यदि उत्तर 'नहीं' में है तो विधाना भी इस प्रयत्न में सफल नहीं होगा। (सम्पदा)

प्रश्न

- (१) उपर्युक्त सन्दर्भ को उपयुक्त विशेषक दीजिए और लगभग ७५ शब्दों में उनकी संक्षेपिका बनाइए।
 (-) काले भागा का भावार्थ समझाइए।

अभ्यास ११

मानव जाति के लिए एक नये युग का सूत्रपात हो गया है। यह नया युग आणविक शान्ति का युग है। भविष्य में इतिहासकार इस युग को "आणविक युग" कह कर पुकारेंगे या सन्न्यता के महाविनाश की घोरता और रोमांचकारी गाथा सुनने के लिए कोई इतिहासकार जीवित ही नहीं बचेगा, इसका निर्णय आज हम—समस्त मानव जाति की ही करना है, क्योंकि आज समस्त सभार का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

फिर भी युद्ध में महाविनाश की क्षमता के रखने वाला अणु तैजो से शान्ति के दूत के रूप में परिणत होता जा रहा है। सभार के प्रमुख वैज्ञानिकों और राजनयित्तियों का कहना है कि अणु-शक्ति हमारे युग का सबसे महत्वपूर्ण और मनोरंजक आविष्कार है।

विज्ञान की प्रगति और मानव जाति के बलवाण की दृष्टि से इन आविष्कारों की तुलना अणुवीक्षण यन्त्र और भाप चलित इंजन से की जा सकती है। वस्तुतः अभी से अणु शक्ति का उपयोग रोगों से संघर्ष करने, औद्योगिक उत्पादन की कठिनाई और विधियाँ को सुधारने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और समस्त मानव जाति के रहन-सहन को उन्नत करने के लिये किया जा रहा है।

बहुत से लोग 'अणु-विस्फोट' शब्द से 'महाविनाश' या 'अपरिमित शक्ति' की कल्पना करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को ज्ञात है कि हमारे कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण 'अणु विस्फोट' परीक्षणशालाओं में हुये हैं। ये अणु-विस्फोट न तो देखे जा सकें और न इनमें किसी प्रकार की आवाज ही हुई। परीक्षणशालाओं में हुए इन 'आणविक-

विस्फोटो' द्वारा महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की गयी हैं और आज मानव जाति अग्नि-युग को उदय होते देख रही है ।

अग्नि का आकार बहुत सूक्ष्म है, परन्तु इसमें अपरिमित शक्ति निहित है । १५ पौंड आणविक ईंधन से ३ करोड़ ६० लाख पौंड कोयले जितनी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है । साथ ही एक पौंड विखण्डनीय सामग्री में २,४०,००० गैलन पेट्रोल जितनी शक्ति भी निहित है । भारत तथा संसार के अल्प-विकसित देशों के लिए यह खोज बहुत अधिक महत्त्व रखती है ।

मनुष्य अग्नि की इस आश्चर्यजनक और विस्मयकारी शक्ति का उपभोग विनाश के लिए करेगा या संसार की सुख-वृद्धि के लिए ? जिस प्रकार प्रारम्भिक काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज करने के बाद धीरे-धीरे उससे उपयोगी शक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार आज मनुष्य शनैः शनैः यह सीख रहा है कि अग्नि शक्ति किस प्रकार मानव जाति के लिए उपयोगी बनाई जा सकती है । (अमृत पत्रिका)

प्रश्न

- (१) काले पदों का अर्थ समझाइए ।
- (२) उक्त प्रश्नोत्तरों को उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षिप्त कीजिए ।
- (३) अग्नि शक्ति के रचनात्मक रूपों का विवरण दीजिए ।

अभ्यास १२

साधारणतः संकीर्ण अर्थ में श्रम का तात्पर्य उस मानवी चेष्टा से है, जो धन की प्रत्यक्ष उत्पत्ति के लिए की जाती है, परन्तु श्रम की यह व्याख्या अपूर्ण है । धन से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध रखने वाली मनुष्य की प्रायः सभी क्रियायें होती हैं । धन से परोक्ष सम्बन्ध रखने वाली चेष्टायें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली । एक देश भवन की देश-सेवा की चेष्टा भले ही प्रत्यक्ष रूप से उमें धन अर्जित करने में सहायक न हो फिर भी हम उस व्यक्ति की चेष्टाओं को श्रम ही कहेंगे क्योंकि देश-सेवा की चेष्टा करते समय उमें जो आवश्यकताएँ पड़ती हैं—वे धन उत्पत्ति का कारण भी होती हैं । इस दृष्टिकोण से श्रम की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं—वे समस्त मानवी चेष्टाएँ, जो अपेक्षाकृत न्यून साधनों द्वारा असीम साध्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं, श्रम हैं । इसी दृष्टिकोण से श्रमिक उन सभी व्यक्तियों को कहेंगे, जिनके समक्ष सीमित साधनों द्वारा असीम साध्यों की पूर्ति की समस्या है ।

परन्तु आज की औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिक वर्ग एक अर्थ वर्ग ही समझा जाता है, जो आर्थिक कार्यों में भाग लेता है और ब्याज, लाभ, लगान और धेतन से भिन्न 'पारिश्रमिक' पर निर्भर करता है । वह अपने आर्थिक कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों की पूँजी प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है और जो अपने हित की आशा एक विशिष्ट 'श्रम शिविर' से रखता है ।

वर्तमान औद्योगिक युग में उत्पादन का कार्य वृद्ध परिमाण में किया जाता है। उन सभी देशों में जहाँ व्यक्तिगत पूँजीवाद है और राज्य द्वारा नियंत्रित तथा योजना-बद्ध ग्रहण प्रणाली कार्य-रूप में लाई जाती हैं, वहाँ उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा की एक सीधे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा में ग्रामों बढ़ने के लिए ग्रहण अपने को व्यावसायिक क्षेत्र में हट करने के लिए उत्पादक-व्यय में कमी करते हैं, जैसे—पारिश्रमिक में कटौती, कार्यशील घण्टों में वृद्धि इत्यादि। श्रमिकों की श्रम-नियोजकों की अपेक्षा सौदा करने की शक्ति की कमी के कारण और उनकी रचना तथा व्यावसायिक गतिशीलता में बाधा होने के कारण उन्हें अधिकतर झुकना पड़ता है, परन्तु श्रमिक वर्ग में श्रम-नियोजकों के प्रति श्रमन्तोष की भावना बलवती होती जाती है और श्रम-समूह उसी के परिणाम होते हैं। अपनी कष्टप्रद समस्याओं को दूर करने के लिए श्रम समूह को उत्पादकों से सघर्ष करना पड़ता है—हड़तालें और तालाबन्दी होने लगने हैं। फलस्वरूप देश को महान् क्षति उठानी पड़ती है। श्रम प्रति शीघ्र नाश होने वाला पदार्थ है। समस्त व्यवसायों में एक दिन की हड़ताल अथवा तालाबन्दी पूरे राष्ट्र के लिए करोड़ों रुपये के नाश का कारण बन सकती है। रूपों की क्षति-पूर्ति तो येनकेन प्रकारेण की जा सकती है परन्तु श्रमशील घण्टों की क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त हड़ताल अथवा तालाबन्दी की अवधि में श्रमिकों को अपने पारिश्रमिक से वंचित रहना पड़ता है, पूर्व अर्जित पारिश्रमिक में भी उसकी मूल्यता के कारण कोई वंचन नहीं रहती, अतः श्रमिकों के पूरे परिवार को अर्द्ध गम और वृद्धि अवस्था में रहना पड़ता है। उनकी कार्य-क्षमता ऋषा घटती जाती है, जिसका परिणाम भविष्य में पूरे समाज को उत्पादन की कमी के रूप में उठाना पड़ता है। उपभोक्ता को वस्तुओं की महान् कमी हो जाती है। देश के ममक्ष मुद्रा स्फूर्ति और आर्थिक सकट का भय उत्पन्न हो जाता है। श्रमिक समस्या का यह प्रथम स्वरूप है।

(विशाल भारत)

प्रश्न

- (१) काले भागों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
- (२) उपर्युक्त अवतरण की संक्षेपिका बनाइए।
- (३) श्रम की व्यापक व्याख्या कीजिए।
- (४) श्रम समूहों का जन्म कैसे हुआ और उनका क्या कर्तव्य है ?
- (५) हड़तालों से विविध पक्षों को क्या हानि होती है ? हड़ताले राष्ट्रीय क्षय का कारण क्यों हैं।

अभ्यास १३

यह तो सर्वमान्य है कि बेकारी व्यक्तिगत पूँजीवाद की अत्यादि नहीं, अपितु स्थायी और रुढ़िगत समस्या है। इस प्रकार की व्यवस्था में हर समय एक "संचित श्रम" अथवा बेकार श्रमिकों का एक समूह होता है, जो घटता है और बढ़ता है, परन्तु उसका नितान्त लोप नहीं होता। वस्तुओं की उत्पत्ति उनकी माँग के अनुपात में नहीं

सकने के कारण, जैसा पूँजीवादी व्यवस्था में होना स्वाभाविक है, व्यापारिक-चक्र में परिवर्तन होता रहता है। कभी-कभी व्यापार में समृद्धि आती है उत्पादकों को लाभ अधिक मिलने लगता है उद्योगों का विस्तार किया जाता है और श्रमिकों की नियुक्ति उत्तरोत्तर बढ़ाई जाने लगती है। उद्योग विस्तार की स्पर्धा में तथा किसी निश्चित सामाज्यपूर्ण योजना के अभाव में वस्तुएँ माँग से अधिक पैदा हो जाती हैं और उनके मूल्य में भीषण कमी होने लगती है। उत्पादकों को घाटा होने लगता है। अधिकांश फैक्ट्रियों को काम कम कर देना पड़ता है। फलतः एक विशाल जनसमूह बेकार हो जाता है। वस्तुओं की माँग और पूर्ति के असन्तुलन के कारण ही बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है।

इन सभी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत पूँजीवाद के स्थान पर समष्टि पूँजीवाद की प्रतिस्थापना से ही सम्भव हो सकता है अर्थात् उन सभी उद्योगों और उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व उत्तरदायित्वपूर्ण राज्य के हाथों में हो, जो केवल उन्हीं वस्तुओं को उतने ही परिमाण में उत्पन्न करेगा जितनी उनकी वास्तविक माँग होगी। तब न स्पर्धा की कोई समस्या होगी और न उत्पत्ति व्यय को कम करने की व्यग्रता। अतः श्रमिकों की मजदूरी में कटौती, काम करने के घंटों में घृष्टि और उन्हें यत्र की पूरी गति से चलाने का आदेश नहीं होगा। व्यापारिक समृद्धि और ह्रास की समस्या न होने के कारण बेकारी की भी समस्या न होगी।

परन्तु सिद्धांततः यह कथन कितना भी सत्य क्यों न प्रतीत होता हो, व्यावहारिक रूप में उत्पत्ति के साधनों का सहजा राष्ट्रीयकरण असम्भव नहीं तो कष्ट साध्य प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण के साधन द्वारा साध्य तक पहुँचने की नीति में तनिक भी असावधानी या अवाङ्मनीय शीघ्रता देश को महान् सङ्कट में डाल सकती है और साध्य को और दूर फेंक सकती है। उद्योगपतियों को बिना उचित पूर्तिधन दिए ही उनके उद्योग पर राज्य द्वारा स्वामित्व स्थापित करने की नीति खून की नदियाँ बहाने का कारण बन सकती है। यदि पूर्तिधन देने की नीति हो भी तो किसी राज्य के पास इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि सब उद्योगों को सहसा वह अपने हाथ में ले ले। फिर भी राज्य की श्रमशक्ति बढ़ने के साथ साथ उद्योगों का भी उनके सापेक्षिक महत्त्व के अनुसार श्रमशक्ति राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है परन्तु प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत पूँजीवाद को हटाकर समष्टि पूँजीवाद स्थापित करने तक की अवधि में राज्य को आर्थिक समस्याओं का निवारण, जिनका सम्बन्ध श्रमिकों के हित से है, किस प्रकार करना उचित है।

(विशाल भारत)

प्रश्न

- (१) काले भागों का अर्थ समझाइये।
- (२) उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण क्यों कष्ट साध्य है ?
- (३) व्यक्तिगत पूँजीवाद बेकारी के लिए क्यों उत्तरदायी है ?
- (४) इस अवतरण को संक्षिप्त करके अपने शब्दों में लिखिये।

अभ्यास १४

जनन-त्र के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण आज के युग की माँग है। नवीन समाज की रचना सबल आर्थिक प्राचीर पर सुदृढ़ और स्थाई हो सकती है, इसी से धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के अगो की पूर्ति भी होती है। साथ ही यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ मुख्यतः आर्थिक विषमताओं से ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य समाज का अंग है, अतएव मानव-जागरण का अध्ययन मूलतः सामाजिक विषय है। आर्थिक क्रियाओं का आधार भी समाज ही है, क्योंकि समाज में व्याप्त वातावरण द्वारा ही हमारी आवश्यकताएँ निश्चित होती हैं, जो सभी आर्थिक क्रियाओं की जननी हैं। समाज के संगठन, नीति, विकास अथवा उन्नति की पृष्ठ-भूमि में आर्थिक क्रियाओं को मुख्य स्थान मिलता है। जिस समाज अथवा जाति के लोग पारस्परिक सहानुभूति एवं सहृदयता से काम लेते हैं उस समाज अथवा जाति के व्यक्तियों की उन्नति होती है और वह समाज सदा सुखी रहता है। इस प्रकार की सहानुभूति का मुख्य आधार आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय होता है किन्तु उनकी विपरीत अवस्थाओं में समाज के अभ्युदय में बाधा पड़ती है और सदा आर्थिक संकट छाया रहता है। आर्थिक संगठन के युग में किसी भी सामाजिक विषय का आर्थिक पक्ष जब तक दृढ़ नहीं रहता, उत्थान की चर्चा निरर्थक जान पड़ती है। फलतः उसके अभाव में कोई भी विश्वव्यापी सस्था बयो न हो, सफल नहीं हो सकती।

समाज-निर्माण का कार्य समाज के सुधारों की प्रचेष्टा, राज्य के विधान तथा समाजसेवा की भावनाओं से अग्र-प्रोत राष्ट्रीय जनता द्वारा सम्पन्न होता है। समाज-सेवा के अन्तर्गत वे सभी सेवाएँ आती हैं, जिनमें सामाजिक जीवन का स्तर निर्धारित होता है, किन्तु कभी कभी समाज के कुछ ऐसे कार्य भी आ जाते हैं, जो साधारणतः लोगों के ध्यान से दूर हो गये रहने हैं और उनके प्रति राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। व्यापक दृष्टि से समाज सेवा का कार्य वास्तविक रूप में उन लोगों से सम्बन्धित होता है, जो अशिक्षित एवं उपेक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं अथवा जो समाज में निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा उन्हें शारीरिक एवं नैतिक दृष्टि से अभावग्रस्त दशा में कार्य करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश पहुँचाना, शारीरिक तथा मानसिक विकास का अवसर तथा आनन्द वृद्धि करना एक उच्च कोटि की समाज-सेवा है। व्यक्तियों में मितव्ययिता की आदत, मादक-द्रव्य का निषेध तथा अमानद-प्रभेद में विशेष व्यय को रोकना भी समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि समाज सेवा का रूप ऐसा हो, जिसमें राष्ट्रीय-जीवन में ऐसा विकास हो जाये कि राष्ट्र सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ उन्नत मस्तक होकर एवं साथ कदम मिला कर चल सक। उसमें अस्म-गौरव की भावना प्रबल हो उठे।

(विशाल भारत)

प्रश्न

- (१) उक्त अवनरण की संक्षेपिका बनाइये जो उसके मूल आधार के एक चौथाई से बड़ी न हो ।
- (२) काले भागों की व्याख्या कीजिए ।
- (३) वास्तविक समाज-सेवा क्या है ?

अभ्यास १५

दान की नई कल्पना

भूमि-हस्तान्तर के लिए आन्दोलन के आचार्य सन्त विनोबा का साधन है, दान की प्राचीन परम्परा, लेकिन उनके हाथ में दान भूमि हस्तान्तर के लिए एक नई क्रान्तिकारी व्यूह रचना बन गया है। सन्त विनोबा ने इसे इसलिए श्रेष्ठ माना है कि वह एक सामाजिक अन्वेषण की अन्त्येष्टि के लिए अमोघ अस्त्र है।

विनोबा का कहना है कि हवा, पानी, प्रकाश की भाँति भूमि भगवान की देन है, जैसे पानी नहीं बेचा जाता और हवा की कोई कीमत नहीं कूनी जानी, वैसे भूमि भी अनमोल है। वह खरीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से लेन-देन के लिए है, इसलिए उस पर किसी एक का स्वामित्व सामाजिक पाप है। इस पाप में मुक्ति का एक ही उपाय है कि भूपति अपनी भूमि का दान कर दे। इसी में उसका मनुष्यत्व और पुरुषार्थ है और यही उसके लिए पुण्य का सबसे बड़ा काम है। युग-युग से भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पुण्य कार्य माना जाता रहा है। वे भूखे दान की अनिवार्यता है कि मेहनतकश भूमिहीन को भूमि देना हम अपना धर्म समझे।

भूदान केवल पुण्य के लिए ही नहीं, बल्कि दाना की रक्षा के लिए भी जरूरी है। वर्तमान युग में वर्ग-संघर्ष और सामाजिक असन्तोष की जो आँधी चल रही है, उसमें यदि भूदान द्वारा बचाव न हुआ तो भूपति की जमीन तो जायेगी ही, लेकिन वह अपनी इज्जत भी खोयेगा। मगर समय के पहले, वर्ग-संघर्ष और खूनी क्रान्ति को टालने के लिए यदि दाता अपनी जमीन का त्याग करता है तो वह अपनी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है और महान् यश का भागी होता है। भूदान हमारे लिए बतावनी मात्र है कि सामने खम्भा है। आँखों से लोभ की पट्टी हटा दो, नहीं तो उसमें टकराकर अपना माया फोड़ोगे।

भूदान की नई कल्पना में दान केवल दया-करुणा का कार्य नहीं रहा है। वह हमारी सदियों से सोई हुई न्याय वृद्धि की जगाने का कार्य बन गया है। भूदान में याचक कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं, अपन ही कुटुम्ब का एक स्वजन, एक लडका है। उसमें दरिद्र नारायण की प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए उसकी याचना को एक हक माना गया है। दाता से कहा गया है कि वह भूदान कर याचक के हक को स्वीकार करे और इस तरह याचक ने उसे न्यायपूर्ण कार्य के लिए जो सहनियत दी है, उसके

लिए वह अपने को उपवृत्त माने। याचक की स्वजन मानकर दान की क्रिया सरल बना दी गई है। दाता से विनोय कहते हैं—“भाई, तेरे घर में पाँच बेटे हैं। मैं छठवाँ होकर तेरे घर में घगट हुआ हूँ। तू मुझे दरिद्रनारायण की खातिर मेरा हक मुझे वापस कर दे।” दान की इस नई क्रान्तिकारी कल्पना से जहाँ अमीर-गरीब के बीच की खाई हटती है वहाँ सामाजिक शान्ति और सहयोग के लिए उनके गठबन्धन की सम्भावना भी मजबूत होती है।

अन्त में साधारण दान एक प्रसंग मात्र है। लेकिन भूदान सग्रह के समर्पण का एक सिलसिला है जो तब जाकर समाप्त होता है जब व्यक्ति के पास उतनी ही भूमि बच रहे जितनी वह जोत सके और बाकी पालतू जमीन दरिद्रनारायण के हेतु समर्पित हो जाय। दूसरे शब्दों में मालकियत का मोह ही आज के समाज का सबसे बड़ा रोग है और भूदान इसी राज रोग के इलाज के लिए सतत् चलती हुई प्रणिया है।
(सरस्वती)

प्रश्न

- (१) काले पदों का अर्थ समझाइये।
- (२) इस अवतरण को उपयुक्त शीर्षक देते हुए उसका सक्षिप्तीकरण कीजिए, जो अपने मूल आकार की लगभग पाँचवा भाग हो।

अभ्यास १६

एक अहिंसक क्रांति

गांधी जी ने जिस सत्य और अहिंसा का उपयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया, उसी का उपयोग उनके परम शिष्य विनोय एक कदम आगे जाकर आर्थिक और सामाजिक शान्ति के लिए कर रहे हैं। भूदान का आधार प्रेम और अहिंसा द्वारा लोगों की मानवता जगाकर उनका मत परिवर्तन और हृदय परिवर्तन है। तलवार या कानून लोगो को मिलाने की जगह उनमें फाँके पैदा करते हैं। तलवार से घादमी का गला भले ही काट दिया जाय, लेकिन उससे घादमी का हृदय नहीं जीता जा सकता है। वैसे ही कानून से दो विरोधी नहीं मिलाए जा सकते हैं जहाँ एक अपनी जीत में खुश होता है वहाँ दूसरा अपनी हार से दिल ही दिल में कुदता है। सज्जनता किसी एक वर्ग की विरासत नहीं। कई अच्छे अमीर होते हैं और कई बुरे गरीब होते हैं लेकिन समाज की शान्ति के लिए सभी अच्छे अमीरों और सभी अच्छे गरीबों के सहकार की आवश्यकता है, इसलिए अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन का मार्ग ही ऐसा मार्ग है, जो वर्गों का तो निराकरण करता है, मगर धर्मियों का समाह्वय सम्भव बनाता है। दिना किसी बलह प्रतिहिंसा और वैमनस्य को उपजाए वह अमीर और गरीब दोनों को पास लाकर खड़ा कर देता है। अभी कुछ दिन पहले अपने देश में तैलगाना

प्रश्न

- (१) काले पदों की व्याख्या कीजिए ।
- (२) उपर्युक्त भ्रवतरण को उपयुक्त शीर्षक दीजिए और उसकी संक्षेपिका बनाइए ।
- (३) भूदान को हृदय-परिवर्तन की क्रांति क्यों कहा गया है ?

अभ्यास १७

लोक-शक्ति निर्माण

भूदान-यज्ञ-ग्रान्दोलन का कार्यक्रम एक नई ग्रहिसक समाज-रचना का है, जिसमें विषमता न हो, शोषण और उत्पीडन न हो, स्वार्थ और लोभ न हो, जिसमें ग्राहमी-ग्राहमी के बीच परस्पर प्रेम और सद्भाव हो । जैसा ग्रान्दोलन का साध्य है, वैसे ही उस तक पहुँचने के लिए उसकी मोर्चाबन्दी है । उसे न अमेरिका की द्रव्यशक्ति का भरोसा है और न रूस की हिंसा शक्ति का । उसने एक तीसरी शक्ति, लोक-शक्ति को अपना आधार बनाया है । माता द्रव्य के लोभ में या हिंसा के भय से बच्चे को स्तन पान नहीं कराती । जो प्रेम और सद्भाव उसमें है, वही सारे मनुष्यों में है और वे ही मानव-जीवन की समृद्धि के मूल्य हैं । भूदान-यज्ञ इसी प्रेम और सद्भाव की शक्ति को सामाजिक रूप में विकसित करके लोक-व्यापक बनाना चाहता है । इसी का दूसरा नाम लोक-शक्ति है । इस शक्ति के द्वारा भूदान-यज्ञ का उद्देश्य कोई सम्प्रदाय या दल स्थापित करना नहीं है । वह तो इसके द्वारा और इसे अधिक व्यापक बनाकर ग्राम जनता में घुल-मिल जाना चाहता है और लोगों को केवल युद्ध मनुष्य बने रहने की सीख देना चाहता है ।

भूदान-यज्ञ द्वारा उत्पन्न यह नई लोक-शक्ति सामान्य दण्ड-शक्ति से भिन्न है, लेकिन उसकी विरोधी नहीं है । दण्ड-शक्ति सारा समुदाय सरकार के हाथ में सौंपता है । यह निरी ग्रहिसक भी नहीं है और इसके द्वारा जन-सेवा के कार्य भी हो सकते हैं और हो रहे हैं, लेकिन उसका कार्य-क्षेत्र संकुचित है । अगर चन्द लोगों के संकट-निवारण की समस्या हो तो दण्ड-शक्ति उसे मुलभूत सकती है । वह जनसेवा के लिए कई रचनात्मक कार्य भी कर सकती है, लेकिन जहाँ विचार की विचार से टक्कर हो, जहाँ एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने की बात हो, वहाँ दण्ड-शक्ति बेकार है । सरकार अपनी मेना से युद्ध लड़ सकती है और शान्ति कायम कर सकती है, लेकिन जहाँ युद्ध को जड़-मूल से ही समाप्त करना हो, वह हथियार डाल देती है । इसलिए विनोद विनोदपूर्ण ढंग से कहते हैं—“दो बैल जब गाड़ी में लग चुके हों, तब मैं और तीसरा बैल दबूंगा तो गाड़ी को क्या मदद मिलेगी ? अगर मैं यह बर सूँ कि रास्ता जरा ठीक बनाऊँ ताकि गाड़ी उचित दिशा में जाय तो उस गाड़ी को मैं अधिक मदद पहुँचा सकता हूँ ।” तो भूदान-यज्ञ दण्ड-शक्ति का विरोधी नहीं है, पूरक है । जब

तक समाज को दण्ड-शक्ति की जरूरत है, तब तक उसके हाथ मजबूत करना ही हमारा धर्म है, लेकिन भूदान इससे भी एक कदम और आगे जाना चाहता है। वह लोक-शक्ति का निर्माण कर ऐसी परिस्थिति खड़ी करना चाहता है, जिसमें दण्ड-शक्ति के उपयोग का प्रबन्ध ही न रहे। उसकी यह मान्यता है कि कानून कुदृष्ट भी हो, जनता में ऐसी न्याय-बुद्धि का निर्माण हो कि लोग अपने आप भूमि का बंटवारा करें। जनता में इस न्याय-बुद्धि का सृजन उसके विचारों में क्रांति करके ही सम्भव है और इस वैचारिक क्रांति के लिए लोक-शक्ति के निर्माण की अपेक्षा है, जो अहिंसक समाज की आधार-शिला है।

इस नई लोक-शक्ति के निर्माण के लिए भूदान-यज्ञ-आन्दोलन को न द्रव्य का भरोसा है, न हिंसा का और न कानून का। उसका एक मात्र संबल विचार शासन है, अथवा विचार पर धरना और निष्ठा और विचार-प्रचार के लिए अटूट उत्साह। भूमि का दान विचार-परिवर्तन का एक कारण मात्र है, लेकिन उसका फल जीवन-शुद्धि और सामाजिक परिवर्तन है। इस फल की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब हम विचार-प्रचार के लिए गांव-गांव जाकर जनता में धुल-मिल जायें। कानून का 'छोट-काट' इस कार्य के लिए बिलकुल अनुपयुक्त है। भूदान-यज्ञ का अभियान सामाजिक क्रांति और जीवन-शोधन के लिए है, जिसके लिए अपने-आप विचार-परिवर्तन की अनिवार्यता है, इसलिए यह आन्दोलन विचार-शक्ति और उसके अभिमन्त्रित लोक-शक्ति के सिवाय और किसी अन्य शक्ति को मान्यता नहीं देता।

(सरस्वती)

प्रश्न

- (१) इस अवतरण को एक चौथाई के बराबर संक्षेप करके लिखिए।
- (२) काले भागों का अर्थ समझाइए।
- (३) लोक-शक्ति की व्याख्या कीजिए और भूदान-यज्ञ के मार्ग का औचित्य समझाइए।

अभ्यास १८

दो या तीन सौ वर्ष पूर्व एशिया और यूरोप का ढाँचा प्रायः एक ही समान स्तर पर था। तब एशिया के कई देश औद्योगिक शक्ति और समाज के उन्नतिशील संगठन में यूरोप से भी आगे बढ़े हुए थे, किन्तु एशिया पर यूरोप की राजनैतिक सत्ता कायम होने के कारण यूरोप को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगीकरण और युद्ध सम्बन्धी नई प्रक्रियाओं के निर्माण से यूरोप में समाज का जो नया निर्माण हुआ, उससे वह एशिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बन गया। यूरोप एशिया से न केवल आगे बढ़ गया, वह उसका राजनैतिक दृष्टि से स्वामी भी बन गया। मगर पिछले दशक की घटनाओं ने एशिया के बहुत बड़े भाग को राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रदान की और आज यह राजनैतिक असन्तुलन मिटाने के मार्ग में है। पर केवल राजनैतिक

स्वतन्त्रता प्राप्त होने से ही आर्थिक विकास का ल्पांतर होना सम्भव नहीं है। स्वतन्त्र होने पर भी इस क्षेत्र क कराडा व्यक्ति अन वस्त्र और स्थान की जीवन-सम्पत्त की आधारभूत आवश्यकताया क यभावो स दुख भेन रहे हैं, अतएव आज एशिया के विभिन्न देशा म जा नय गामन स्थापित हुए है उनकी परीक्षा इसी म होगी कि क इस क्षेत्र की निधनता दूर करने म कटा तक भाग लत ह।

पिछल कुछ दशका से ससार क सभी सभ्य देशो म लागा की आय सम्पत्ति और काम पाने क अवसरा की समानता पर पूरा बल दिया गया है। वर्तमान असमानता को दूर करन क लिए उत्तरातर अधिक कर लगाय जा रह है। यद्यपि देग क आतरिक जीवन म आय और साधना की असमानता कम हो रही है कि तु उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से तुलना नहा का जा सकती। ससार क विभिन्न भागा म आय और सम्पत्ति की असमानता इतनी अधिक है कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरिका—जिसम सब मिलकर ससार का जनसंख्या का दो तिहाई भाग है उसकी आय ससार की आय का लगभग एक छठवाँ भाग है। एशिया म ससार की आधी से अधिक जनसंख्या है परंतु उनकी आय ससार की राष्ट्रीय आय का बवल एक दसवा भाग है। दूसरी और उत्तरी अमरिका जिसम ससार की जनसंख्या का दस प्रतिगत स भा कम भाग है ससार का राष्ट्रीय आय का ४५ प्रतिगत भाग है। यह असमानता इस कारण स भी है कि ससार क सभी क्षेत्रा म एक समान प्राकृतिक साधन नहो हैं इसलिए ससार के अविकसित देगो म नया विकास होने पर भी उनक जीवन स्तर म अंतर बना ही रहेगा।

(सम्पदा)

प्रश्न

- (१) काले पदा का भावार्थ समझाइय।
- (२) उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दते हुए सक्षिप्त करके लिखिए जो १०० शब्दा स अधिक म न हो।
- (३) ससार क अविकसित देशा म नया विकास होने पर भी उनक जीवन स्तर म अंतर बना ही रहेगा। क्या आप इस कथन से सहमत है ?
- (४) एशिया और यूरोप क असमान स्तर के कारण पर प्रकाश डालिय।

अभ्यास १९

सूती वस्त्रा क उत्पादन का आदि स्रोत हान क कारण सहज ही भारत म पुरातन काल से इग प्रकार का प्राकृतिक वस्तुभा का व्यवहार हाता आया है जो वस्त्रो पर सीबत ग दगा काीनराकरण करती था। अभी तक भारतीय ग्रामा म रीठा खार (धार) आदि का उपयोग कम्बो न स्वच्छ करने म किया जाता है। रेशम, कोसा, अण्डी सभ्य कुछ वस्त्र ता आन भा चतुर स चतुर धात्री राठा की सहायता से ही

व्यतीत करने का वरदान देना भी पूँजीवाद का ही काम है। अधिकांश मनुष्यों की निर्धनता और घाबे से मनुष्यों की असीम धनसम्पन्नता पूँजीवाद का मुख्यतम अंग है। अत्यन्त निर्धनता तथा अल्पतम धनसम्पन्नता में बहुत पनिकट सम्बन्ध है, क्योंकि निर्धनों का ही शोषण करके उनकी राटी छीन कर, पूँजीपति अपनी थैलियाँ भरते हैं। फलतः एक धार किसान तथा मजदूर वकार घूमते हैं। क्षुधा की विभीषिका में सतृप्त होते हैं, ग्रीष्म में प्रचण्ड सूर्य की धातनात्रा को सहन करते तथा शीतकाल में नये ठिठुरते हैं, गंदी तथा अन्धकारपूर्ण गलियाँ में जीवन की घड़ियाँ गिनते तथा मृत्यु का आह्वान करते हैं, तो दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत पूँजीपति तथा जमींदार धनराशि संचित करके मोटरों तथा वायुयानों में देश विदेश की यात्रा करते तथा वाश्मीर और स्विट्जरलैंड की मनाहर घाटियों में भोग-विनासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस आर्थिक विषमता, शोषण भेद तथा बीभत्स शोषण का यन्त्र है पूँजीवाद। इस शोचनीय अवस्था में मनुष्य के समस्त विचारवान पुरुषों के मस्तिष्क में यह भय उत्पन्न कर दिया है कि यदि सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जायगा, तो न मानव समाज की क्या अवस्था होगी। वर्तमान समय में परिश्रम तथा साधनों की बरबादी से (जो बेकारी की बढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट है और जिसके दुःखदायी परिणाम से अनेक मनुष्य भूखा मरते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते) शायद ही कोई मनुष्य सतृप्त हो। हम प्रकृति के उदारतापूर्ण प्रदान किये गये अनेक पदार्थों के उपयोग से इसीलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उनका प्रयोग करना नहीं जानते। यह अवस्था देखकर विद्वानों का कहना है कि समाज के इतिहास में अब प्राणामी विकास का समय आ गया है। वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन की प्रणाली में एक उच्च श्रेणी के परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके द्वारा एक ऐसा समाज उत्पन्न हो जिसमें एक उच्च नैतिक आदर्श तथा एक उचित और उपयुक्त औद्योगिक प्रणाली का सामंजस्य हो, जो औद्योगिक क्रान्ति की पान्त्रिक सफलताओं को मनुष्य के हित के लिए अधिक सुगमतापूर्वक प्रयोग में ला सके जिसमें स्वतन्त्रता का अधिक विस्तार हो सके और सुख तथा सस्कृति की समृद्धि हो सके। इस प्रणाली को 'समाजवाद' का नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद का दावा है कि वह समाज को वर्तमान गति से निकाल कर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँचा सकता है।

(समाजवाद की रूप-रेखा)

प्रश्न

- (१) समाजवाद की व्याख्या कीजिए।
- (२) इस अवतरण को संक्षेप करके लिखिए।
- (३) कान्ते पदों का भावार्थ समझाइए।

अभ्यास २१

समाज के अतीत अन्धकार शोषण का सामूल नाश करने के लिए इसकी अर्थ-व्यवस्था में सामूल परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है। यह परिवर्तन तीन

रूप से कुछ नहीं किया गया है। तीसरी समस्या का सम्बन्ध हमारी खाद्य स्वावलम्बन नीति से है। विस्तृत आर गहन कृषि सम्बन्धी अनेक याजनाओं से कितना अधिक खाद्य पदार्थ पैदा होता है ? इसके आगलन की विधि बहुत अवैज्ञानिक है। खाद की एक निश्चित मात्रा के लिए अधिक अन्न की एक निश्चित मात्रा मान लेते हैं। परन्तु किसान की परिस्थितियों, देश के विभिन्न भाग और सभी ऋतुओं में यह कैसे ठीक होगी ? चायद लगातार न्यायादर्शन अधीक्षण से इसका विश्वसनीय आगलन मिल सकेगा।

(Agra, B Com I, 1954 S)

प्रश्न

(क) उन्मुक्त का अपन शब्दा में सक्षेप दीजिये।

(ख) काले भागा की व्याख्या कीजिए।

अभ्यास २४

प्राधुनिक आर्थिक उन्नति का एक अनिवार्य लक्षण है, अधिग्रहण द्राविक तथा वास्तविक आग्र हेतु अन्न का य न द्वारा विस्थापन, और अन्न का कृषि तथा सम्बन्धित उद्योग से हटना। भारत के भावी आदर्श वृत्ति-वितरण का रूप निश्चित नहीं किया जा सकता है। उस पर जनसंख्या सम्बन्धी शक्तियों, जनता की रूचि तथा मांग, उत्पादन प्रणाली और साधन स्रोतों का प्रभाव पड़ेगा। आयोजन नीति, पश्चिमी देशों का अनुभव तथा ज्ञान विज्ञान की सुविधाय प्राप्त होते हुए भी धातुओं तथा पूँजीगत वस्तुओं की कम पूर्ति, सुकुचित निर्यात क्षेत्र, नौकरशाही भावना तथा राजनीतिक गुट-बन्दी, भारतीय आर्थिक उन्नति की प्रगति को धीमा कर सकती है।

आर्थिक उन्नति कृषि क्षेत्र में देर से होगी। यह सर्वविधित है कि ग्रामों का अधिक महत्व है। वे अधिक कर-भार वहन करते हैं। नगर के बेकार वहा शरण पाते हैं। लागत अधिक होने पर भी वहाँ से श्रमिकों की पूर्ति होती है। परन्तु प्राकृतिक सकट, आन्तरिक अराजकता, शोषण तथा रोगों के कारण ग्रामवासी जनसंख्या नियंत्रण को कम महत्व देते हैं, यद्यपि किसी बात की उपयोगिता और आवश्यकता समझकर वे उस हेतु कोई उपाय उठा नहीं रखते। प्रति बीघा तथा प्रति अन्निक की औसत उपज में वृद्धि करना चाहिये। परन्तु दीर्घ काल के बाद ही किसान को औद्योगिक श्रमिक के समान पारिभ्रमिक मिल सकेगा। उसकी निम्न स्थिति का सुधार ग्राम और नगर में होने वाले अन्य परिवर्तनों पर निर्भर होगा। औद्योगिक उन्नति होने पर कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योग ध या से विस्थापित व्यक्तियों को पहले काम मिलेगा। अन्न जीवन स्तर की विभिन्नता के कारण ग्रामीणों के मन में उठने वाले क्षोभ और लोकतन्त्र के कारण सम्भव ग्रामीणों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिये शिक्षा-प्रसार तथा उच्च स्तर की राजनीति दोनों वाछनीय है।

औद्योगिक उन्नति के हित में ग्राहक को निम्न श्रेणी का माल धोखे से देना, कृषकों और उपभोक्ताओं की बेवसी से लाभ उठाना तथा श्रमिकों को उचित उच्च

सब धर्मों ने सत्य पर जोर दिया है, परन्तु हम “व्यावसायिक ईमानदारी” के भक्त बन रहे हैं। मक्किकल के लिए तर्क तो पेश करना ही पड़ेगा। इन्स्पेक्टर साहब धार रहे हैं, अतः स्कून की सफाई करानी ही चाहिए। बिना उपस्थित रहे दूसरों के द्वारा हाजिरी लग सकती है। वक्तृत्व कला का प्रदर्शन करना है, अतः त्रिपक्ष के समर्थ में गलत दलीले देना उचित है। अपने माल की भूठी तारीफ करना क्षम्य है। कम ज्यादा मोल-तोल बताना मामूली बात हो गई है। विज्ञापन बाजी को कला का रूप मिल गया है। डाक-गस्करण पर दो चार रोज वाद की तारीख डालना भी व्यावसायिक ईमानदारी है। तीर्थस्थानों में धर्म के नाम पर एक ही बद्धिया की पूछ पर अनेक लोग पानी छोड़ कर गोदान का पूर्य प्राप्त करते हैं। परन्तु क्या यह धर्म है? मत्स्य है? ईमानदारी है। (Agra B Com I, Supplementary 1956)

प्रश्न

- (१) निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेप लगभग ७५ शब्दों में दीजिये।
- (२) गद्यांश के काले पदों के अर्थ तथा महत्व स्पष्ट कीजिए।

अभ्यास २६

क्या यान्त्रिक उन्नति ही यथार्थ उन्नति है तथा भौतिक सफलता ही सभ्यता की एकमात्र कसौटी है? यदि पूर्वी जनता भी पश्चिम वामियों की भांति यन्त्रों और यान्त्रिक विधियों की ओर आकर्षित हो जाय, यदि वह भी विशाल औद्योगिक संस्थाओं तथा सामरिक संगठनों को कार्यान्वित करे तो वह शक्ति सघर्ष में फँसकर मृत्यु का आवाहन करेगी। वैज्ञानिक तथा यांत्रिक सभ्यता वृहत् अवसर और फल की दाता है, परन्तु वह वृहत् क्षतरे और मिथ्या आकर्षण भी लाती है। यह ममय्या मंमारध्यापी है। पूर्व और पश्चिम दोनों को वही भय है और वही भाग्य। विज्ञान तथा यांत्रिक प्रणाली न भले हैं, न बुरे, उनमें डरो नहीं। उन्हें मेवक बनाकर उनमें उचित कार्य लो।

प्राचीन समय में किसी मानव ने चकमक से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से मध्यकालीन युग में गुजर कर आज रेडियो और वम के आविष्कारक एक ही माला के मनके हैं। मानव निरन्तर यान्त्रिक उन्नति करता गया है। लेखनी, वृत्त, चक्र, पावडा, नाव, लीवर, इंजन, आन्तरिक-शक्ति चलित यंत्र सभी भौतिक विकास श्रम की देन हैं। यंत्र पदार्थ पर मस्तिष्क की विजय के प्रतीक हैं। वे साध्य नहीं हैं और न लक्ष्य ही। वे मानव ध्येय के साधन मात्र हैं। यदि हमारे लक्ष्य गलत हैं तो दौप हमारा है, यंत्रों का नहीं। उद्देश्य सही हो तो यंत्रों द्वारा अन्याय का निराकरण किया जा सकता है, मानव-अवस्था सुधारी जा सकती है तथा आत्म-विकास सुलभ हो सकता है।

इसी प्रकार धन की इच्छाएँ सभ्यता की मापदण्ड नहीं हैं। यह धनिचार्य नहीं है कि धन वृद्धि से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इच्छाओं की वृद्धि से अनर्ति

बढ़ती है। क्या खुसी हवादार अट्टालिकाओं में रहने वाले और आधुनिक यंत्रों के बल पर नाचने गाने वाले यथार्थतया सुखी है? कैसे बहे? गृहस्थ से पूछिए वह बहेगा कि आज की अपेक्षा अस्सी वर्ष पूर्व बाबा जी का जीवन अच्छा था। कम आय थी तब भी मजे में गुजर हो जाती थी। आज इस पक्के गृह में भी रात दिन चिंता पीछे लगी रहती है। सादगी तो उपात्म्य का शिखार बन गई है। धन और इच्छाओं को हटा कर सादगी और सन्तोष का प्रतिष्ठान कीजिए। सभ्यता और सुख दोनों मिल जायेंगे।

(Agra, B Com I, 1957 S)

प्रश्न

(क) उपर्युक्त गद्यांश का लगभग ७५ शब्दों में संक्षेप दीजिए।

(ख) काले भागों की व्याख्या कीजिए।

अभ्यास २७

यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ खो गया। यदि चरित्र गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के मार्ग में चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण रोड़ा है। यह सत्य है कि हमारी योजना देश के औद्योगीकरण हेतु है परन्तु उससे भी बड़ा सत्य है कि योजना के कारण भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीविका-साधन की पूर्ति में यथोचित वृद्धि होनी चाहिए। चारित्रिक कमी के दो पहलुओं के कारण हम पहले सत्य को तो ध्यान में रखते हैं, परन्तु दूसरे को भूल जाते हैं। चारित्रिक कमी का पहला पहलू यह है कि हम अक्सर पाकर भेड़क से सौंड बनना चाहते हैं। सामुदायिक योजना, रेल यातायात, बड़ी मिर्चाई-योजना-विधी से भी सम्बन्धित अधिकारी योजना के अन्तर्गत अपने मत्त्व को बढ़ा कर सिद्ध करते और अनुदान प्राप्त करते हैं। अड़तालीस अरब में से ११ अरब से अधिक रेल-विकासार्थ हैं। साठे तीन अरब सामुदायिक योजनाओं पर हैं। एक दही रबम मिर्चाई पर व्यय होगी। इन सभी के सम्बन्ध में लेखा-जोखा-निरीक्षण अपव्यय का सूचक है। बड़ी दुकान से बड़प्पन नहीं आता, न सफलता मिलती है। उसके लिए दूरदर्शिता तथा समन्वय-शक्ति का आवाहन आवश्यक है। उसके लिए त्याग की आवश्यकता है। शीघ्र औद्योगीकरण की तृष्णा में योजनाकार यह भूल गए हैं कि साधनों को शीघ्र गतिशील बनाना, उपलब्ध करना एवं अधिकतम क्षमतापूर्वक उपयोग करना अति आवश्यक है। वे यह भी भूल गए कि बेकारों का पोषण करने की जिम्मेदारी किसान अधिक भ्रदा कर सकता है क्योंकि पेट को भरना जितना उसके हाथ में है। किसी प्रकार की सफलता मिली हो उसका श्रेय योजनाकारों को मिल जाए, इस तृष्णा ने भी इस बात को और से योजनाकारों का ध्यान हटा दिया कि कृषि उत्पादन कम है। सन् १९५०-५५ में औसत एक सौ बीस करोड़ रुपये का खाद्यान्न प्रतिवर्ष आयात करते थे, परन्तु सन् १९५३-५४ की आशातीत फसल ने अधिकारियों को सन्तुष्ट कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि खाद्यान्न की कमी की समस्या भूमिगत हो गई। सन् १९५६-५७ में

खाद्यान्न-प्रायात लगभग एक अरब रुपए का पुन हुआ है। राज्य-सत्ता को घाँसे पुनः खुल रहीं हैं और घोटियों के फँटे बाँधे जा रहे हैं परन्तु चारित्रिक कमी के दूसरे पहलू पर ध्यान पूरा नहीं दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति मन लगाकर काम नहीं करता : वह अपनी कमजोरी और समस्या को दूसरे से मिलकर दूर नहीं करता। वह दूसरो के मत सुनने और उससे लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। केवल सघबल से सभी लोग बढ़ते भ्रूत्य और भ्रक्षमता की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु क्या रुपए से वस्तु बढ़ जावेगी ? वस्तुओं की मात्रा तभी बढ़ेगी जब हम उनको अधिक उत्पन्न करें। वस्तु नहीं होगी तो मिदाम का स्वर्ण क्या काम धायगा।

(Agra, B Com I, 1958 S)

प्रश्न

- (क) उपर्युक्त गद्यांश का ६० शब्दों में सक्षेप दीजिए।
 (ख) काले भागा की विवेचना कीजिए।

अभ्यास २८

१६ सितम्बर, १९५७ को ब्रिटिश बैंक दर में हृद में ज्यादा ऊँची वृद्धि करके उसे ७ प्रतिशत कर दिया गया था। यह नरीका इमीलिय अपनाया गया था कि ब्रिटेन के भीतर मूल्यो को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके और उसके विदेशी बित्त-मयो के प्रारक्षित कोष में उतनी मात्रा में वृद्धि हो, जिसमें पौड स्ट्रिंग क सकट में होने के सम्बन्ध में जो पूर्वानुमान लगाये जा रहे थे, व समाप्त हो जाय। इस तरह, यह एक बचाव का तरीका था। वस्तुओं के मूल्य की गिरावट, विदेश व्यापार की मन्दी और सयुक्त-राज्य अमेरिका में मन्दी की भावना की पृष्ठ-भूमि में उठाया गया यह कदम बहुते के विचार से एक निश्चित जुधा था। लेकिन कम मात्रा में जाना है कि इस जुए के दाँव में ब्रिटेन को सचमुच लाभ हुआ। यद्यपि अभी भी रिजर्व बैंक में बाहर नहीं हुआ है क्योंकि अभी विदेशों में उनकी मोटिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है, फिर भी पौण्ड पर सट्टेबाजी का दबाव समाप्त हो गया है। पौंड कुछ समय तक डालर के खिलाफ अपने ऊपरी सरक्षण बिन्दु के निवट ही नहीं कायम रहा है, बल्कि पौंड स्ट्रिंग की उन किम्पा के मामला में स्वतन्त्र-वाजाग्य दरों में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है जो कि पूर्णतः परिवर्त्य नहीं है। स्ट्रिंग की ताकत, जो कि कुछ हद तक ता चानू व्यापारिक मीदा में हुई वचता के कारण से और कुछ हद तक पिछले हेमन्त काल में घट गई व्यापारिक बचतो की मात्रा के फिर से पूरी हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है, पौण्ड क्षेत्र के साने और बाहर की प्रारक्षित निधि सम्बन्धी सरकारी आँकड़ों में हुई ठोस वृद्धि में व्यक्त हुई है। यह प्रारक्षित निधि पिछले मितम्बर से मूल्यों में गिरावट लाने के लिये अपनाया गये उपायों के फलस्वरूप हर महीने लगातार बढ़ती रही है। इसलिय ब्रिटेन ने बैंक दर को ७ प्रतिशत से घटाकर ६ प्रतिशत कर देने की घोषणा की और यह घोषणा एक दम उचित

पाया। बिहार के राज्यपाल ने भी उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा उनके हाथ से छोटी इलायची के छिलके में बन्द एक जनेऊ भेंट रूप में लिया। यह घटना हमें भारतीय कुटीर उद्योगों के प्राचीन वैभव और ढाका की मसमल की याद दिलाती है। कहा जाना है कि कनिष्क के समय भारतीय वस्त्रों की रोम में इतनी माँग थी कि वहाँ से प्रति वर्ष साढ़े पाँच करोड़ रुपए का सोना भारत आता था। यह घटना इस बात की साक्षी है कि भारत की उस कला में अब भी सजीवता है तथा वह भारत के कल्याण का कारण बन सकती है।

अभ्यास ३

भारतीय वस्त्र-निर्यात

कुछ काल पूर्व भारत करोड़ों रुपए का कपड़ा विदेशों से मँगाता था। अब यह स्थिति बदल गई है। अब भारत न केवल अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने लगा है, बल्कि बहुत सा कपड़ा विदेश भी भेजने लगा है। यह निर्यात भारतीय वस्त्र-उद्योग की अपूर्व उप्रति का सूचक है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये भारतीय वस्त्र-उद्योग को भारी संघर्ष करना पड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रयत्नों, स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रगति और स्वदेशी की भावना से अपनी स्थिति सुधारने में उसे अपार सहायता मिली है। तो भी कुछ न कुछ कपड़ा (महीन एवं उच्च कोटि का) भारत को अभी भी विदेश से मँगाना पड़ता है, क्योंकि आदान-प्रदान व्यापार का मूलभूत आधार है और पारस्परिक लाभ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रेरक।

अभ्यास ४

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन वस्तुओं के मूल्य-परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और मूल्यों के उतार-चढ़ाव देश के व्यापार-व्यवसाय के लिए घातक हैं। सन् १९५० के बेरियार्ड युद्ध-जनित मुद्रास्फीति से यद्यपि विश्व का कोई देश अछूता नहीं बचा तो भी कच्चे माल के उत्पादक एशियाई देशों पर इसका शीघ्र और गहरा प्रभाव पड़ा, तैयार माल के उत्पादक देशों पर कुछ कम और देर में। कारण? कच्चे माल के मूल्य परिवर्तन आमदनी में शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, तैयार माल के मूल्य परिवर्तन देर में। अतएव प्रथम श्रेणी के देशों में मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन दूसरी श्रेणी के देशों की अपेक्षा शीघ्र सामने आते हैं। भारत का स्थान दोनों श्रेणियों में समान रूप से है, क्योंकि उसके आयात-निर्यात में कच्चे और तैयार दोनों प्रकार के माल लगभग समान रूप में सम्मिलित हैं। मुद्रास्फीति के अस्वस्थ प्रभावों को रोकने के लिए युद्धोपरात काल में भारत ने अनेक प्रयत्न किए हैं, किन्तु उन्हें आंशिक सफलता ही मिली है।

अभ्यास ५

आर्थिक योजना का महत्त्व

मनुष्य की शक्ति में विश्वास रखने वाली बीसवीं शताब्दी की आर्थिक योजना दार्शनिकता की आधार मानती है। नियोजित कार्यक्रम में उत्पादन की स्वतन्त्र इकाइयों संगठित इकाइयों का समूह समझी जाती हैं और प्रत्येक इकाई सर्वमान्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही लक्ष्य का पालन करती है। योजना का उद्देश्य निश्चित अवधि के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों के सदुपयोग द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन में त्रुटिबद्धता लाना है। यह उत्पादन की प्रगति और रहन-सहन के स्तर में समतुलन स्थापित करती है तथा आज की सभी आर्थिक बुराइयों की दवा समझी जाती है।

अभ्यास ६

विदेशी पूँजी के दोष

विदेशी पूँजी से देश के साधनों का विदेशी हित में उपयोग होने, विदेशी राजनीतिक सत्ता स्थापित होने और औद्योगिक प्रबन्ध-संचालन विदेशियों के अधिकार में जाने की पूर्ण सम्भावना है। राष्ट्र-रक्षा एवं आधारभूत उद्योगों में विदेशी पूँजी का विनियोग भयानक है। इससे देश का स्वाभाविक औद्योगीकरण और पूँजी-निर्माण रुक जाता है तथा देश के युवक आवश्यक व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव और ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। (७१)

अभ्यास ७

नैतिक गुण

संसार के राष्ट्रों के आपसी मतभेद का मूल कारण नैतिक गुणों का ह्रास है जिसने संसार की स्वतन्त्रता संकट में डाल दी है। इसकी रक्षा नैतिक आदर्शों के विकास द्वारा ही संभव है, किन्तु आज के भौतिकवादी वातावरण में नैतिकता की चर्चा मात्र दम्भपूर्ण कही जाती है। वैज्ञानिक सफलताओं एवं आधुनिक यंत्रों ने इस प्रवृत्ति को और भी बल दिया है। (६२)

अभ्यास ८

लाभकर खाते

भूमि पर किसान को कानून द्वारा पूर्ण अधिकार देकर उसे लाभकर खातों में बांट देना चाहिए। लाभकर खाना १० एकड़ से कम न हो। इससे छोटे खातों का बटवारा न हो और न किसी को ३० एकड़ से अधिक भूमि रखने की आज्ञा हो। अतिरिक्त भूमि लाभकर खाते वालों को देदी जाए और खातों से बची भूमि पर गाँव-

समाज का अधिकार हो जिसे भूमि-कर उठाने और उसे खर्च करने का भी अधिकार हो । (७४)

अभ्यास ९

अणु-शक्ति और विकेन्द्रित उत्पादन

बहुधा लोग लघु-उद्योगों को पिछड़ेपन और बड़े उद्योगों को वैज्ञानिक प्रगति का सूचक समझते हैं । उनका यह भी विश्वास है कि बड़े-उद्योग और बड़े नगर भाई-भाई हैं । वस्तुतः, घनी-वस्तिवासी पूँजीपतियों और सरकारों के स्वार्थ और विचित्र मन्त्राजगटन के परिणाम हैं । विकेन्द्रित उत्पादन एवं सहकारी समाज के लिए यश-वना का उपयोग वैज्ञानिक भ्रमनति नहीं बड़ी जा सकती । अब अणुशक्ति न विकेन्द्रित उत्पादन का माग खोना दिया है । (७४)

अभ्यास १०

सयुक्त कृषि

यद्यपि सयुक्त कृषि के आलोचक भी उसके आदर्श से सहमत हैं, किन्तु वे उसे व्यावहारिक नहीं मानते । सयुक्त कृषि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसान का भूमि के प्रति भारी मोह है । अपनी भूमि पर दूसरे को खेती करने देना अथवा उस पर बहु-स्वामित्व उसे सह्य नहीं है । कृषि का केन्द्रीयकरण होने से किसान कारखाने के मजदूर की भाँति परतंत्र हो जायगा और उसकी कठिन परिश्रम सम्बन्धी प्रेरणा समाप्त हो जायेगी । ग्रामीण समाज के पारस्परिक भगड़े तथा ईमानदार एवं निस्वार्थ जन-सेवका का अभाव भी सयुक्त कृषि के मार्ग में बाधक है । (६५)

अभ्यास ११

अणु-युग

सूक्ष्म आकार के अणु में कोशले और पेट्रोल से लाखों गुनी शक्ति निहित है, जिनके विनाशकारी स्वरूप को दखकर सत्तार भयभीत हो उठा है, किन्तु अणु-शक्ति के अनेक रचनात्मक प्रयोग, जैसे रोग निवारण, औद्योगिक उत्पादन की कोटि और विधि सुधारने, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा मानव जाति के रहन-सहन को ऊँचा उठाने के लिए भी हो रहे हैं । इनकी सफलता मसार के अल्प विकसित देशों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और आज हम अणु-युग के सूत्रपान की कल्पना कर सकते हैं । (६२)

अभ्यास १२

अम-सघर्ष

वस्तुतः सीमित साधना द्वारा प्रसीम माध्या की प्राप्ति के लिए की जाने वाली ममत्त मानवी चपटायें अम हैं और एनी चपटायें करन वाले सभी व्यक्ति अमिक वर्ग में सम्मिलित हैं, किन्तु आज की औद्योगिक व्यवस्था में अम और अमिक की सकृचिन

व्याख्या करके श्रमिक वर्ग उत्पादको से भिन्न वर्ग माना जाता है, जो व्याज, लाभ, लगान और घेतन से भिन्न 'पारिश्रमिक' पर निर्भर रहता है और जिसे अपनी हित-रक्षा के लिए श्रम-नियोजको से समर्प्य करना पड़ता है। हड़ताले और तालाबन्दी होते हैं, जिनसे देश, उत्पादक, श्रमिक और उपभोक्ता सभी को भारी हानि होती है। (६८)

अभ्यास १३

बेकारी

बेकारी व्यक्तिगत पूँजीवाद की स्थायी और रुढ़िगत समस्या है, जो माँग और पूर्ति के असंतुलन से उत्पन्न होती है। कुछ लोग समष्टि पूँजीवाद की स्थापना में इसका हल बनलाते हैं, जो व्यावहारिक सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि न तो उत्पत्ति के सम्पूर्ण साधनों का सहसा राष्ट्रीयकरण ही सम्भव है और सम्भव भी हो तो यह अत्यन्त कष्टसाध्य है, क्योंकि उसके मार्ग में अनेक बाधाये हैं, जैसे उद्योगपतियों को पूर्तिधन देना, न देने पर गृह-युद्ध की आशंका तथा उद्योगों में सापेक्षक महत्व स्थापित करना इत्यादि। (८५)

अभ्यास १४

समाज का पुर्ननिर्माण

आर्थिक क्रियाओं का आधार समाज है और सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण आर्थिक विषमताएँ। अतएव एक सुदृढ और स्थायी समाज की रचना भी आर्थिक समता द्वारा ही सम्भव है। ऐसा समाज धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए भी श्रेयस्कुर है। अतएव जनतन्त्रीय शासन, राष्ट्रीय जनता तथा समाज-सुधारको का कर्तव्य अधिकारित एवं उपेक्षित क्षेत्रों के निवासियों, निम्न श्रेणी के लोगों तथा अभावग्रस्त जनता के प्रति विशेष है। ऐसे लोगों को मितव्ययता सिखाना, उन्हें व्यसनो से बचाना, उनका शारीरिक व मानसिक विकास, उनकी आनन्द वृद्धि इत्यादि कार्य उच्च कोटि की समाज-सेवा और सुखी एवं समृद्ध राष्ट्रीय जीवन के प्रतीक हैं। (१०४)

अभ्यास १५

भूदान

भूदान दान की एक नई कल्पना है, जो दान के प्रसंग से संग्रह के समर्पण, सामाजिक न्याय तथा सम्पत्ति के समान वितरण का साधन है। हवा, पानी, प्रकाश की भाँति भूमि भगवान की देन है, जिस पर किसी एक का अधिकार सामाजिक पाप है। उस पाप का प्रायश्चित्त भूस्वामी द्वारा उसके दान करके पुण्य कमाने और अपनी इज्जत बचाने में है। भूमिहीन को भूमि देना वैसा ही धर्म है जैसा भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। भूदान में याचक एक स्वजन है और याचना उसका अपना हक है, जिसे पाने का उसे पूर्ण अधिकार है। (६८)

अभ्यास १६

भूदान-यज्ञ

तेलगाना को हिंसात्मक घटनाओं से द्रवीभूत होकर विनोबाजी ने भूदान की अहिंसक, आर्थिक एवं सामाजिक शान्ति शुरू की, जिसका आधार प्रेम और अहिंसा द्वारा लोगों का मन-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन है। यह शान्ति वर्गों का निराकरण करके व्यक्तियों (अच्छे अमीरा और अच्छे गरीबों) के समन्वय पर जोर देती है। भूदान एक और अमीरा-गरीबों में न्याय-नुद्धि पैदा करके उनमें आत्मीयता उत्पन्न करता है और दूसरी ओर कानून बनाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। यह अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी दोनों की मालकीयत मांगता है ताकि अमीरों का अहंकार और गरीबों की दीनता दूर हो और दोनों की अंतःचेतना जागे। (११०)

अभ्यास १७

लोक-शक्ति

भूदान-यज्ञ आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य एक अहिंसक समाज रचना है, जिसमें विषमता, शोषण उत्पीड़न, स्वार्थ और लोभ न हो, केवल प्रेम और सद्भाव ही हो। साध्य के अनुरूप ही उसे प्राप्ति के साधन अपनाए गये हैं। द्रव्य शक्ति, शिक्षा-शक्ति और कानूनी बल उसके आधार नहीं, प्रेम और सद्भावना का लोक-अप्रापक रूप अर्थात् लोक-शक्ति और विचार-शासन ही उसके समूल हैं। यह लोक-शक्ति दण्ड-शक्ति से भिन्न होते हुए भी उसकी विरोधी नहीं पुरक है। तो भी भूदान ऐसी परिस्थिति खड़ी करना चाहता है जिसमें दण्ड शक्ति के उपयोग का अवसर ही न रहे अर्थात् जनता में ऐसी न्याय-नुद्धि उत्पन्न हो कि लोग स्वतः ही भूमि का बटवारा कर ले। भूमि का दान इस विचार-परिवर्तन का एक कारण मात्र है। उसके वास्तविक फल जीवन-शुद्धि और सामाजिक-परिवर्तन हैं। (१३६)

अभ्यास १८

एशिया का आर्थिक विकास

दो-तीन सौ वर्ष पूर्व एशिया भी यूरोप की भांति समृद्ध था, किन्तु औद्योगिक शान्ति और नई युद्ध-नीति ने यूरोप को एशिया से आगे बढ़ने और उसका राजनीतिक स्वामी बनने का अवसर दिया। अब एशिया और यूरोप का राजनीतिक असन्तुलन मिट चुका है, किन्तु उनकी आर्थिक विषमता शेष है। अतएव आर्थिक विकास द्वारा निर्धनता को दूर करता एशियाई देशों की सर्वे सरकारों का अग्र प्रथम कर्तव्य है। सभार के कई सभ्य देश भी इस ओर प्रयत्नशील हैं और शीघ्र सफलता की प्राप्ति है। तो भी प्राकृतिक साधनों से उत्पन्न असमानता से सर्वथा छुटकारा मिलना सम्भव नहीं। (१००)

अभ्यास १९

भारतीय साबुन उद्योग

शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के लिए प्राचीन काल से भारत में उबटन, रीठा, खार, सीकाकाई इत्यादि प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग होता आया है। उन्नीसवीं शताब्दी में साबुन के आगमन से हमारी स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी यह पुरातन पद्धति नष्ट हो गई और प्रथम युद्ध-काल में भारत में साबुन उद्योग की नींव पड़ी। तब से यह उद्योग बराबर उन्नति करता गया है और अब देश साबुन के लिए आत्म-निर्भर हो गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध में हमारे इस उद्योग को उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला। इसके मुख्य कारण विदेशी प्रतिযোগिता का अन्त, सुरक्षा विभाग की मांग, देश की बड़ी हुई जनसंख्या, लोगों की विलास-प्रियता, शहरी जीवन का शोक तथा साबुन निर्माताओं के सफल विज्ञापन इत्यादि हैं।

अभ्यास २०

समाजवाद

अधिकांश मनुष्यों की निर्धनता और थोड़े मनुष्यों की प्रसीम धन-सम्पन्नता पूँजीवाद के प्रधान लक्षण हैं, क्योंकि निर्धनों के शोषण द्वारा ही पूँजीपति अपनी रैलियाँ भरते हैं। एक ओर किसान-मजदूर भूखे, नंगे तथा बेकार यातनाएँ सहते हैं। दूसरी ओर पूँजीपति विवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्राथिक विषमता, भौषण भेद तथा वीभत्स शोषण का यन्त्र है पूँजीवाद। यह व्यवस्था हमें अनेक प्राकृतिक साधनों के उपयोग से वंचित रखती है। अतः इसके विरुद्ध अब भारी आन्दोलन होने लगा है और एक ऐसी प्राथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की मांग की जाती है जिसमें उच्चकोटि के नैतिक आदर्श, उपयुक्त औद्योगिक प्रणाली तथा स्वतन्त्र वातावरण का सामंजस्य हो। इस नवीन व्यवस्था को 'समाजवाद' कहा जाता है तथा सुख और समृद्धि उसके लक्षण बताये जाते हैं।

अभ्यास २१

भूदान यज्ञ

वर्तमान सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को बदलना आवश्यक है। इस परिवर्तन के तीन मार्ग हैं : एक हिंसात्मक, दूसरा कानूनी और तीसरा अहिंसात्मक। हिंसात्मक मार्ग प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि इससे केवल अस्थायी सफलता मिलती है तथा प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है और हिंसात्मकता बढ़ती है। तेलंगाना का अनुभव इसका साक्ष्य है। कानूनी मार्ग व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भूमि बिना प्रतिकर नहीं ली जा सकती और प्रतिकर के लिए अथवा धन चाहिए, जिसे न सरकार और न भूमिहीन

बर्ग ही देने में समर्थ हैं। विनोबा भावे द्वारा अग्रनाया हुआ तीसरा प्रेम और अहिंसा का मार्ग है, जिसे पर्याप्त सफलता मिल चुकी है और आगे भी मिलने की आशा है।

अभ्यास २२

स्वदेशी

देश की उन्नति और विकास के लिए आज हमें स्वदेशी की भावना और स्वदेशी के प्रचार की विशेष आवश्यकता है, यद्यपि आज स्वदेशी का रूप और कार्यक्रम पहले से भिन्न है। अब स्वदेशी की भावना केवल देश-भक्ती और उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए आवश्यक है। स्वदेशी का वर्तमान अर्थ है उत्पादन वृद्धि और आदान निपन्त्रण। यद्यपि इस कार्यक्रम की सफलता उपभोक्ता, सरकार और उत्पादक सभी के सम्मिलित सहयोग पर निर्भर है और सभी को यथाशक्ति स्वागभाव दिखाना चाहिए, तथापि सरकार और उत्पादकों का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व है।
